हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –**वाल्तेयर**

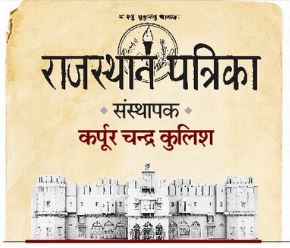

प्रकृति के संकेतों को नहीं समझने के भयावह नतीजे

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के ताजा पूर्वानुमान में उत्तर भारत में बरसात को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार सितंबर में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जो दीर्घकालीन औसत 109 फीसदी से अधिक हो सकती है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बरसात ने पहले ही तबाही मचा रखी है। पंजाब में सेना और एनडीआरएफ राहत कार्यों में जुटी है। वहीं दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश को पहले ही आपदाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जबकि उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे में आइएमडी का पूर्वानुमान सचमुच चिंताजनक है और स्थिति के और बिगड़ने का संकेत देने वाला है।

खास बात है कि इस संकट का प्रभाव केवल बाढ़ और भूस्खलन तक सीमित नहीं है। अत्यधिक बारिश ने कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई की आशंका बढ़ गई है। बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हैरत की बात है कि हर साल बारिश के मौसम में ऐसी ही स्थितियां पैदा हो जाती हैं और हम तैयारियों के नाम पर खुद को पहले जैसी ही स्थिति में खड़ा पाते हैं। इस संकट से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तात्कालिक स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करना, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और विस्थापित लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करना जरूरी है। बाढ़ प्रबंधन के लिए बेहतर जल निकासी व्यवस्था, नदियों के किनारों का सुदृढ़ीकरण और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन भी अनियमित मौसम, अचानक भारी बारिश और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का बड़ा कारण है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। वनों की कटाई पर रोक, नदियों और जलाशयों की सफाई और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। इसके साथ ही हमें अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना होगा और ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक उपयोग जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा।

प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो ऐसी आपदाएं बार-बार चेतावनी देती रहेंगी। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनना होगा ताकि हम प्रकृति के प्रकोप से बच सकें। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक सहभागिता को शामिल करते हुए नीतियां बनानी होंगी। यह समय केवल राहत कार्यों तक सीमित रहने का नहीं, बल्कि भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाने का है।

कर्पूर चन्द्र कुलिश
जन्म शताब्दी वर्ष
भाग -24

पुरानी शिक्षा पद्धति में शिक्षक अपने घर पर ही शाला चलाता था और उसके योग-क्षेम की व्यवस्था बच्चों के माता-पिता करते थे। आज भी...

चटशाला पद्धति रहती तो कम होता शिक्षा पर भार

हमारा जोर शिक्षक के बजाय स्कूल भवनों पर हो गया

शिक्षा प्रणाली में बदलाव के दौर में शिक्षक की भूमिका भी बदलती रही है। गुरुकुल परम्परा में ज्ञान लेने वाले शिष्य भी अब कम ही हैं तो चटशालाओं के माध्यम से अपने घर पर ही शाला चलाते शिक्षक भी नही हैं। शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) जरूर शिक्षकों का स्मरण कराता रहता है। कुलिश जी ने तीस बरस पहले ही हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के स्वरूप की चर्चा करते हुए लिखा कि मैकाले की शिक्षा प्रणाली में अब शिक्षक की बजाय स्कूल भवनों पर जोर हो गया है। आलेख के प्रमुख अंश:

पुरानी शिक्षा पद्धति का स्वरूप यह था कि शिक्षक अपने घर पर ही शाला चलाता था। विद्यार्थी वहीं पढ़ने जाते थे। शिक्षक के योग-क्षेम की व्यवस्था अपनी मर्जी से बच्चों के मां-बाप करते थे। प्रत्येक मास की प्रतिपदा (पड़वा) को सीधा-पेट्या (भोजन सामग्री) अवश्य नियमपूर्वक जोशी जी (शिक्षक) के घर पहुंचा दी जाती थी। गुरु पूर्णिमा और अन्य पर्वों पर भी गुरुजी का विशेष ध्यान रखा जाता था। इन घरेलू चटशालाओं में बच्चों को गणित और वर्णमाला तो पढ़ाई जाती ही थी । कहीं-कहीं ऊंची शिक्षा भी दी जाती थी, जिसमें रामायण, महाभारत, गीता जैसे काव्यशास्त्र पढ़ाए जाते थे। ऐसे संस्थान भी सैंकड़ों थे जहां कॉलेज जैसी ऊंची शिक्षा दी जाती थी। समय बहुत-कुछ बदल गया है। हमारी

शिक्षा को रोजगार से हर्गिज न जोड़ें

शैक्षणिक आवश्यकताएं भी बदल गईं परन्तु फिर भी गणित और वर्णमाला जैसी आवश्यकता आज तक बनी हुई है। आज भी हम उस प्रणाली का उपयोग क्यों नहीं करते? जब से मैकाले छाप शिक्षा प्रणाली चालू हुई तब से हमारा जोर शिक्षक के बजाय स्कूल भवनों पर अधिक हो गया। सरकारीकरण के कारण शिक्षक भी राज्याश्रित वर्ग या वेतनभोगी बन गए। शिक्षक की इच्छा से बड़ी इच्छा अब स्कूल इंस्पेक्टर की हो गई। पहले अभिभावक, शिक्षक के योगक्षेम की व्यवस्था करते थे, परन्तु कोई शिक्षक उनके अधीन नहीं था।

यदि पुरानी पद्धति का यथेष्ट उपयोग किया जाता या उसे मान्यता देकर चालू रखा गया होता तो हमारा देश कभी का साक्षर हो गया होता। उन शालाओं में जो गणित पढ़ाई जाती थी वह उम्र भर काम में आती थी। उस वर्णमाला की शिक्षा में वर्ण के स्वरूप को इस तरह समझाया जाता था कि सारी सृष्टि समझने की क्षमता पैदा हो जाए। उदाहरण है '**सिद्धौ वर्णाः समामनायः** 'अर्थात वर्ण समाम्नाय सिद्ध हैं। वर्ण एक नित्य पदार्थ है। वह भिन्न-भिन्न रूपों में हमारे सामने आता है। इन भिन्न रूपों को वर्णमाला की पढ़ाई में भलीभांति समझा दिया जाता। अब जरा सोचें कि इस छोटी सी बात को समझने के लिए न तो कोई कमीशन बैठाने की जरूरत हैं और न कोई नई नीति बनाने की जरूरत है।

साक्षरता के लिए खर्चीले कार्यक्रम

सरकार के सिर से प्राथमिक शिक्षा का सारा भार उतर जाता यदि वह इतना सा तय कर लेती कि पुरानी चटशाला पद्धति को चालू रखती। उसे प्राथमिक शिक्षा के समान कर दिया जाता। उस पढ़ाई के बाद माध्यमिक शालाओं में सीधे प्रवेश दे दिया जाता। प्राथमिक शाला के हजारों भवन, लाखों शिक्षक एव पाठ्यसामग्री का भार सरकार को उठाना नहीं पड़ता। कुछ विशेष प्रयत्न करके ऐसे क्षेत्रों में भी शालाएं खुलवाई जा सकती थीं जो उपेक्षित हैं। यह काम भी गैर सरकारी तौर पर किया जा सकता था। मेरे कथन में यदि कोई अव्यावहारिक कठिनाई है तो उसे दूर करने का उपाय सोचा जा सकता था। साक्षरता के लिए तरह-तरह के खर्चीले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आज सरकार चलाती है क्योंकि यह अमरीका से 'आइडिया' आयात किया गया है।

(3 मई 1995 को *'शिक्षा को रोजगार से हर्गिज न जोड़ें'* आलेख के अंश)

पढ्या-अनपढ्या

***पापी पेट भरै सभी,
पढ्या-अनपढ्या एक।
पढ़-लिख कर तो चायजे,
भरणूँ पेट अनेक।।***

('सात सैंकड़ा' से)

शिक्षक भी नौकर और शिक्षा पाने वाला भी

अभी हम यह नहीं सोच पाए कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? हम यह भी नहीं सोच पाए कि हमारी अगली पीढ़ी किस तरह की बने? शिक्षक भी नौकर है और शिक्षा पाने वाला भी नौकर ही बनना चाहता है। नौकरी प्रधान इस शिक्षा को स्वावलम्बन की दिशा देना प्रमुख शर्त होनी चाहिए। कैसी विडम्बना है कि शिक्षित बेरोजगार भी देश की अनेक समस्याओं में से एक समस्या है। शिक्षा पाकर भी पेट की चिंता में ही भटकना है तो अशिक्षित और पशु से वह किस प्रकार भिन्न होगा। पेट तो अशिक्षित को भी, पशु को भी भरना है।

(कुलिश जी के आलेखों पर आधारित पुस्तक ***'दृष्टिकोण'*** *से)*

(जारी... कुलिश जी का सृजन संसार पढ़ें आगामी गुरुवार को भी)

डिजिटल संप्रभुता : अपनी विशाल डेटा संपदा पर अमरीकी कंपनियों का वर्चस्व करना होगा खत्म

डेटा हमारा, नियंत्रण पराया : 'आत्मनिर्भर डिजिटल भारत' के करने होंगे प्रयास

डॉ. मिलिंद कुमार शर्मा
प्रोफेसर, एमबीएम यूनिवर्सिटी, जोधपुर
@patrika.com

गूगल वर्कस्पेस एवं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्थानीय विकल्पों को सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य करने पर सोचना होगा। सोशल मीडिया के विभिन्न भारतीय विकल्प खोजना कठिन नहीं है।

भारत का डिजिटल आधार विदेशी कंपनियों विशेषकर अमरीकी संस्थानों यथा गूगल अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एक्स और मेटा इत्यादि पर अत्यधिक निर्भर है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आज भारत की ईमेल सेवाओं से लेकर क्लाउड स्टोरेज, सर्च इंजन और ऑपरेटिंग सिस्टम तक अधिकांश आधारभूत ढांचे पर अमरीकी कंपनियों जैसे मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि का ही वर्चस्व है। निसंदेह यह स्थिति भारत की डिजिटल संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौती है।

डिजिटल निर्भरता का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह किसी भी समय राजनीतिक अस्त्र में परिवर्तित हो सकती है। सभी ने देखा है कि हाल में अमरीका ने किस प्रकार टैरिफ वॉर की नीति अपनाते हुए कई देशों पर ऊंचे आयात शुल्क थोपे हैं। यदि यही रणनीति डिजिटल क्षेत्र में अपनाई जाती है, तो इसके परिणाम कहीं अधिक भयावह होंगे। यदि अमरीकी राष्ट्रपति कोई कार्यकारी आदेश पारित कर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन जैसी कंपनियों को भारत की क्लाउड सेवाओं, ई-मेल सेवाओं या सॉफ्टवेयर अपडेट रोकने को निर्देशित करे तो क्षणभर में भारत के बैंकिंग, स्वास्थ्य, रक्षा, आपूर्ति सेवा, ऊर्जा, परिवहन और संचार क्षेत्र संकट में आ जाएंगे। कुछ समय पूर्व देखा गया था कि किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ठप होने से वैश्विक स्तर पर एयरलाइंस, बैंक और मीडिया हाउस प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त भारत में डिजिटल विज्ञापन, क्लाउड सेवाओं और ऑपरेटिंग सिस्टम का अधिकांश हिस्सा अमरीकी कंपनियों के हाथ में है। यदि किसी दिन ये कंपनियां शुल्क अचानक बढ़ा दें या भारत संस्थानों को प्रतिबंधित सूची में डाल दें, तो भारतीय उद्योग जगत और समस्त वाणिज्य व व्यापार भारी संकट में आ जाएंगे। यदि यूट्यूब, गूगल सर्च या माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं से अचानक भारतीय भाषाओं की सामग्री को हटा दिया जाए या सीमित कर दिया जाए, तो करोड़ों भारतीय उपभोक्ता व कंटेंट क्रिएटर्स डिजिटल रूप से हाशिये पर चले जाएंगे।

वहीं चीन और यूरोपीय संघ के उदाहरण भारत के लिए अनुकरणीय हो सकते हैं। चीन तकनीक के अन्य क्षेत्रों के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से रणनीतिक प्रयोग को जल्द ही भांप के समझ लिया था कि डिजिटल संप्रभुता के बिना कोई भी राष्ट्र अपने दीर्घकालीन राजनीतिक हितों की रक्षा नहीं कर सकता है। यूरोपीय संघ भी कड़े डेटा सुरक्षा कानून बनाकर अमरीकी कंपनियों के प्रभाव को सीमित करने के लिए प्रयासरत हैं। डिजिटल स्पेस में भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका विशाल डेटा भंडार है। विश्व में भारत एक बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता बाजार है। यह डेटा अमरीकी आइटी कंपनियों के लिए सोने की खान सिद्ध हो रहा है। वे इसी डेटा का उपयोग अपने एआइ मॉडल और एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने में कर रहे हैं। भारत का डेटासेट न केवल विशाल है अपितु अत्यंत विविधतापूर्ण भी है। भारत को भी अपने डेटा की सुरक्षा और नियंत्रण पर ध्यान देकर अपनी सबसे बड़ी संपदा पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करने होंगे। इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारत में पास विकल्प कम नहीं हैं। विशाल आइटी प्रतिभा, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल साक्षरता मिलकर एक स्वतंत्र डिजिटल मॉडल खड़ा कर सकते हैं। नीतिकारों के लिए आवश्यक है कि वे स्थानीय क्लाउड और ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए सक्षम नीतियों को दिशा दें, सरकारी विभागों में घरेलू तकनीकी समाधानों का अनिवार्य प्रयोग करे और डेटा लोकलाइजेशन के नियमों को और सख्त बनाए। रक्षा क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर लिनक्स अथवा स्थानीय प्लेटफार्म को प्राथमिकता देने पर विचार करना होगा।

इसी प्रकार स्थानीय प्लेटफार्म विकसित कर मोबाइल फोन में भी गूगल के एंड्राइड व एप्पल के आइओस पर निर्भरता कम करने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे। गूगल वर्कस्पेस एवं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्थानीय विकल्पों को सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य करने पर गंभीरता से सोचना होगा। आत्मनिर्भर डिजिटल 2.0 अभियान, डिजिटल स्वराज मिशन को क्रियान्वित कर वर्ष 2030 तक गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवा इत्यादि के साथ-साथ सोशल मीडिया व मैसेजिंग के विभिन्न भारतीय विकल्प खोजे जाना कठिन नहीं होगा। स्थानीय क्लाउड कैपेसिटी के लिए 'मेघराज' जैसे प्लेटफार्म को सरकारी वित्तीय सहायता से और सुदृढ़ करना होगा। राष्ट्रहित में साइबर सिक्योरिटी के लिए डीआरडीओ, सी-डेक, तकनीकी संस्थानों, स्टार्टअप्स को संयुक्त प्रयास करने होंगे।

बीहाइव हट्स: आयरलैंड के द्वीप पर अनोखी झोपड़ियां

यह तस्वीर आयरलैंड के दक्षिण-पश्चिमी तट से दूर स्थित छोटे से द्वीप स्केलिग माइकल की है। यहां पत्थर की झोपड़ीनुमा संरचनाएं हैं जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी बनी हुई हैं। ये गुम्बदाकार 'बीहाइव हट्स' वास्तव में प्राचीन मठवासियों ने बनाई थीं। माना जाता है कि छठी से बारहवीं शताब्दी के बीच यहां एक एकांतवासी ईसाई मठवासी समुदाय निवास करता था। समुद्र से घिरा यह द्वीप अत्यंत दुर्गम था, जहां जीवन यापन करना बेहद कठिन था।

खूबसूरती व गुणों से भी भरपूर है पैशन फ्लावर

पासिफ्लोरा, जिसे आमतौर पर पैशन फ्लावर के नाम से जाना जाता है खूबसूरत और औषधीय पौधा है। यह पौधा मुख्य रूप से गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके फूलों की सुंदरता और चिकित्सीय गुण इसे खास बनाते हैं। पासिफ्लोरा न केवल प्रकृति का एक आकर्षण है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इस पौधे के फूल रंग-बिरंगे और जटिल डिजाइन के होते हैं, जो इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इसके फल, जिन्हें पैशन फ्रूट कहते हैं। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में इसकी जड़ों, पत्तियों और फूलों का उपयोग चिंता, अनिंद्रा और तनाव जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है।

इसके लिए इसकी हर्बल टी या अर्क बनाया जाता है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। पासिफ्लोरा की खेती अब भारत के कई हिस्सों में शुरू हो रही है खासकर दक्षिणी राज्यों में जहां जलवायु इसके लिए अनुकूल है। किसानों को इससे अच्छी आय भी मिल रही है।

फैक्ट फ्रंट

प्रसंगवश

मेडिकल फिटनेस की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ पारदर्शी बनाएं

सरकारी नौकरी पाने में अपात्र सफल हो गए और पात्र दिव्यांगों का हक छीन लिया गया

सरकारी नौकरियों में पेपरलीक और नकल के मामलों से अलग बड़े भ्रष्टाचार के उदाहरण फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के भी हैं। यह ऐसा भ्रष्टाचार है, जिसमें मिलीभगत के जरिए न केवल अपात्रों का सरकारी भर्तियों में चयन हो गया, बल्कि जो इसके पात्र थे उनका भी हक छीन लिया गया। ताजा मामला फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी होने का है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। चिंताजनक तथ्य यह है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है वे ही इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में हाल के वर्षों में शिक्षक, नर्सिंग और पुलिस बेड़े में हुई भर्तियों में कई अभ्यर्थी इन फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी पाने में सफल हो गए। यों तो कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय से ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन जयपुर और भरतपुर जिलों में ऐसे मामले सबसे ज्यादा सामने आए। दिव्यांगों के साथ पहले ही नियति ने क्रूर मजाक किया है। सरकारी आरक्षण की वजह से नौकरी पाने की उम्मीद में ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। नौकरी वे पा जाते हैं, जो शारीरिक दृष्टि से अच्छे-भले हैं लेकिन सीएमएचओ के प्रमाणपत्रों के हिसाब से दिव्यांग। जब डॉक्टर की कलम बिक जाए और अफसर की मुहर झुक जाए, तो हकदार वंचित रह जाते हैं।

अब वक्त है कि मेडिकल सर्टिफिकेट का डिजिटल वेरिफिकेशन और सख्त कार्रवाई अनिवार्य हो। तकनीक आधारित जांच और पारदर्शिता से ही ऐसी गड़बड़ी रोकी जा सकती है। एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल में सभी रिपोर्ट अपलोड हों और उम्मीदवार सत्यापित कर सके। सरकार मेडिकल फिटनेस को 'औपचारिकता' की बजाय पारदर्शी और सरल प्रक्रिया बनाए। तभी युवाओं की मेहनत का सही सम्मान होगा

- **राजीव जैन**
rajiv.jain@in.patrika.com

जन धन योजना के 11 वर्ष पूर्ण | योजना ने बढ़ाया आर्थिक आत्मविश्वास, बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

जन धन से जन विश्वास तक: वित्तीय समावेशन की क्रांति

वी.अनंत नागेश्वरन
(लेखक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं)
@patrika.com

योजना की स्थिति

शुरुआत
28 अगस्त 2014

67.0 तक पहुंच गया मार्च 2024 तक वित्तीय समावेशन सूचकांक

अब तक खुले खाते
56 करोड़ से अधिक (8 अगस्त 2025 तक), जिसमें **67%** ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों में।

55% से ज्यादा खाते **महिलाओं के हैं।**

वित्तीय समावेशन सतत विकास की एक अनिवार्य शर्त है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 7 इसे दुनियाभर में समावेशी विकास के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में मानते हैं। वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला कदम बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से शुरू होता है क्योंकि बैंक खाता औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

इसलिए वित्तीय समावेशन के लिए स्पष्ट और संरचित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि शुरू से ही इस सुविधा से वंचित लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा सके। इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के पहले संबोधन में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) की घोषणा की गई, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के अंतर्गत 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इस मिशन का विजन 'मेरा खाता, भाग्य विधाता' के नारे में समाहित था। इसका उद्देश्य गरीबों और लंबे समय से वंचित वर्ग के लोगों को आर्थिक मुख्यधारा में लाना, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक उनकी पहुंच को साकार कराना और यह सुनिश्चित करना था कि वे भारत की विकास गाथा के हितधारक और लाभार्थी बनें। जन धन खातों ने लाभार्थियों को न्यूनतम कागजी कार्रवाई और सरलीकृत केवाईसी/ई-केवाईसी प्रक्रियाओं के साथ जीरो-बैलेंस और शून्य-शुल्क वाले खाते खोलने की अनुमति दी। इसके अंतर्गत रुपे डेबिट कार्ड पर दो लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर और दस हजार रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपनी शुरुआत के बाद से अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 2017 के बीच भारत में खाताधारकों की संख्या में 26 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसका श्रेय दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन अभियान-पीएमजेडीवाय को दिया जा सकता है। यह वैश्विक खाता वृद्धि (6.57) से लगभग चार गुना अधिक है और इसी अवधि के दौरान विकासशील देशों (7.27) की तुलना में तीन गुना अधिक है। 8 अगस्त 2025 तक 56 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 67 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित बैंक शाखाओं में हैं। इस योजना ने लैंगिक असमानताओं को भी स्पष्ट रूप से पाट दिया है- पीएमजेडीवाय के 55 प्रतिशत से अधिक खाते यानी 31 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के पास हैं। इसके अलावा, जन धन खाते सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। हाल के संसदीय आंकड़ों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाय) के तहत लगभग एक-तिहाई नामांकन पीएमजेडीवाय से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की आधारशिला के रूप में भी उभरा है। इसने भुगतान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है और लाखों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सफलता को आधार प्रदान करके, पीएमजेडीवाय ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, कल्याणकारी वितरण में लीकेज को कम किया है और सरकारी योजनाओं में विश्वास को मजबूत किया है। आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने में सहायक रही है। जन धन खातों और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआइ) के बीच तालमेल ने अनौपचारिक क्षेत्र के छोटे और सीमांत उद्यमियों को व्यवसाय करने के लिए औपचारिक वित्तीय चैनलों तक पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया है। वर्ष 2021 की एसबीआइ रिसर्च रिपोर्ट में पाया गया कि जनधन खातों में ज्यादा जमा राशि वाले राज्यों में अपराध की घटनाओं में कमी देखी गई और जिन राज्यों में प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता ज्यादा खुले हैं, वहां शराब और तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों के सेवन में महत्त्वपूर्ण कमी दर्ज की गई। बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच अब जब साकार होने की ओर है, ऐसे में आगे की चुनौती वित्तीय समावेशन को और गहरा करने की है। उत्साहजनक रूप से, आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस दिशा में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। वित्तीय समावेशन के तीन आयामों- पहुंच (35 प्रतिशत), उपयोग (45 प्रतिशत) और गुणवत्ता (20 प्रतिशत)- से संबंधित जानकारी को समाहित करने वाला यह समग्र सूचकांक 2021 में अपनी शुरुआत के बाद से लगातार बढ़ रहा है और मार्च 2024 तक 67.0 तक पहुंच गया है। इस पैमाने पर जहां शून्य पूर्ण बहिष्कार और 100 पूर्ण समावेशन को दर्शाता है, भारत का निरंतर शीर्ष की ओर बढ़ना देशभर में वित्तीय समावेशन के गहन और व्यापक होने को रेखांकित करता है।

बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को आर्थिक मुख्यधारा में लाने में प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता, एक बार की उपलब्धि नहीं है। यह गहन वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

आपकी बात

माइक्रोप्लास्टिक से प्रदूषण

फास्ट फैशन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जिसमें जल प्रदूषण, भारी मात्रा में पानी और ऊर्जा का उपयोग, माइक्रोप्लास्टिक कचरा, हरित गृह गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसमें भूमि व जलीय पारिस्थितिक तंत्रों का क्षरण शामिल है। फास्ट फैशन उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 92 मिलियन टन कचरे के लिए उत्तरदायी है। फास्ट फैशन में इस्तेमाल होने वाले 60 फीसदी से अधिक कपड़े नायलॉन व पॉलिस्टर के होते हैं।

- **सुरेन्द्र कुमार**, हनुमानगढ़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'फास्ट फैशन से पर्यावरण पर किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

https://shorturl.at/McXyG

आज का सवाल

सेमीकंडक्टर चिप देश में ही बनने के बाद तकनीकी क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन होने की उम्मीद है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

प्रेरणा

बहुत ज्यादा सोचना एक रोग है, जो इस रोग से मुक्त हैं, वे स्वस्थ हैं, वे धन्य हैं।- **हरिशंकर परसाई**

संपादकीय

गरीब-अमीर की खाई असंतोष बढ़ा सकती है

आईटी विभाग के वर्ष 2024-25 के रिटर्न्स पर आधारित आंकड़े बताते हैं कि एक साल में 10 करोड़ सालाना कमाने वाले 73% बढ़े, 5 से 10 करोड़ आय वाले 66.96%, 1 से 5 करोड़ आय वाले 47.56%, 50 लाख से 1 करोड़ आय वाले 31.92% और 10 से 50 लाख आयवर्ग वाले 17.23%। लेकिन 5 से 10 लाख आय वाले वर्ग में मात्र 10.93% वृद्धि हुई। यानी जो लोग पहले ही उच्च आय वर्ग में हैं, उस वर्ग में आय बढ़ाने के मौके ज्यादा हैं। इस तालिका से यह भी पाया गया कि हर माह 1 करोड़ कमाने वाले के पास आयवृद्धि के मौके ज्यादा होंगे और यह विस्तार कम आय के कम होता जाएगा। यानी जो लोग हर माह 1 लाख से कम आय करते हैं, उनके आय बढ़ाने के अवसर कम हैं। इसके अलग एक और आंकड़ा है, जिसके तहत सबसे बड़े आधार- 1 लाख से 5 लाख सालाना (या 8 हजार से 42 हजार महीने तक की कमाई)- वाला वर्ग 18.59% बढ़ा। इन आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापक निजी क्षेत्र खासकर टेक-ड्रिवन जॉब्स में तो उच्च और मध्यम श्रेणी के कामगारों की वेतन वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक उपक्रमों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में जहां पारम्परिक सेवाओं में नियोजन होता है, आय बढ़ने के अवसर कम हैं। नीतिकारों को सोचना होगा कि कृषि- जो 46% रोजगार देती है- में मजदूरों की स्थिति बदतर क्यों है?

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

बुद्धि होने से नहीं, बुद्धि को मांजने से बुद्धिमान होते हैं

हम अपने बच्चों का नाम बहुत सोच-संभलकर रखते हैं। पहले सीधे-सादे नाम हुआ करते थे। अब जिसका भी नाम पूछो, उसका अर्थ भी जानना पड़ता है। लेकिन अपने बच्चों की परवरिश में पैसा, समय और परिवार की कीमत जरूर समझाइएगा। उनके नाम को त्याग और उत्साह से जोड़िए। ये प्रदर्शन का युग है। लोग अपने संकल्पों का भी प्रदर्शन करने लगते हैं और यहीं से दबाव में आ जाते हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि संकल्प तो लें पर बिना शोर-शराबे के उसे पूरा करें। और जब वो ऐसा कर रहे होंगे तो सुख और दुःख जीवन में आएंगे। इसकी तैयारी बहुत कम माता-पिता अपने बच्चों को कराते हैं। क्योंकि सुख भी दुःखों का मध्यांतर है। हम अपने बच्चों से कहें कि स्वाभिमान उतना ही रखें कि गरिमा बनी रहे। बुद्धि होने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। बुद्धि को मांजने से होता है। और बुद्धि को मांजने के लिए सांसारिक और आध्यात्मिक तरीके संयुक्त रूप से आजमाए जाएं। यह बात बच्चों को समझाने का समय आ गया है। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • हम किसी खेमे या गुट में नहीं होना चाहते

अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों में संतुलन साधना ही हमारी ताकत रही है

देश-दुनिया

शशि थरूर
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद
office@tharoor.in

वैश्विक कूटनीति के रंगमंच पर भारत ने लंबे समय से एक सधा हुआ संतुलन साधने में दक्षता हासिल की है- सिद्धांत रूप में गुटनिरपेक्ष, व्यवहार में व्यावहारिक। आज जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, निष्ठाएं बदल रही हैं और विश्व-व्यवस्था बिखर रही है, भारत एक बार फिर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है।

अमेरिका से हमारे संबंध विशेष रूप से तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रम्प टैरिफ के व्यापक आर्थिक परिणाम होंगे, क्योंकि पिछले साल भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का योगदान 18% था। लेकिन यह केवल एक व्यापारिक मुद्दा भर नहीं है। अमेरिका और भारत एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से अपने रणनीतिक संबंधों को गहरा कर रहे थे और अमेरिका उभरते भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी प्रभाव के एक महत्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखता आता रहा है। लेकिन नए टैरिफ इस बात की याद दिलाते हैं कि मजबूत साझेदारियां भी किसी नेता की सनक के आगे झुक सकती हैं।

पाकिस्तान के साथ अमेरिका की गलबहियां रणनीतिक रूप से और परेशान करने वाली हैं। अमेरिका के दीर्घकालिक आर्थिक, तकनीकी और सामरिक हित अभी भी भारत के साथ जुड़े हैं। इन हालात में चीन का पाकिस्तान को समर्थन भारतीय सुरक्षा के लिए जोखिम को बढ़ाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य और राजनयिक समर्थन की पेशकश की थी। वह पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है और उनमें वे हथियार भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। इसके अलावा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की सबसे बड़ी परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, जो दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर केंद्रित है। चीन-पाकिस्तान धुरी अब महज एक सामरिक गठबंधन नहीं; रणनीतिक समझौता भी है। यह भारत से व्यापक प्रतिक्रिया की मांग करता है, जिसमें घरेलू आर्थिक लचीलापन, सैन्य तैयारी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक पहुंच शामिल है।

इस सबके बीच, रूस के साथ भारत की साझेदारी मजबूत साबित हुई है। शीत युद्ध के गुटनिरपेक्षता के दौर में गढ़े गए इस द्विपक्षीय संबंध का आधार दोनों देश की रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति साझा सम्मान है। हालांकि दोनों देश हर बात पर सहमत नहीं हैं, फिर भी भारत रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण प्राप्त करता है और पुतिन इस वर्ष के अंत में भारत यात्रा पर आने वाले हैं। लेकिन यहां भी चिंता का एक कारण है। जैसे-जैसे रूस चीन पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा है, रूस के साथ भारत की साझेदारी को भी क्षति पहुंच सकती है।

बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के इस दौर में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में विविधता ला रहा है। यूरोप अपनी आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्गठन की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत ने यूके से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने और ईयू के साथ सुस्त हो चुकी व्यापार वार्ता को फिर गति देने का अवसर देखा था। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश चीन के लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में भारत को अपनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत अफ्रीका के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को भी पुनर्जीवित कर रहा है। जहां चीन ने लंबे समय से इस महाद्वीप के प्रति शोषणकारी दृष्टिकोण अपनाया है, वहीं भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारतीय निवेश का विस्तार करना भी शामिल है।

हम अमेरिका से प्रौद्योगिकी, रूस से ऊर्जा और हथियार, यूरोप से व्यापार और जलवायु और अफ्रीका और खाड़ी के साथ विकास और प्रवासी समुदायों के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। ऐसी नपी-तुली जटिलताएं स्पष्टता की मांग करती हैं।

खाड़ी क्षेत्र में 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं, और उनके द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि उनके परिवारों के लिए आर्थिक जीवनरेखा का काम करती है। आज खाड़ी देश तेल के कारोबार के अलावा भी अपने आयामों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत के पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है : तकनीक, प्रतिभाएं और व्यापार। यूएई से भारत का व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता और साथ ही सऊदी अरब से उसका बढ़ता रक्षा सहयोग रणनीतिक गहराई की ओर बदलाव का संकेत देता है।

एशिया में भारत को निश्चित रूप से शिंजो आबे के नेतृत्व की कमी खल रही है, जिन्होंने जापान से पहले से ही हमारे घनिष्ठ संबंधों को और गहरा करने का प्रयास किया था। लेकिन भारत की वास्तविक ताकत उसकी रणनीतिक चपलता में निहित है। कठोर गठबंधनों से बंधे रहने के बजाय हम अपने हितों से संचालित होते हैं। बदलते परिदृश्य में भी हमें समावेशी, नियम-आधारित और लोकतांत्रिक विश्व-व्यवस्था के दृष्टिकोण का समर्थन करते रहना होगा।

(© प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

मुद्दा • नौकरी के बजाय अच्छा लड़का मिलने की जिद

लड़कियों के लिए शादी ही प्राथमिक लक्ष्य कब तक?

दहेज प्रताड़ना

बरखा दत्त
फाउंडिंग एडिटर, मोजो स्टोरी
X @BDUTT

क्यों माता-पिता अपनी बेटियों को अपमानजनक, एब्यूसिव और दुःखभरे वैवाहिक जीवन में लौट जाने के लिए मजबूर करते हैं? क्यों यह जिद है कि लड़कियां शादी करें और फिर हर कीमत पर उसे बनाए भी रखें? कम से कम जो माता-पिता सम्पन्न हैं, वो भी क्यों बेटियों की खुशी खरीदने के लिए कार, नकदी और सोना देने को तैयार हो जाते हैं? हम महिलाओं के लिए शादी को प्राथमिक लक्ष्य बनाना कब छोड़ेंगे? ऐसी संस्कृति में पली-बढ़ी लड़कियों के साथ हमेशा हिंसा और दुर्व्यवहार की आशंका अधिक होती हैं, जिसमें बेहतर नौकरी के बजाय अच्छा लड़का मिलने को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

ग्रेटर नोएडा में रहने वाली 28 साल की मेकअप आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर निक्की भाटी की दुःखद मृत्यु के मामले में भी हम सभी ने यह सब देखा है। लेकिन इस और इस जैसे हादसों के बावजूद क्या हम वो सवाल कर रहे हैं, जो हमें करने चाहिए? कोई महिला यदि अपमानजनक रिश्ते को तोड़ना चाहे तो उसके समर्थन में परिवार की कोई भूमिका होनी चाहिए या नहीं? क्या हम तलाक को सामाजिक तौर पर कलंक जैसा मानते रहेंगे, भले ही हमारी बेटियों की जान जाती रहे? या अगर वे मरें नहीं तो पूरा जीवन दुःख में काटें।

क्या आपको पता है कि निक्की भाटी छह माह पहले अपने पति विपिन भाटी द्वारा मारपीट किए जाने के बाद मायके लौट गई थीं। लेकिन उन्हें फिर से पति के साथ रहने का फरमान सुना दिया गया। आज उनकी मां कहती हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी। उनकी बहन कंचन कहती हैं कि यदि निक्की को शादी तोड़ने दी गई होती तो आज वे जिंदा होतीं। लेकिन एक महिला के माता-पिता का दोष तो लेन-देन की संस्कृति से ही शुरू हो जाता है। अकसर तो धूमधाम से होने वाले भारतीय विवाहों का विचार ही वधू पक्ष से की जाने वाली मांगों के लिए सम्मानजनक सामाजिक आवरण बन जाता है। बामुश्किल गुजारा करने वाले लोग भी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लेते हैं। दहेज के लिए बिचौलिए लेन-देन का जरिया बनते हैं। निक्की भाटी के माता-पिता ने भी एक स्कॉर्पियो, सोना और नकदी दी थी। फिर भी कथित रूप से उनसे और अधिक मांगा जा रहा था।

भारतीय कानून के तहत दहेज लेना और देना, दोनों ही अपराध हैं। दुर्व्यवहार के चलते अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता का दर्द मैं समझती हूं। लेकिन परिवारों को भी सोचना होगा कि ऐसा क्या है, जो उन्हें अपनी बेटियों को वैवाहिक हिंसा से बचाने से रोकता है। अगर उनके लिए समाज में स्वीकार्यता की जरूरत बच्चे की बेहतरी से अधिक बड़ी है, तो वे भी अपराधी हैं। समाज और उसका नजरिया कब और कैसे बदलेगा, इस पर चर्चा जारी रह सकती है। लेकिन कानून इसका इंतजार नहीं कर सकता। कानून को अब अपना काम करना पड़ेगा।

दहेज हिंसा को लेकर महज निक्की भाटी का मामला ही इधर सुर्खियों में नहीं रहा। मैंने अभी अपनी पढ़ाई ही पूरी कर रहे छात्र मयंक से बात की। वे रोजाना अपनी बहन सोनाली के लिए खून जुटाने की ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं। बहन दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। उनके हाथों पर जलाए जाने के निशान हैं। परिवार का कहना है कि उसके पति और ससुराल वालों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश की। गर्म चिमटे से उसकी खाल जलाई गई। फिर से वही कहानी, दहेज दिया गया था, लेकिन और मांगा गया।

अगर विवाह सम्मानजनक और खुशहाल है, तो अच्छा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो क्या हम बेटियों को मौत की सजा देने जा रहे हैं? या जीवन भर का दुःख? क्या तलाक के बारे में बात करना इतना कलंकित करने वाला है?

सोनाली आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी। लेकिन माता-पिता ने उनके सपनों पर पैसा खर्च नहीं किया। यदि आज सोनाली पुलिस अधिकारी होतीं तो जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़ रही होतीं।

बेशक, आर्थिक तौर पर सक्षम महिलाओं के साथ भी घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार होता है। पढ़ी-लिखी महिलाएं भी इन रिश्तों को तोड़ने में हिचकती हैं, क्योंकि हम सभी एक संस्था के तौर पर विवाह की प्रधानता में भरोसा करते हैं। यदि विवाह सम्मानजनक, बराबरी का दर्जे वाला और खुशहाल है, तो यह बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो क्या हम अपनी बेटियों को मौत की सजा देने जा रहे हैं? या जीवन भर का दुःख?

क्या तलाक और घरेलू हिंसा के बारे में बात करना इतना कलंकित करने वाला है कि हाल के एक सर्वे में 31% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने घरेलू हिंसा झेली है। यदि हम सिर्फ दर्ज शिकायतों पर भी जाएं तो हर दिन 18 महिलाओं की मौत दहेज हिंसा से होती है। इनमें से ज्यादातर की खबरें भी सामने नहीं आतीं। ऐसे में क्या हमारा खून नहीं खौलना चाहिए?

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • 5 ऐसे स्पष्ट अवसर हैं, जिन्होंने भारत और अमेरिका की तकरार को बढ़ाया

ट्रम्प को चुनौती दी इसलिए हम पर थोपा गया टैरिफ

कूटनीति

मनोज जोशी
विदेशी मामलों के जानकार
manoj1951@gmail.com

भारत-अमेरिका के रिश्ते अपने निम्नतम स्तर पर क्यों पहुंच गए? इसके पीछे कई विचार सामने आ रहे हैं। पहला यह कि भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका वाकई परेशान था। लेकिन यह सर्वविदित तथ्य है कि बाइडेन प्रशासन में भारत को निर्धारित मूल्य सीमा में रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ताकि तेल कीमतें स्थिर रखी जा सकें। यह भी स्पष्ट है कि चीन रूसी तेल का कहीं बड़ा खरीदार है और अब तक उसे कोई सजा नहीं मिली है। दूसरी थ्योरी कहती है कि अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि और डेयरी उत्पादों की पहुंच बनाना चाहता है। जाहिर है, भारत सरकार ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह अपने किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन इस तर्क को अमेरिका में भरोसेमंद प्रतिक्रिया नहीं माना गया। तीसरा कारण यह हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई। यह ऑपरेशन अपने आप में शानदार सफलता थी, लेकिन भारत ने युद्धविराम का श्रेय ट्रम्प देने से इनकार कर दिया। और यहीं से समस्या शुरू हुई।

कुछ और भी कारण हैं। चौथा यह कि प्रवासन के मसले पर भारत-विरोधी लॉबी विदेश नीति को प्रभावित कर रही है। एक और कारण यह बताया जाता है कि ट्रम्प चाहते हैं भारत ब्रिक्स से अलग हो जाए, क्योंकि वहां वह एक ग्लोबल साउथ क्लब बनाता है, जो अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने की क्षमता रखता है। ट्रम्प और मोदी के बीच व्यक्तिगत तनाव ने इस दरार को और बढ़ा दिया है। ऊपरी तौर पर मोदी और ट्रम्प के बीच गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत संबंध नजर आते हैं। फरवरी में मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ऐसा दिखा भी था। लेकिन इसकी गहराई में टकराव भी छिपा है, जिसने समय के साथ नकारात्मक रूप ले लिया। मीडिया में पांच ऐसे अवसर गिनाए गए हैं, जिन्होंने इस तकरार को बढ़ाया।

पहला मामला यह कि ट्रम्प ने जुलाई 2019 में अपने पहले कार्यकाल में कहा था कि मोदी ने उन्हें कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए कहा था। यह स्पष्ट झूठ था और भारत ने कड़े शब्दों में इससे इनकार किया। दूसरा मसला सितंबर 2024 में सामने आया, जब मोदी बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड समिट में भाग लेने अमेरिका गए। मोदी की ट्रम्प के साथ एक बैठक तय हुई। और चूंकि वह चुनाव का समय था, इसलिए वे कमला हैरिस के साथ भी बैठक करना चाह रहे थे। हैरिस के साथ बैठक नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने ट्रम्प वाली बैठक भी रद्द कर दी। इससे अति-अहंकारी ट्रम्प नाराज हो गए। तीसरा कारण वॉशिंगटन डीसी में इलॉन मस्क के साथ मोदी की बैठक हो सकता है। मोदी की फरवरी 2025 की अमेरिका यात्रा सफल रही थी, लेकिन मस्क के साथ उनकी बहु-प्रचारित बैठक से संभवतः ट्रम्प नाराज हो गए। वे इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे कि टेस्ला या एपल जैसी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करें। चौथा अवसर ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें ट्रम्प को लगता है कि उन्होंने भारत-पाक संघर्ष रोका और परमाणु युद्ध टालने में मदद की। ट्रम्प ने अपना दावा कई बार दोहराया, लेकिन भारत ने उनकी किसी भी प्रकार की भूमिका से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसी से ट्रम्प नाराज हो गए। पांचवां और अंतिम कारण तब बना, जब मोदी ने कनाडा में जी-20 समिट से लौटते वक्त व्हाइट हाउस आने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। यह वही दिन था, जब ट्रम्प ने आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया था। माना जाता है कि ट्रम्प, मुनीर और मोदी को अपने आजू-बाजू खड़े करके एक फोटो खिंचवाना चाहते थे।

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक सितंबर में रूस से भारत में तेल का निर्यात बढ़ने वाला है। यूक्रेन के हमलों से रूस की कई रिफाइनरियों को नुकसान हुआ है और कच्चा तेल सस्ते दामों पर उपलब्ध है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत पर रियायती रूसी तेल से मुनाफाखोरी की बात कही है। जबकि भारत ने पश्चिम पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है, क्योंकि यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा अरबों डॉलर के रूसी उत्पादों की खरीद जारी है। चीन की मेजबानी में हुई एससीओ समिट ने ट्रम्प प्रशासन की नाराजगी को और बढ़ाया। इस बैठक में संगठन के अन्य सदस्यों के साथ मोदी और पुतिन, दोनों शामिल हुए। इसे भारत की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकी के तौर पर देखा गया।

भारत को अमेरिका का कुल निर्यात 87 अरब डॉलर है और 2024 में भारत की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर की थी। भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ जीडीपी का लगभग 2.2% है। यह भारत के विकास को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

डिफ्रेंट एंगल • जब एल्गोरिदम भावनाओं की दुनिया में घुसने लगे तो चिंता होनी जायज

चैटबॉट से क्यों बातें करने लगे हैं हमारे बच्चे?

युवामन

नन्दितेश निलय
वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक
nanditeshnilay@gmail.com

अभी तक तो पैरेंट्स इसी बात से परेशान रहे कि उनके बच्चे फोन बहुत देखते हैं, खेलते कम हैं। न वे किसी से घुल-मिल पाते हैं, और न ही अपने माता-पिता के साथ भावनात्मक वक्त बिता पाते हैं। लेकिन दुःख-सुख या मन की परेशानियां तो कैद होने के लिए बनी नहीं होतीं। वे तो अभिव्यक्त होने के लिए बेचैन रहती हैं। बच्चे भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं।

ऐसी परिस्थिति में अगर चैटबॉट पर सवार कोई बहुरुपिया स्त्री या पुरुष के वेश में काउंसलर बनकर उन बच्चों की भावनात्मक दुनिया में प्रवेश कर जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि चैटबॉट पर वे काउंसलर उन बच्चों की समस्याओं को सुन रहे हैं और त्वरित समाधान देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। अब इन बच्चों के लिए एआई होमवर्क में सहायता करने का ही माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि ऐसा साथी बन गया है, जो दोस्त बनकर उस तरह की भाषा बोलता और समझता है, जिस भाषा में वो सुनना और समझना चाहते हैं।

आज वह चैटबॉट बच्चों के मन में उठते किसी भी तरह के भावनात्मक या मेंटल हेल्थ से संबंधित विषयों पर सलाह दे रहा है। वह बच्चों को सुनता है, उनके प्रश्नों के उत्तर देता है और उनकी समस्याएं सुलझा भी रहा है। वह उन्हें आजादी देता है, कुछ भी पूछने की, अभिव्यक्त करने की। वह उन्हें घूरता नहीं, ऊंची आवाज में नहीं बोलता। तो वह बच्चा इस अनुभव को ज्यादा इंसानी समझने लगता है।

जब एल्गोरिदम इमोशन की दुनिया में प्रवेश करने लगे तो चिंता होनी चाहिए। उन बच्चों के अंदर वह आत्मविश्वास क्यों नहीं आ सकता कि उनके माता-पिता भी उनके लिए वह चैटबॉट बन सकते हैं, और उनके मन में उठते ज्वार-भाटे को समझ सकते हैं? शायद इसका उत्तर इतना आसान है नहीं। अगर कोई बच्चा अपनी कक्षा में बुली से परेशान है या परीक्षा के रिजल्ट से। या कोई युवा कॉलेज में रैगिंग से या टीचर्स के धमकाने से, या कोई नए पनपते रिश्ते से तो फिर माता-पिता की प्रतिक्रिया बहुत तरह की हो सकती है। वह बच्चा या युवा आश्वस्त नहीं होता कि उसे या उसकी भावनाओं को सही ढंग से समझा जाएगा। उसका अंतर्मुखी मन उसे उस चैटबॉट के पास ले जाता है, जो उसे वह कम्फर्ट देता है और पलक झपकते ही जवाब भी। वह उस माता-पिता की तरह नैतिकता का तर्क नहीं देता। वह तो उस बच्चे को हर प्रकार के प्रश्न पूछने का मौका देता है और फिर एक सहृदय जवाब भी तैयार रखता है। वह बच्चे को हर परिस्थिति में स्वीकार करता है।

पर बच्चा यह नहीं समझ पाता कि भावनाओं के उभार में वो स्पर्श, वो आलिंगन, वो पिता का कंधे पर हाथ रखना, वो मां का मस्तक चूमना, वो सबकुछ जो बहुत असर करता है, वो चैटबॉट से तो मिल नहीं सकता। लेकिन जब माता-पिता अपने बच्चे को वो स्पर्श, वो धैर्य, वो आवाज नहीं दे पाते तो चैटबॉट ही उन भावनाओं का स्रोत बन जाता है।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि वह एल्गोरिदम नैतिकता के स्तर पर जाकर किसी उलझन या अंतर्द्वंद्व को संबोधित नहीं करता। वह तो सबकुछ उन बच्चों के मनोनुकूल ही कहना चाहता है। सही और गलत के बीच का फर्क या सही और सही नहीं के बीच का जो अंतर है, चैटबॉट नहीं समझाना चाहता। वह तो बस प्रश्नों का जवाब देता चला जाता है और उस उलझन की दुनिया में उन बच्चों की निर्भरता खुद पर बढ़ाता जाता है।

इसलिए सबसे पहले तो माता-पिता को और भावनात्मक रूप से सजग होने की जरूरत है और यह भी समझना जरूरी है कि बच्चे अब सिर्फ मोबाइल या स्क्रीन देख नहीं रहे, बल्कि चैटबॉट उनके जीवन का भावनात्मक हिस्सा बनता जा रहा है। जबकि वह भावनात्मक कमान तो माता-पिता को संभालनी है; उनको कुछ ज्यादा संवेदनशीलता से सुनकर, समझकर और कुछ ज्यादा उनके जीवन में शामिल होकर। यह जरूरी है कि बच्चों की स्मृतियों का निर्माण इंसानी भावनाएं करें, कोई मशीन नहीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भास्कर विशेष CAT 2025 : पार्ट-3

मैनेजमेंट गाइड • कैट एग्जाम के लिए छात्र ये स्ट्रेटजी अपनाएं

अगले तीन महीने : रोज अखबार के एडिटोरियल पढ़ें, 30+ मॉक टेस्ट दें

भास्कर एक्सपर्ट

करुण कन्दोई
फाउंडर, विद्यासी एजुकेशन
(करिअर काउंसलर)

क्या MBA से पहले वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है? क्या इस कोर्स से बिजनेस शुरू करने में मदद मिलती है? ऐसे कई सवाल छात्रों के मन में आते हैं। हां, जॉब एक्सपीरियंस वालों को इंटरव्यू और प्लेसमेंट में फायदा होता है। लेकिन फ्रेशर्स को भी IIM मिलता है। एमबीए करने से आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए नेटवर्क, नॉलेज और फंडिंग सपोर्ट मिलता है। कैट की तैयारी में छोटे-छोटे गोल सेट करना, ग्रुप स्टडी और पोमोडोरो तकनीक (25 मिनट के सत्र में पढ़ाई करना) को अपनाना मददगार हो सकता है।

अक्सर छात्र एमबीए और पीजीडीएम में कंफ्यूज होते हैं। हालांकि, दोनों की वैल्यू समान ही है, फर्क सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा का होता है। कैट पास करने के लिए बैकग्राउंड (स्ट्रीम) नहीं, एप्टीट्यूड देखा जाता है, इसलिए इसमें नॉन-इंजीनियर्स भी सफल हो सकते हैं। एमबीए में इंटर्नशिप अहम हिस्सा है। यह नेटवर्किंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ाता है। कॉलेज चुनते समय प्लेसमेंट, एलुमनाई नेटवर्क जैसे फैक्टर ध्यान रखें।

इनमें कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन

- **फाइनेंस:** बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च जैसी फील्ड में कई मौके हैं।
- **मार्केटिंग:** FMCG, डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रेटजी चुन सकते हैं।
- **ऑपरेशन्स:** ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स में पढ़ाई कर सकते हैं।
- **बिजनेस एनालिटिक्स:** डेटा, कंसल्टिंग, टेक स्ट्रेटजी जैसे कई विकल्प हैं।
- **एचआर:** इस सेक्टर में लीडरशिप रोल्स, टैलेंट मैनेजमेंट जैसे फील्ड है।
- **इंटरनेशनल बिजनेस:** ग्लोबल ट्रेड और MNC स्ट्रेटजी जैसे विषय में भविष्य में कई मौके मौजूद है।

दैनिक भास्कर की विशेष कैट सीरीज के तीनों आर्टिकल को एक जगह पढ़ने के लिए इस क्यूआर को स्कैन करें।

कैट से जुड़े ये 8 कॉमन सवाल-जवाब

Q एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए?
A तैयारी का सही समय एग्जाम से 12 से 15 महीने पहले होता है। वहीं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स 5वें सेमेस्टर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। नौकरीपेशा वाले लोग रोज 2 से 3 घंटे या वीकेंड में पढ़ें। पढ़ाई करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है।

Q परीक्षा से पहले छात्रों को कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए?
A अगले 3 माह में छात्रों को कम से कम 20-30 फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए। शुरुआत में हर दो हफ्ते में एक और एग्जाम नजदीक आते ही हफ्ते में 1 से 2 पेपर देने चाहिए। इन टेस्ट से असली फायदा टेस्ट के एनालिसिस से होता है, सिर्फ हल करने से कुछ नहीं होगा।

Q क्या सिर्फ कैट/जैट स्कोर के आधार पर प्रवेश होता है?
A नहीं। एंट्रेंस स्कोर, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन के अंक, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर/बैकग्राउंड और इंटरव्यू/जीडी के आधार पर सिलेक्शन होता है। कुछ कॉलेज एकेडमिक्स को ज्यादा वजन देते हैं, कुछ इंटरव्यू पर।

Q क्या तैयारी के लिए कोई फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं?
A फ्री मॉक टेस्ट के लिए करिअर लॉन्चर, आईएमसी सिमकैट, टाइम एआईएमकैट देखना चाहिए। प्रेक्टिस के लिए क्रैक्यू, टू-आईआईएम, हांडा का फंडा जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करना चाहिए। वहीं, जीके के लिए जीके टुडे, अफेयर्स क्लाउड और द हिंदू आदि पढ़ें।

Q ग्रुप डिस्कशन (जीडी) की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
A रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अंग्रेजी अखबार (द हिंदू, मिंट, ईटी) का एडिटोरियल पढ़ें। अपने बोलने का पैटर्न - इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स, उदाहरण और समरी, इस पैटर्न में बनाएं। जीडी के दौरान सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। तर्कसंगत और सार्थक बातें रखें।

Q CAT और GMAT/GRE की तैयारी साथ हो सकती है?
A हां। बेसिक क्वांट और वर्बल कॉमन हैं। फर्क यह है कि GMAT/GRE में रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी ज्यादा है, कैट में स्पीड और एक्यूरेसी अहम है। कॉमन बेसिक्स से शुरू करें और फिर स्ट्रेटेजी अपनाएं।

Q स्कॉलरशिप मिल सकती है?
A हां। बिजनेस स्कूल मेरिट और जरूरत के आधार पर स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट, आदित्य बिरला, फुलब्राइट, Inlaks और OPJEMS जैसी स्कॉलरशिप भी उपलब्ध हैं। विदेश में पढ़ने के लिए छात्रों को Fulbright और Inlaks से स्कॉलरशिप मिल सकती हैं।

Q कोचिंग करना जरूरी है?
A कोचिंग से गाइडेंस और रेगुलरिटी मिलती है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं और ऑनलाइन मटेरियल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेल्फ-स्टडी से भी तैयारी हो सकती है। कई टॉपर्स दोनों का मिक्स अपनाते हैं। बेसिक्स के लिए कोचिंग और प्रैक्टिस के लिए सेल्फ स्टडी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान धर्म कर्म संस्कार मनुष्यों को दीजिए

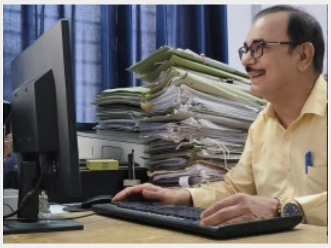

इस जगत को संचालित करने वाले हर मनुष्य के कर्म, धर्म और ज्ञान पर अपना आधिपत्य रखने वाले हे प्रभु इस जगत में मनुष्य रूपी सभी को जिसको आपने जगत में उतारा है सबका कल्याण करें, सबको सुखी जीवन जीने और दुखों से उबर कर जीने का रास्ता भी परमात्मा ही दे सकते हैं। क्योंकि मानवीय जीवन कर्म धर्म और संस्कार से ही सार्थक कहलाता है। परमात्मा ने मानव रूपी जीव को जगत में इसीलिए पैदा किया है कि वह इस जगत में होने वाले सारी गतिविधियों पर अपनी नजर रखें और जीवन को सार्थक बनाने में सफलता प्राप्त करें। इस जगत में लाखों तरह के जीव जंतु ईश्वर ने पैदा किया है लेकिन सबसे अलग मानव जन को बनाया है, जिसमें सोच और समझदारी का समावेश किया है मानव रजनी एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन जान को चलाने के लिए प्रयत्न करता है और पेट भरता है, जिससे उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा के बल पर बड़े-बड़े कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह जीवन ऐसा है कि जब धरा पर मनुष्य अवतरित होता है तब से लेकर इस धरा से गुजरते वक्त तक परमात्मा ही मनुष्य को संचालित करते नजर आते हैं। मनुष्य का सहारा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होते हैं गलत और सही दिशा में जीने का माध्य भी उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है सही लोगों को सही मुकाम तक पहुंचाना और गलत लोगों को उसके कर्मों का फल देना भी ईश्वर के हाथ में ही होता है। क्योंकि गीता में कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इस संसार में अच्छे कर्म धर्म और भागवत प्रति आस्था जरूरी माध्य है जीवन को सफल बनाने का। लेकिन यहां लोग अपने-अपने मन की करते हैं। गलत करने वाले ईश्वर को तो ध्यान में रखते हैं और हाथ जोड़कर माफी भी मांगते हैं लेकिन गलत तो गलत होता है इसे ईश्वर ही जानते हैं, इंसान को एहसास भरा होता है और उसके कर्म के हिसाब से फल भी भुगतना पड़ता है। इस आधुनिक काल में इंसान में जो खामियां उजागर हुई है और ईश्वर को पूजने की जो परंपरा चली है वह निश्चित रूप से बदले हुए स्थितियां और परिस्थितियों का परिणाम दिखता है। इसीलिए कहा गया है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए लीजिए मुझको शरण में हम सदाचारी बने धर्म रक्षक व्रत धारी बने। वर्ना ईश्वर तो तब भी थे आज भी हैं और सदैव रहेंगे।आज समाज के लोग स्वार्थ में वशिभूत है। संसार के लोगों में जब स्वार्थ आता है तो निश्चित रूप से लोग पतन की राह पर चल पडते है। अपने आप में सिमटकर दूसरे लोगों को शोषन दोहन करने में सफलता प्राप्त करता है। स्वार्थी मनुष्य अपने हित गलत ढंग से हासिल कर दूसरे को आहत करता है। जीवन को जीने के लिए दूसरे का भी भला करना होता है, जो दुख में है, उन्हे सुखी बनाने में अपना योगदान दें। जो उलझे हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने में हम लगे तो निश्चित रूप से यह जीवन धर्म और परोपकार के लिए बना है और तभी यह सार्थकता को प्राप्त करता हुआ सफलता की ओर अग्रसर होता है।

प्रभात वर्मा

डोगरा समाज में बाल विमर्श

डोगरी समाज, जिसे डोगरा भी कहा जाता है, भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में रहने वाला एक समुदाय है।उनकी भाषा डोगरी है, जो एक इंडो - आर्यन भाषा है।इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।यह भाषा जम्मू और कश्मीर के कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर रियासी और जम्मू संभाग के अन्य निकटवर्ती जिलों में बोली जाती है।डोगरा समाज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में भी रहते हैं।डोगरा शब्द का उपयोग एक जातीय पहचान के रूप में किया जाता है, जिसमें वे लोग शामिल हैं जो डोगरी भाषा बोलते हैं।डोगरा समुदाय में राजपूत, ब्राह्मण और सिख शामिल है।डोगरा राजवंश, जो 19वीं शताब्दी में प्रमुखता से आया, जम्मू- कश्मीर पर शासन करता था, इस राजवंश की स्थापना महाराज गुलाब सिंह ने की थी।डोगरा लोग, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के राजपूत बहादुर योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं। डोगरा समाज में बालकों की स्थिति-शिक्षा-डोगरा समाज के बच्चे स्कूल जाते हैं।डोगरी भाषा को स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ स्कूलों में इसे आठवीं या पांचवीं कक्षा तक ही सीमित कर दिया गया है, जिससे नई पीढ़ी को डोगरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।डोगरी भाषा का पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया जाता है कि विद्यार्थियों की इसमें रुचि कम हो रही है।डोगरी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्य है। इसे 22 दिसंबर 2003 को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।पिछले वर्ष 02 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए राज्य के सभी स्कूलों में डोगरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाने के संबंध में एक आदेश लागू करने का निर्देश दिया था।शिक्षा विभाग ने प्रतिबद्ध किया था कि कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी और बोधि को कक्षा छह से आठवीं तक के अनिवार्य विषयों में से एक के रूप में पढ़ाया जाएगा, जहां ऐसी भाषाएं जम्मू - कश्मीर और लद्दाख प्रांतों में मातृभाषा के रूप में बोली जाती है।इसके बाद भी शिक्षा विभाग अभी तक स्कूल स्तर पर डोगरी को इतनी अहमियत नहीं दिला पाया जितनी आवश्यकता थी।डोगरी भाषा में

बाल साहित्य की कमी है, जिसके चलते विद्यार्थियों में डोगरी भाषा में पढ़ने की रुचि खत्म हो रही है।स्वास्थ्य- डोगरा समाज में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुपोषण और बीमारियां जैसी समस्याएं मौजूद हैं। सांस्कृतिक संरक्षण-डोगरी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बच्चों को अपनी भाषा और परम्पराओं से परिचित कराना आवश्यक है।डोगरी साहित्य, लोकगीत और पारम्परिक कलाओं को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहे।बाल श्रम एवं बाल विवाह-डोगरा समाज में बाल विवाह की प्रथा, हालांकि कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में आज भी जारी है।अभी भी बाल विवाह प्रथा एक समस्या है।इस प्रथा में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लड़कों के अपेक्षा लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती हैं।इस प्रथा के परिणाम स्वरूप ज्यादातर लड़कियां ही गुलामी की शिकार होती हैं।डोगरा समाज में बाल श्रम देखा जा सकता है।यह एक गंभीर समस्या है। भेंटवार्ता-जम्मू-कश्मीर की शोधार्थी छात्रा आरती देवी का कहना है कि जम्मू के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है-सरकारी पाठशालाओं में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, लाइब्रेरी और खेल मैदान जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।सर्वे के अनुसार 60%से अधिक सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, जिससे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई दोनों बाधित होती है।सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति के कारण उस समय स्कूल बंद रहते हैं।डोगरा समाज के अभिभावकों ने बतलाया कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के बीच आपदा संबंधित जानकारी न के बराबर दी जाती है। दिव्यांग बच्चों के माता-पिता ने बतलाया कि डोगरा समाज के दिव्यांग बच्चे पारंपरिक विद्यालयों तक पहुंचने से वंचित रहते हैं।सर्वे के अनुसार 2020-21 सत्र में 22, 736 बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले थे लेकिन केवल आठ विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय उपलब्ध थे। R P W D Act 2016 और R T E Act 2009 के बावजूद निजी विद्यालय इन बच्चों को दाखिला देने में अनिच्छुक है। दिशाः-डोगरा समाज के एक संगोष्ठी दौरान सामूहिक सहभागिता के साझी समझ से स्वस्थ दिशा के लिए निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आईं:-स्कूलों में बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास कक्ष, खेल का मैदान, खेल सामग्री और स्कूल भवनों के मजबूती पर ध्यान देना होगा।स्कूल बसों की सुरक्षा, आग एवं बिल्डिंग सेफ्टी प्रमाण पत्रों का अनिवार्यता।विशेष शिक्षा वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, संसाधन कक्षों और पहुंच योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास।स्कूल के बच्चों को आपदा संबंधित हमेशा जानकारी देना। विद्यालय में आपदा प्रबंधन कमिटी का गठन, बाल प्रेरक कमिटी का गठन, बाल संसद का गठन, मीना मंच का गठन एवं प्रत्येक शनिवार को बच्चों के बीच खेल-खेल में, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से आपदा संबंधित जानकारी देना। बच्चों के बीच डोगरी भाषा में बाल साहित्य विकसित करना।बच्चों को आवश्यक आवश्यकता एवं विलासिता संबंधित आवश्यकता की जानकारी देना।बचत एवं निवेश संबंधित महत्त्वपूर्ण बातों की जानकारी देना।बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना और लोक भाषा से मानक भाषा का ज्ञान देते हुए दुनिया को जानने में मदद करना।

दस्तक प्रभात
डॉ.सुधांशु कुमार चक्रवर्ती

सीस दिये जो गुरु मिलै, तो भी सस्ता जान

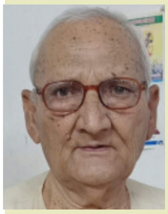

शिक्षा जगत के महान गुरु एक महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक साहित्यिक अभिरुचि के धनी व्यक्ति थे। उनका लघुकथा संग्रह गल्लिपका नाम से सन 1956 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। शिक्षक दिवस के मौके पर गलिपका लघु कथा प्रकाशित तथा कथा का संक्षिप्त रूप के तहत लघु कथा ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा व पिपासा के कश्य को लेकर चली है। जिसमें शिष्य ऋजिस्वान गुरु अत्रि के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के समाधान के साथ बोध और ज्ञान चाहता है का भाव नहीं था। गुरु अत्रि के आश्रम में रहकर शिष्य ऋजिस्वान ज्ञान बोध की बात सुनकर वैसा ही आचरण कर के अंतर में प्रकाश भर लेता है। ज्ञान की व्यवहारिक परीक्षा लेने के लिए जब वह संसार सागर में उतरता है तो उसका सारा ज्ञान छूमंतर हो जाता है। यह निराश भाव से पुनः गुरु आश्रम में लौट आता है और गुरु के सामने अपनी समस्या रखता है। गुरु मुस्कुराकर मौन रह जाते हैं। ज्ञान की सैद्धांतिक प्राप्ति और आदर्श की बातें लेकर उसका संसार के लोगों के साथ मध्य व्यवहार के प्रयोग करने में बहुत कठिनाई है। गुरु का ज्ञान प्रयोग स्थल समाज के साथ परिवार के साथ और व्यवस्था के साथ समन्वय ले ही स्पष्ट होता है कि ज्ञान के साथ विवेक का कितना महत्व है। प्राचीन भारतीय संस्कारों में माता-पिता के बाद सबसे अधिक महत्त्व गुरु या ज्ञान दाताओं का सदा रहा है। संत तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं। प्रातः काल उठ जागे रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाही माथा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। अर्थात प्रातः जागने के बाद भगवान राम और उनके भाई सर्वप्रथम माता-पिता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद गुरु को प्रणाम करते हैं। दूसरे पंक्ति में स्पष्ट करते हैं कि गुरु गिरीश जाने के बाद कम समय में शिक्षा पूर्ण करते हैं। आज के 600 साल पूर्व युग प्रवर्तक संत और महाकवि कबीर दास हुए थे उनके दोनों और पदों आदि की रचनाओं में जीवन को सही तरह से जीने की प्रेरणा मिलती है। गुरु गोविंद दाउ खड़े काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए दिखाएं। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात अगर एक साथ गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तब सबसे प्रथम गुरु को प्रणाम करना चाहिए। दूसरे दोहे में तन को विश भरा मानकर और गुरु अमृत का खान जानकर अगर शीश अर्थात सर देकर गुरु मिल जाए तो जान भी सस्ता है। उपरोक्त कवियों संतो और दार्शनिकों के कथन के अनुसार व्यक्ति के जीवन में सच्चे ज्ञानी गुरु का महत्व बहुत है। इस कसौटी पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली के कुछ तथ्यों को जानना भी सही होगा। अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया भारतीय संस्कार भाव की शिक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई। इस संदर्भ में राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर की कृति शहीद हिंदी खंडकाव्य में अंकित है। कुछ लोग विदेशों में पढ़ते थे पढ़ते बहुत कम गुनते थे। विदेशी हो गया ताना-बाना, भूल गए सब बात पुराना । माई किले की शिक्षा प्रणाली, बिना बात के खाली थाली। संदर्भ गुरु का है। पूर्व के गुरु और आज के गुरु में भेद है। यही कारण है कि गुरु गरिमा के सामने प्रश्नचिन्ह हर मोड़ पर लगा है या व्यवस्था दोष को भी उजागर कर रहा है। बिहार में पिछले चालीस साल में शिक्षा और परीक्षा दोष के कारण उदाहरण स्पष्ट कर रहा है। प्रधानाध्यापक पद के लिए ली गई परीक्षा प्रायः स्कूल व्यवस्था में सीनियर और जूनियर को लेकर विवाद होता रहा है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने 6421 प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा की व्यवस्था की। संभव है इसके लिए अनुभवी शिक्षकों को परीक्षा में भाग लेने का पात्र माना गया है। इस में भाग लेने वाले अधिकांश शिक्षक मैट्रिक से लेकर स्नातक तक शिक्षा प्राप्त हैं और 10 साल का शिक्षण का अनुभव भी रखते हैं।यह विडंबना पूर्ण स्थिति है कि 6421 स्थान के परीक्षा में भाग 13 हजार शिक्षकों ने लिया। उसमें मात्र 421 परीक्षा में सफल सफल रहे। शेष असफल हो गए। इसमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है तो यह भी स्पष्ट हो गया कि बिहार में 1980 से लेकर आज तक शिक्षण का माहौल नहीं है । कदाचार के सहारे सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। इससे गुरु की महिमा पर भी धब्बा लगा है। शिक्षक दिवस के मौके पर यह चिंतन का विषय है। विषय है आखिर कैसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। एक आग्रह है कि शिक्षक खुद पढ़ें और छात्र छात्राओं को शिक्षा दें। कारण पिछले 40 सालों में शब्द बदले हैं। संस्कार बदले हैं और ज्ञान की खोज के रास्ते बदले हैं। जिस कारण बहुत पहले पढ़े गए विषय को उसी रूप में मानना उचित नहीं है। पत्र पत्रिका और अखबार से नई जानकारी मिलती है। इस कारण दृष्टि और दृष्टिकोण में नीर क्षीर विवेक की आवश्यकता है।

दस्तक प्रभात
राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर

"आकाश की ओर: भारत का अंतरिक्ष स्टेशन और विज्ञान की नई उड़ान"

भारत, जिसकी वैज्ञानिक परंपरा प्राचीन युग से ही गणित, खगोलशास्त्र और यन्त्र विज्ञान में प्रकट होती रही है, आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नए शिखरों की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष स्टेशन योजना का खुलासा किया, जो न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक महत्वाकांक्षा का परिचायक भी है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल एक ठोस संरचना अंतरिक्ष में स्थापित करना नहीं है। यह भारत के लिए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक मंच है। अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जाने वाले प्रयोग जैविक विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, भौतिकी और जलवायु अध्ययन जैसे क्षेत्रों में नई खोजों का मार्ग खोलेंगे। इस दृष्टि से यह केवल विज्ञान का प्रयोगशाला नहीं, बल्कि मानव चेतना और ज्ञान की उड़ान है। भारतीय दृष्टिकोण में, आकाश केवल बाहरी सीमाओं का विस्तार नहीं, बल्कि चेतना और संभावनाओं का प्रतीक है। वेदों में "आकाशं परेण ब्रह्म" की संकल्पना हमें यह स्मरण कराती है कि ज्ञान और अन्वेषण का उद्देश्य केवल भौतिक विजय नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन और चेतना का विस्तार है। इसी दार्शनिक आधार पर भारत का अंतरिक्ष स्टेशन केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवता के लिए अनुसंधान, स्थायित्व और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक भी बनता है। इस परियोजना से आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी कई अवसर उत्पन्न होंगे। उन्नत तकनीक, रॉकेट विज्ञान, उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक विज्ञान समुदाय में भारत की भागीदारी और प्रतिष्ठा भी सशक्त होगी। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, जब अंतरिक्ष अनुसंधान केवल राष्ट्रवाद या शक्ति प्रदर्शन तक सीमित होता जा रहा है, भारत का दृष्टिकोण शिक्षा, विज्ञान और मानव हित पर केंद्रित दिखाई देता है। यह परियोजना उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी जड़ें हमारी सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं में गहरी हैं—जैसे ज्ञान का सार्वभौमिक आदान-प्रदान, प्रकृति और अंतरिक्ष की गहरी समझ, और मानवता के लिए समर्पित अनुसंधान। अंततः भारत का अंतरिक्ष स्टेशन केवल लोहे और तारों का ढांचा नहीं, बल्कि मानव चेतना का विस्तार है। यह हमें याद दिलाता है कि जब विज्ञान और दर्शन साथ चलें, तब मानवता के लिए असीम संभावनाएँ खुलती हैं। यह परियोजना न केवल युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक विज्ञान मंच पर न केवल सहभागी, बल्कि अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी।

दस्तक प्रभात/डॉ. पुष्पराज गौतम

विवाद नहीं संवाद से हल निकले

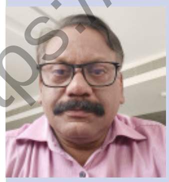

मनुष्य के जीवन में असहमति स्वाभाविक है, और यह भी सच है कि विचार, संस्कार, परंपरा और स्वार्थ की भिन्नता से टकराव उत्पन्न होता है। ऐसे में समस्या को सुलझाने के दो रास्ते सामने आते हैं विवाद और संवाद। विवाद का मार्ग तनाव, कटुता और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि संवाद का मार्ग सहयोग, समझ और समाधान की ओर। इसलिए कहा जाता है कि "विवाद नहीं, संवाद से ही हल निकले।" विवाद में मनुष्य का अहंकार प्रधान हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति शत्रु प्रतीत होता है तथा ऐसे में लक्ष्य केवल उसे परास्त करना बन जाता है। जबकि संवाद में विचार विनिमय होता है, सुनने और समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है। संवाद में समाधान की तलाश रहती है, न कि जीत हार की। यही कारण है कि संवाद से निकले निर्णय लंबे समय तक टिकते हैं भारतीय संस्कृति ने संवाद को सदैव महत्व दिया है। उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से ही गहन सत्य उद्घाटित हुए। भगवद्गीता का उपदेश भी अर्जुन और श्रीकृष्ण के बीच संवाद से ही संभव हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश प्रश्नोत्तर पद्धति से दिए। महात्मा गांधी का सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन भी संवाद की शक्ति पर आधारित था। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि भारतीय चिंतन में विवाद नहीं, संवाद ही समाधान का आधार है।आज अधिकांश पारिवारिक तनाव संवादहीनता के कारण ही जन्म लेते हैं। पति पत्नी या माता पिता और संतान के बीच यदि खुलकर बातचीत न हो तो छोटी सी असहमति भी बड़ा विवाद बन जाती है। यदि समय रहते संवाद हो तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। परामर्श का आधार भी यही है कि बातचीत और विचार विनिमय से समस्या का हल खोजा जाए।समाज और राजनीति में भी संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का आधार ही संवाद है और इसी उद्देश्य से ही तो संसद और विधानसभाएँ बनी हैं कि विभिन्न मतों के बीच बहस और विमर्श हो। किंतु जब यहाँ विवाद और शोर शराबा हावी हो जाता है, तब लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। गांधीजी ने भी अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान संवाद और अहिंसा का मार्ग अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि हिंसा से अस्थायी परिणाम मिल सकते हैं, किंतु स्थायी स्वतंत्रता केवल संवाद से ही संभव है।विश्वयुद्धों ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि विवाद केवल विनाश देता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो राष्ट्रों के बीच संवाद का मंच बना। आज भी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद या सीमाई विवाद का समाधान संवाद से ही खोजा जा सकता है। दरअसल, संवाद की सबसे बड़ी बाधाएँ हैं अहंकार, अधीरता और असहिष्णुता। सोशल मीडिया के युग में त्वरित और आक्रामक प्रतिक्रियाएँ संवाद को कमजोर कर रही हैं। इसलिए शिक्षा से ही बच्चों को संवाद कौशल सिखाना होगा, राजनीति में स्वस्थ बहस की परंपरा स्थापित करनी होगी और परिवारों में आपसी बातचीत का वातावरण बनाना होगा। विवाद में सभी हारते हैं, जबकि संवाद में सब जीतते हैं। विवाद अस्थायी समाधान देता है, संवाद स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि आज के समय में यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है कि समस्याओं का हल तलवार या तकरार से नहीं, केवल संवाद से निकलेगा।

दस्तक प्रभात/राजेश कुमार सिन्हा

विधना नाच नचावे, तूम्माफेरी, निखट्टू आंसू, भूख, कामसूत जैसी अनेक जीवन की समस्या निदान को बनी प्रभात प्रोडक्शन की बेहतरीन फिल्में

प्रभात फिल्म प्रोडक्शन की एक नहीं अनेकों छोटी बड़ी फिल्मे दर्शकों को देखने के लिए उपलब्ध है। इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री प्रभात वर्मा जी एक अच्छे संपादक व लेखक होने के साथ एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। इनमें कला कूट-कूट कर भरी हुई है।इस फिल्म में इनके हुनर का जलवा देख विस्मित हूं। यह कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही मार्मिक और अच्छी है जिसमें नारी की व्यथा कथा समाहित है। फिल्म सभी तरह से अच्छी बन पड़ी है। फिल्म सामाजिक धरातल पर केंद्रित है। गांव और वहां के लोगों की मनोदशा का चित्रण बेहतरीन ढंग से किया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस फिल्म के सभी गाने मन को लुभाने वाले हैं, जो कर्णप्रिय बन पड़े हैं।इस फिल्म की खासियत यह भी है कि

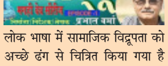

लोक भाषा में सामाजिक विद्रूपता को अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है और इस फिल्म में सामाजिक समस्या

को बेहतरीन ढंग से पेश करने का प्रयास किया गया है।फिल्म में आम मौजूदा हिंदी फिल्मों की तरह इस में अश्लीलता को स्थान नहीं दिया गया। यह फिल्म पूरे परिवार के साथ देखने लायक बन पड़ी है। इसके लिए श्री वर्मा जी को कोटिश साधुवाद। इन फिल्मों के जरिए बिहार की लोक संस्कृति, यहां की बोलचाल, पारिवारिक व सामाजिक जीवन पर बेहतर ढंग से फोकस किया गया है।की खासियत यह है कि यह जीवन के दुख सुख को मानस पटल पर चित्रित करता है।इन फिल्मों में मुख्य कलाकारों की भूमिका ने अपनी भूमिका के प्रति ईमानदारी से कार्य किया है, जो बनावटी नहीं लगता है। यही फिल्म की सफलता का मानक कहा जा सकता है। फिल्म भले ही मगध की भाषा मगही में बनाई गई है लेकिन इसे सभी भाषा के लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।यह मेरा विश्वास है। निर्माण, निर्देशन, अभिनय कथा गीत, इतने सारे विभागों को एक साथ संभालते हुए कार्य करना बहुत दुरूह कार्य है, जिसे श्री प्रभात वर्मा जी ने कर दिखाया है।यकीनन यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा यकीन अभी है कि या फिर भेजो व्यक्ति के

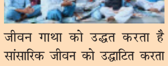

जीवन गाथा को उद्धत करता है सांसारिक जीवन को उद्घाटित करता है और यह साबित करता है कि भगवान के बनाए इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जीना उसी के नाम है, जो औरों के लिए जीता हो। प्रभात वर्मा ने प्रभात प्रिंस प्रोडक्शन के माध्यम से विधान नाच नचावे भूख कामसूत निखट्टू तुम्माफेरी साधना और लिलकहवा जैसी अनेक फिल्मों का निर्माण किया है जो देखने लायक है और यह सिनेमाघर में तो चली अब यूट्यूब पर यह लोड कर दिया गया है जिसे दुनिया भर के लोग इसे आसानी से देख सकते हैं बस एक शर्त यही होगा कि आप इसे देखें और निमार्ता निर्देशक का हौसला बढ़ाने के लिए उनके हौसले को अप्लाई करने के लिए अपनी ओर से सब्सक्राइब और घंटी दबाना ना भूले ताकि आगे भी आने वाली फिल्में आप देख सकें।

दस्तक प्रभात/प्रभु आनंद

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक प्रभात वर्मा द्वारा चित्रांश प्रिन्टर्स, हरनाहा टोला, पटना- 8 में मुद्रित व न्यू कॉलनी, चित्रांश कुटी, हरनाहा टोला, पटना- 800008 से प्रकाशित
दूरभाष- 9334978033, 9304341881, नोट- समाचार-पत्र में प्रकाशित समस्त लेखए वं समाचारों की जिम्मेवारी लेखकोंए वं पत्रकारों की होगी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

“ सफलता में समय का विशेष महत्व है जिसने समय के महत्व को जान लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं। -आचार्य चाणक्य

देश का पहला मेड इन इंडिया चिप तैयार होना निश्चित ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे साबित होता है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

डिजिटल संप्रभुता की ओर

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश के पहले स्वदेशी चिप को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का क्षण ऐतिहासिक तो खैर है ही, इस उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल, नाखून के आकार के ये चिप, जिन्हें सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। शीतयुद्ध काल में परमाणु हथियारों की जैसी होड़ विभिन्न देशों के बीच दिखती थी, वही आज ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक चिप के निर्माण को लेकर दिख रही है। भारत पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में पिछड़ा ही रहा, तो इसकी वजह समझी जा सकती है। कई बार एक विकासशील देश की बुनियादी प्राथमिकताएं महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ने की उसकी गति को धीमा कर देती हैं। दूसरी ओर, ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों की पकड़ इस क्षेत्र में बेहद मजबूत रही है। ताइवान तो दुनिया के साठ फीसदी से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, जिसमें 90 फीसदी सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं। पिछले कुछ दशकों से भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता अधिक ही रही है, जिससे उसे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन, 2021 में शुरू हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत महज चार वर्षों के भीतर अपना चिप बनाकर भारत ने इस क्षेत्र में विश्वास अर्जित किया है। देश का सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में 38 अरब डॉलर का था, जो 2024-25 में करीब 45-50 अरब डॉलर का हो चुका है और अब 2030 तक इसके दोगुने से भी अधिक होकर 100-110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, यह महज एक शुरुआत है। कुशल मानव संसाधन, उन्नत अनुसंधान और मजबूत आपूर्ति शृंखला सेमीकंडक्टर उद्योग में कामयाबी की पूर्व-शर्त माने जाते हैं। वैश्विक शोध के अनुसार, भारत में पहले से ही वैश्विक चिप डिजाइन इंजीनियरों का

तकरीबन 20 फीसदी हिस्सा मौजूद है। इसके अतिरिक्त, क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया जैसे वैश्विक दिग्गजों ने बंगलूरू, हैदराबाद और नोएडा में अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। यही नहीं, सरकार ने 278 विश्वविद्यालयों में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरण मुहैया कराए हैं, ताकि एक मजबूत प्रतिभा पूल तैयार हो सके। नीतियों को अधिक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाने के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से भारत इस क्षेत्र की अग्रणी शक्ति के रूप में उभर सकेगा। फिलहाल, अपना चिप बनाना देश के लिए यकीनन गर्व का क्षण है, लेकिन वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

स्वतंत्र विदेश नीति की मिसाल

भारत की ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की नीति उसके लिए लाभकारी स्थिति पैदा करती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिका से जुड़ना चाहता है और न ही चीन-रूस खेमे में बंद होना चाहता है। वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहता है।

तियानजिन में हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने एशिया की राजनीति को एक नया आयाम दिया है। यह सम्मेलन केवल बहुपक्षीय सहयोग का मंच नहीं था, बल्कि इसने भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को कुछ हद तक कम करने और दोनों को संवाद की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया। पिछले कुछ वर्षों से भारत-चीन संबंध गलवान की घटनाओं की छाया में उलझे हुए थे। सीमा पर हुए टकराव ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई, बल्कि अविश्वास भी गहरा कर दिया। इसके बावजूद तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी ने संकेत दिया कि दोनों देश अब भी रिश्तों को सामान्य बनाने के इच्छुक हैं और बहुपक्षीय मंचों का उपयोग इसी दिशा में किया जा सकता है।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपी-आईडीएसए

इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए नए व्यापारिक शुल्कों और संरक्षणवादी नीतियों ने वैश्विक आर्थिक ढांचे को झकझोर दिया है। इसके अलावा, यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सक्रियता ने चीन और रूस को करीब ला दिया है। ऐसे समय में भारत का इस मंच पर सक्रिय भागीदारी करना और संतुलित भूमिका निभाना अपने आप में रणनीतिक संदेश है। भारत एक ओर पश्चिमी देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर वह इस बात से भी अवगत है कि पड़ोसी देशों से कटकर वह अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता।

तियानजिन सम्मेलन में भारत और चीन, दोनों ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आपसी संवाद अनिवार्य है। बेशक सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे अब भी दोनों देशों के रिश्तों पर भारी हैं, लेकिन आर्थिक साझेदारी और वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा के लिए तालमेल आवश्यक है। भारत ने यह रेखांकित किया कि

आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ जैसी चुनौतियों का सामना केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। चीन ने भी इस पर जोर दिया कि सहयोग और साझेदारी ही एशिया की स्थिरता और समृद्धि की कुंजी है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक संदेश यह है कि भारत और चीन, दोनों अब टकराव से हटकर संवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसमें निश्चित ही रणनीतिक गणना भी शामिल है। चीन को यह भलीभांति पता है कि उसकी बेल्ट एंड रोड पहल और वैश्विक आर्थिक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकतीं, जब तक भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण बने रहेंगे। भारत भी यह समझता है कि एक ही समय में चीन और पाकिस्तान, दोनों से खुले टकराव की स्थिति में रहना उसकी दीर्घकालिक विदेश नीति और आर्थिक विकास लक्ष्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए भारत ऐसे अवसरों की तलाश में है, जहां वह अपने सुरक्षा हितों से समझौता किए बिना चीन से संवाद बनाए रख सके।

एससीओ की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संगठन भले ही अब तक नाटो जैसी सैन्य प्रभावशाली ताकत के रूप में उभर कर सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता इस बात में है कि यह एशिया के बड़े देशों को एक साझा मंच प्रदान करता है। ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर एससीओ के माध्यम से ठोस प्रगति की संभावना बनी रहती है। खासकर ऐसे समय में, जब पश्चिमी मंचों पर एशियाई देशों की आवाज अक्सर दब जाती है, एससीओ उन्हें अपने हितों को सामने रखने का अवसर देता है। इस सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि रूस और चीन, दोनों ने भारत की भागीदारी को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पश्चिमी दुनिया से लगभग कट चुका है। उसके लिए चीन तथा भारत जैसे साझेदारों का महत्व और भी बढ़ गया है। चीन भी नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह पश्चिमी खेमे की ओर झुक जाए। इस संदर्भ में भारत की ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की नीति उसके लिए लाभकारी स्थिति पैदा करती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिका से जुड़ना चाहता है और न ही चीन-रूस खेमे में बंद होना चाहता है। वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहता है।

उल्लेखनीय है कि भारत-चीन संबंधों में सुधार की संभावना केवल सम्मेलनों या औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि तमाम तनावों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2024 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यह बताता है कि व्यावहारिक धरातल पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए किसी भी बड़े राजनीतिक टकराव से दोनों को नुकसान होगा और यह बात दोनों की समझ में भी आती है। फिर भी, यह कहना जल्दबाजी होगी कि तियानजिन सम्मेलन ने भारत-चीन संबंधों को पूरी तरह सामान्य बना दिया है। सीमा विवाद, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति जैसे कई मुद्दे अब भी जटिल बने हुए हैं। यह जरूर कहा जा सकता है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को संवाद के एक ऐसे रास्ते पर ले गया है, जहां तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सके और भविष्य में बेहतर संबंधों की संभावना बनी रहे।

दीर्घकालिक दृष्टि से देखें, तो भारत और चीन के बीच सहयोग की संभावना केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि बहुपक्षीय मंचों पर भी है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, खाद्य सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकियों के नियमन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों का सहयोग वैश्विक दक्षिण को मजबूती दे सकता है। दोनों देश यह भी जानते हैं कि अगर वे आपसी टकराव में उलझे रहे, तो तीसरे पक्षों के लिए हस्तक्षेप करना और भी आसान हो जाएगा। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच एक न्यूनतम समझ बनाए रखना आवश्यक है। तियानजिन शिखर सम्मेलन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह सम्मेलन कोई चमत्कारिक समाधान लेकर नहीं आया, लेकिन इसने यह संदेश अवश्य दिया कि संवाद और सहयोग के रास्ते बंद नहीं हुए हैं।

भारत और चीन के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि वे अपने मतभेदों को बातचीत और धैर्य से सुलझाने की दिशा में कदम उठाएं। अगर ऐसा होता है, तो न केवल दक्षिण एशिया व पूर्वी एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता और शांति को बढ़ावा मिलेगा।

जीवन धारा

जे. कृष्णमूर्ति

दूसरों के बारे में बात करना स्वयं से पलायन है, चाहे वह खुशगवार हो या खराब, और पलायन ही बेचैनी का कारण है। यह प्रवृत्ति ही बेचैनी का सबब होती है। इससे बचने का तरीका खुद से परिचय करना है।

समझ और प्रसन्नता का विनाशक है बेचैन मन

गपशप में समय बिताने की वृत्ति और चिंताग्रस्त रहने की वृत्ति में कितनी विचित्र समानता है। दोनों एक ही बेचैन मन की उपज हैं। बेचैन मन को अभिव्यक्तियों और कार्यकलाप की सदा बदलती हुई विविधता चाहिए, इसे व्यस्त रहना जरूरी लगता है। इसे सदा बढ़ती हुई संवेदना, बदलती रुचियां चाहिए और गपशप में इस सब की सामग्री मिल जाती है। शप-शप में रमे रहने की यह वृत्ति उत्कटता और गांभीर्य से सर्वथा विपरीत है। दूसरों के बारे में बात करना स्वयं से पलायन है, चाहे वह खुशगवार हो या खराब, और पलायन ही बेचैनी का कारण है। पलायन की प्रवृत्ति ही बेचैन होती है। दूसरों के झमेलों में रुचि रखना अधिकतर लोगों को व्यस्त रखता प्रतीत होता है। चूंकि, हम इसको लेकर चिंतित रहते हैं कि औरों का हमारे बारे में क्या मत है, और हम उनके बारे में सब कुछ जानने को उत्सुक रहते हैं।

गपशप बेचैन मन की अभिव्यक्ति है, पर केवल चुप्पी साध लेना ही शांत मन का लक्षण नहीं है। शांति संयम या त्याग से अस्तित्व में नहीं आती, इसका आगमन तो ‘जो है’ की समझ के साथ होता है। ‘जो है’ को समझने के लिए तत्पर सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है, वह स्थिर नहीं रहता। यदि हम चिंता न करते रहें, तो हमें लगता है कि हम जीवित ही नहीं हैं। हममें से अधिकांश के लिए किसी समस्या से जूझते रहना ही जीवित रहने का लक्षण है। समस्यारहित जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी समस्या में हम जितने अधिक उलझते हैं, उतना ही अधिक सतर्क हम खुद को समझते हैं। किसी समस्या में मन को सतत उलझाए रखने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्या चिंता से समस्या हल हो जाने वाली है? या, समस्या का उत्तर तभी आता है, जब मन शांत हो। किंतु अधिकतर लोगों के लिए शांत मन भयप्रद होता है; वे शांत होने से भयभीत रहते हैं, क्योंकि कौन जाने उन्हें अपने विषय में क्या पता चल जाए, और चिंता उसे टालने का उपाय बन जाती है। जो मन कुछ पता चल जाने से डरा हुआ है, बराबर अपना रक्षण करना चाहता है; इसकी बेचैनी ही इसका रक्षण होती है।

गपशप की तरह ही चिंतातुर रहने में भी उत्कटता और गंभीरता का आभास पैदा होता है; किंतु यदि हम अधिक सूक्ष्मता से अवलोकन करें, तो दिखाई देने लगता है कि इस आभासी गंभीरता का जन्म आकर्षण से होता है, सच्चे सरोकार से नहीं। आकर्षण तो सदैव अस्थिर रहता है, और इसी कारण गपशप और चिंता का अंत केवल तभी हो सकता है, जब मन की इस बेचैनी को समझ लिया जाए। सिर्फ संयम, नियंत्रण या अनुशासन से शांति का जन्म नहीं होगा, बल्कि इनके कारण तो मन कुंद हो जाता है, असंवेदनशील और सीमित बन जाता है। अनुमान-अटकल, कुतूहल की तरह ही बेचैनी का परिचायक है। एक बेचैन मन, वह चाहे जितना प्रतिभाशाली हो, समझ और प्रसन्नता का विनाशक ही है।

उलझनों से बचें

सूत्र

हमारे मन के ऊपर की जो ज्ञात परतें हैं, उन पर सतत तनाव पड़ते रहने से, आदत के कारण और परिस्थितियों के दबाव से वे उद्वेलित और बेचैन बन गई हैं। जीवन की समझ का आधार अपने आप से परिचय करना है। जब तक हम दूसरों के झमेलों में पड़े रहेंगे, तब तक हमारा बेचैन मन शांत नहीं होगा। इसलिए इनसे बचना जरूरी है।

दूसरा पहलू

क्लीसनर वॉल स्ट्रीट की नौकरी में करोड़ों डॉलर कमा चुके थे, पर दूसरों की जिंदगी की खातिर उन्होंने अलग ही रास्ता चुन लिया।

जीवन जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का सुख

एक महिला मेट्रो की सीढ़ियों पर गिरी पड़ी थी, जोनाथन क्लीसनर ने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, ‘हम यहां आपकी मदद के लिए आए हैं, बताइए क्या हुआ?’ किसी ने 911 पर सूचना दी थी कि मेट्रो स्टेशन पर एक महिला गिरी पड़ी है। थोड़ी देर बाद उस महिला को होश आया और उसने देखा कि उसके सामने नीली वर्दी पहने एक दुबला पतला-सा व्यक्ति खड़ा था। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और यह बुदबुदाते हुए चली गई कि वह ठीक है। उसे नहीं पता था कि वह देश के श्रेष्ठ प्रशिक्षित चिकित्सा सहायक से दूर जा रही है।

क्रिस्टोफर माग

एक करोड़पति से पैरामेडिक (चिकित्सा सहायक) बनने का जोनाथन क्लीसनर का सफर 13 वर्ष पहले शुरू हुआ था।

क्लीसनर के लिए यह मामला कोई चुनौती भरा नहीं था, लेकिन यह वॉल स्ट्रीट में उनकी पुरानी नौकरी से जरूर बेहतर था। उन्होंने सामान समेटते हुए साथियों से कहा, ‘हमें इस तरह के बेकार कॉल खूब आते हैं, लेकिन हमारी रोजी-रोटी बड़े हादसों जैसे-ट्रेन से कटने से चलती है।’ एक करोड़पति से पैरामेडिक (चिकित्सा सहायक) बनने का क्लीसनर का सफर 13 वर्ष पहले शुरू हुआ था। वह कमोडिटी ट्रेडर के रूप में वॉल स्ट्रीट में काम करते थे और उन्हें 32,000 डॉलर वेतन मिलता था। अभी उनका मासिक वेतन करीब 1,10,000 डॉलर होता। लोग उनसे कहते हैं कि एक घंटे के 18 डॉलर के लिए अपना जीवन क्यों खतरे में डाल रहे हो, लेकिन क्लीसनर के मन में लोगों को बचाने की धुन सवार है।

2008 में वह माउंट रेनियर की चोटी घूमने गए थे। बर्फीले तूफान में एक महिला का घुटना फट गया। तब किसी ने कहा, ‘इस तरह की चोटियों पर आने के लिए चिकित्सकीय प्रशिक्षण लेना जरूरी है।’

2008 में वह एक समूह के साथ माउंट रेनियर की चोटी घूमने गए थे, उसी दौरान बर्फीले तूफान में एक महिला का घुटना फट गया। तब किसी ने कहा, ‘इस तरह की चोटियों पर आने के लिए चिकित्सकीय प्रशिक्षण लेना जरूरी है।’ उन्होंने न्यूयॉर्क लौटते ही आपातकालीन चिकित्सा सहायक का काम सीखा। फिर अग्निशमन विभाग ने पैरामेडिक्स अकादमी में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर वह लोगों को बचाने की खातिर फायर डिपार्टमेंट में शामिल हो गए। अभी 4,500 आपातकाल चिकित्साकर्मियों में से क्लीसनर चुनिंदा 60 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें आग से लोगों को बचाने, मेट्रो कारों के नीचे फंसे लोगों को निकालने, घायलों की मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वह अन्य बचाव चिकित्सा दलों को भी प्रशिक्षण देते हैं। यही नहीं, वह छुट्टियों और शिफ्ट की चिंता किए बिना बड़े-बड़े हादसों में अपने जीवन को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में सबसे आगे रहते हैं।

आंकड़े

फेसबुक यूजर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है तो मूल रूप से अमेरिका का, लेकिन अन्य देशों की तुलना में उसके सबसे ज्यादा यूजर भारत में हैं।

भारत	58.2
अमेरिका	28.0
इंडोनेशिया	20.2
ब्राजील	11.3
मेक्सिको	9.2

आंकड़े फेसबुक यूजर्स की संख्या के, करोड़ में | स्रोत : Statista, 2025

अंतर्यात्रा

एक सज्जन मूर्ति और शालिग्राम में भेद करते थे। श्रीवल्लभाचार्य जी ने उन्हें समझाया कि भगवद्-विग्रह में इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

भक्ति में भेदभाव ठीक नहीं

आचार्यपाद श्रीवल्लभाचार्य जी ग्यारह वर्ष की उम्र में अध्ययन समाप्त करने के बाद तीर्थाटन के लिए रवाना हुए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर वहां बड़े-बड़े विद्वानों को शास्त्रों में हराया। वहीं पर उन्हें वैष्णवाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। बताया जाता है कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने की इच्छा व्यक्त की। श्री विट्ठल के रूप में विट्ठल भगवान को उन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया।

श्रीवल्लभाचार्य जी के संबंध में भक्ति-भाव बढ़ाने वाली कई कथाएं हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं मूर्ति, दोनों की एकसाथ पूजा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में भेदभाव था। वह शिला को अच्छी और मूर्ति को निम्न श्रेणी की समझते थे। श्रीवल्लभाचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवद्-विग्रह में इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पर वह सज्जन बिगड़ गए और अकड़कर मूर्ति के सीने पर रात में शालिग्राम को रखकर चले गए।

अंतर्यात्रा
संकलित

सुबह देखने पर मालूम हुआ कि शालिग्राम की शिला चूर-चूर हो गई है। तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्रीवल्लभाचार्य जी से क्षमा मांगी। फिर श्रीवल्लभाचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने के लिए कहा, ऐसा करते ही शिला फिर ज्यों-की त्यों हो गई। इसके बाद उन्हें समझ आ गया कि भक्ति मार्ग में इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है।

आज का इतिहास

टाइटैनिक के डूबने के 73 वर्ष बाद पहली बार उसकी तस्वीरें सामने आईं

दुनिया का सबसे बड़ा, वाष्प इंजन चालित यात्री जहाज टाइटैनिक, इंग्लैंड के साउथहैंप्टन से अपनी प्रथम यात्रा पर, 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ लेकिन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। समुद्र में डूबे इस जहाज की पहली तस्वीरें इसके डूबने के 73 वर्ष बाद चार सितंबर 1985 को पहली बार सामने आईं। दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला बताया गया यह जहाज चार दिन की यात्रा के बाद, 14 अप्रैल 1912 को एक हिमशिला से टकरा कर डूब गया था। इतिहास की शांतिकाल की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक इस घटना में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1665 : मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंधर की संधि पर हस्ताक्षर। 1825 : प्रमुख राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरोजी का जन्म। 1888 : महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरु की। 1944 : द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया। 1946 : भारत में अंतरिम सरकार का गठन। 1967 : महाराष्ट्र का कोयना बांध भूकंप की चपेट में आकर ध्वस्त, 200 से ज्यादा लोगों की मौत।

वित्तीय रूपांतरण का लॉन्चपैड

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.16 करोड़ खाते खुल चुके हैं। बीते 11 साल में यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है।

दिलीप अस्बे

आर्थिकी

अगस्त, 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 11 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है। अगस्त 2025 तक इसके तहत 55.16 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं और कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

पीएमजेडीवाई ने न केवल बहुत से लोगों को बैंकिंग तक पहुंच प्रदान की है, बल्कि इसने देश के विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, डिजिटल वित्तीय ईकोसिस्टम की नींव भी रखी है। इस दायरे को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्रमुखता से बढ़ाया है, जिनकी कुल खातों (43.56 करोड़) और जमा राशि (2.08 लाख करोड़ रुपये) में लगभग 78 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 10.57 करोड़ खातों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी इसमें योगदान दिया है,

जिनके पास 51,000 करोड़ रुपये से अधिक की शेष राशि है। यह भारत के दुर्गम क्षेत्रों में भी औपचारिक बैंकिंग में विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।

सरकार ने निष्क्रिय खातों को फिर से प्रचलन में लाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पुनः केवाईसी और पुनः सक्रियण अभियान (जुलाई-सितंबर 2025) आरंभ किया है। वित्त मंत्रालय की निगरानी में ‘खोले गए खातों’ से ‘सार्थक रूप से उपयोग किए गए खातों’ की ओर यह परिवर्तन पीएमजेडीवाई के अगले चरण को परिभाषित करेगा और इसके प्रभाव को प्रतीकात्मक समावेशन से स्थायी सशक्तीकरण की ओर ले जाएगा। जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी (जेएएम ट्रिनिटी) ने भारत के आर्थिक ईकोसिस्टम में क्रांति ला दी है। आज, 99 प्रतिशत वयस्कों के पास बायोमेट्रिक आईडी है, जिससे बैंक खाते खोलना सरल हो गया है और तत्काल डिजिटल भुगतान की नींव रखी गई है। लगभग 67 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण हैं, जो 36.6 करोड़ से अधिक बैंक खातों के बराबर हैं।

इतना ही नहीं, 55 प्रतिशत से अधिक खातों के साथ पीएमजेडीवाई ने वित्तीय समावेशन को वास्तव में जेंडर-समावेशी बना दिया है। ये खाते पेंशन से लेकर मनरेगा मजदूरी और पीएम-किसान सब्सिडी से लेकर उज्ज्वला हस्तांतरणों तक सरकारी लाभों के लिए वितरण का माध्यम बन गए हैं। जन धन के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने लीकेज और बिचौलियों को समाप्त कर दिया है, जिससे सीधे लाभार्थियों के हाथों में तत्काल पैसा पहुंचाया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापता है, वर्ष 2025 में बढ़कर 67 हो गया, जो वर्ष 2021 की तुलना में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह निरंतर प्रगति ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम के विस्तार, लक्षित सरकारी योजनाओं और मजबूत बैंकिंग पहुंच के प्रभाव को रेखांकित करती है। जन धन खाताधारकों को अगस्त 2025 तक 38.6 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

पीएमजेडीवाई ने ‘खाते खोलने’ से हटकर सक्रिय, डिजिटल रूप से सशक्त उपयोगकर्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अनौपचारिक नकदी रखने के बजाय ग्रामीण परिवारों के पास अब बिचौलियों के बिना सरकारी योजनाओं तक पहुंच और औपचारिक बचत चैनल हैं। साथ ही, ऐसे डिजिटल टूल हैं, जो महिलाओं को धन पर अधिक नियंत्रण, त्वरित राहत और कोविड जैसी घटनाओं के दौरान अधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म-व्यवसाय और किसान अब दैनिक लेनदेन को डिजिटल रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं और औपचारिक ऋण तक अधिक सुगमता से पहुंच सकते हैं। इससे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम होती है और आर्थिक लचीलापन बढ़ता है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 101 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वदेशी चिप विक्रम

राष्ट्रीय राजधानी में 'सेमीकॉन इंडिया, 2025' सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सदी चिप की होगी और जल्द ही भारत की बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की शुरुआत करेगी, वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहली स्वदेशी विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और चार सेमीकंडक्टर टेस्ट चिप प्रधानमंत्री को सौंपकर इस दिशा में भारत की प्रगति का उदाहरण भी पेश किया. विक्रम भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसे इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) के सहयोग से तैयार किया गया है. इस चिप को खासकर स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की चरम स्थितियों में काम करने के लिए तैयार किया गया है. यह उपग्रह प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष यान के लिए आवश्यक जटिल निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है और इसका मजबूत डिजाइन इसे रक्षा, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और ऊर्जा क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है. इस चिप को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव जैसी चरम परिस्थितियों को सहन कर सके. यह माइक्रो प्रोसेसर चिप गणना करने, डाटा प्रोसेस करने और कंट्रोल सिस्टम को चलाने जैसे कई काम कर सकती है और एक बार में 32 बिट्स डाटा प्रोसेस कर सकती है, जो इसकी क्षमता के बारे में बताती है. यह पहले से तैयार स्वदेशी 16 बिट विक्रम 1601 का, जिसे 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा है, एडवांस्ड वर्जन है और इसरो ने इस प्रोसेसर के लिए सभी सॉफ्टवेयर टूल्स खुद ही विकसित किये हैं. विक्रम 3201 का परीक्षण चूंकि पहले ही पीएसएलवी सी-60 मिशन में किया जा चुका है, लिहाजा इस सफलता के बाद इसरो अब इसे अपने आगामी लॉन्च व्हीकल्स में व्यापक रूप से अपनाने जा रहा है. कुछ ही वर्ष पहले भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी और आज देश में पांच सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण चल रहा है. इनमें से एक की पायलट लाइन पूरी हो चुकी है, जबकि दो अन्य में भी जल्द उत्पादन शुरू होगा. भारत अभी तक विदेशों से चिप आयात करता रहा है. लेकिन यह उपलब्धि विदेशी चिप पर भारत की निर्भरता कम करने के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हो सकती है. इसे सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, जिससे सप्लाई चेन बाधाओं और आयात निर्भरता में कमी आने की उम्मीद है.

स्वदेशी चिप विक्रम को सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है. यह उपलब्धि विदेशी चिप पर भारत की निर्भरता कम करने के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

सुनवाई के बाद फैसले में देरी नुकसानदेह

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील
एक्स@viraggupta

सुप्रीम कोर्ट मे हाल ही में कहा है कि हाईकोर्ट को सुनवाई के तीन महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा. दरअसल यह धारणा मजबूत हो रही है कि ताकतवर लोगों के मामलों में जल्द सुनवाई के साथ त्वरित फैसले हो जाते हैं. मुकदमों में विलंब का खामियाजा अधिकांशतः कमजोर और गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है. फैसले में विलंब से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने के साथ न्यायिक अनुशासन को भी ठेस पहुंचती है. लिखित आदेश में विलंब से जनता की अपील का अधिकार भी बाधित होता है.

अग्रिम जमानत के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म होने के तीन सप्ताह बाद तक आदेश जारी नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद हाईकोर्ट की वेबसाइट में आदेश अपलोड हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज साहब के स्टेनो की डायरी जब्त करने और एनआइसी के लॉग रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया है. सुनवाई खत्म होने के बाद आदेश जारी करने में देरी का मर्ज देशव्यापी होने के साथ बहुत पुराना है. एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्टेटस रिपोर्ट मंगायी. उसके अनुसार जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2024 के दौरान 56 मामलों में सुनवाई खत्म होने के बावजूद आदेश जारी नहीं हुए थे. सुप्रीम हस्तक्षेप के बाद 10 याचिकाओं का निपटारा हो गया. उनमें से अधिकांश मामले गरीब लोगों से जुड़े थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट का हाल तो और भी बेहाल है. वहां एक मामले में दिसंबर, 2021 में सुनवाई पूरी होने के बाद जनवरी, 2025 तक आदेश पारित नहीं हुआ. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत कुमार मिश्रा ने 25 अगस्त के फैसले में कहा कि ऐसे विलंब से न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा कमजोर होता है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विलंब से निपटने के लिए हाईकोर्टों में शिकायत निवारण का प्रभावी तंत्र नहीं है. इससे पहले अक्तूबर, 2020 के फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद हाईकोर्ट के फैसलों के विलंब पर रोष व्यक्त किया था.

यह धारणा मजबूत हो रही है कि ताकतवर लोगों के मामलों में जल्द सुनवाई के साथ त्वरित फैसले हो जाते हैं. मुकदमों में विलंब का खामियाजा अधिकांशतः कमजोर और गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है. फैसले में विलंब से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने के साथ न्यायिक अनुशासन को भी ठेस पहुंचती है. सिविल प्रोसिजर कोड (सीपीसी) के अनुसार सुनवाई खत्म होने के 30 दिन में आदेश जारी होना चाहिए. विशेष मामलों में यह अवधि 60 दिन हो सकती है. पुराने क्रिमिनल प्रोजिसर कोड (सीआरपीसी) में ट्रायल खत्म होने के बाद जल्द फैसले के नियम के बावजूद स्पष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं थी. नये बीएनएसएस कानून के अनुसार सुनवाई खत्म होने के 45 दिन के भीतर आदेश जारी होना चाहिए. अनिल राय बनाम बिहार सरकार के 2001 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजों के फैसले के लिए समयसीमा निर्धारित करने का आदेश दिया था. उसमें चीफ जस्टिस कांफ्रेंस की 1989-90 की रिपोर्ट का जिक्र है. उसके अनुसार सुनवाई खत्म होने के छह सप्ताह के भीतर लिखित फैसला जारी होना चाहिए. अगर तीन महीने के भीतर फैसला न हो, तो खुली अदालत में फैसला जारी करने के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदेश दे सकते हैं. वह मामले को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए भी भेज सकते हैं. पर फैसला लिखने में देरी करने वाले जजों को दंडित करने की बजाय उनके द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई होने से पक्षकारों की पीड़ा और बढ़ जाती है.

सुनवाई खत्म होने के बाद लिखित फैसला जारी करने में देरी और मुकदमे की सुनवाई में देरी, दोनों अलग-अलग बातें हैं. सुनवाई में देरी से जिला अदालतों में 4.6 करोड़ और हाईकोर्ट में 63.30 लाख मुकदमे लंबित हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट में 2,185 मुकदमे 50 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित हैं. दिल्ली की जिला अदालतों में लंबित 15.62 लाख मुकदमों में से 2.21 लाख मुकदमों में स्टे मिला है. आपराधिक मुकदमों में जमानत और सिविल मुकदमों में स्थगन के बाद मुख्य मामलों की सुनवाई और फैसला टलता रहता है. सुप्रीम कोर्ट की 'प्रिजन इन इंडिया-2024' की रिपोर्ट के अनुसार जेलों में बंद 70 फीसदी कैदी गरीब परिवार से हैं. झारखंड के 56 मामलों में सुनवाई के बावजूद फैसलों में देरी से साफ है कि गरीबों के पास पैरवी के लिए अच्छे वकील न होने से उन्हें जल्द न्याय नहीं मिलता. गरीबों की निःशुल्क कानूनी मदद के लिए सरकार की विधिक सेवा योजना भी मकसद पूरा करने में विफल है. सोशल मीडिया में व्यंग्य चल रहा है कि आवारा कुत्तों को तुरंत राहत मिल गयी, पर आम जनता को जीवनकाल में न्याय नहीं मिलता. सरकारी डीटीसी बस में 15 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा कराने के आरोप में बर्खास्त कंडक्टर को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से राहत मिली. पर कई दशक की मुकदमेबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की सुनवाई में देरी के दौरान कंडक्टर की मृत्यु हो गयी. ऐसी देरी से न सिर्फ पक्षकारों का भरोसा कमजोर होता है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में बाधा भी होती है. हाईकोर्ट के सिविल मुकदमों में सिविल प्रोसिजर कोड (सीपीसी) की धारा-151 के अनुसार अर्जियां दायर होती हैं. इसलिए संवैधानिक अदालतों पर भी सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं. संविधान के अनुच्छेद-141 के अनुसार भी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हाईकोर्ट के जजों पर बाध्यकारी हैं. उसके बावजूद सुनवाई के बाद फैसलों में देरी के बढ़ते देशव्यापी मर्ज से कई सवाल खड़े होते हैं. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मामले में स्टेनो की डायरी जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाहिर है कि ऐसे विलंब के पीछे न्याय को प्रभावित करने वाले दूसरे कारण भी हो सकते हैं. लिखित आदेश में विलंब से जनता की अपील का अधिकार भी बाधित होता है.

हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत हैं और उनका स्वतंत्र क्षेत्राधिकार भी है, लेकिन संवैधानिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए जजों को संक्षिप्त और सारगर्भित फैसले लिखने चाहिए. इसके लिए जटिल मामलों की सुनवाई के बाद फैसलों को तुरंत लिखवाने और वेबसाइट में अपलोड करने से पारदर्शिता के साथ न्यायिक सिस्टम में ईमानदारी भी बढ़ सकती है. अगर आम आदमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करे, तो उसके खिलाफ अवमानना का मामला चल सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के खिलाफ भी अवमानना मामलों में सख्त आदेश पारित होते हैं. जजों को संवैधानिक सुरक्षा हासिल है और उनके खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चल सकता. इसके बावजूद कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करने वाले जजों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है. इससे मुकदमों का जल्द निपटारा होने के साथ न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा और सम्मान बढ़ेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

भीषण बाढ़ से जूझते पंजाब को मदद की जरूरत

पंकज चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
pc7001010@gmail.com

बाढ़ से तीन लाख एकड़ से ज्यादा फसली जमीन को नुकसान हुआ है और 2.56 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. जितनी बड़ी यह आपदा है, उतनी ही व्यापक पैमाने पर मदद की आवश्यकता उस राज्य के बाढ़ पीड़ितों को है.

देश की भूख मिटाने वाला पंजाब इन दिनों बीते कई दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है. गांव के गांव बह गये हैं. खेतों में बालू ने घर बना लिया है. पंजाब के ये हालात पानी उतरने के बाद भी नहीं सुधरने वाले. बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद पांच नदियों के इस राज्य की दिक्कतें और बढ़ेंगी. सारा देश पंजाब के साथ खड़ा है और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है. खेती और पशुधन से संपन्न पंजाब में नदियों-नालों में आये उफान के कारण तीन लाख एकड़ से ज्यादा फसली जमीन को हानि पहुंची है. सबसे अधिक असर धान, मक्का, सब्जियों और अन्य खरीफ फसलों पर हुआ है. सीमा से लगे गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, फाजिल्का, कपूरथला और आसपास के गांवों में घर, सड़क और दुकानें पानी में डूब गयी हैं. अब तक 29 लोगों की मौत हुई है और 2.56 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं.

पंजाब का समाज बहुत जीवट वाला है, लेकिन आज वहां हुई तबाही को देखते हुए बड़ी मात्रा में मदद जरूरी है. कई हजार वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है, जहां अगले कई महीनों तक पानी व उसके साथ आयी रेत व गाद जमा रहेगी. पानी में फंसे लोगों के लिए भोजन जरूरी है और उसकी व्यवस्था स्थानीय सरकार व कई जन संगठन कर रहे हैं. लेकिन वहां पीने के लिए साफ पानी की बहुत कमी है और राज्य के सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं. गंदा पानी पीने से हैजा फैलने का खतरा है. वहां लाखों बोतल पेयजल की रोज की मांग के साथ बगैर बिजली वाले फिल्टर, बड़े आरओ, बैटरी, इन्वर्टर व आम लोगों के लिए मोमबत्तियां व माचिस की सख्त जरूरत है, क्योंकि बिजली की आपूर्ति सामान्य करने में बहुत से अड़ंगे हैं. पानी भरे क्षेत्रों में महामारी को रोकने के लिए फिनाइल, क्लोरीन पाउडर, मच्छर मारने के स्प्रे आदि चाहिए.

वर्षा खत्म होने पर गलियों-मोहल्लों में भरे पानी को निकालना, कीचड़ हटाना, मरे जानवरों व इंसानों का निस्तारण और सफाई सबसे बड़ा काम होगा. जब तक गंदगी, मलबा और पानी हटेगा नहीं, तब तक जीवन को फिर से पटरी पर लाना मुश्किल है. बाढ़ प्रभावितों में हजारों लोग ऐसे हैं, जो मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें नियमित दवाई लेनी पड़ती है और बाढ़ उनकी सारी दवा बहा कर ले गयी है. अपना सब कुछ लुटने के दर्द और राहत शिविरों की सीमित व्यवस्था के चलते मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की संख्या भी बढ़ रही है. उनकी नियमित दवाएं, पानी की बोतलें, डेटॉल, फिनाइल, क्लोरीन की गोलियां, पेट में संक्रमण और बुखार की दवाएं, ग्लूकोज पाउडर, औरतों के लिए सेनेटरी नैपकिन आदि तत्काल जरूरत की चीजें हैं. पंजाब के दूरस्थ अंचलों में नवनिर्माण के लिए सीमेंट, लोहा जैसी निर्माण सामग्री भेजना भी आवश्यक है. फिलहाल तो राज्य के गांवों से ढाई लाख लोग अपने घर से पूरी तरह विस्थापित हुए हैं. वहां के बाजार बह गये हैं, वाहन नष्ट हो गये हैं. ऐसे में जान-माल के नुकसान के बीमा दावों का तत्काल निपटारा एक बड़ी राहत होगी. चूंकि राज्य सरकार का बिखरा-लुटा-पिटा अमला अभी खुद को संभालने में लगा है, ऐसे में नुकसान के आकलन, दावे पेश करने, बीमा कंपनियों पर तत्काल भुगतान के लिए दबाव बनाने आदि के लिए बहुत से पढ़े-लिखे लोगों की वहां जरूरत है. ऐसे लोगों की भी जरूरत है, जो दूरदराज में हुए माल-असबाब के नुकसान की सूचना और सही मूल्यांकन सरकार तक पहुंचा सकें और यह सुनिश्चित करें कि केंद्र या राज्य सरकार की किन योजनाओं का लाभ बाढ़ प्रभावितों को मिल सकता है.

पानी उतरने पर जीवन को फिर से पटरी पर लाना भी गंभीर समस्या होगी, क्योंकि सरकारी राहत का पैसा बैंक खाते में जायेगा और उसी खाते में जायेगा, जिनके पास आधार कार्ड है. जिनका घर व सामान बाढ़ में बह गया, उनके पास आधार तो होने से रहा. ऐसे में लोगों को उनकी पहचान के कागजात उपलब्ध कराने के लिए ऐसे लोगों को आगे आना होगा, जो बाढ़ प्रभावितों के डुप्लीकेट आधार आदि कंप्यूटर से निकाल कर उन तक पहुंचा सकें. जब हालात कुछ सुधरेंगे, तब स्कूल व शिक्षा की याद आयेगी और तभी पता चलेगा कि सैलाब में स्कूल, किताबें, बच्चों के बस्ते सब बह गये हैं. जाहिर है, कम से कम दो लाख बच्चों को बस्तों, कॉपी-किताबों, पेंसिल, पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी. वहां की पाठ्यपुस्तकों को फिर से छपवाना पड़ेगा, ब्लैकबोर्ड व फर्नीचर बनवाने पड़ेंगे. जाहिर है, संस्थागत या निजी तौर पर बच्चों के लिए काम करने की जरूरत है. उनके पौष्टिक आहार के लिए बिस्किट और सूखे मेवे जैसी चीजों की मांग भी है. हमारे यहां आज तक कोई दिशानिर्देश बनाये ही नहीं गये कि आपदा की स्थिति में किस तरह की तात्कालिक तथा दीर्घकालिक सहयोग की जरूरत होती है. यह कोई दान या मदद नहीं है, हम एक मुल्क का नागरिक होने का अपना फर्ज अदा करने के लिए अपने संकटग्रस्त देशवासियों के साथ खड़े होते हैं. ऐसे में, यदि हम जरूरत के मुताबिक पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हों, तो यह सार्थक होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश दुनिया

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा में अधिक निवेश जरूरी

चौदह वर्षों में लगातार गिरावट के बाद बांग्लादेश में स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि चिंताजनक है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (डीपीइ) द्वारा जारी वार्षिक प्राथमिक विद्यालय सांख्यिकी 2024 के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय छोड़ने की दर 2023 के13.15 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 16.25 प्रतिशत हो गयी. रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि जैसे-जैसे छात्र उच्च कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, स्कूल छोड़ने की दर बढ़ रही है. यह दर्शाता है कि स्कूली शिक्षा में आगे बढ़ने के साथ छात्रों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. चिंताजनक है कि स्कूल छोड़ने की यह दर लड़कों में अधिक है. वर्ष 2010 में, लगभग 10 में से चार छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी करने में असफल रहे थे. तब से बांग्लादेश ने निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण, वजीफे की संख्या बढ़ाने और मध्याह्न भोजन जैसे उपायों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है. हालांकि, पिछले वर्ष जुलाई में देश में हुए विद्रोह के दौरान और उसके बाद हुई राजनीतिक अशांति ने स्कूलों और कॉलेजों सहित पूरे शिक्षा क्षेत्र में बड़े व्यवधान उत्पन्न किये. रिपोर्ट ने स्कूल छोड़ने की दरों में वृद्धि के लिए कई अन्य कारकों की भी पहचान की है. इनमें बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत के कारण छात्र वजीफों के वास्तविक मूल्य में आयी कमी भी है, जिससे कई परिवारों के लिए शिक्षा का खर्च वहन करना मुश्किल हो गया है. इसके अतिरिक्त मौसमी प्रवास, घरेलू आर्थिक झटके और जलवायु संबंधी कठिनाइयों ने भी इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, विशेष रूप से वंचित समुदायों के बीच. ऐसे समय में, जब देश से सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा की जा रही है, तब हम कड़ी मेहनत से अर्जित प्रगति से पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते. विशेषज्ञों की मानें, तो छात्रों को स्कूल में बनाये रखने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा में अधिक निवेश करना अत्यंत आवश्यक है.

The Daily Star

200वीं जयंती पर विशेष

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे दादाभाई नौरोजी

सुधीर कुमार
टिप्पणीकार
sudhirphd@bhu.ac.in

ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय दादाभाई नौरोजी का योगदान केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने समाज सुधारक, शिक्षाविद, राजनेता, आर्थिक चिंतक, पत्रकार, संगठनकर्ता और ब्रिटिश भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी उल्लेखनीय भूमिका निभायी. आज से ठीक दो सौ वर्ष पहले एक साधारण पारसी परिवार में जन्मे नौरोजी भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे, जिन्हें अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रथम भारतीय होने का सम्मान मिला. नौरोजी देश के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना कर इसे मात्र बीस रुपये प्रतिवर्ष बताया था. वे धन की निकासी सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक के रूप में भी जाने जाते हैं. ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे वे. वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से 'स्वशासन' की मांग रखी थी.

एक शिक्षक के रूप में उनके जीवन का आरंभ तब हुआ, जब बंबई (अब मुंबई) के एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने गणित पढ़ाना शुरू किया. वर्ष 1851 में उन्होंने खरशेदजी नुसरवानजी कामा के साथ 'रास्त गोफ्तार' नामक आंग्ल-गुजराती साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनी. इसी वर्ष 'रहनुमाई मजदायस्नान' सभा की स्थापना के जरिये उन्होंने पारसी समाज की कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया. बाद में उन्होंने शिक्षण छोड़ व्यवसाय जगत में कदम रखा. वर्ष 1855 में इंग्लैंड पहुंचकर वे पहली भारतीय व्यावसायिक फार्मा कंपनी 'कामा एंड कंपनी' से जुड़ गये. यहां काम करते हुए उन्हें लगा कि भारत की वास्तविक उन्नति केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता से संभव नहीं, इसके लिए राजनीतिक चेतना और सामाजिक सुधार भी आवश्यक है. उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश जनता को भारत में हो रहे शोषण और अन्याय की सच्चाई से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है. उनका विश्वास था कि यदि ब्रिटिश जनमानस को भारत की वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी हो जायेगी, तो वे औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध आवाज उठायेंगे. इसी उद्देश्य से उन्होंने विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक संगठनों की स्थापना और संचालन में सक्रिय भागीदारी की. इसी क्रम में 1865 में 'लंदन इंडिया सोसाइटी' की स्थापना हुई, जो विदेश में गठित पहला भारतीय संगठन था. इसका उद्देश्य भारतीय और अंग्रेजों को सामाजिक एवं बौद्धिक संवाद के जरिये जोड़ना था. एक दिसंबर, 1866 को यही संस्था 'ईस्ट इंडिया एसोसिएशन' में परिवर्तित हो गयी, जिसने भारत की राजनीतिक मांगों को व्यवस्थित रूप देने और उन्हें ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया.

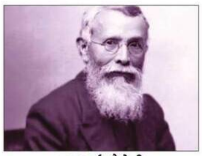

दादाभाई नौरोजी
(04 सितंबर, 1825-30 जून, 1917)

नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को संगठन, राजनीति और आर्थिक चेतना की राह दिखाई. इतना ही नहीं, उन्होंने औपनिवेशिक शासन की नीतियों का गहन अध्ययन कर भारत की गरीबी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषणकारी चरित्र को उजागर किया. विशेष रूप से उनके द्वारा प्रतिपादित 'धन निकासी सिद्धांत' भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधार का केंद्रीय स्तंभ बन गया. दरअसल, 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार मिला, तभी से भारत में संगठित आर्थिक लूट की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी. नौरोजी उन पहले भारतीय बुद्धिजीवियों में से थे, जिन्होंने इस शोषण का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन शासन के अंतर्गत भारत की आर्थिक समस्याओं का गहन अध्ययन किया और तथ्यों व तालिकाओं के आधार पर कई शोधपत्र प्रस्तुत किये. दो मई, 1867 को 'ईस्ट इंडिया एसोसिएशन' की बैठक में उन्होंने अपने शोधपत्र 'भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य' में पहली बार धन निकासी के सिद्धांत (ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी) को प्रस्तुत किया. इस सिद्धांत के अनुसार, भारत से इंग्लैंड में जो विशाल धनराशि भेजी जाती थी, उसके बदले भारत को कोई प्रत्यक्ष आर्थिक या व्यापारिक लाभ नहीं मिलता था. नौरोजी का स्पष्ट मत था कि धन निकासी की यह प्रक्रिया भारतीय निर्धनता और पिछड़ेपन का मूल कारण है. वर्ष 1876 में उक्त संस्था के समक्ष उन्होंने 'द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया' शीर्षक से एक और शोधपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दर्शाया गया कि 1835 से 1872 के बीच भारत से लगभग 50 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग (आज के संदर्भ में हजारों करोड़ रुपये) इंग्लैंड भेजे गये. उनके अनुसार, हर वर्ष औसतन 30 मिलियन पाउंड की धनराशि भारत से बाहर इंग्लैंड भेजी जाती है. नौरोजी ने एक सच्चे देशभक्त और प्रखर अर्थशास्त्री के रूप में न केवल इस शोषण को संख्यात्मक रूप में प्रमाणित किया, बल्कि अपने तर्कों से अंग्रेज अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं को भी इस विषय पर गंभीर बहस करने के लिए विवश कर दिया. अपने विलक्षण व्यक्तित्व के लिए वे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे.

आपके पत्र

सफल व्यक्ति से सीखने की जरूरत

प्रभात खबर के एक सितंबर के संपादकीय पेज पर प्रकाशित आलोक पुराणिक के आलेख में, 'जो पिछड़ जाते हैं, वही ईर्ष्या करते हैं', सत्य बयान किया गया है. देखा गया है कि कई असफल लोग सफल व्यक्ति को नीचा दिखाने और उसे परेशान करने के लिए तरह-तरह के प्रपंच रचते हैं, ताकि सामने वाले को दुख पहुंचे. पर वे इस बात की तह में जाने की कोशिश नहीं करते कि जो व्यक्ति आज सफल है, उसने इसके लिए कितनी मेहनत की है. हमें ईर्ष्या करने की जगह सफल व्यक्ति से सीखने की जरूरत है.

जीतेंद्र कुमार, रांची

स्थानीय कलाकारों को मिला मंच

हाल ही में हजारीबाग के स्थानीय कलाकारों द्वारा बनायी गयी वेब सीरीज 'अटकल बियाह' का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज हुआ. इसे दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जो संकेत देती है कि झारखंड में फिल्मों और वेब सीरीज का भविष्य उज्ज्वल है. झारखंड अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां के कलाकार प्रतिभाशाली हैं, पर उन्हें अवसरों और मंच की कमी अक्सर खलती रही है. 'अटकल बियाह' जैसी पहल कलाकारों को अपनी पहचान बनाने का अवसर दे रही है.

अमित कुमार कुशवाहा, हजारीबाग

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

बारिश और पुनरावृत्ति

जल-द्वारों की उपेक्षा से होने वाले नुकसान के लिए अत्यधिक वर्षा कोई बहाना नहीं है। इस मौसम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी वर्षा

टी और बाढ़ इस बात को रेखांकित करती है कि चरम मौसम किस प्रकार परस्पर क्रिया करता है।

शासन के साथ। 2024 में, आंध्र प्रदेश ने दो दिनों में अपनी वार्षिक वर्षा का 27% रिकॉर्ड किया; इस अगस्त में, विजयनगरम में 46% अधिक वर्षा दर्ज की गई, कुछ हिस्सों में 90% तक की रिपोर्ट की गई। लगातार वर्षों से अत्यधिक वर्षा मानसून के व्यवहार में बदलाव का संकेत देती है। नदी घाटियों में जलाशय और बैराज प्रणालियों को मौसमी बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन हाल की बारिश की घटनाओं का समय और तीव्रता मायने रखती है। इस वर्ष एक समय पर, श्रीशैलम 94% और नागार्जुन सागर 96% भरा हुआ था, जिससे अतिरिक्त बाढ़ की बहुत कम गुंजाइश थी। संकट वास्तव में अतिरिक्त वर्षा और छोटे-छोटे विस्फोटों में इसकी सांद्रता है जब जलाशय पहले से ही लगभग भरे हुए हैं। पिछले साल, 7,000 क्यूसेक की क्षमता वाली एक छोटी नदी बुडामेरु में 35,000 क्यूसेक पानी बरसा और विजयवाड़ा में बाढ़ आ गई। यह पुनरावृत्ति इस ओर इशारा करती है कि कैसे छोटी सहायक नदियाँ और जल निकासी चैनल, जिन्हें अक्सर नीतियों में नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, दुर्बल करने वाले अवरोध बिंदु बन जाते हैं। जहाँ विशाल जलस्तर बाढ़ के एक हिस्से को स्पष्ट करता है, वहीं बुनियादी ढाँचे की कमज़ोरियाँ नुकसान को और बढ़ा देती हैं। प्रकाशम बैराज में, पिछले साल क्षतिग्रस्त हुआ एक गेट इस मौसम में भी मरम्मत के बिना पड़ा रहा, जिससे पानी का सुचारू निकास बाधित हुआ। गोदावरी के किनारे, भद्राचलम के पास बाढ़ के तटबंध जगह-जगह डूब गए या ढह गए, जिससे सीमा के दोनों ओर के निवासियों में चिंता बढ़ गई। शहरी क्षेत्रों में, आंशिक रूप से गाद से मुक्त नालों, अतिक्रमित वर्षा जल चैनलों और कंक्रीट की सतहों ने जल अवशोषण को सीमित कर दिया है। कुल मिलाकर, बुनियादी ढाँचा मौजूद है, लेकिन उसका रखरखाव या तत्काल उन्नयन नहीं किया जा रहा है।

दोनों राज्यों में आपदा प्रबंधन तंत्र परिपक्व है और उसने कई लोगों की जान बचाई है। फिर भी, जोखिम कम करने में संस्थाएँ उतनी सक्रिय नहीं हैं। साल दर साल, तत्काल राहत के लिए बड़ी रकम मंजूर की जाती है (तेलंगाना ने हाल ही में अल्प सूचना पर प्रति ज़िला ₹1 करोड़ जारी किए), लेकिन जल-तटों को मज़बूत करने और जल-मार्ग परिवर्तन चैनलों को पूरा करने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2024 और 2025 में, अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में अत्यधिक वर्षा हुई। दोनों ही बार, कृष्णा और गोदावरी प्रणालियाँ बुरी तरह प्रभावित हुईं और विजयवाड़ा जलमग्न हो गया।

दोनों बार, विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें बुडामेरु के अधूरे कार्यों और राहत निधि के अस्पष्ट उपयोग को उजागर किया गया। अत्यधिक वर्षा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका पूर्वानुमान लगाकर इसके परिणामों को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जलाशय प्रबंधन में वास्तविक समय के जलविज्ञान मॉडलिंग को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ से पहले जल स्तर कम हो जाए और बाढ़ के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवच तैयार हो। शहरी नियोजन को जल निकासी नेटवर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए और जल अवशोषण के लिए पारगम्य भूमि आरक्षित करनी चाहिए, केवल दिखावटी गाद हटाने के अभियानों से आगे बढ़कर। बाढ़ के किनारों और नालों को निरंतर, न कि आकस्मिक, रखरखाव की आवश्यकता होती है, और उनके रखरखाव को राजनीतिक चक्रों से अलग रखा जाना चाहिए। कोई भी राज्य यह तर्क देने में गलत नहीं है कि असाधारण बारिश मजबूत प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन अगर वे इसे सुधार से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों ही घातक परिणाम भुगतने का जोखिम उठाते हैं।

पारिवारिक राजनीति

कविता बीआरएस के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार द्वारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई

टी परियोजना से संबंधित कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के फैसले ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के संरक्षक के. चंद्रशेखर राव के परिवार में कलह शुरू कर दिया है। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री, श्री राव, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए, 2023 में पुनरुत्थानशील कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने के बाद राजनीतिक अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष का सामना कर रहे हैं। उनकी बेटी के. कविता ने सार्वजनिक रूप से अपने चचेरे भाइयों - वरिष्ठ नेता टी. हरीश राव और पूर्व संसद सदस्य जे. संतोष कुमार को अपने पिता की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दोनों नेताओं को संरक्षक के साथ-साथ उनके बेटे और अभिषिक्त उत्तराधिकारी केटी रामाराव का भी करीबी माना जाता है। श्री राव नौसिखिए नहीं हैं और वह किसी और के बहकावे में आने से बेहतर जानते हैं। इसलिए, सुश्री कविता के आरोप परिवार के भीतर विरासत और सत्ता के लिए रस्साकशी से ज़्यादा जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद, उन्हें पार्टी ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के रूप में मनोनीत किया, लेकिन उन्हें लगता है कि वे इससे बेहतर की हकदार थीं। उनके पिता, भाई और चचेरे भाई उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए सुश्री कविता ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए और पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। सुश्री कविता ने पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है।

सुश्री कविता का अपने पिता के समर्थकों के खिलाफ गुस्सा उनके लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है। दरअसल, वरिष्ठ श्री.

2023 के चुनाव से पहले राव की गलतियां। अपने लिए एक राष्ट्रीय भूमिका का दावा करते हुए, उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया था - एक नेता और एक पार्टी के लिए विरोधाभासी, जिसके पास वैधता के प्रमुख स्रोत के रूप में क्षेत्रवाद से ज्यादा कुछ नहीं था। 2024 के आम चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय भूमिका का एहसास करने से दूर, श्री राव ने पाया कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है और भ्रष्टाचार के आरोप उनके चारों ओर घूम रहे हैं। मई 2025 में, सुश्री कविता ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में अपने पिता की मौन स्थिति पर सवाल उठाया था। बीआरएस से उनका बाहर निकलना एक क्षेत्रीय दल के लिए संकट का संकेत है जिसने अपने वादे बहुत जल्द पूरे कर दिए। अपने शासन में एक संसाधन संपन्न और गतिशील राज्य के साथ, बीआरएस और राव परिवार शासन और विकास में एक शानदार विरासत छोड़ सकते थे।

चुनावी और संगठनात्मक राजनीति को सत्ता के घिनौने सौदेबाज़ी और लेन-देन तक सीमित करके, बीआरएस ने खुद को और नए राज्य को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। राजनीति में, नेताओं और पार्टियों के लिए दूसरा मौका हमेशा संभव होता है। लेकिन, फिलहाल, बीआरएस कमज़ोर पड़ गया है।

न्यायाधीश की असहमति को छिपाना, न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करना

सी संवैधानिक लोकतंत्र न केवल लिखित कानूनों से बल्कि दक्षिण अफ्रीकी कानून के प्रोफेसर द्वारा बताए गए सिद्धांतों से भी कायम रहते हैं।

एटियेन मुरेनिक, जिसे पहले एक के रूप में वर्णित किया गया था "न्याय की संस्कृति"। यानी, यह विचार कि सार्वजनिक शक्ति के हर प्रयोग की व्याख्या और बचाव किया जाना चाहिए। जैसा कि मुरेनिक ने कहा, "सरकार द्वारा दिया गया नेतृत्व उसके निर्णयों के बचाव में प्रस्तुत मामले की तार्किकता पर आधारित होता है, न कि उसके अधीन बल द्वारा प्रेरित भय पर।"

भारत में न्यायाधीश राज्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए नियमित रूप से इस सिद्धांत का सहारा लेते रहे हैं। लेकिन मीडिया में आई खबरों के अनुसार, कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति विपुल एम.

पंचोली ने न्यायालय को बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय की यह संस्कृति कॉलेजियम के दरवाजे पर समाप्त हो जाती है।
जब न्यायालय द्वारा अपने सदस्यों के चयन की बात आती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं है।

व्यवस्था पर एक अभियोग इस तरह की असहमति आमतौर पर एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कॉलेजियम और इसकी लगभग पूर्ण अपारदर्शिता का मतलब है कि विरोध एक विफलता के बजाय एक निरर्थक कवायद साबित हुआ है। न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रस्ताव, जिसमें सिफारिश प्रदर्शित है, सर्वसम्मति का संकेत देता है। इसमें असहमति का कोई उल्लेख नहीं है। हमें न्यायमूर्ति नागरत्ना की आपत्ति के बारे में मीडिया में आई खबरों से ही पता चला। उन्होंने जो नोट लिखा था वह छिपा हुआ है, लेकिन हमें बताया गया है कि उनकी आपत्तियाँ "गंभीर" थीं। यह स्पष्ट नहीं है कि असहमति केंद्र सरकार के साथ साझा की गई थी या नहीं, जिसने सिफारिश के 48 घंटों के भीतर ही नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया।

जो हम जानते हैं और जो हमें जानने की अनुमति है, उसके बीच का यह अंतर, उस प्रणाली में निहित अधिकारों का प्रतीक है जिससे हम अपने न्यायालयों में सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। भारत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक ने शायद यह माना होगा कि उम्मीदवार की पदोन्नति न होने के ठोस कारण थे, फिर भी उनके तर्क और बहुमत की प्रतिक्रिया, दोनों ही अज्ञात हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि असहमति केवल एक नियुक्ति से संबंधित हो सकती है। यह संभव है कि कॉलेजियम के अन्य सदस्यों के पास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए भारी कारण रहे हों।

लेकिन यह तथ्य कि जनता को कुछ भी नहीं बताया जाता, अपने आप में इस व्यवस्था पर दोषारोपण है - इसकी पारदर्शिता की कमी, इसकी लोकतांत्रिक नैतिकता, तथा उन लोगों के समक्ष अपनी बात रखने से इनकार करना जिनके नाम पर यह काम करती है।

कॉलेजियम शुरू से ही पारदर्शिता के प्रति प्रतिरोधी रहा है। यह न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून का परिणाम है। इसे "द्वितीय न्यायाधीश मामले" (1993) में बनाया गया था और "तृतीय न्यायाधीश मामले" में इसकी जड़ें गहरी हो गई हैं।

सुहृथ पार्थसारथी
एक वकील है जो अभ्यास कर रहा है
मद्रास उच्च न्यायालय

"केस" (1998) के अनुसार, यह व्यवस्था उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों को प्रधानता प्रदान करती है। वे निजी तौर पर विचार-विमर्श करते हैं, न्यूनतम प्रकटीकरण के साथ निर्णय दर्ज करते हैं, और शायद ही कभी अपने तर्क स्पष्ट करते हैं।

2017 की शुरुआत में, कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव प्रकाशित करना शुरू किया। लेकिन ये प्रस्ताव बहुत ही कम थे और औपचारिक घोषणाओं से ज़्यादा कुछ नहीं थे। 2018 में थोड़े समय के लिए, न्यायालय ने कॉलेजियम के निर्णयों और अस्वीकृतियों के विस्तृत कारण अपलोड किए। हालाँकि, यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि यह तर्क दिया गया कि खुलासे से प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच सकती है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति गोपनीयता के इस दुराग्रह की कीमत को उजागर करती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश की आपत्ति भी जनता के लिए अति संवेदनशील मानी जाती है, तो हमें यह पूछना होगा कि क्या कॉलेजियम ने न केवल अस्पष्टता को अपनाया है, बल्कि जवाबदेही को पूरी तरह से नकार दिया है।

कमज़ोर बचाव अपने तर्कों को
गोपनीय रखने का बचाव हमेशा दो दावों पर टिका रहा है: यह कि खुलापन उन उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकता है जिनका चयन नहीं होता, और यह कि इससे व्यवस्था राजनीतिक दबावों के सामने आ जाएगी। उचित जाँच-पड़ताल करने पर, दोनों ही दावे ध्वस्त हो जाते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पारदर्शिता और प्रतिष्ठागत निष्पक्षता के बीच तालमेल बिठाने के लिए सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता है।
लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य संवैधानिक लोकतंत्र इसे भारत से बेहतर तरीके से प्रबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन का न्यायिक नियुक्ति आयोग अपने मानदंड खुले तौर पर निर्धारित करता है और रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन कैसे किया गया। दक्षिण अफ्रीका में, उच्च न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार न्यायिक सेवा आयोग द्वारा लिया जाता है, और उनकी उपयुक्तता पर सार्वजनिक रूप से बहस की जाती है। दोनों ही प्रणालियाँ त्रुटिपूर्ण नहीं हैं, बल्कि दोनों ही इस मान्यता से आगे बढ़ती हैं कि वैधता खुलेपन से आती है।

इसके विपरीत, भारत कॉलेजियम को एक निजी सम्मेलन मानता आ रहा है।
यहाँ तक कि असहमति का अस्तित्व भी हम तक लीक के ज़रिए ही पहुँचता है। अगर प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान एक वास्तविक चिंता है, तो इसका समाधान इसे कम करने के लिए सावधानीपूर्वक खुलासे की संरचना में निहित होना चाहिए। औचित्य को पूरी तरह से नकारना इसका समाधान नहीं हो सकता। और अगर राजनीतिक दबाव का डर है, तो गोपनीयता शायद ही इसे रोक पाए। आखिरकार, कार्यपालिका कॉलेजियम की असुविधाजनक सिफारिशों में देरी और अड़चन डालती रहती है। वह पुनर्विचार के लिए नाम वापस कर सकती है या, पुनः सिफारिश होने पर, राष्ट्रपति की नियुक्ति का वारंट जारी करने से पहले ही उसे लंबित रख सकती है।

एक न्यायपालिका जो स्वयं को खुलेपन के उन्हीं मानकों के अधीन रखती है जिनकी वह दूसरों से अपेक्षा करती है, उसे लोगों का अधिक विश्वास और भरोसा ही प्राप्त होगा।

यहाँ दांव भारत के लोकतंत्र के मूल पर है। आज चुने गए न्यायाधीश भारत के सबसे ज़रूरी संवैधानिक प्रश्नों के परिणामों को आकार देंगे, जिनमें नागरिक स्वतंत्रता से लेकर कार्यपालिका की शक्ति की सीमाओं और संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन। जब नागरिकों को बिना किसी कारण के केवल यह सूचित किया जाता है कि किसी न्यायाधीश को पदोन्नत किया गया है, या जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की असहमति को गोपनीयता में छिपाया जाता है, तो संस्थागत वैधता समाप्त हो जाती है। हम अपनी अदालतों से राज्य की अन्य शाखाओं से जवाबदेही पर ज़ोर देने की अपेक्षा बिल्कुल उचित रूप से करते हैं। लेकिन ऐसा करके, क्या वे अपने लिए छूट का दावा कर सकते हैं?

न्यायमूर्ति नागरत्ना की असहमति ने न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति को नहीं रोका है। वास्तव में, यह संभव है कि कॉलेजियम के अन्य सदस्यों के पास उनकी नियुक्ति का समर्थन करने के अच्छे कारण रहे हों। वे क्या थे, यह हम कभी नहीं जान पाएँगे। लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा एक नाम से आगे तक फैला हुआ है। यह इस बात से संबंधित है कि क्या न्यायालय उसी सिद्धांत पर चलने के लिए तैयार है जिसे वह राज्य के हर अन्य अंग पर थोपना चाहता है: कि सार्वजनिक शक्ति के प्रत्येक प्रयोग को न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए।

कई लोकतंत्रों में, गैर-निर्वाचित न्यायाधीशों द्वारा कानूनों को रद्द करने की चिंता को बहुसंख्यकवाद-विरोधी कठिनाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर जनता द्वारा चुने गए लोग ही इतने अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? पहली नज़र में, यह चिंता वास्तविक लगती है। लेकिन यह लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। लोकतंत्र केवल संख्याबल के आधार पर बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। सही ढंग से समझा जाए, तो यह इससे कहीं अधिक है: नागरिकों के बीच एक साझेदारी जो अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि स्वतंत्रता और समानता सार्वजनिक जीवन का आधार बनें।

यहां अनिर्वाचित न्यायाधीश कानून की व्याख्या करके तथा बहुसंख्यकवादी ज्यादतियों के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यही कारण है कि संविधान एक अनिर्वाचित न्यायपालिका को असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। न्यायाधीशों का उद्देश्य स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, सरकार पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखना और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। ऐसा करके, वे लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करते, बल्कि उसकी सर्वोच्च आकांक्षाओं को पूरा करते हैं।

कॉलेजियम को सुधार स्वीकार करना होगा। हालाँकि, न्यायपालिका को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वयं जवाबदेही के सबसे कड़े मानकों पर खरा उतरना होगा। कॉलेजियम अक्सर न्याय को छिपाने की संस्कृति में धँस गया है। जब तक यह सुधारों को नहीं अपनाता, तब तक यह उस वैधता को कम करने का जोखिम उठाता है जिस पर इसका अधिकार टिका है। अतीत में बदलाव के कई अवसरों को ठुकरा दिया गया है; हर कदम आगे बढ़ने के बाद दो कदम पीछे हट गए हैं, और हर पीछे हटने से पारदर्शिता और ईमानदारी के वे मूल्य नष्ट होते गए हैं जिन पर लोकतंत्र निर्भर करता है।

एक न्यायपालिका जो खुद को खुलेपन के उन्हीं मानकों के अधीन रखेगी जिनकी वह दूसरों से अपेक्षा करती है, उसकी स्वायत्तता कमज़ोर नहीं होगी। इसके विपरीत, वह अपनी स्वतंत्रता को जनता के विश्वास और भरोसे पर और भी मज़बूती से स्थापित करेगी।

भारत के हालिया समुद्री सुधारों में सुधार की आवश्यकता है

टी 18 अगस्त को राज्यसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 का पारित होना भारत के समुद्री विधायी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 1908 के अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से, यह विधेयक नव-अधिनियमित तटीय नौवहन अधिनियम, 2025, समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2025 और व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 2025 के साथ आता है। यह एक ऐसा विधायी पैकेज है जिसे सरकार समुद्री शासन को सुव्यवस्थित करने और भारत के नौवहन विनियमन को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप लाने के लिए महत्वपूर्ण मानती है।

प्रगति, लेकिन नुकसान के साथ। पहली नज़र में, ये नए कानून भारत के समुद्री शासन को आधुनिक बनाने के एक व्यापक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का समुद्री विनियमन खंडित और पुराना है, आधुनिक नौवहन वित्त, तटीय संचालन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने लंबे समय से मौजूद कानूनी और परिचालन ढाँचों को पीछे छोड़ दिया है।

भारत के लिए अपने व्यापार का विस्तार करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपनी समुद्री स्थिति को मज़बूत करने के लिए, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना वास्तव में आवश्यक है। विशेष रूप से, भारतीय बंदरगाह अधिनियम को एक सुविधाजनक कानून के रूप में सराहा गया है - जो व्यापार को आसान बनाता है, सतत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देता है, और भारत के अन्यथा असंबद्ध नियामक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है।

फिर भी, विधेयक को बिना किसी गंभीर संसदीय बहस या स्थायी समिति को भेजे पारित किया जाना, प्रश्न उठाता है, तथा राजनीतिक आम सहमति और सार्वजनिक जांच के अभाव को रेखांकित करता है।

उल्लेखनीय रूप से, बंदरगाह अधिनियम, 2025 की राज्यों की कीमत पर शक्तियों का केंद्रीकरण करने और भारतीय संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को कमजोर करने के लिए आलोचना की गई है। आलोचक इसकी मुख्य विशेषता, समुद्री राज्य विकास परिषद (केंद्रीय बंदरगाह मंत्री की अध्यक्षता में) को एक केंद्रीकृत नीति-निर्माण प्राधिकरण के रूप में देखते हैं, जिसके पास राज्यों को केंद्रीय दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देने की शक्ति है। उनका तर्क है कि सहकारी संघवाद के उदाहरण से कोसों दूर, नया बंदरगाह अधिनियम संघीय अधीनता का एक उदाहरण है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राज्य अपनी प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना अपने बंदरगाह विकास को सागरमाला और पीएम गति शक्ति जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ संरेखित करें।

आलोचक समुद्री राज्य विकास की ओर इशारा करते हैं

Abhijit Singh
एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी और पूर्व समुद्री प्रमुख
नीतिगत पहल
पर्यवेक्षक अनुसंधान
नींव,
नई दिल्ली

भारत को अपने समुद्री कानून का आधुनिकीकरण करना चाहिए, लेकिन सुधार संघीय संतुलन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

परिषद की संरचना और मंशा, जहां राज्य समुद्री बोर्ड केंद्रीय अनुमोदन के बिना अपने स्वयं के ढांचे को समायोजित नहीं कर सकते हैं, तटीय राज्यों की स्वायत्तता और लचीलेपन को छीन रहे हैं, जबकि उन पर बंदरगाह प्रबंधन की कड़ी जिम्मेदारियों का बोझ है।

यह आलोचना संघीय चिंताओं से प्रेरित नहीं है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि नया कानून अस्पष्ट, विवेकाधीन नियामक शक्तियों का प्रावधान करता है जो छोटे ऑपरेटरों पर असहनीय अनुपालन बोझ डाल सकता है। विवाद समाधान का तरीका भी उतना ही चिंताजनक है: विधेयक का खंड 17 दीवानी अदालतों को बंदरगाह संबंधी विवादों की सुनवाई करने से रोकता है, जिससे पक्षों को उन्हीं अधिकारियों द्वारा गठित आंतरिक विवाद समाधान समितियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिनके विरुद्ध वे विवाद कर रहे हैं। विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा का अभाव निजी निवेश को हतोत्साहित कर सकता है और नियामक प्रणाली में विश्वास को कम कर सकता है।

स्वामित्व का मुद्दा: मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 भी AWS से मुक्त नहीं है। यह पंजीकरण, स्वामित्व नियमों, सुरक्षा मानकों, पर्यावरणीय दायित्वों और देयता ढाँचों को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है, जिसके कुछ उल्लेखनीय लाभ भी हैं: तटीय ड्रिलिंग इकाइयों और गैर-विस्थापन शिल्पों को कवर करने के लिए पोत परिभाषाओं का विस्तार करना; समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी को कड़ा करना; और भारत के देयता और बीमा नियमों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप बनाना। फिर भी, नए प्रिंट में स्वामित्व सुरक्षा उपायों में एक खामी छिपी हुई है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत, भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों का पूर्ण स्वामित्व भारतीयों के पास होना आवश्यक था। नया अधिनियम प्रवासी भारतीय नागरिकों और विदेशी संस्थाओं सहित "आंशिक रूप से" भारतीय स्वामित्व की अनुमति देता है, जबकि वास्तविक सीमा बाद में सरकारी अधिसूचना द्वारा तय की जाएगी।

कानून ने औपचारिक रूप से बेअरबोट को भी मान्यता दी है चार्टर-कम-डेमिस (बीबीसीडी) पंजीकरण, जिसका उद्देश्य भारतीय संचालकों को अंततः स्वामित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशी जहाजों को पट्टे पर देने की अनुमति देना है। वैश्विक वित्तपोषण उपकरण के रूप में वैध होने के बावजूद, बीबीसीडी भारत की नियामक क्षमता का परीक्षण कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हस्तांतरण वास्तव में हो। स्पष्ट, प्रवर्तनीय नियमों के बिना, विदेशी पट्टादाता अनिश्चित काल तक प्रभावी नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा, अधिनियम

यह विधेयक सभी जहाजों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, चाहे उनका आकार या प्रणोदन कुछ भी हो, और छोटे संचालकों पर पड़ने वाले नौकरशाही बोझ की परवाह किए बिना। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह कार्यपालिका को स्वामित्व संबंधी आवश्यकताओं को अपनी सुविधानुसार कम करने का एक खाली चेक थमा देता है, जिससे भारत के सुविधानुसार अधिकार क्षेत्र में जाने का जोखिम बढ़ जाता है, जहाँ विदेशी मालिक भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को नियंत्रित करते हैं।

छोटे खिलाड़ियों को खतरे में डालना भारत के समुद्री सुधार पैकेज का अंतिम घटक, तटीय नौवहन अधिनियम, जाहिरा तौर पर कैबोटेज नियमों को स्पष्ट और मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल भारतीय-लक्षित जहाज ही घरेलू तटीय व्यापार में शामिल हों। हालांकि अच्छी मंशा से, यह शिपिंग महानिदेशक को "राष्ट्रीय सुरक्षा" या "रणनीतिक योजनाओं के साथ संरेखण" जैसे अस्पष्ट आधारों पर विदेशी जहाजों को लाइसेंस देने का व्यापक विवेकाधिकार देता है - खुले अंत वाले खंड जो मनमाने या चयनात्मक आवेदन को आमंत्रित करते हैं। वास्तविक बोझ छोटे ऑपरेटरों पर पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से शिपिंग उद्योग में, जो इस तरह के डेटा का उपयोग या सुरक्षा कैसे की जाएगी, इस बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन के अभाव में अनिवार्य यात्रा और कार्गो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने के लिए संघर्ष करेंगे।

विपक्षी सांसदों ने चेतावनी दी है कि यह अधिनियम केंद्र को बहुत अधिक नियंत्रण सौंपता है, जिससे स्थानीय स्वायत्तता को नुकसान पहुंच सकता है - यह चिंता केंद्र द्वारा अधिदेशित राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना पर भी समान रूप से लागू होती है।

इनमें से किसी का भी यह मतलब नहीं है कि एक अद्यतन कानूनी ढाँचे की ज़रूरत को नकारा जाए। भारत को निश्चित रूप से अपने समुद्री कानून का आधुनिकीकरण करना चाहिए। लेकिन सुधार संघीय संतुलन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कीमत पर नहीं होने चाहिए। स्वामित्व की सीमा और लाइसेंसिंग नियमों को कानून में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, न कि कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में, बहुत से प्रावधान मनमाने हैं—न्यायिक स्वतंत्रता से रहित विवाद समाधान से लेकर योजना बनाने में राज्यों की किसी भी सार्थक भूमिका से राज्यों को बाहर रखने तक। ये उपाय एक शुरुआत हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण संशोधनों के बिना, ये कुछ लोगों के लिए व्यापार करने में आसानी प्रदान करने का जोखिम उठाते हैं, जबकि संघीय समझौते को कमजोर करते हैं और भारत की दीर्घकालिक समुद्री सुरक्षा को कमजोर करते हैं।

द टटर्सटूदएडिटर

'भावनाएँ' और राजनीति: अब समय आ गया है कि राजनेता अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करें। "भावना कार्ड" का इस्तेमाल अब आम आदमी के असली मुद्दों, जिनमें गरीबी भी शामिल है, से ध्यान भटकाने के लिए एक "मास्टरस्ट्रोक" के तौर पर किया जा रहा है।

बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति, आय असमानता और भ्रष्टाचार। चुनाव से पहले जनमत को प्रभावित करने के लिए अप्रासंगिक मुद्दे उठाना एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, "आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, और बाकी सभी को।"

कुछ समय के लिए लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते।" ऐसे मुद्दों पर मतदाताओं को बुद्धिमता से मार्गदर्शन मिलना चाहिए।

Dr. Biju C. Mathew,
Thiruvananthapuram

रेल यात्रियों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है सैकड़ों यात्री

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले के अंकोला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को प्लेटफ़ॉर्म 1 से उतरकर और कई पटरियाँ पार करके अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है।

चिंताजनक बात यह है कि रेलवे अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है।

यह एक ख़तरनाक प्रक्रिया है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि एक अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ सकती है।

30 अगस्त को, वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों सहित यात्रियों को नीचे उतरने के लिए एक अस्थायी सीढ़ी का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था।

प्लेटफार्म 1 से अपनी ट्रेन तक पहुंचने के लिए सक्रिय पटरियों को पार करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें एक अस्तित्वहीन "प्लेटफार्म 2" पर भेज दिया जाता है।

Gurudatt Badageri,
Ankola, Karnataka

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता और पूरा नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

अमेरिका की बेचैनी

आखिर, वही हुआ जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा ने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। इसका संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के बयानों से मिला है। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की बढ़ती करीबी पर चिंता जताते हुए नवारो ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस की बजाय अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ खड़ा होने की अनचाही सलाह दे डाली। उनकी यह स्वतः स्फूर्त सलाह ट्रंप के ऊलजलूल टैरिफ से बिगड़े हालात को संभालने की बौड़म सी कोशिश लगती है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर मोदी, शी और पुतिन के बीच घनिष्ठता के प्रदर्शन को नवारो ने 'व्हाइट हाउस' की प्रेस ब्रीफिंग में चिंताजनक बताया। नवारो यहीं नहीं रुके और बोल पड़े कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी का दो सबसे बड़े तानाशाहों, पुतिन और शी, के साथ देखा जाना शर्म की बात है। यह साफ-साफ अमेरिका की खीझ को दिखाता है। नवारो के बयान ऐसे समय सामने आए हैं, जब भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले दो दशकों के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। व्यापार एवं शुल्क (टैरिफ) पर ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका-भारत के बीच रिश्तों में गिरावट आने के बाद से ही नवारो कुछ दिनों से लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। नवारो ने कहा, मुझे समझ नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या है, चीन के साथ तो भारत कई दशकों से तनाव और संघर्ष की स्थिति में रहा है। भारत को रूसी तेल खरीद बंद करके अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के साथ होना चाहिए। समझ नहीं आता कि नवारो भारत को बिन मांगे सलाह क्यों दे रहे हैं। वह भी तब जब ट्रंप की दादागीरी रुकने के कोई संकेत नहीं हैं। भारत पर अमेरिका का कुल शुल्क 50 फीसद हो चुका है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच भारत को सस्ता रूसी तेल खरीदने से कैसे रोका जा सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही जब से पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाए हैं, तब से रूस भारत का शीर्ष ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। नवारो ने चीन की पाकिस्तान से बढ़ी नजदीकियों पर भी भारत को चेताया लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप ने भारत को क्यों निशाना बनाया हुआ है? संप्रभु राष्ट्र होने के नाते यह भारत को ही तय करना है कि वह किससे संबंध रखेगा या किससे नहीं। रूस भारत का सबसे पुराना मित्र और सहयोगी है। चीन भी इस गठजोड़ में आ जाए तो क्या कहने!

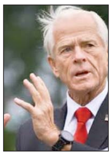

पारित विधेयक पर रुख

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह विधेयकों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजे जाने (प्रेसिडेंट रेफरेंस) पर विचार करते समय केवल संविधान की व्याख्या करेगा कि क्या अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि इस संदर्भ का विरोध करने वाले पक्षों की ओर से अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी अन्य के अलावा आंध्र प्रदेश से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के उदाहरणों का हवाला देंगे तो उन्हें जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने उन पहलुओं पर दलील नहीं दी है। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस एएस चंदुरकर भी शामिल थे। दरअसल, विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, जिनकी मंजूरी के बाद ही संबंधित विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार कर सकता है। कई दफा होता यह है कि विधानसभा में पारित विधेयक को राज्यपाल के यहां से मंजूरी मिलने में दिक्कत दरपेश होती है, खासकर जब तब राज्य और केंद्र में अलग-अलग पार्टियों की सरकार हो। ज्यादातर पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस संबंधित विधानसभा को भेज दिया जाता है, या फिर काफी समय तक उन्हें राज्यपाल के कार्यालय में लंबित पड़े रहना पड़ता है। एक तरह से चुनी हुई सरकार के संवैधानिक कार्यकलाप इस तरीके से बाधित किए जाते हैं। ऐसा किया जाना लोकतांत्रिक तकाजों के मददेनजर अनुचित है। और ऐसा कोई हाल-फिलहाल की बात नहीं है, बल्कि संविधान के साथ उसकी स्थापना के समय से ही यह खिलवाड़ होता रहा है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों के भविष्य पर फैसला करने के लिए 'यथाशीघ्र' शब्द का उल्लेख किया गया है लेकिन इससे कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। बहरहाल, अदालत ने स्पष्ट कहा है कि पारित विधेयकों को लेकर राज्यपाल या राष्ट्रपति की कार्रवाई के खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कह कर शीर्ष अदालत में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।

कटाक्ष/ सहीराम

प्रथम कौन?

प्रथम रहने का जुनून ऐसा ही होता है जी। बेचारे बच्चों का बचपन छीन लेता है। इसी जुनून में अनुराग ठाकुर ने बेचारे यूरी गागरिन से उनका प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का तमगा छीन लिया और हनुमान जी को दे दिया। अरे भैया मान लिया कि दुनिया को सबसे पहले जीरो आप ही ने दिया। इस तमगे को आपसे कोई नहीं छीन रहा। लेकिन हर मामले में पहला स्थान क्यों चाहिए। यह बात माता-पिता को भी समझ में नहीं आती। इसी चक्कर में बेचारे बच्चों को मानसिक ब्याधियों से गुजरना पड़ता है। अब माता-पिताओं और अभिभावकों की तरह सरकार भी यही करने लगी है। कोई कहता है कि विमान सबसे पहले राइट बंधुओं ने बनाया। हमने बनाया। पुष्पक विमान नहीं सुना क्या? त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देब ने तो इंटरनेट के मामले में हमें प्रथम साबित कर दिया था। भाजपा के सत्ता में आने का यही फायदा हुआ है जी कि अब हम हर चीज में प्रथम पाए जाते हैं। वेद-पुराणों ने इसमें और मदद कर दी। इसीलिए इतिहास को ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा। वह हर चीज में हमें प्रथम साबित नहीं करता न। सो, किस काम का। अनुराग ठाकुर जी के शब्दों में गोली मारो...

खैर, अनुराग जी ने घोषणा कर दी कि हनुमान जी ही प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। इसके बाद से सारा ब्रह्मांड थर्राया हुआ है। गैलेक्सियों में खलबली मची हुई है कि भैया हनुमान जी तो अपने सौर मंडल के सूर्य को ही निगल गए थे। ऐसे में पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगे। उधर, इंद्र का इंद्रासन डोल गया। इंद्रासन डोलता है तो इंद्र जी इंद्रासन के लिए खतरा बनने वाले परम तपस्वियों का तप भंग करने के लिए अपने यहां की परम सुंदरियों की सेवाएं लेते हैं, वैसे ही जैसे इधर सरकार विपक्ष को सेट करने के लिए ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों की सेवाएं लेती है। इधर तो सुना है चुनाव आयोग की सेवाएं भी लेने लगी है। सरकार के पास तो ये विकल्प थे, लेकिन इंद्र महाराज के पास सुंदरियों के अलावा क्या विकल्प है बताइए! लेकिन हनुमान जी ठहरे विकट ब्रह्मचारी। देखिए, खलबली तो स्वर्ग में भी मची है। देवी-देवताओं को शिकायत है कि भाई हर शुभ अवसर पर आकाश से फूल तो हम बरसाएं, बल्कि उन्होंने तो यह दावा भी किया कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर भी हमने फूल बरसाए थे। पर देखो प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का श्रेय हनुमान जी को दिया जा रहा है। अरे यार हम यहां घर बसाए बैठे हैं। कुछ तो ख्याल करो। कहीं यहां भी तो एसआईआर नहीं लागू कर रहे हो। भाई, बख्श दो!

नकली बादल सच नहीं जानते

सामयिक

पंकज चतुर्वेदी

जयपुर से कोई 32 किमी. दूर जमवारामगढ़ की झील कभी पूरे जयपुर शहर की प्यास बुझाती थी। कोई 15.5 वर्ग किमी. में फैली झील पर 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने बांध बनवाया ताकि जयपुर शहर की प्यास बुझ सके। आजादी के बाद एक तरफ जयपुर का दायरा बड़ा और दुर्भाग्य कि रामगढ़ का दायरा घटता गया। 1982 के एशियाई खेलों के दौरान रामगढ़ झील पर नौकायन स्पर्धाएं आयोजित की गई थीं। फिर नदी पर कब्जे बढ़े, नहर लुप्त होती गई और 1999 की बाद तो इससे पानी ही रूठ गया।

अब राजस्थान सरकार ने नकली बादल से झील भरने के लिए देश-विदेश की कंपनियां बुला लीं। दो बार प्रयास हुए लेकिन ड्रोन बगैर एक बूंद बरसाए नीचे गिर गया। दुर्भाग्य है कि बांध भरने के नैसर्गिक तरीके न अपना कर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। असल में यह झील बाणगंगा नदी पर बांध बना कर तैयार की गई थी। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही राजस्थान की कई नदियां, जिनमें बाणगंगा नदी प्रमुख है, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई हैं। बाणगंगा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है, और इसका यमुना की जलधारा में विलय हो जाता है। बाणगंगा नदी का उम बैराठ की पहाड़ियों से होता है। इस नदी के किनारे बैराठ सभ्यता भी विकसित हुई थी। 380 किमी. का लंबा सफर तय करते हुए यह नदी जयपुर दौसा भरतपुर और अंततः उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद आगरा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है।

जिम्मेदार लोगों ने कभी यह विचार किया ही नहीं कि तीन दशक पहले तक बरसात के दिनों में तबाही मचाने वाली नदी का पानी गया कहां? नकली बादल से बरसात कर झील भरने वालों ने अपने ही कागज पलट कर नहीं देखे कि किसानों के लिए कामधेनु कहलाने वाली बाणगंगा नदी में 1996-97 तक पानी की इतनी आवक रहती थी कि मैड गांव में बाणगंगा तट पर हर साल मेला भरता था, जिसमें हजारों लोग गंगा समान पवित्र जल आचमन कर धन्य होते थे। हजारों साल से बह रही नदी के सूखने का कोई शोक नहीं और विदेश से एक कंपनी बुला ली कि ड्रोन उड़ा कर बारिश कर दो जिससे बांध भर जाए। बाणगंगा पर दौसा जिले में माधो सागर बांध परियोजना है। इसी नदी की तरावट से भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण हुआ। इसके बाद इसका विलय यमुना में हो जाता है। चंबल नदी के बाद राजस्थान की बाणगंगा दूसरी नदी है, जिसका जल सीधा यमुना नदी में मिलता है। चूंकि इसका यमुना में मिलन स्थल बहुत कटा-फटा है, इसलिए इसे लोक में रुंडित नदी भी कहते हैं। काश! कोई यह सोचता कि जब यह नदी जयपुर

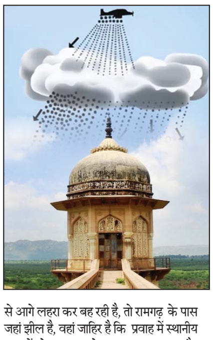

से आगे लहरा कर बह रही है, तो रामगढ़ के पास जहां झील है, वहां जाहिर है कि प्रवाह में स्थानीय कारणों से व्यवधान के कारण सूखा पड़ा है। रामगढ़ बांध में बाणगंगा (विराटनगर से), माधोबेणी नदी (मनोहरपुर से), गौमती का नाला सहित अन्य नदियों से पानी आता था। समझना होगा कि विराटनगर के दोलाज गांव के समीप बाणगंगा नदी का उद्गम है और यह नदी रामगढ़ बांध में पानी आवक की मुख्य नदी है।

हुआ यूं कि नदी और बांध के रास्ते में पहले सरकार और फिर आम लोगों ने जम कर कई एनीकट, चेकडेम बना लिए, इससे जल-धारा सिकुड़ने लगी। जैसे ही यह भाव क्षेत्र सूखा तो सैकड़ों एकड़ में लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। यह बात सभी सरकारी महकमे जानते हैं कि बाणगंगा से झील तक के मार्ग पर बेशुमार अतिक्रमण के चलते यह संकट खड़ा हुआ, लेकिन कब्जाधारियों के रसूखदार होने के चलते कागजों पर झूठी रिपोर्ट दर्ज की जाती रहीं। विराटनगर के दोलाज और ज्ञानपुरा गांव के पास अतिक्रमणकारियों ने नदी के मुख्य बहाव क्षेत्र को ही बदल दिया। दोलाज की पहाड़ियों से ज्ञानपुरा होते हुए कपासन माता के मंदिर तक 6 किमी. की दूरी में करीब साढ़े चार किमी. तक नदी का बहाव क्षेत्र गायब है। ठीक ऐसे ही कब्जे माधोबेणी और गौमती नाले से बांध की आवक के रास्ते में हैं। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने नदी और नालों के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य करने को लेकर भले ही रोक लगा रखी है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते नदी और नालों के बहाव क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन कार्य जोरों पर है। यह बात एक आम इंसान भी जानता है कि जब तक किसी नदी-तालाब से मानसून या ग्लेशियर से निकली सरिताओं के पानी का लेन-देन नियमित न हो, उसे जिंदा नहीं किया जा सकता और बड़े बड़े इंजीनियर नदी की धारा में व्यवधान के बनिस्बत एक संदिग्ध और लगभग असफल तकनीक से बांध में बहाव लाने लगे।

जमवारामगढ़ बांध में देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग अभियान सबसे पहले 31 जुलाई 25 को तय किया गया लेकिन उन दिनों राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ थी और बरसात उम्मीद से 130 फीसद ज्यादा हो चुकी थी, सो उसे रोक दिया गया। फिर 12 अगस्त को पूजा-पाठ, महिलाओं के लोक गीत, मंत्री से ले कर विधायक की उपस्थिति में हजारों लोग एकत्र हो गए। राज्य के कृषि विभाग ने इसका ठेका अमेरिका और बेंगलूरु की टेक्नोलॉजी कंपनी जेन एक्स एआई को दिया और उस दिन सुबह दस बजे से दो बजे के बीच दो बार असफल कोशिश के बाद ड्रोन हवा में उड़ा और नीचे गिर गिया। इस तमाशे को देखने को इतनी भीड़ थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सत्रह अगस्त को फिर भीड़ जमा हुई, ड्रोन उड़ा और गोपालगंज गांव के पास खेत में औंधे मुंह गिर गया। अब विदेशी कंपनी कह रही है कि नकली बरसात से बांध को भरने के लिए ड्रोन को दस हजार फुट ऊपर उड़ाना होगा जबकि भारत सरकार ने 400 फुट से अधिक की अनुमति दी नहीं।

शायद यह बात तो कंपनी पहले से जानती होगी कि ड्रोन को कितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। भले विदेशी कंपनी को यह न पता हो लेकिन राजस्थान सरकार की फाइलें तो जानती थी कि दो साल पहले चित्तौड़गढ़ के भैसुंदा बांध पर 10 करोड़ रुपये खर्च कर ऐसे ही कृत्रिम बारिश का प्रयास असफल हो चुका था और तब बहाना बनाया गया कि नमी की कमी थी। हमें समझना होगा कि कोई भी दिखावटी उपाय इंसान द्वारा पैदा किए गए पर्यावरणीय संकट का निदान नहीं हैं। रामगढ़ बांध को पानीदार बनाने वाली तीनों जलधाराओं को बांध तक अविरल आने दो, रास्ते के अतिक्रमण हटा दो, फिर से वहां लोक-मंगल मेला लगने लगेगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

जमवारामगढ़ की झील कभी पूरे जयपुर की प्यास बुझाती थी। 15.5 वर्ग किमी. में फैली झील पर 1876 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने बांध बनवाया था ताकि शहर की प्यास बुझ सके। आजादी के बाद जयपुर का दायरा बड़ा और दुर्भाग्य कि रामगढ़ का दायरा घटता गया। नदी पर कब्जे बढ़े, नहर लुप्त होती गई और 1999 के बाद तो इससे पानी ही रूठ गया। अब राज्य सरकार ने नकली बादल से झील भरने के लिए देश-विदेश की कंपनियां बुला ली हैं

- 'सौंफ' स्वाद और खुश्बू के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी वरदान से कम नहीं है। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले यौगिक जैसे फेनोलिक एसिड्स और फ्लावोनोइड्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं
- रिसर्च में पाया गया है कि सौंफ भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। जब हम इसे चबाते हैं, तो मुंह में लार अधिक बनती है, जिससे पेट भरा-भरा लगता है, और फालतू खाने की इच्छा कम होती है। इस वजह से यह वजन घटाने में भी सहायक हो सकती है बशर्ते इसका सेवन सही मात्रा में किया जाए

(मीडिया इनपुट्स)

एससीओ की बैठक ने यह भी रेखांकित करने का काम किया है कि अंग्रेजी के बिना भी वैश्विक मंच पर संवाद हो सकता है।

अखिलेश शर्मा, पत्रकार
@akhileshsharma1

गंगा-यमुना को न समझने की भूल

प्रकृति का रौद्र रूप

सुरेश भाई

गंगा की मुख्य धारा भागीरथी को धरती पर उतारने के लिए राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या की थी लेकिन पिछले 4 दशकों से गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। 'इसरो' और 'वाड़िया भूगर्भ विज्ञान संस्थान' के वैज्ञानिक भागीरथी की संवेदनशीलता के विषय पर अध्ययन इंसान को सचेत रहने के लिए पर्याप्त हैं। भागीरथी के उद्गम गौमुख ग्लेशियर में बर्फ लगभग 30 किमी. पीछे हट गई है। ग्लेशियर के स्थान पर मलबे के ढेर दिखाई देते हैं क्योंकि इसके आसपास भी भूस्खलन का मलबा टूट कर बिखर रहा है। यही स्थिति गंगा-जमुना के उद्गम से आगे 100 किमी. के आर-पार के सहायक गाड़-गदेरे की है, जो अधिकांश ग्लेशियर से आ रहे हैं।

यहां की धरती में लगातार आ रहे भूकंप से भी कंपन हो रहा है। परिणामस्वरूप ग्लेशियर, झीलें, पहाड़ दरक रहे हैं। इसी बात को लेकर 2009 में उत्तरकाशी में हुए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन के बाद 1000 मेगावॉट की सुरंग आधारित लोहारीनाग-पाला और पाला-मनेरी जल विद्युत परियोजनाएं तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा रद्द की गई थीं। भागीरथी के उद्गम से 120 किमी. दायरे में पर्यावरण अनुकूल विकास और सुधार के लिए 2012 में 'इको सेंसेटिव जोन' घोषित किया गया जिसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। लेकिन चिंता तब और भी बढ़ जाती है जब गंगोत्री के पास हरसिल और धराली में 24 घंटे में भारी बारिश की भविष्यवाणी के संबंध में सैटेलाइट के माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने पहले ही जानकारी दे दी थी। इसके बावजूद प्रभावित गांव तक सूचना नहीं पहुंच सकी।

वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 5 अगस्त को भागीरथी की सहायक खीरगंगा में भीषण बाढ़ आने से धराली गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से यहां बड़े-बड़े होटल बन गए हैं। लेकिन बढ़ती आबादी और बेतरतीब निर्माण कार्यों से उत्पन्न असुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 11 हजार फुट की ऊंचाई पर श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर से आ रही खीरगंगा के मुहाने पर ही बहुमंजली इमारतें खड़ी हो गईं जबकि भागीरथी के आर-पार

के गाड़-गदेरों से लगातार भूस्खलन की घटनाएं होती रही हैं। खीरगंगा के अलावा तिल गाड़, सुखी के सामने भेला गाड़ में भी भारी जल प्रलय हुआ है। यहां पहले से इस तरह की आपदाओं का सिलसिला बना हुआ है। 1978, 2010-11-12-13, 2017-18 और 2023-24 में भी यहां भीषण बाढ़ आ चुकी है।

हरसिल और धराली के बीच में भागीरथी पर जमा हुए भारी मलबे के कारण झील बनने से हेलीपैड भी मलबे में डूब गया था। सुरक्षा बलों की मेहनत से झील का पानी आगे बहाव क्षेत्र में निकालने के बाद भी फिर 24 अगस्त की शाम को तिल गाड़ में भारी मलबा बह कर आया है, जिसके बार-बार झील का आकार लेने से हरसिल कस्बे के अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। यह भागीरथी के निचले बहाव क्षेत्र के लिए भी खतरनाक संकेत है।

उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में दर्जनों स्थानों पर डेंजर जोन बन चुके हैं। उत्तरकाशी और कुथनौर तक बनी चौड़ी सड़क के कारण भी पहाड़ नासूर बन गए हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राज मार्ग के मुख्य यात्रा पड़ाव स्याना चट्टी में 22 अगस्त को यमुना का बहाव दूसरी बार रुक कर झील के रूप में सामने आया है। झील बनने से यहां पर 250 आबादी के होटल, घर, पुल, राजमार्ग आदि पानी में डूब गए। दिन में बनी झील से लोगों में हाहाकार मच गया था। लोगों की आजीविका के साधन झील में डूब गए। अलकनंदा की सहायक पिंडर नदी के तट पर बसे थराली गांव में भी भीषण बाढ़ से दर्जनों परिवारों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ के समय भागीरथी, अलकनंदा, यमुना आदि नदियों पर बनाई गई जल विद्युत परियोजनाओं के गेट बार-बार खोलने से तटों पर बसी आबादी प्रभावित होती रहती है। हिमाचल के कुल्लू, मनाली, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, चंबा में भीषण बाढ़ आई है। व्यास नदी रौद्र रूप दिखा रही है। पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पर किश्तवाड़, चिशौती, डोडा आदि स्थानों में तवी और झेलम नदी के कहर से दर्जनों लोग लापता हैं।

तीनों राज्य में 500 से अधिक सड़कें बंद हैं। खूबसूरती और देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्यटन के लिए मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है जहां की नदियों में जल प्रलय थम नहीं रहा। नदियों के किनारों पर बनाई जा रहीं चौड़ी सड़कें कमजोर साबित हो रही हैं। सवाल है कि क्या इसके बाद भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विकास का वही मॉडल रहेगा जो मैदानों में लागू है? इसमें सुधार नहीं करेंगे तो पहाड़ जल्द ही नीचे उतर सकते हैं, और मैदानों में भीषण तबाही रोके नहीं रुकेगी।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

कर्म गति गहन | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

कर्म की गति अत्यंत गहन है। यह विषय केवल दार्शनिक चिंतन का नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण का अनुभव है।

मनुष्य अपने कर्मों से ही बनता है और उन्हीं से उसका भविष्य भी निर्मित होता है। शास्त्रों ने कर्म को बीज के समान माना है। जैसे बीज बोने पर समय आने पर फल अवश्य मिलता है, वैसे ही कर्म का भी प्रतिफल निश्चित है। कर्म का रहस्य इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। कभी-कभी हमें तुरंत फल दिखाई देता है, पर कई बार वर्षों बाद या जन्मों बाद ही परिणाम सामने आते हैं। यही कर्म की गहनता है। गीता कहती है कि कर्म चाहे कितना भी छिपा हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका संस्कार आत्मा पर अंकित हो जाता है, और अवसर आने पर उसका परिणाम सामने आता ही है। महाभारत में युधिष्ठिर का उदाहरण कर्म की गहनता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सत्य और धर्म का पालन करने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वनवास तक झेलना पड़ा। परंतु अंततः उन्हीं के धर्मनिष्ठ कर्मों ने उन्हें हस्तिनापुर का राजा और धर्मराज का पद दिलाया। यह बताता है कि सत्कर्मों का फल देर से ही सही, परंतु मिलता है। कर्म की गति इतनी गहरी है कि कभी-कभी मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि क्यों अच्छे लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं, और क्यों दुष्ट सुख भोगते प्रतीत होते हैं। परंतु यह केवल एक क्षणिक दृश्य है। कर्मों का हिसाब बहुत व्यापक और दीर्घकालिक होता है। पिछले जन्मों के कर्म, वर्तमान जीवन की परिस्थितियां और भविष्य की दिशा-सब इसमें जुड़ी रहती हैं। जैसे कोई खाता वर्षों चल सकता है, और बाद में संतुलन किया जाता है, वैसे ही कर्म का लेखा-जोखा बहुत लंबा चलता है, इसे एक जन्म के आधार पर देखना हमारी सीमितता है क्योंकि यह केवल एक जन्म या घटना तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की अनादि यात्रा से जुड़ी हुई है। इसलिए महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों को सत्कर्म में बदलना चाहिए। भूतकाल के कर्मों पर उसका बस नहीं है, परंतु वर्तमान उसके हाथ में है। सत्य निष्ठा से वह अपने जीवन को सत्कर्मों की दिशा में मोड़ सकता है।

रीडर्स मेल

शिक्षक बने रहना बड़ी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियों के तहत उन शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त हुए हैं एवं 5 साल से अधिक उनकी सेवा बची है। फैसले का मजमून बताता है कि अदालत इस बात से वाकिफ थी कि ऐसे कुछ शिक्षकों की पठन-पाठन में रुचि नहीं रह गई है। फैसले ने समाज खासकर शैक्षिक जगत में हलचल मचा दी है। इस फैसले से सरकार को शिक्षकों को नौकरी से बाहर निकालने का बहाना मिल जाएगा जबकि स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है। दिलचस्प है, ऐसे लोग यह ध्यान नहीं देते कि उन शिक्षकों का आखिर, क्या काम? बहरहाल, फैसले का समय माकूल है क्योंकि देश 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मना रहा है। शिक्षा जगत की कई बड़ी चुनौतियों में से यह भी एक बड़ी चुनौती है कि शिक्षक वास्तव में शिक्षक कैसे बने रहें?

मुकेश कुमार मनन, ई मेल से

नवारो का घटिया बयान

कहावत 'खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे' अमेरिका पर सही बैठती है। पहलगाम घटना के बाद से अमेरिका और भारत के कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन का श्रेय और भारत द्वारा रूस से तेल क्रय नहीं रोकने से क्षुब्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत को यदि आर्थिक मोर्चे पर परेशान किया जाए तो वह विवश होकर अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा। इसके लिए उसने भारत पर 50% की टैरिफ भी लगा कर देख लिया किंतु उसका भी जब भारत पर प्रभाव होते नहीं दिखा तो ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो अनर्गल प्रलाप पर उतर आए। चीन में एससीओ सम्मेलन के दूसरे दिन नवारो ने एक बहुत ही घटिया बयान दे डाला कि रूसी तेल खरीद से भारत के ब्राह्मण मालामाल हो रहे हैं, जबकि तेल खरीद और बिक्री से भारत के किसी ब्राह्मण का कोई लेना-देना नहीं। भारत को इसका उचित मंच पर उचित उत्तर देना चहिए।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

अमेरिका में वैज्ञानिकों पर 'हंटर'

तानाशाहों एवं धर्मांधता के शिकार लोगों एवं नेताओं को विज्ञान से दिक्कत होती है क्योंकि विज्ञान तर्क पर आधारित होता है, जो उनकी सत्ता को चुनौती देता है, और उनकी विचारधारा को कमजोर करता है। विज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास और धार्मिक कथाओं पर आधारित सत्ताएं कमजोर होती हैं, और लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने का प्रोत्साहन मिलता है, जो तानाशाही शासनों और धार्मिक संगठनों के लिए खतरा है। विज्ञान स्वतंत्र सोच और प्रश्न पूछने को बढ़ावा देता है, जबकि तानाशाह अपनी प्रजा को अंधभक्ति और सरकार पर आंख बंद करके विश्वास करने को मजबूर करते हैं। विज्ञान में आलोचना-सत्यापन एक हिस्सा है, जबकि तानाशाह आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। सूचना पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। ट्रंप भी वही कर रहे हैं, वैज्ञानिकों के बजट में कटौती शुरू कर दी है जिसके चलते हजारों वैज्ञानिक यूरोप तथा अन्य देशों में पलायन कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट केनेडी जूनियर टीकाकरण एवं टीकों पर विश्वास नहीं करते।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 21
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

राजनीति में लोकलज्जा

राजनीति में गाली-गलौच के लिए कोई स्थान नहीं होता क्योंकि इसकी मार्फत लोकतन्त्र में आम जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। यह लड़ाई पूर्णत: वैचारिक आधार पर होती है अत: जब भी राजनीति में भाषा का स्तर गाली पर उतर आता है तो उसे वैचारिक खोखलेपन का सबूत माना जाता है। वैचारिक खोखलापन राजनीति में तब भी माना जाता है जब नीतिगत सिद्धान्तों के स्थान पर व्यक्तिगत आलोचना होने लगती है। प्रख्यात समाजवादी चिन्तक डॉ. राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में जब वैचारिक स्तर पर खोखलापन शुरू होता है तो व्यक्तिगत आलोचना शुरू होती है और यह चरित्र हत्या तक पहुंच जाती है। मगर भारत में पिछले दो दशक से राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है जिसके लिए सत्ता व विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को मां की गाली दी गई, उसकी हर हाल में हर पक्ष द्वारा निन्दा की जानी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि यह गाली एक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा दी गई, बल्कि असल सवाल यह है कि यह गाली कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल के मंच से दी गई। यह भी सवाल नहीं है कि उस समय मंच पर कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी व राजद नेता श्री तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे और उनकी सभा समाप्त हो चुकी थी, बल्कि सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमन्त्री को गाली दी उसने इन दोनों नेताओं के मंच का ही प्रयोग किया। अत: बहुत स्वाभाविक सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी सभा के आयोजनकर्ता को लेनी चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि बिहार के दरभंगा शहर में जहां यह घटना घटी वहां के सभा आयोजक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने घटना के लिए माफी मांग ली है जिसके बाद विवाद समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर घटना के लिए यदि कांग्रेस व राजद का शीर्ष नेतृत्व भी दुख प्रकट कर देता है तो उससे उसका कद छोटा नहीं हो जायेगा। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है और इसकी विरासत बहुत विशाल व गरिमामयी है। महात्मा गांधी ने 1920 में अपना असहयोग आन्दोलन इसीलिए वापस ले लिया था कि चौरी-चौरा में हिंसक घटना हो गई थी और आन्दोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। अपने आन्दोलन में हिंसा को होते देख राष्ट्रपिता ने आन्दोलन की वापसी की घोषणा कर दी थी। अत: कांग्रेस पार्टी को दरभंगा के मामले पर गंभीरता और गहराई से विचार करने के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी और राजद की यात्रा आम जनता के हकों के लिए ही हो रही थी इसलिए इन दोनों पार्टियों को आम जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए था। इस यात्रा के दौरान गाली जैसी विसंगति के पैदा होने के बाद इस मुद्दे की गंभीरता पर विचार करना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि उनका मुकाबला उस भाजपा पार्टी है से है जो ऐसे मुद्दों को अपने पक्ष में भुनाने की माहिर मानी जाती है।

> **हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी को मां की गाली दी गई, उसकी हर हाल में हर पक्ष द्वारा निन्दा की जानी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि यह गाली एक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा दी गई, बल्कि असल सवाल यह है कि यह गाली कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल के मंच से दी गई। यह भी सवाल नहीं है कि उस समय मंच पर कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी व राजद नेता श्री तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे और उनकी सभा समाप्त हो चुकी थी, बल्कि सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमन्त्री को गाली दी उसने इन दोनों नेताओं के मंच का ही प्रयोग किया। अत: बहुत स्वाभाविक सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी सभा के आयोजनकर्ता को लेनी चाहिए।**

विचारणीय पक्ष यह है कि स्वतन्त्र भारत में भाजपा की राजनीति पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की खामियों पर ही टिकी हुई है। इसके वैचारिक पक्ष का प्रमुख हिस्सा कांग्रेस की आलोचना ही रहा है अत: विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस को हर कदम फूंक- फूंक कर रखना होगा और देश की जनता को दिखाना होगा कि उसकी राजनीति केवल भाजपा की आलोचना पर टिकी हुई नहीं है बल्कि वह अपनी मौलिक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। राजनीति में व्यंग्य-विनोद के लिए तो पर्याप्त स्थान है मगर गाली जैसी कलुषता के लिए लेशमात्र भी जगह नहीं है। भाजपा को जनता के बीच स्थापित करने में इसके स्वर्गीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का विशिष्ट स्थान माना जाता है। 1969 में जब स्व. वाजपेयी भारतीय जनसंघ (भाजपा) के नये-नये अध्यक्ष बने थे तो उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना अधर में लटक गई थी। इसकी वजह यह थी कि 1962 में भारत की चीन से लड़ाई हुई और 1965 में पाकिस्तान से। इन दोनों लड़ाइयों के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना अधूरी ही रह गई तो स्व. वाजपेयी ने एक जनसभा में कहा कि 'हम सरकार से पूछते हैं कि पंचवर्षीय योजना का क्या हुआ तो वह कहते हैं कि यह प्रसव में है। हम कहते हैं कि जल्दी निकालों तो वे कहते हैं कि पीड़ा होती है'।

श्री वाजपेयी के इस कथन को तब विपक्ष की ही स्वतन्त्र पार्टी के नेता स्व. पीलू मोदी ने बहुत गंभीरता से लिया था और कहा था कि श्री वाजपेयी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए क्योंकि उन्होंने नारी की प्रसव वेदना का उपहास उड़ाया है। इस पर वाजपेयी ने दुख भी प्रकट कर दिया था। अत: भारतीय राजनीति की यह पंरपरा रही है। ऐसा नहीं है कि दो दशक पहले तक राजनीति पूरी तरह साफ-सुथरी थी। इससे पहले भी सत्ता पक्ष की आलोचना विपक्ष में बैठी पार्टियां जमकर किया करती थीं, खासकर जनसंघ पार्टी तो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी और व्यक्तिगत आलोचना तक पर उतर आती थी मगर उसमें लोकलज्जा का भाव जरूर रहता था। सबसे बड़ी चिन्ता की बात आज यह है कि राजनीति से लोकलज्जा समाप्त होती जा रही है जबकि यह लोकतन्त्र का गहना मानी जाती है। लोकलज्जा को कायम रखना केवल विपक्ष का ही काम नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष की भी यह जिम्मेदारी होती है कि उसका हर काम इसी दायरे में हो। डॉ. लोहिया यह भी कहा करते थे कि लोकतन्त्र केवल लोकलज्जा से ही चल सकता है क्योंकि इसके समाप्त होते ही राजनीतिक द्वेष घृणा का रूप ले लेता है।

डुबो ले गया वो सैलाब

गीता पाढा

"घर, खेत ही नहीं, सपनों की नींव तक को
डुबो ले गया वो सैलाब,
पीछे छोड़ गया चीखें और लोगों का करुण विलाप,,
इस विनाशकारी आपदा ने जान,माल सब कुछ कर दिया बर्बाद,
केंद्र और राज्य सरकारों के राहत कार्यों से ही
दोबारा हो सकता जन सामान्य का जीवन आबाद...।।"

मर्यादाएं

चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

डोनाल्ड ट्रम्प को गुस्सा क्यों आता है?

भारत और अमेरिका के रिश्ते लड़खड़ा रहे हैं। अगर जल्द न रोका गया तो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि मरम्मत की गुंजाइश नहीं रहेगी और जब तक ट्रम्प व्हाइट हाउस छोड़ेंगे तब तक इन रिश्तों का कुछ नहीं बचेगा। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% टैरिफ (कुल 50%) लगा दिया गया है जबकि चीन जो हमसे भी अधिक खरीदता है पर 30% टैरिफ है। कूटनीतिक शालीनता को एक तरफ रख न केवल ट्रम्प बल्कि उनके कई सलाहकार रोज़ाना हमें लताड़ रहे हैं। एक कथित सलाहकार पीटर नावरो का कहना है कि यूक्रेन का युद्ध 'मोदी का युद्ध है' !फिर कहना था कि "रूस से तेल खरीद से भारत में ब्राह्मण मुनाफ़ा कमा रहे हैं"। भारत-अमेरिका विवाद में हमारे ब्राह्मण कहां से टपक गए? न जाने यह बंदा क्या खा-पीकर बात करता है ! खुद ट्रम्प भी बहक रहे हैं। वह भारत को 'डैड इकानिमी' कह चुके हैं जबकि पहली तिमाही में हमने 7.8%ग्रोथ दिखाई है। यह भी उस समय जब हम पर टैरिफ की तलवार लटक रही थी।

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की सफल जापान यात्रा के दौरान जापान ने भारत में निवेश के टार्गेट को दो गुना बढ़ाते हुए 68 अरब डालर कर दिया है। ऐसा करते हुए जापान ने हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास प्रकट कर दिया है लेकिन ट्रम्प खफ़ा है और बहुत खफ़ा हैं,पागलपन की हद तक खफ़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा करते हुए ट्रम्प का यह भी कहना था, "मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। मैंने उनसे कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं। आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ व्यापार या कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा"। क्या यह किसी मानसिक रूप से स्वस्थ राष्ट्राध्यक्ष की भाषा है? क्या किसी रणनीतिक साझेदार देश के प्रधानमंत्री को यह धमकी दी जा सकती है कि 'आपका सिर चकरा जाएगा'?

ट्रम्प को रूसी तेल की चिन्ता नहीं। अलास्का में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का लाल गलीचा बिछा कर स्वागत किया था। हमारे साथ समस्या और है। हमने उनकी ईगो की मालिश करने से इंकार कर दिया। सारा यूरोप, जापान, कोरिया सब उनके आगे झुक गया। केवल भारत और ब्राज़ील अड़ गए। भारत ने उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का श्रेय देने से इंकार कर दिया जिससे ट्रम्प चिढ़ गए। अमेरिका में हमारी पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने अमेरिका के साथ बिगड़े रिश्ते को ट्रम्प की 'निजी चिढ़' बताया है। यही शब्द अमरीकी फाइनेंशल सर्विस कम्पनी जैफरीज ने भी कहे हैं। उनके अनुसार ट्रम्प की चिढ़ का कारण है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ झगड़े में उन्हें मध्यस्थता नहीं करने दी। न्यूयार्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, "राष्ट्रपति ट्रम्प ने बार-बार दावा किया कि उन्होंने युद्ध 'हल' कर दिया...जून 17 को नरेन्द्र मोदी के साथ टेलीफोन वार्ता में ट्रम्प ने यह बात फिर उठाई कि उन्हें कितना गर्व है कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया...उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल सम्मान के लिए मनोनीत करने जा रहा है... उनके कहने का एक प्रकार से अभिप्राय यह था कि मोदी भी ऐसा करें"।

उस 35 मिनट की तल्ख कॉल में मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि सारे घटनाक्रम के दौरान न तो किसी भी स्तर पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बात हुई थी और न ही अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता का कोई प्रस्ताव ही आया था। इसी में इस बात का जवाब भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प को गुस्सा क्यों आता है? जैसे कोई बच्चा चाकलेट के लिए ज़िद्द करता है, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार खुद को नोबेल के सच्चे दावेदार कह रहे हैं। अगर हम तेल पर समझौता कर लेते तो फिर मांग यह होती कि हम रूस से हथियार लेना बंद कर दें क्योंकि 'इस पैसे से रूस यूक्रेन में युद्ध चला रहा है'। यह भी मांग हो सकती थी कि हम ब्रिक्स छोड़ दें और दूसरे देशों के साथ डालर के सिवाय दूसरी किसी मुद्रा में व्यापार करना बंद कर दें।

अगर हम झुकते तो झुकते चले जाते। ईयू और जापान जैसे देशों ने रियायतें दी हैं, पर हमने स्पष्ट कर दिया कि कृषि, डेयरी और छोटे उद्योग जैसे क्षेत्र किसी के लिए खुले नहीं हैं। भारत में इंग्लैंड के पूर्व हाई कमिश्नर डॉमिनिक एसक्विथ का सही कहना है कि, "कोई प्रमाण नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प के पास संगत मांग है ...या समझौते का कोई रास्ता है"। इसका कारण यही है कि मामला ट्रेड का इतना नहीं जितना अमेरिका के राष्ट्रपति की ईगो का है। उनके लिए मानना मुश्किल है कि भारत झुकने को तैयार नहीं। मैक्सिको के बारे ट्रम्प ने डींग मारी है कि 'वह करते हैं जो हम कहते हैं'। भारत मैक्सिको नहीं है। हम अमेरिका के साथ अच्छे सम्बंधों की अहमियत को समझते हैं, पर हम निर्देश लेने को तैयार नहीं। एक साम्राज्यवादी ताक़त को हटा कर दूसरी को अपने ऊपर लादने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ से कुछ सैक्टरों को धक्का ज़रूर पहुंचेगा, पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही निर्भर नहीं है। वियतनाम की अर्थव्यवस्था का लगभग 90% निर्यात पर निर्भर है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था का यह केवल 21-22% ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प अपने भक्तों को यह प्रभाव देना चाहते थे कि दुनिया के बड़े नेता उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। जैसे पहले बादशाह को नजराना चढ़ाया जाता था वैसा ट्रम्प अपने लिए चाहते हैं कि सब व्हाइट हाउस के दरबार में सलाम बजाए। पर जबरदस्त दबाव के बावजूद यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन एक इंच नहीं हिले। चीन ने भी आंखें दिखाई तो ट्रम्प पीछे हट गए। सारी भड़ास हम पर निकाली जा रही है जो उलटी पड़ गई है। ऐसी ही स्थिति हमने बंगलादेश युद्ध के समय देखी थी जब इंदिरा गांधी ने निक्सन के आगे झुकने से इंकार कर दिया था। 1998 में परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, पर भारत झेल गया। उसी नीति पर अब प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। हमने ट्रम्प को बता दिया कि हम तुम्हारी धुन पर नाचने के लिए तैयार नहीं हैं। सीएनएन पर एक विश्लेषक ने कहा है, "अमेरिका ने भारत को खो दिया। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा"।

इस बीच चीन के तिआनजिन शहर में एससीओ की बैठक में 20 देशों के नेता मौजूद रहे। चीन दुनिया में खुद को वैकल्पिक लीडर पेश करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की बेवक़ूफ़ी ने चीन को और भी बड़ी ताकत बना दिया है। पहलगाम हमले के चार महीने के बाद ही मोदी की चीन यात्रा असामान्य है। शी जिनपिंग ने जरूर कहा कि 'हम पार्टनर हैं विरोधी नहीं', पर उनकी बात पर भारत में शायद ही कोई विश्वास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद का वर्णन किया और घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निन्दा की गई है। यह हमारी कूटनीतिक विजय है क्योंकि अभी तक चीन पहलगाम का नाम लेने से कतरा रहा था। इस सम्मेलन से बड़ा संदेश यह है कि वर्ल्ड आडर हिल रहा है। प्रक्रिया तो पहले से शुरू है, पर ट्रम्प की विचित्र नीतियों के कारण इसमें तेज़ी आ गई है। उन्हीं की नीतियों के कारण भारत और चीन कुछ नजदीक आ रहे हैं। पर गर्मजोशी नहीं है। गलवान का टकराव भूलना मुश्किल है, पर कूटनीति एक जगह ठहर नहीं सकती। समय के साथ उसे बदलना है। भारत ने भी बता दिया है कि उसके पास भी विकल्प हैं। हमने रूस से तेल लेना बंद करने से भी इंकार कर दिया है।

भारत की नीति का प्रभाव नजर आने लगा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो ट्रम्प की गुर्राने वाली टीम के प्रमुख सदस्य हैं, ने मोदी-पुतिन वार्ता से कुछ मिनट पहले सुर बदलते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता 'नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है' और यह रिश्ता21वीं सदी को परिभाषित करेगा।हमारे लोगों को ज़ंजीरों में वापिस भेजने के बाद रूबियो ने "हमारे दो लोगों के बीच चिरस्थायी दोस्ती" की बात कही है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि "भारत के मूल्य चीन से कहीं ज़्यादा हमारे साथ मेल खाते हैं"। यह बात अब क्यों समझ आ रही है? दुनिया में दो खेमे हैं, अमेरिका-पश्चिम तो दूसरी तरफ़ चीन-रूस। पलड़ा उसका भारी रहेगा जिस तरफ़ भारत जाएगा। इसीलिए अनर्गल बयानबाज़ी से रिश्ते को जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई की जा रही है। पर भारत का इतिहास है कि हम ख़ेमाबाज़ी से ऊपर हैं। हम अमेरिका को छोड़ नहीं रहे, न ही छोड़ सकते हैं। उनके साथ कई स्तर पर मज़बूत रिश्ता है। रक्षा संबंध तगड़े हैं, वह हमारी सबसे बड़ी निर्यात मार्केट है और जो आज ड्रैगन और हाथी के टैंगो की बात कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि कम से कम अमेरिका हमारी सीमा पर तो नहीं बैठा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस नाज़ुक समय में अमेरिका की बागडोर ट्रम्प जैसे अस्थिर आदमी के हाथ में है इसीलिए यह संदेश भेजना ज़रूरी था कि हम मैक्सिको या पाकिस्तान नहीं हैं। हम किसी के भी आधीन नहीं रहने वाले। चीन के खेमे में जाने का सवाल ही नहीं। रूस के साथ पुरानी दोस्ती चलेगी। पर हाल का घटनाक्रम यह ज़रूर बता गया है कि ट्रम्प की अजीबोगरीब नीतियों और हरकतों के कारण अमेरिका की ताकत और प्रभाव का तेज़ी से ह्रास हो रहा है।

सिख सियासत

सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

तबाही के बाद भी पंजाबियों के हौसले बुलंद

पंजाब इस समय कुदरती आपदा का शिकार हो चुका है और पंजाब के ज्यादातर गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लोगों के मकान, दुकानें, सामान यहां तक कि पशु भी ज्यादातर पानी में बह चुके हैं या फिर मर गए हैं। बावजूद इसके पंजाबियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद देखे जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1947 में देश के बंटवारे में अगर किसी को जान-माल का नुक्सान हुआ तो वह पंजाब के लोग ही थे मगर कुछ ही सालों में अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से

उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि समूचे देश में सबसे अधिक अनाज की पैदावर पंजाब में होने लगी। 80 के दशक मे पंजाब ने काला दौर देखा जिसने पंजाब की युवा पीढ़ी को खेती से दूर कर विदेश भागने के चलन को जन्म दिया। देश के किसी भी राज्य में किसी तरह की आपदा आई तो पंजाबियों ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना काल में तो पंजाबियों ने अपनी सांसों तक के लंगर लगा दिए, पर अफसोस कि आज पंजाब पर आपदा आई तो कोई और राज्य मदद करने के लिए नहीं आया। पंजाब की मदद स्वयं पंजाबियों के द्वारा की जा रही है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, शिरोमणि कमेटी, तख्त पटना साहिब, तख्त हजूर साहिब, मुम्बई से शिरोमणि कमेटी सहित कई बड़ी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े गुरविन्दर सिंह बावा के द्वारा हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। शहीद भगत सिंह सेवादल के जतिन्दर सिंह शन्टी द्वारा एम्बुलेंस भेजी गई हैं ताकि मैडिकल सेवा में किसी प्रकार दिक्कत ना हो। पंजाबी गायक, कलाकार भी मददगार बनकर सामने आ चुके हैं यहां तक कि विदेशों में बैठे ज्यादातर भारतीय जिनके दिलों में आज भी पंजाब बसता है वह अपना काम-धन्धा छोड़कर अपने पंजाब को पुन: खुशहाल बनाने के लिए पहुंचने लगे हैं।

सिखों को भारत के सिवाए और किसी मुल्क में आजादी नहीं : सिख समुदाय को जितनी आजादी भारत में मिली है शायद संसार के किसी और मुल्क में नहीं मिल सकती। भारत में सिख समुदाय के लोग गुरु साहिबान द्वारा दी गई मर्यादा, परंपरा के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। सिखों के पांच ककारों में से एक कृपाण के संग कहीं भी आ-जा सकते हैं, यहां तक कि संसद और अति संवेदनशील जगहों पर भी सिख कृपाण के साथ प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संविधान सिखों को कृपाण रखने की अनुमति देता है। वहीं दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। भारत के भीतर हवाई जहाज में भी सिख कृपाण पहनकर यात्रा कर सकते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करते समय कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। गुरुद्वारों या नगर कीर्तनों सिख समुदाय कृपाण के संग गतका के प्रदर्शन करते हैं और अब तो गतका को ओलंपिक खेलों में भी स्थान दिया गया है।

मगर विदेशों में कृपाण लेकर चलने की आजादी नहीं है जिसका ताजा उदारहण उस समय देखने को मिला जब अमेरिका के लॉस एंजेल्स से एक शख्स ने अचानक अपनी कार बीच सड़क पर रोक दी और और 'गतका' (सिखों की पारंपरिक युद्धकला) करने लगा।

घटना उस स्थान के पास हुई, जहां अक्सर भीड़ रहती है। वहां मौजूद लोग डर गए और तुरंत पुलिस को कॉल किया। मौके पर पुलिस पहुंची तो उसने बार-बार उस शख्स से कृपाण नीचे रखने को कहा लेकिन वह लगातार कृपाण घुमाता रहा और कभी पुलिस की तरफ तो कभी राह चलते वाहनों की ओर बढ़ने लगा जिसके बाद पुलिस ने उस सिख युवक पर अनगिनत कई गोलियां चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। भारत में आज तक किसी सिख के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ फिर भी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी प्रवृति के लोग भारत में सिखों को गुलाम बताते हैं जबकि देखा जाए तो भारत के सिवाए और किसी भी देश में सिखों को अपने धार्मिक चिन्हों के साथ जीवन व्यतीत करने की आजादी हासिल नहीं है।

कैनेडा के हिन्दू सिखों को खालिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने की आवश्यकता : आज से 40 साल पहले कैनेडा की धरती पर बैठकर खालिस्तानियों के द्वारा बम तैयार किया गया और उसी बम से कैनेडा से भारत आने वाले एयर इन्डिया के एक जहाज को हवा में ही बम से उड़ा दिया जिसमें 329 यात्री मारे गए जिनमें 82 मासूम बच्चे भी थे। उसी समय, टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर एक और बम विस्फोट हुआ जो एयर इंडिया की एक अन्य उड़ान ए आई-301 के लिए था। यह बम चढ़ाए जाने से पहले ही फट गया, जिसमें दो जापानी बैगेज हैंडलर्स की मौत हो गई। मगर ऐसा लगता है कि कैनेडा के लोगों ने 40 साल पूर्व हुई इस घटना से अब तक कोई सबक नहीं लिया जिसके चलते आज भी खालिस्तानी खुलेआम अपनी गतिविधियों को अन्जाम देते आ रहे हैं। इस घटना के मास्टर माईंड को उल्टा एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है फिर भी ना जाने क्यों कैनेडा की सरकार इन लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई करना तो दूर उल्टा उन्हें प्रोत्साहन देती आ रही है जिसके परिणाम स्वरूप खालिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं और वह खुलकर भारत के खिलाफ गतिविधियों को अन्जाम देते हैं।

कनिष्क बम काण्ड में अपना पूरा परिवार खो चुके संजय लाजार नामक शख्स ने जिसकी उम्र उस समय मात्र 17 साल की थी और आज 57 साल का हो चुका है। कैनेडा में रहते हिन्दू-सिख भाईचारे के लोगों से अपील की है कि उन 329 लोगों को श्रद्धांजलि यही होगी कि खुलकर खालिस्तानियों का विरोध करने के लिए आगे आएं जिससे सरकार को भी यह समझ आ जाए कि कोई भी सिख भले ही संसार के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो ना तो कभी खालिस्तानी समर्थक था और ना हो सकता है। इस हादसे का जिक्र करते हुए तख्त पटना साहिब के प्रवक्ता हरपाल सिंह जौहल का कहना है कि हमें तो आज तक यह समझ नहीं आ रहा कि खालिस्तानी असल में क्या चाहते हैं क्योंकि एक ओर वह सिख समाज के लोगों के लिए अलग देश की मांग करते हैं और दूसरी ओर सिखों पर ही अत्याचार करते हैं, क्योंकि कनिष्क हवाई हादसे में भी मरने वाले ज्यादातर सिख समाज के ही लोग थे जिससे एक बात संसार भर के सिखों को समझ लेनी चाहिए कि खालिस्तानी समर्थकों का मकसद पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंक का माहौल बनाने से अधिक और कुछ नहीं है।

करतारपुर कोरीडोर खोलने की उठी मांग : बीते समय में जंग के ऐलान के बीच करतारपुर कोरीडोर को सरकार ने पुन: बन्द कर दिया था जिसे खोलने की मांग अब फिर से उठने लगी है। असल में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के मेन हॉल सहित समूचे परिसर में पानी जमा हो गया था और पानी निकलने के बाद जमा गार की सफाई पाकिस्तान प्रशासन के द्वारा की गई जिसे लेकर सिख संगत में काफी रोष देखा जा रहा है। संगत का मानना है कि अगर संगत को वहां जाने की मंजूरी होती तो संगत द्वारा स्वयं इस सेवा को मर्यादा पूर्वक निभाया जाता। इसी के चलते श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार एवं नए बने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह के द्वारा देश की मोदी सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द करतार पुर कोरीडोर को संगत के लिए खोला जाना चाहिए। असल में सिख संगत में रोष इसलिए भी है कि एक ओर संगत को दर्शनों से वंचित रखा जा रहा है वहीं क्रिकेट सहित अन्य खेलों के लिए दोनों देशों में सहमति बनी हुई है, इसलिए अब संगत चाहती है कि बिना देरी के कोरीडोर खोला जाए ताकि जो संगत अभी भी दर्शन नहीं कर सकी वह दर्शन कर पाए।

जब दादा भाई नौरोजी ने कहा- 'हमें अनुकंपा नहीं, न्याय चाहिए'

नई दिल्ली, (आईएएनएस)साल था 1906 और जगह थी कलकत्ता (अब कोलकाता)। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था और इसमें दादा भाई नौरोजी ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रमुखता से 'स्वराज' का जिक्र किया और ब्रिटिश हुकूमत को ललकारते हुए कहा था, 'जिस प्रकार सभी सेवाओं, विभागों और अन्य कार्यों में ब्रिटेन का प्रशासन उस देश की जनता के हाथों में होता है, वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। हमें अनुकंपा नहीं बल्कि न्याय चाहिए।''डिजिटल संसद' वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, 1906 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान दादा भाई ने स्वदेशी को भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए एक अनिवार्य कदम बताया था।

उन्होंने इसे भारत के 'अस्वाभाविक आर्थिक दलदल' से निकलने का रास्ता माना था और कहा था कि जिस प्रकार ब्रिटेन में प्रशासन, सेवाएं और अन्य कार्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में हैं, उसी प्रकार भारत में भी होना चाहिए। यह स्वशासन का आधार था।

दादाभाई का यह भाषण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने 'स्वराज' को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, बल्कि आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता के रूप में परिभाषित किया। उनके विचारों ने स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया, जिसे बाद में महात्मा गांधी समेत कई नेताओं ने व्यापक रूप से अपनाया।

दादाभाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बंबई (अब मुंबई) में एक पारसी परिवार में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1886, 1893 और 1906 में इसके अध्यक्ष रहे। उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे ब्रिटेन में भारतीय हितों की वकालत का मंच था। 1892 में वे यूनाइटेड किंगडम की संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) में चुने गए और वहां पहुंचने वाले वे पहले भारतीय बने।

नौरोजी को उनके समर्पण, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति के लिए 'भारत का महान युगपुरुष' और 'भारतीय राष्ट्रवाद का जनक' कहा जाता है। उनकी ड्रेन थ्योरी, स्वराज की अवधारणा और स्वदेशी के समर्थन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी।

दादाभाई ने अपनी किताब 'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में 'ड्रेन थ्योरी' प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति को ब्रिटेन की ओर स्थानांतरित कर रहा था, जिस कारण भारत में गरीबी बढ़ रही थी। यह सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार बना।

नौरोजी ने पारसी समुदाय में सुधारों का समर्थन किया और महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए काम किया। वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे और शांतिपूर्ण तरीकों से बदलाव लाने में विश्वास रखते थे।

अपने अंतिम दिनों में भी उन्होंने भारत के हितों के बारे में ही सोचा। डिजिटल संसद की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, 1 जून, 1917 को वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। 30 जून, 1917 की शाम को उनका बंबई में निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 92 साल थी। दादाभाई का पार्थिव शरीर पारसी रीति-रिवाज के अनुसार 'टावर ऑफ साइलेंस' को अर्पित कर दिया गया।

दादाभाई के निधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 32वें अधिवेशन (1917, कलकत्ता) में एक शोक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनकी 'भारत और उसकी जनता के प्रति लोक सेवा भावना से अर्पित बहुमूल्य सेवाओं' को स्मरण किया गया। यह प्रस्ताव उनके राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का प्रतीक था। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादाभाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, उनका जीवन आदर्श रहा है। गंगा के समान पवित्र, पृथ्वी के समान सहनशील, अहंकार से एकदम शून्य, देशभक्ति से परिपूर्ण, प्रेम से ओत-प्रोत और ऐसे उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील, जब कोई इस पर विचार करता है तो उसे लगता है कि मानो वह एक महान शक्ति से अनुप्राणित हो उठा है।

वहीं, महात्मा गांधी ने कहा था, दादाभाई ने देश की जो निर्बाध और सतत सेवा की, वह भारत के लिए एक अनुकरणीय आदर्श सिद्ध होगी।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 04-09-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP6 User: kamlesh.mestry Time: 09-03-2025 22:14 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । गुरुवार, 4 सितंबर 2025

विरोध कहां तक

देश ने आरक्षण की एक और लड़ाई देखी। मराठा आरक्षण को लेकर पांच दिनों तक देश की आर्थिक राजधानी में हंगामा मचा रहा। प्रदर्शनकारी आखिरकार माने, लेकिन अपनी कई मांगें मनवा कर। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, पर इससे जुड़े कुछ सवाल अब भी बाकी हैं - अपनी मांग को लेकर कोई आंदोलन किस हद तक जा सकता है और क्या विरोध-प्रदर्शन का अधिकार छीना जा सकता है?

अदालत की सख्ती । बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल से जवाब मांगा है कि आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, उसका जिम्मेदार कौन है? जरांगे की तरफ से बताया गया कि आंदोलन शांतिपूर्ण था। हालांकि यह माना गया कि आम जनता को असुविधा हुई। गौरतलब है कि यह आंदोलन खत्म भी तभी हुआ, जब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई - भले इसके लिए सरकार ने जरांगे की मांगें मानीं।

मराठा आरक्षण आंदोलन

आंदोलन से परेशानी । आम लोगों को हुई असुविधा पर हाई कोर्ट की नाराजगी बिल्कुल सही है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी शहर की रफ्तार को रोक देना उचित नहीं माना जा सकता। दुर्भाग्य से दक्षिण मुंबई को जबरदस्त परेशानी झेलनी पड़ी - कई लोकल ट्रेन कैंसल हुईं और कभी न थमने वाली मुंबई का कुछ हिस्सा आरक्षण आंदोलन में जकड़ गया।

प्रशासन की जिम्मेदारी । लेकिन यहां जितनी जिम्मेदारी आंदोलनकारियों, उनके नेता जरांगे की है, उतनी ही एडमिनिस्ट्रेशन की भी। मुंबई में भीड़ का उमड़ना कोई नई बात नहीं है। गणेश पूजनोत्सव के दौरान ही देश के तमाम हिस्सों से लोग गणपति बप्पा के दर्शन को मुंबई पहुंचते हैं। तो क्या आंदोलन की जानकारी होने के बाद हालात को संभालने के लिए उचित इंतजाम किए गए थे? अगर परमिशन पांच हजार की थी, तो इससे कई गुना ज्यादा भीड़ कैसे महानगर में दाखिल हो गई?

संतुलन जरूरी । विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। सरकार से असहमति जताना और जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाना हर नागरिक का हक है। अगर किसी समुदाय-वर्ग को लगता है कि सरकार उसके हितों की अनदेखी कर रही है, तो उसे विरोध जताने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन, मामला है हद का - कि उस विरोध की सीमा क्या होगी? जिस तरह विरोध का अधिकार नहीं छीना जा सकता, उसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि एक का प्रदर्शन दूसरे के लिए आफत बन जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जरूरी है कि इस सवाल को सुलझा लिया जाए।

आमची मुंबई

आंदोलन के निशान!

हरि मृदुल

जैसे बाढ़ अपने निशान छोड़ जाती है, उसी तरह आंदोलन भी निशान छोड़ जाते हैं। आजाद मैदान के इर्द-गिर्द देखिए, कितनी ही निशानियां पड़ी मिल जाएंगी। पॉलीथिन की थैलियां, पानी की छोटी-बड़ी बोतलें, बिस्किट्स के रैपर, चिप्स के खाली पैकेट, पैरों से बिछुड़ गए जूते-चप्पल, और भी पता नहीं क्या-क्या। सुबह से सफाईकर्मी लगे पड़े हैं। पॉलीथिन की पतली थैलियां उड़-उड़ जा रही हैं। हाथ नहीं आ रही हैं। बिना ढक्कन की पानी की बोतलें ऐसे लुढ़क रही हैं, जैसे कि वे खुद भी कोई नया आंदोलन करना चाहती हों! वह एक चप्पल रुआंसी-सी अपने जोड़ीदार को ढूंढ़ रही है, जो अब उसे कभी नहीं मिलने वाला। आंदोलन के निशान तमाम चेहरों पर भी साफ देखे जा सकते हैं। खैनी फटकारते वॉचमैन को देखो, कैसा उनींदा दिख रहा है। पुलिसवालों को देखो, अब जाकर उन्हें थोड़ी राहत की सांसें मिली हैं। हां, भेल-कुरमुरे बेचनेवाले उस छोकरे के चेहरे की चमक जरूर बता रही है कि आंदोलन की वजह से इन पांच दिनों में उसका धंधा कई गुना बढ़ गया था!

असल में जिस इलाके में आंदोलन होता है, उस इलाके के लोगों के चेहरे देखकर पता किया जा सकता है कि आंदोलन का स्वरूप कैसा रहा होगा। आंदोलन को लेकर हर कोई अपने एंगल से सोचता है। कोई दुआ करता है कि मांगें मान ली जाएं, तो खत्म हो तमाम झंझट। किसी की दुआ होती है कि इसी बहाने चलती रहे राजनीति। उम्मीद से पहले खत्म हो गया आंदोलन, तो विपक्षी दलों के नेता खीझ गए हैं। वे तो सोच रहे थे कि आंदोलनकारी राशन-पानी लेकर चढ़े हैं, इसलिए अब महीनेभर तो हिलने से रहे। सत्ता पक्ष की शामत आना तय है। परंतु अब विपक्षी नेता हैरान हैं कि सत्ता पक्ष ने यह कैसी तो चाभी घुमा दी!!

मीडिया के लोगों को भी रोज कुछ न कुछ मसाला मिल जा रहा था। पन्ने भरने में आसानी थी। चैनलों में तय था कि यह दिखाना है और इतना दिखाना है। किसी को नहीं लगता था कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आंदोलन निपट जाएगा। खुद आंदोलनकारी हैरान हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी। यह भी कहीं धोखा तो नहीं। हां, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जरूर खुश हैं कि उम्मीद से काफी पहले उनका मैदान आजाद हो गया है।

एकदा

ज़िम्मेदारी का निर्वाह

सन 1939 की बात है, मदन मोहन मालवीय तबीयत खराब होने के कारण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना और उनसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया। राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के वित्तीय संकट से अच्छी तरह परिचित थे। मालवीय जी बिना वेतन इस पद पर रहते थे और अपने सीमित संसाधनों से विश्वविद्यालय को चलाते थे। राधाकृष्णन ने सप्ताह में दो दिन बिना वेतन काम करने की स्वीकृति दी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वह ऑक्सफोर्ड नहीं जा सके और पूरी तरह विश्वविद्यालय की सेवा में जुट गए। उन्होंने फिजूलखर्ची पर रोक लगाई और उदार दानदाताओं से मदद जुटाई, जिससे विश्वविद्यालय आर्थिक संकट से बाहर निकला। वेतन न लेने की उनकी इच्छा पर बड़ौदा के राजा प्रतापसिंह ने हस्तक्षेप किया और सयाजी राव के नाम से तीन फेलोशिप शुरू करवाई। साथ ही 'सयाजी राव चेयर ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री' नामक पद बनाया गया, जिसे राधाकृष्णन ने आजीवन स्वीकार किया। 20 मार्च, 1941 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रफेसरशिप छोड़ दी और पूरी तरह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए समर्पित हो गए।

Subrata Dhar

संकलन : **हरिप्रसाद राय**

चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान से सहयोग की कीमत वसूलेंगे, जिससे वह मुश्किल में फंस सकता है

पाक को महंगी पड़ेगी दो नावों की सवारी

अविनाश मोहनाने

कैसी है ये उलझन
- पाक की सीमा ईरान से लगती है
- अमेरिका इसका लाभ लेना चाहता है
- चीन-US दोनों खुश कैसे रहेंगे

पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहा है। वह दो नावों पर सवार हो गया है। चीन उसका 'ऑल वेदर फ्रेंड' है और पाकिस्तान को सबसे अधिक हथियार बेचता है। दूसरी ओर अमेरिका है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्थिरता देने में मदद कर रहा है। उसने पाकिस्तान पर बहुत कम 19% का टैरिफ लगाया है। साथ ही, उसे आसानी से कर्ज मिले, इसमें भी मदद कर रहा है।

खुशी नहीं टिकेगी । मई में जब भारत-पाकिस्तान के बीच चंद रोज की जंग हुई, तब पड़ोसी देश की सरकार और फौज चीन से मिले समर्थन पर इतरा रही थीं। अब ट्रंप सरकार से जो अटेंशन-अहमियत मिल रही है, वे उस पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। पाकिस्तान इस बात से भी प्रसन्न है कि भारत पर ट्रंप ने 50% का भारी-भरकम टैरिफ लगाया है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली।

चीन होगा नाराज । चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान पर इधर जो मेहरबानियां की हैं, वे जल्द ही उसकी कीमत भी वसूलना चाहेंगे। दोनों देश एक दूसरे से उलट मांगें रखेंगे, जिसे पूरा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा।

फरेबी पाकिस्तान । एक बड़ा सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान की अमेरिका हाल के वर्षों में अनदेखी कर रहा था, उसे अचानक ट्रंप 'शानदार सहयोगी' क्यों बताने लगे? पिछले कार्यकाल में तो उन्होंने पाकिस्तान को झूठा और फरेबी बताया था। इसका जवाब पाकिस्तान की अनोखी भौगोलिक स्थिति में है। उसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और चीन से भी लगती हैं। पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके अमेरिका इस क्षेत्र में अपने सामरिक-आर्थिक हित साध सकता है।

अमेरिका की सोच । इन तीनों देशों के अलावा पाकिस्तान का एक और पड़ोसी भारत है। अमेरिका भारत को लेकर चिंतित नहीं है। यह सच है कि अभी दोनों के बीच तनाव बढ़ा है, लेकिन यह दौर अस्थायी ही साबित होगा। ईरान की सरकार को अस्थिर करने से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिनरल रिजर्व पर नियंत्रण करने और चीन को अलग-थलग करने तक अमेरिका की नीतियों से दक्षिण एशिया का सामरिक चेहरा बदल सकता है। इसका असर अमेरिका से संबंधों को लेकर भारत की सोच पर भी हो सकता है। कुछ समय पहले जब इस्राइल-अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा था, उसी बीच पाकिस्तान के मिलिटरी चीफ आसिम मुनीर की ट्रंप ने एक प्राइवेट लंच पर मेजबानी की। जब इस्राइल-अमेरिका, ईरान की धार्मिक लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश में जुटे थे, तब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर के साथ ईरान पर चर्चा की।

ईरान के खिलाफ प्लान । सवाल उठता है कि अमेरिका, ईरान के मामले में पाकिस्तान से चाहता क्या है? क्या वह 1953 जैसा एक और 'operation Ajax' प्लान कर रहा है? यह ऑपरेशन CIA और MI6 ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देग को हटाने के लिए लॉन्च किया था। उनकी जगह वे शाह को ईरान की सत्ता पर बिठाकर उसके तेल भंडारों को नियंत्रित करना चाहते थे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जिसकी धरती का इस्तेमाल अतीत में अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य गतिविधियों की खातिर किया है। क्या पाकिस्तान, ईरान के खिलाफ ऐसी गतिविधि के लिए तैयार होगा?

ईरान की चिंता । इस्राइल-अमेरिका के हमलों के खिलाफ रूस-चीन, ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो चीन उससे नाराज हो जाएगा। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भागे-भागे पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी कंपनियों को उसकी सीमा से लगे बलूचिस्तान में आने दिया गया तो ईरान की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा।

रेयर अर्थ पर नजर । हालांकि, इस इलाके में अमेरिका और चीन के बीच मिनरल रिसोर्सेज को लेकर प्रतिस्पर्धा दिख सकती है। बलूचिस्तान और खैबर पखतूनख्वा में ऐसे मिनरल्स होने की उम्मीद है। लेकिन अगर इन इलाकों में अमेरिका की मौजूदगी होती है तो उसका असर ईरान, अफगानिस्तान और चीन पर पड़ेगा।

चीन की परेशानी । चीन को शक है कि अमेरिका, बलूच अलगाववादियों और तहरीक-ए-तालिबान (TTP) का इस्तेमाल पाकिस्तान में उसके हितों को निशाना बनाने के लिए करता है। बलूच अलगाववादी चीन को नव-साम्राज्यवादी शक्ति बताते हैं, जिसकी नजर इलाके के खनिज संसाधनों पर है। इसी तरह, ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूमवेंट के लोग TTP में हैं, जो इसे चीन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उकसाते हैं।

पाक को हिदायत । उधर, दक्षिण एशिया में चीन अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अमेरिका को इससे दूर रख सके। वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आपसी रिश्ते सुधारने के लिए भी कह रहा है। ध्यान रहे, पाकिस्तानी सैन्य शासकों के संबंध अमेरिका से बेहतर ही रहे हैं, जिसकी शुरुआत अयूब खान के शासनकाल से हुई थी। पाकिस्तान में अभी फौज के इशारे पर बनी सरकार सत्ता में है और देश के सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में हैं। इसके लिए भी अमेरिका से पाकिस्तान ने मुहर लगवाई होगी।

(लेखक पूर्व IB ऑफिसर हैं और वह पाकिस्तान में भी तैनात रह चुके हैं)

FIR की संख्या नहीं, पुलिस का प्रदर्शन देखें

गुलशन राय खत्री

हाल ही में दिल्ली में दिनदहाड़े VIP इलाके में बदमाश एक महिला सांसद की सोने की जंजीर छीनकर भाग निकले। उन्होंने इसकी शिकायत की। मामला सामने आते ही पुलिस एक्टिव हुई और कुछ देर में बदमाश को पकड़कर जंजीर भी बरामद कर ली। चूंकि मामला VIP से जुड़ा था इसलिए पुलिस फौरन हरकत में भी आ गई। लेकिन अगर किसी आम आदमी के साथ यही हो, तो क्या पुलिस इतनी फुर्ती दिखाएगी?

पब्लिक बनाम पुलिस । इस मामले में भी कई लोगों की प्रतिक्रिया थी कि अगर वे भी VIP होते तो उनके मामलों में भी पुलिस ऐसे ही फुर्ती दिखाती। पुलिस को लेकर इस तरह की प्रतिक्रियाएं नई नहीं हैं। दूसरी ओर पुलिस की अपनी भी शिकायतें हैं। काम का दबाव, लंबी ड्यूटी और कम संसाधनों के साथ ही कानून की पेचीदगियों को भी वे अपनी सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। यह स्थिति किसी एक शहर या राज्य की नहीं, बल्कि कमोबेश पूरे देश की है।

बदला कानून । केंद्र सरकार ने लगभग एक साल पहले IPC की जगह BNS के जरिए न सिर्फ अपराध की धाराओं में बदलाव किया है बल्कि कई और बुनियादी बदलाव भी किए हैं। इनमें E-FIR को मान्यता देने के साथ ही जांच को वैज्ञानिक बनाने के कई प्रावधान हैं। जमानत से लेकर कोर्ट में तेजी से ट्रायल के लिए कुछ पहलुओं को भी बदला गया है। इन सभी का मकसद यही रहा कि पुलिस के साथ ही लीगल सिस्टम को भी ऐसा बनाएं कि अपराधी बच न पाएं और जांच भी वैज्ञानिक तरीके से की जाए।

आंकड़ों पर सवाल । क्या इतने भर से पुलिस की छवि सुधर पाएगी? मूल समस्या यह है कि पुलिस की परफॉर्मेंस को आंकड़ों से ही नापा जाता है। मसलन, आम लोगों की FIR दर्ज न होने शिकायत होती है। सचाई यह है कि अगर पुलिस हर शिकायत पर FIR दर्ज करती है और साल भर में दर्ज होने वाले आंकड़ों की संख्या बढ़ती है तो संसद से लेकर अखबारों तक सुर्खियां बन जाती हैं। नतीजा, पुलिस की आलोचना होती है। कई बार पुलिसकर्मियों के तबादले तक हो जाते हैं और उनके लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाता है।

AI Image

कॉमन रूम

दिक्कतें ज्यादा । जरूरत के हिसाब से पुलिसकर्मी नहीं हैं। ऐसे में एक FIR दर्ज करने का मतलब होता है, लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई। पुराने केसों को सुलझाने का ही इतना दबाव होता है कि जब तक जरूरी न हो, केस दर्ज नहीं किया जाता। असल में केस दर्ज करने पर मचने वाला शोर ही पुलिस को केस दर्ज न करने के लिए प्रोत्साहित करने लगता है।

क्या है हल । पहले यह आकलन होना चाहिए कि पुलिस को कर्मचारी व संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ज्यादा जरूरी यह है कि पुलिस की परफॉर्मेंस को देखने का पैमाना भी बदला जाना चाहिए। दर्ज होने वाले आपराधिक आंकड़ों को पैमाना बनाना गलत है। इसकी बजाए पुलिस की परफॉर्मेंस को समग्र तौर पर आंका जाना चाहिए। अगर FIR के आंकड़ों को लेकर ही पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं तो पुलिस FIR दर्ज न करके इस आलोचना से बचने की कोशिश करती है।

सर्वे हो । सबसे बेहतर है कि न सिर्फ FIR के आंकड़े देखे जाएं, बल्कि अपराध सुलझाने का प्रतिशत और अपराध रोकने की कवायद को भी शामिल किया जाए। पुलिस परफॉर्मेंस के लिए निष्पक्ष सर्वे हों। इसके बाद रैंकिंग के आधार पर थानों, जिलों या राज्यों की पुलिस की सही परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। लेकिन इसमें भी सर्वे की गोपनीयता व निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि असरदार पुलिसकर्मी अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए किसी को प्रभावित न कर सकें।

नूरजहां और रजिया से किसे है डर

इरा मुखोटी

महान फ्रांसीसी दार्शनिक सिमॉन दि बोउवार ने कहा है कि लड़कियां जन्म से ही 'औरत' नहीं होतीं। खास सामाजिक माहौल और परिवेश में पलते-बढ़ते हुए वे धीरे-धीरे 'औरत' होना सीखती हैं। यह प्रक्रिया बचपन में ही सुनाई जाने वाली परियों की कहानियों से शुरू हो जाती है।

त्याग की मूरत । दूसरी तरफ भारत जैसे समाज में पितृसत्ता से जुड़ी सोच इन लड़कियों के दिलोदिमाग में अलग-अलग तरीकों से यह बात बिठाती रहती है कि लड़कियां तो त्याग और बलिदान की मूरत होती हैं। उन्हें परिवार और समाज के हित में अपनी इच्छा को दबाना सीखना ही चाहिए।

किताब से गायब । ऐसे में भारत में यह ज्यादा जरूरी है कि लड़कियों को बचपन से ही उन ऐतिहासिक किरदारों से परिचित कराया जाए, जिन्होंने तमाम बाधाओं और तत्कालीन सामाजिक नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी क्षमता का लोहा मनवाया ताकि ये लड़कियां भी उन किरदारों में अपने भविष्य की झलक देख सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि NCERT की सामाजिक विज्ञान की सातवीं की किताब से दो असाधारण महिलाओं - रजिया सुल्तान और नूर जहां - का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया।

सह-शासक नूर जहां । नूर जहां चौथे महान मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम थीं। जहांगीर के शासन काल में नूरजहां की शक्ति ऐसी असीमित थी, उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि इतिहासकार रुबी लाल ने उनका वर्णन सह-शासक के रूप में किया है। पूरे मुगल काल में वह इकलौती ऐसी महिला रही हैं, जिन्हें सह शासक का खिताब देने लिया गया।

महिला सुल्तान रजिया । रजिया सुल्तान की जहां तक बात है तो वह दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासक थीं। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के काल में उन्होंने सुल्तान के रूप में अपने नाम से शासन किया। उस दौर में जब कैथलिक यूरोप में रजिया की समकालीन महिलाएं घरों की चारदीवारी के भीतर ही सीमित थीं, दिल्ली की इस सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए।

AI Image

टाइम मशीन

गलत चित्रण । दिलचस्प है कि शानदार उपलब्धियों के बावजूद इन दोनों महिलाओं की शानदार विरासत आम लोगों के दिलोदिमाग तक सही रूप में पहुंच नहीं पाई। नूरजहां को ऐसी अति महत्वाकांक्षी और झगड़ालू महिला के रूप में चित्रित किया गया, जो अपने सौंदर्य के मोहपाश में जकड़े बादशाह को गुमराह किया करती थी। रजिया सुल्तान को इस बात के लिए आलोचना का पात्र बनाया गया कि उन्होंने परदा प्रथा को अंगूठा दिखा दिया था।

अंधकार युग का ठप्पा । आठवीं क्लास की किताब में इन दोनों साम्राज्यों का जिक्र अंधकार युग के रूप में किया गया है। दोनों रानियां जो लड़कियों की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकती थीं, उनका इन बच्चियों के जेहन में दर्ज होना भी मुश्किल हो गया। यह इन दोनों ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की छवि ही नहीं, नई पीढ़ी की लड़कियों की हसरतों पर भी चोट है।

(लेखिका इतिहासकार हैं)

लेकर रहेंगे अपना हक़

राहुल पाण्डेय

भारत की महिलाएं अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में MBA कर रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि दस साल पहले जहां MBA करने वाली भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 28 फीसदी थी, वहीं आज यह बढ़कर 42 फीसदी हो गई है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2024 में ही 6,100 से अधिक भारतीय छात्राओं ने नामी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जर्मनी जैसे देशों में भारतीय छात्र-छात्राओं की संख्या 15 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आवेदन 21 फीसदी बढ़े हैं। यह साफ दिखाता है कि भारतीय महिलाएं शिक्षा और अवसरों की वैश्विक दौड़ में किसी से पीछे नहीं। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं। एक अंतरराष्ट्रीय MBA की लागत 40 से 80 लाख रुपये के बीच होती है। यही वजह है कि आर्थिक अड़चन अब भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। लेकिन एजुकेशन लोन और नए फाइनेंसिंग मॉडल इसे आसान बना रहे हैं।

AI Image

आधी दुनिया

गौरतलब है कि दुनिया भर के MBA प्रोग्राम्स में महिलाओं के आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषकर लचीले और हाइब्रिड पाठ्यक्रम उन महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं, जो करियर और परिवार दोनों को संतुलित रखना चाहती हैं। असल सवाल यह है कि भारत इस रुझान से क्या सीख ले? अगर महिलाएं वैश्विक मंचों पर अपनी जगह बना रही हैं तो क्या देश के भीतर के संस्थान उनके लिए पर्याप्त अवसर दे रहे हैं? क्या कॉरपोरेट सेक्टर महिलाओं को नेतृत्व की असली हिस्सेदारी देने को तैयार है? रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा जिंदगियों को बदलने की ताकत रखती है। अगर भारत इस ताकत को पहचाने और सही ढंग से इस्तेमाल करे, तो आने वाले वर्षों में भारतीय महिलाएं वैश्विक नेतृत्व की नई परिभाषा लिख सकती हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

दिल की बीमारियां

महोदय, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कभी यह परेशानी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित थी, वहीं अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे समय पर सही समय पर पहचान और इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है। इसी बीच डॉक्टरों ने एक नई उम्मीद जगाई है AI स्टेथोस्कोप के रूप में। यह स्मार्ट डिवाइस महज पंद्रह सेकेंड में तीन जानलेवा हार्ट कंडीशन्स को पकड़ सकता है। यानी मरीज को अब घंटों तक टेस्ट या महंगी जांचों का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि तुरंत सही डायग्नोसिस मिल सकेगा और इलाज शुरू हो पाएगा। यह स्टेथोस्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है जो हार्टबीट और ब्लड फ्लो की आवाजों को रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण करता है और बता देता है कि दिल में कोई असामान्यता है या नहीं।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

शिक्षक का सम्मान

सितंबर आते ही शिक्षक दिवस की याद आ जाती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दरअसल, हर किसी के जीवन में कही न कहीं गुरु विद्यामान रहता है। विश्व में सभी देशों में शिक्षक को बड़े ही सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है। गुरु का आशीर्वाद मिले, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। गुरु-शिष्य का संबंध ऐसा होता है, जैसे एक संतान का अपने माता-पिता से। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है। देश और समाज के लिए शिक्षक का योगदान हमेशा से ही महत्वपूर्ण है।

साजिद अली, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

भारत से चीन के लिए शुरू हो सकती है डायरेक्ट फ्लाइट - खबर
- दोस्ती की इस उड़ान में कितना ईंधन है, वक्त बताएगा!

श्वेता राजवंशी

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

भविष्य की चिंता आपका वर्तमान भी ख़राब कर देगी

जयति गोयल

मनुष्य का स्वभाव है कि वह बहुत सोचता है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब यह चिंतन की बजाय चिंता में बदल जाता है, तब घातक साबित होता है। अनेक लोग चिंता में जीते हैं, जबकि कुछ ही चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, लेकिन चिंतन में गिने-चुने दो-चार ही सफल हो पाते हैं। चिंता जीवन की परीक्षा का एक कठिन प्रश्न है, जिसका उत्तर खोजते-खोजते हम चिंता के जाल में फंस जाते हैं और वह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। चिंता के बुरे प्रभाव हम सभी जानते हैं, फिर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। जहां भी जाते हैं, चिंता हमारे साथ चलती रहती है।

भारतीय धर्मग्रंथों, साहित्यकारों और दार्शनिकों ने चिंता के नकारात्मक परिणामों को बार-बार स्पष्ट किया है। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी भविष्य की चिंता को व्यर्थ बताया है। उनका ज्ञान था कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता में फंस जाएगा तो वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएगा, जिससे उसका भविष्य भी दुखदायी होगा। क्योंकि वर्तमान न जिया होगा, और भविष्य के लिए भी खुश रहना कठिन हो जाएगा। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, वह ईश्वर को कैसे जान सकता है? और आत्मज्ञान के लिए चिंतन आवश्यक है, चिंता नहीं।

भारतीय संस्कृति में चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय हैं। यहां 'चित्त' और 'चेतन' में अंतर किया गया है। चित्त के स्वभाव पर नियंत्रण करना और चेतना को जागृत रखना मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। चिंतन हमारे विचारों को पुष्ट करता है और हमारे व्यक्तित्व को सशक्त बनाता है। एक शोध में यह भी पाया गया है कि चिंता पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति अधिक मजबूत और सक्षम बन सकता है। कहते हैं, चिंता चिता के समान होती है। जैसे चिता जलती रहती है, वैसे ही चिंता भी मनुष्य को जलाती रहती है। इसलिए कहा गया है- चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता को अर्थहीन कल्पना माना गया है। जरूरी मामलों में चिंता स्वाभाविक है, लेकिन बेकार की चिंता मूर्खता है। चिंतनशील व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेता है। वह समस्या से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है

जो कुछ हो रहा है, उसकी चिंता करने की बजाय उससे सीख लेकर चिंता के दलदल से बाहर निकलना बुद्धिमानी है। भूत और भविष्य की चिंता में व्यर्थ गया समय नष्ट हो जाता है और हमारे पास केवल शून्यता रह जाती है। इसलिए हमें बंद दरवाजों की बजाय खुले द्वार को देखना चाहिए। कैसे होगा - इस पर ध्यान न देकर, कैसे करना है - इस पर ध्यान देना चाहिए। धर्म और अध्यात्म हमें वही मार्ग दिखाते हैं, जिसका पालन करके हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

निर्णय अहंकार या अपमान के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि रणनीति के साथ लिए जाने चाहिए। -नेल्सन मंडेला

देश की पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार होना निश्चित ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे साबित होता है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

डिजिटल संप्रभुता की ओर

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश की पहली स्वदेशी चिप को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का क्षण ऐतिहासिक तो खैर है ही, इस उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल, नाखून के आकार की ये चिप, जिन्हें सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। शीतयुद्ध काल में परमाणु हथियारों की जैसी होड़ विभिन्न देशों के बीच दिखती थी, वही आज ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक चिप के निर्माण को लेकर दिख रही है। भारत पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में पिछड़ा ही रहा, तो इसकी वजह समझी जा सकती है। कई बार एक विकासशील देश की बुनियादी प्राथमिकताएं महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर बढ़ने की उसकी गति को धीमा कर देती हैं। दूसरी ओर, ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों की पकड़ इस क्षेत्र में बेहद मजबूत रही है। ताइवान तो दुनिया के साठ फीसदी से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, जिसमें 90 फीसदी सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं। पिछले कुछ दशकों से भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता अधिक ही रही है, जिससे उसे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन, 2021 में शुरू हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत महज चार वर्षों के भीतर अपनी चिप बनाकर भारत ने इस क्षेत्र में विश्वास अर्जित किया है। देश का सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में 38 अरब डॉलर का था, जो 2024-25 में करीब 45-50 अरब डॉलर का हो चुका है और अब 2030 तक इसके दोगुने से भी अधिक होकर 100-110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, यह महज एक शुरुआत है। कुशल मानव संसाधन, उन्नत अनुसंधान और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला सेमीकंडक्टर उद्योग में कामयाबी की पूर्व-शर्त माने जाते हैं। वैश्विक शोध के अनुसार, भारत में पहले से ही वैश्विक चिप डिजाइन इंजीनियरों का

तकरीबन 20 फीसदी हिस्सा मौजूद है। इसके अतिरिक्त, क्वालकॉम, इंटेल, एनवीडिया जैसे वैश्विक दिग्गजों ने बंगलूरू, हैदराबाद और नोएडा में अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। यही नहीं, सरकार ने 278 विश्वविद्यालयों में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरण मुहैया कराए हैं, ताकि एक मजबूत प्रतिभा पूल तैयार हो सके। नीतियों को अधिक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाने के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से भारत इस क्षेत्र की अग्रणी शक्ति के रूप में उभर सकेगा। फिलहाल, अपनी चिप बनाना देश के लिए यकीनन गर्व का क्षण है, लेकिन वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

स्वतंत्र विदेश नीति की मिसाल

भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति उसके लिए लाभकारी स्थिति पैदा करती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिका से जुड़ना चाहता है और न ही चीन-रूस खेमे में बंद होना चाहता है। वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहता है।

तियानजिन में हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने एशिया की राजनीति को एक नया आयाम दिया है। यह सम्मेलन केवल बहुपक्षीय सहयोग का मंच नहीं था, बल्कि इसने भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को कुछ हद तक कम करने और दोनों को संवाद की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया। पिछले कुछ वर्षों से भारत-चीन संबंध गलवान की घटनाओं की छाया में उलझे हुए थे। सीमा पर हुए टकराव ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई, बल्कि अविश्वास भी गहरा कर दिया। इसके बावजूद तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी ने संकेत दिया कि दोनों देश अब भी रिश्तों को सामान्य बनाने के इच्छुक हैं और बहुपक्षीय मंचों का उपयोग इसी दिशा में किया जा सकता है।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपी-आईडीएसए

इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए नए व्यापारिक शुल्कों और संरक्षणवादी नीतियों ने वैश्विक आर्थिक ढांचे को झकझोर दिया है। इसके अलावा, यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सक्रियता ने चीन और रूस को करीब ला दिया है। ऐसे समय में भारत का इस मंच पर सक्रिय भागीदारी करना और संतुलित भूमिका निभाना अपने आप में रणनीतिक संदेश है। भारत एक ओर पश्चिमी देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर वह इस बात से भी अवगत है कि पड़ोसी देशों से कटकर वह अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता।

तियानजिन सम्मेलन में भारत और चीन, दोनों ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आपसी संवाद अनिवार्य है। बेशक सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे अब भी दोनों देशों के रिश्तों पर भारी हैं, लेकिन आर्थिक साझेदारी और वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा के लिए तालमेल आवश्यक है। भारत ने यह रेखांकित किया कि

आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ जैसी चुनौतियों का सामना केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। चीन ने भी इस पर जोर दिया कि सहयोग और साझेदारी ही एशिया की स्थिरता और समृद्धि की कुंजी है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक संदेश यह है कि भारत और चीन, दोनों अब टकराव से हटकर संवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसमें निश्चित ही रणनीतिक गणना भी शामिल है। चीन को यह भलीभांति पता है कि उसकी बेल्ट एंड रोड पहल और वैश्विक आर्थिक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकतीं, जब तक भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण बने रहेंगे। भारत भी यह समझता है कि एक ही समय में चीन और पाकिस्तान, दोनों से खुले टकराव की स्थिति में रहना उसकी दीर्घकालिक विदेश नीति और आर्थिक विकास लक्ष्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए भारत ऐसे अवसरों की तलाश में है, जहां वह अपने सुरक्षा हितों से समझौता किए बिना चीन से संवाद बनाए रख सके।

एससीओ की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संगठन भले ही अब तक नाटो जैसी सैन्य प्रभावशाली ताकत के रूप में उभर कर सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता इस बात में है कि यह एशिया के बड़े देशों को एक साझा मंच प्रदान करता है। ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर एससीओ के माध्यम से ठोस प्रगति की संभावना बनी रहती है। खासकर ऐसे समय में, जब पश्चिमी मंचों पर एशियाई देशों की आवाज अक्सर दब जाती है, एससीओ उन्हें अपने हितों को सामने रखने का अवसर देता है। इस सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि रूस और चीन, दोनों ने भारत की भागीदारी को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पश्चिमी दुनिया से लगभग कट चुका है। उसके लिए चीन तथा भारत जैसे साझेदारों का महत्व और भी बढ़ गया है। चीन भी नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह पश्चिमी खेमे की ओर झुक जाए। इस संदर्भ में भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति उसके लिए लाभकारी स्थिति पैदा करती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिका से जुड़ना चाहता है और न ही चीन-रूस खेमे में बंद होना चाहता है। वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखते हुए वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहता है।

उल्लेखनीय है कि भारत-चीन संबंधों में सुधार की संभावना केवल सम्मेलनों या औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि तमाम तनावों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2024 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यह बताता है कि व्यावहारिक धरातल पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए किसी भी बड़े राजनीतिक टकराव से दोनों को नुकसान होगा और यह बात दोनों की समझ में भी आती है। फिर भी, यह कहना जल्दबाजी होगी कि तियानजिन सम्मेलन ने भारत-चीन संबंधों को पूरी तरह सामान्य बना दिया है। सीमा विवाद, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति जैसे कई मुद्दे अब भी जटिल बने हुए हैं। यह जरूर कहा जा सकता है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को संवाद के एक ऐसे रास्ते पर ले गया है, जहां तनाव को कुछ हद तक कम किया जा सके और भविष्य में बेहतर संबंधों की संभावना बनी रहे।

दीर्घकालिक दृष्टि से देखें, तो भारत और चीन के बीच सहयोग की संभावना केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि बहुपक्षीय मंचों पर भी है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, खाद्य सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकियों के नियमन जैसे मुद्दों पर दोनों देशों का सहयोग वैश्विक दक्षिण को मजबूती दे सकता है। दोनों देश यह भी जानते हैं कि अगर वे आपसी टकराव में उलझे रहे, तो तीसरे पक्षों के लिए हस्तक्षेप करना और भी आसान हो जाएगा। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच एक न्यूनतम समझ बनाए रखना आवश्यक है। तियानजिन शिखर सम्मेलन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह सम्मेलन कोई चमत्कारिक समाधान लेकर नहीं आया, लेकिन इसने यह संदेश अवश्य दिया कि संवाद और सहयोग के रास्ते बंद नहीं हुए हैं।

भारत और चीन के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि वे अपने मतभेदों को बातचीत और धैर्य से सुलझाने की दिशा में कदम उठाएं। अगर ऐसा होता है, तो न केवल दक्षिण एशिया व पूर्वी एशिया, बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता और शांति को बढ़ावा मिलेगा। edit@amarujala.com

जीवन धारा

जे. कृष्णमूर्ति

दूसरों के बारे में बात करना स्वयं से पलायन है, चाहे वह खुशगवार हो या खराब, और पलायन ही बेचैनी का कारण है। यह प्रवृत्ति ही बेचैनी का सबब होती है। इससे बचने का तरीका खुद से परिचय करना है।

समझ और प्रसन्नता का विनाशक है बेचैन मन

गपशप में समय बिताने की वृत्ति और चिंताग्रस्त रहने की वृत्ति में कितनी विचित्र समानता है। दोनों एक ही बेचैन मन की उपज हैं। बेचैन मन को अभिव्यक्तियों और कार्यकलाप की सदा बदलती हुई विविधता चाहिए, इसे व्यस्त रहना जरूरी लगता है। इसे सदा बढ़ती हुई संवेदना, बदलती रुचियां चाहिए और गपशप में इस सब की सामग्री मिल जाती है। शप-शप में रमे रहने की यह वृत्ति उत्कटता और गांभीर्य से सर्वथा विपरीत है। दूसरों के बारे में बात करना स्वयं से पलायन है, चाहे वह खुशगवार हो या खराब, और पलायन ही बेचैनी का कारण है। पलायन की प्रवृत्ति ही बेचैन होती है। दूसरों के झमेलों में रुचि रखना अधिकतर लोगों को व्यस्त रखता प्रतीत होता है। चूंकि, हम इसको लेकर चिंतित रहते हैं कि औरों का हमारे बारे में क्या मत है, और हम उनके बारे में सब कुछ जानने को उत्सुक रहते हैं।

गपशप बेचैन मन की अभिव्यक्ति है, पर केवल चुप्पी साध लेना ही शांत मन का लक्षण नहीं है। शांति संयम या त्याग से अस्तित्व में नहीं आती, इसका आगमन तो 'जो है' की समझ के साथ होता है। 'जो है' को समझने के लिए तत्पर सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो है, वह स्थिर नहीं रहता। यदि हम चिंता न करते रहें, तो हमें लगता है कि हम जीवित ही नहीं हैं। हममें से अधिकांश के लिए किसी समस्या से जूझते रहना ही जीवित रहने का लक्षण है। समस्यारहित जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी समस्या में हम जितने अधिक उलझते हैं, उतना ही अधिक सतर्क हम खुद को समझते हैं। किसी समस्या में मन को सतत उलझाए रखने की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्या चिंता से समस्या हल हो जाने वाली है? या, समस्या का उत्तर तभी आता है, जब मन शांत हो। किंतु अधिकतर लोगों के लिए शांत मन भयप्रद होता है; वे शांत होने से भयभीत रहते हैं, क्योंकि कौन जाने उन्हें अपने विषय में क्या पता चल जाए, और चिंता उसे टालने का उपाय बन जाती है। जो मन कुछ पता चल जाने से डरा हुआ है, बराबर अपना रक्षण करना चाहता है; इसकी बेचैनी ही इसका रक्षण होती है।

गपशप की तरह ही चिंतातुर रहने में भी उत्कटता और गंभीरता का आभास पैदा होता है; किंतु यदि हम अधिक सूक्ष्मता से अवलोकन करें, तो दिखाई देने लगता है कि इस आभासी गंभीरता का जन्म आकर्षण से होता है, सच्चे सरोकार से नहीं। आकर्षण तो सदैव अस्थिर रहता है, और इसी कारण गपशप और चिंता का अंत केवल तभी हो सकता है, जब मन की इस बेचैनी को समझ लिया जाए। सिर्फ संयम, नियंत्रण या अनुशासन से शांति का जन्म नहीं होगा, बल्कि इनके कारण तो मन कुंद हो जाता है, असंवेदनशील और सीमित बन जाता है। अनुमान-अटकल, कुतूहल की तरह ही बेचैनी का परिचायक है। एक बेचैन मन, वह चाहे जितना प्रतिभाशाली हो, समझ और प्रसन्नता का विनाशक ही है।

उलझनों से बचें

सूत्र

हमारे मन के ऊपर की जो ज्ञात परतें हैं, उन पर सतत तनाव पड़ते रहने से, आदत के कारण और परिस्थितियों के दबाव से वे उद्वेलित और बेचैन बन गई हैं। जीवन की समझ का आधार अपने आप से परिचय करना है। जब तक हम दूसरों के झमेलों में पड़े रहेंगे, तब तक हमारा बेचैन मन शांत नहीं होगा। इसलिए इनसे बचना जरूरी है।

दूसरा पहलू

क्लीसनर वॉल स्ट्रीट की नौकरी में करोड़ों डॉलर कमा चुके थे, पर दूसरों की जिंदगी की खातिर उन्होंने अलग ही रास्ता चुन लिया।

जीवन जोखिम में डालकर लोगों को बचाने का सुख

एक महिला मेट्रो की सीढ़ियों पर गिरी पड़ी थी, जोनाथन क्लीसनर ने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, 'हम यहां आपकी मदद के लिए आए हैं, बताइए क्या हुआ?' किसी ने 911 पर सूचना दी थी कि मेट्रो स्टेशन पर एक महिला गिरी पड़ी है। थोड़ी देर बाद उस महिला को होश आया और उसने देखा कि उसके सामने नीली वर्दी पहने एक दुबला पतला-सा व्यक्ति खड़ा था। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और यह बुदबुदाते हुए चली गई कि वह ठीक है। उसे नहीं पता था कि वह देश के श्रेष्ठ प्रशिक्षित चिकित्सा सहायक से दूर जा रही है।

क्रिस्टोफर माग

एक करोड़पति से पैरामेडिक (चिकित्सा सहायक) बनने का जोनाथन क्लीसनर का सफर 13 वर्ष पहले शुरू हुआ था।

क्लीसनर के लिए यह मामला कोई चुनौती भरा नहीं था, लेकिन यह वॉल स्ट्रीट में उनकी पुरानी नौकरी से जरूर बेहतर था। उन्होंने सामान समेटते हुए साथियों से कहा, 'हमें इस तरह के बेकार कॉल खूब आते हैं, लेकिन हमारी रोजी-रोटी बड़े हादसों जैसे- ट्रेन से कटने से चलती है।' एक करोड़पति से पैरामेडिक (चिकित्सा सहायक) बनने का क्लीसनर का सफर 13 वर्ष पहले शुरू हुआ था। वह कमोडिटी ट्रेडर के रूप में वॉल स्ट्रीट में काम करते थे और उन्हें 32,000 डॉलर वेतन मिलता था। अभी उनका मासिक वेतन करीब 1,10,000 डॉलर होता। लोग उनसे कहते हैं कि एक घंटे के 18 डॉलर के लिए अपना जीवन क्यों खतरे में डाल रहे हो, लेकिन क्लीसनर के मन में लोगों को बचाने की धुन सवार है।

2008 में वह माउंट रेनियर की चोटी घूमने गए थे। बर्फीले तूफान में एक महिला का घुटना फट गया। तब किसी ने कहा, 'इस तरह की चोटियों पर आने के लिए चिकित्सकीय प्रशिक्षण लेना जरूरी है।'

2008 में वह एक समूह के साथ माउंट रेनियर की चोटी घूमने गए थे, उसी दौरान बर्फीले तूफान में एक महिला का घुटना फट गया। तब किसी ने कहा, 'इस तरह की चोटियों पर आने के लिए चिकित्सकीय प्रशिक्षण लेना जरूरी है।' उन्होंने न्यूयॉर्क लौटते ही आपातकालीन चिकित्सा सहायक का काम सीखा। फिर अग्निशमन विभाग ने पैरामेडिक्स अकादमी में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर वह लोगों को बचाने की खातिर फायर डिपार्टमेंट में शामिल हो गए। अभी 4,500 आपातकाल चिकित्साकर्मियों में से क्लीसनर चुनिंदा 60 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें आग से लोगों को बचाने, मेट्रो कारों के नीचे फंसे लोगों को निकालने, घायलों की मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। वह अन्य बचाव चिकित्सा दलों को भी प्रशिक्षण देते हैं। यही नहीं, वह छुट्टियों और शिफ्ट की चिंता किए बिना बड़े-बड़े हादसों में अपने जीवन को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में सबसे आगे रहते हैं।

©The New York Times 2025

आंकड़े

फेसबुक यूजर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है तो मूल रूप से अमेरिका का, लेकिन अन्य देशों की तुलना में उसके सबसे ज्यादा यूजर भारत में हैं।

भारत	58.2
अमेरिका	28.0
इंडोनेशिया	20.2
ब्राजील	11.3
मेक्सिको	9.2

आंकड़े फेसबुक यूजर्स की संख्या के, करोड़ में | स्रोत : Statista, 2025

एक सज्जन मूर्ति और शालिग्राम में भेद करते थे। श्रीवल्लभाचार्य जी ने उन्हें समझाया कि भगवद्-विग्रह में इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

भक्ति में भेदभाव ठीक नहीं

आचार्यपाद श्रीवल्लभाचार्य जी ग्यारह वर्ष की उम्र में अध्ययन समाप्त करने के बाद तीर्थाटन के लिए रवाना हुए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर वहां बड़े-बड़े विद्वानों को शास्त्रों में हराया। वहीं पर उन्हें वैष्णवाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। बताया जाता है कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने की इच्छा व्यक्त की। श्री विट्ठल के रूप में विट्ठल भगवान को उन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया।

श्रीवल्लभाचार्य जी के संबंध में भक्ति-भाव बढ़ाने वाली कई कथाएं हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं मूर्ति, दोनों की एकसाथ पूजा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में भेदभाव था। वह शिला को अच्छी और मूर्ति को निम्न श्रेणी की समझते थे। श्रीवल्लभाचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवद्-विग्रह में इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस पर वह सज्जन बिगड़ गए और अकड़कर मूर्ति के सीने पर रात में शालिग्राम को रखकर चले गए।

अंतर्यात्रा
संकलित

सुबह देखने पर मालूम हुआ कि शालिग्राम की शिला चूर-चूर हो गई है। तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने श्रीवल्लभाचार्य जी से क्षमा मांगी। फिर श्रीवल्लभाचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने के लिए कहा, ऐसा करते ही शिला फिर ज्यों-की त्यों हो गई। इसके बाद उन्हें समझ आ गया कि भक्ति मार्ग में इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 04 सितंबर, 1952

पाकिस्तान में कश्मीर पर हमला करने की गुप्त तैयारियां

पाकिस्तान में कश्मीर पर हमला करने की गुप्त तैयारियां

अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करने की गुप्त तैयारियां कर रहा है। यह हमला कबाइली लोगों द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय रूपांतरण का लॉन्चपैड

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.16 करोड़ खाते खुल चुके हैं। बीते 11 साल में यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है।

दिलीप अस्बे | आर्थिकी

अगस्त, 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) 11 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है। अगस्त 2025 तक इसके तहत 55.16 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं और कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

पीएमजेडीवाई ने न केवल बहुत से लोगों को बैंकिंग तक पहुंच प्रदान की है, बल्कि इसने देश के विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, डिजिटल वित्तीय ईकोसिस्टम की नींव भी रखी है। इस दायरे को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्रमुखता से बढ़ाया है, जिनकी कुल खातों (43.56 करोड़) और जमा राशि (2.08 लाख करोड़ रुपये) में लगभग 78 प्रतिशत हिस्सेदारी है। 10.57 करोड़ खातों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी इसमें योगदान दिया है, जिनके पास 51,000 करोड़ रुपये से अधिक की शेष राशि है। यह भारत के दुर्गम क्षेत्रों में भी औपचारिक बैंकिंग में विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।

सरकार ने निष्क्रिय खातों को फिर से प्रचलन में लाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पुनः केवाईसी और पुनः

सक्रियण अभियान (जुलाई-सितंबर 2025) आरंभ किया है। वित्त मंत्रालय की निगरानी में 'खोले गए खातों' से 'सार्थक रूप से उपयोग किए गए खातों' की ओर यह परिवर्तन पीएमजेडीवाई के अगले चरण को परिभाषित करेगा और इसके प्रभाव को प्रतीकात्मक समावेशन से स्थायी सशक्तीकरण की ओर ले जाएगा। जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी (जेएएम ट्रिनिटी) ने भारत के आर्थिक ईकोसिस्टम में क्रांति ला दी है। आज, 99 प्रतिशत वयस्कों के पास बायोमेट्रिक आईडी है, जिससे बैंक खाते खोलना सरल हो गया है और तत्काल डिजिटल भुगतान की नींव रखी गई है। लगभग 67 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण हैं, जो 36.6 करोड़ से अधिक बैंक खातों के बराबर हैं।

इतना ही नहीं, 55 प्रतिशत से अधिक खातों के साथ पीएमजेडीवाई ने वित्तीय समावेशन को वास्तव में जेंडर-समावेशी बना दिया है। ये खाते पेंशन से लेकर मनरेगा मजदूरी और पीएम-किसान सब्सिडी से लेकर उज्ज्वला हस्तांतरणों तक सरकारी लाभों के लिए वितरण का माध्यम बन गए हैं। जन धन के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) ने लीकेज और बिचौलियों को समाप्त कर दिया है, जिससे सीधे लाभार्थियों के हाथों में तत्काल पैसा पहुंचाया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापता है, वर्ष 2025 में बढ़कर 67 हो गया, जो वर्ष 2021 की तुलना में 24.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह निरंतर प्रगति ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान ईकोसिस्टम के विस्तार, लक्षित सरकारी योजनाओं और मजबूत बैंकिंग पहुंच के प्रभाव को रेखांकित करती है। जन धन खाताधारकों को अगस्त 2025 तक 38.6 करोड़ से अधिक रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

पीएमजेडीवाई ने 'खाते खोलने' से हटकर सक्रिय, डिजिटल रूप से सशक्त उपयोगकर्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अनौपचारिक नकदी रखने के बजाय ग्रामीण परिवारों के पास अब बिचौलियों के बिना सरकारी योजनाओं तक पहुंच और औपचारिक बचत चैनल हैं। साथ ही, ऐसे डिजिटल टूल हैं, जो महिलाओं को धन पर अधिक नियंत्रण, त्वरित राहत और कोविड जैसी घटनाओं के दौरान अधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म-व्यवसाय और किसान अब दैनिक लेनदेन को डिजिटल रूप से प्रबंधित कर सकते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं और औपचारिक ऋण तक अधिक सुगमता से पहुंच सकते हैं। इससे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम होती है और आर्थिक लचीलापन बढ़ता है।

जन धन योजना में निरंतर और सकारात्मक प्रभाव बनाए रखने के लिए कई क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, डिजिटल साक्षरता को और विस्तारित किया जाना चाहिए, जिससे कि हर खाताधारक इनका आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सके। दूसरा, दूरदराज के गांवों में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाना चाहिए, ताकि हर कोने तक रीयल-टाइम भुगतान पहुंच सके। तीसरा, वह दिन दूर नहीं, जब हर घर में एक स्मार्ट फोन होगा, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट एक्सेस करने, यूपीआई और अन्य डिजिटल सिस्टम का उपयोग करने के लिए किया जाएगा और नकदी पर निर्भरता कम होगी।

स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना केवल एक सरकारी योजना भर नहीं है, बल्कि भारत के वित्तीय रूपांतरण का लॉन्चपैड है। रुपे कार्ड, एईपीएस ने द्वार खोले, यूपीआई ने बाजार को हर किसी की अंगुलियों पर ला दिया और साथ मिलकर, यह 'ट्रिनिटी' भारत के बैंकिंग, भुगतान और विकास के तरीके को नया रूप दे रही है और साथ ही आगे भी बढ़ रही है।

-लेखक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

क्या फिर शीतयुद्ध

दुनिया में क्या शीतयुद्ध-2 की शुरुआत हो गई है? यह फिर दो ध्रुवों पर दिख रही है और दोनों के बीच परस्पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यह ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की चीन में मेजबानी को लेकर शी जिनपिंग की आलोचना की है। स्वभाव से कुछ ज्यादा ही मुखर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने चीनी नेता को संबोधित करते हुए कटाक्ष किया है कि वह रूस और उत्तर कोरिया के नेता के प्रति 'हार्दिक सम्मान' प्रकट करें। हालांकि, इसका जवाब रूस ने यह कहकर दिया है कि चीन में वैश्विक नेताओं का समागम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। लगभग यही बात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तियानजिन में बोल चुके हैं। तियानजिन की बैठक को ट्रंप सकारात्मक ढंग से ही ले, तो अच्छा है। दुनिया अगर किसी दूसरे ध्रुव की ओर झुकती लग रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले ध्रुव के खिलाफ साजिश रची जा रही है।

हां, खुद को पहला या अकेला ध्रुव मानने वाले अमेरिका को अवश्य यह विचार करना चाहिए कि वह दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को कैसे साथ लेकर चल सकता है। जब वह दुनिया के ज्यादातर देशों को साथ लेकर चल रहा था, तब ज्यादा मजबूत था। इसमें कोई दोराय नहीं है कि आज चीन की जो तरक्की हुई है, उसमें अमेरिकी तकनीक व उसके प्रयोगों का भारी योगदान है। आज जब चीन दुनिया का एक बड़ा विनिर्माता बन चुका है, तब यह बात अमेरिका को चुभ रही है। टैरिफ की पूरी लड़ाई एक तरह से चीन से ही शुरू हुई थी, पर ट्रंप ने इसे इतना विस्तार दे दिया है कि इसको समेटने में बहुत वक्त लगेगा। खुद अमेरिकी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अनेक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दशकों से जो मेहनत की थी, ट्रंप ने सब पर पानी फेर दिया है। ऐसे में, चीन के सामरिक साजो-सामान के प्रदर्शन पर सबकी निगाह गई है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी चौंकाती नहीं है, पर वहां किम जोंग उन के होने से चिंता है। दुनिया बदल रही है और सारे बदलाव विश्व शांति के पक्ष में नहीं हैं। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा सामरिक प्रदर्शन है, जिसमें उसके करीबी वैश्विक नेताओं की मौजूदगी साफ संदेश है कि चीन बदलती दुनिया में नेतृत्व के लिए पूरी तरह तैयार है।

स्वभाव से कुछ ज्यादा ही मुखर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के विशाल सामरिक प्रदर्शन के बाद उस पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है।

दुनिया के इस बदलते समीकरण को समझने में डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो रहे हैं और उन्होंने फिर कहा है, 'भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर कई वर्षों से यह एकतरफा रिश्ता है।' अच्छे संबंधों को केवल टैरिफ तक घटाकर देखना अमेरिका के लिए नुकसानदायक है। ट्रंप प्रशासन टैरिफ को लेकर ही नहीं, बल्कि भारत के साथ समग्र संबंध को लेकर प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। अस्थिर पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी अलग प्रकार से भारत को चिंतित कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीतयुद्ध शुरू हुआ था, तब भी भारत दोनों ध्रुवों से अलग अपनी गुटनिरपेक्षता लिए मजबूती से खड़ा था। चीन का विशाल सामरिक प्रदर्शन अगर द्वितीय शीतयुद्ध का आगाज है, तो भारत कहां खड़ा होगा? हमारी नीति कहती है कि हमें युद्ध के विरुद्ध खड़ा होना है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है, अमेरिका हमारे साथ कुछ वैसे ही खड़ा हो, जैसे रूस खड़ा है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
04 सितम्बर, 1950

फारमोसा का प्रश्न

गत साल रूसी प्रतिनिधि के सुरक्षा परिषद लौटने का परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से अच्छा ही निकला है, क्योंकि सुविज्ञ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में अब यह आशा प्रकट की जाने लगी है कि कोरियाई युद्ध तुरन्त विश्व-युद्ध का रूप धारण न करेगा। किन्तु कोरियाई युद्ध के साथ अब फारमोसा के प्रश्न की जो चर्चा चल पड़ी है, उससे यह आशंका उत्पन होने लगी है कि कहीं चीन की साम्यवादी सरकार की अमरीका से टक्कर न हो जाये। कोरिया, फारमोसा तथा मंचूरिया पर कथित अमरीकी बमवर्षा के प्रश्न सुरक्षा परिषद के सामने विचारणीय विषय हैं। इसमें तो सन्देह ही नहीं कि इन सब सवालों पर भयंकर वाग्युद्ध होगा, पर सुरक्षा परिषद के निर्णयों की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर विश्व-शान्ति का भविष्य बहुत-कुछ निर्भर है।

यह एक शुभ लक्षण है कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का अपना कार्यकाल पूरा करने पर भी श्री जेकब मलिक अभी उसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन अभी उनको अपना एक विशेष उद्देश्य पूरा करना है। कोरिया में अमरीकी कार्रवाई को आक्रमणात्मक कार्रवाई सिद्ध करने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक का पसीना एक किया और इसमें पूरा एक महीना लगा दिया। अब वह फारमोसा के सवाल पर तथा कोरिया-मंचूरिया की सीमा पर कथित अमरीकी बमवर्षा के मामले पर और भी जोरों से अमरीका को आक्रमणकारी देश सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। इस संबंध में पेकिंग सरकार ने सुरक्षा परिषद के गत मास के अध्यक्ष श्री जेकब मलिक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री श्री त्रिग्वेली के पास अपनी शिकायत भेजी थी। अतः इसमें अधिक सन्देह नहीं कि अभियोग की सुनवाई के लिए पेकिंग सरकार का प्रतिनिधि बुलाया जायेगा और इस स्थिति में उसकी सहायता के लिए रूसी प्रतिनिधि का सुरक्षा परिषद में रहना आवश्यक है।

अब ब्रिटिश प्रतिनिधि सर ग्लैडवीन जेब की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है, किन्तु इससे दोनों पक्षों के तौर-तरीकों तथा उनकी मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया है। नये अध्यक्ष ने कार्यभार संभालते ही 25 जून के निर्णयानुसार दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि को सुरक्षा परिषद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और उसने अपना स्थान ग्रहण किया। इस पर श्री मलिक ने ग्लैडवीन के निर्णय को चुनौती दी...।

बारिश और बाढ़ से हम बार-बार बेहाल

यहां स्कैन करें

के जे रमेश | पूर्व निदेशक, भारतीय मौसम विभाग

लोगों को बताना चाहिए कि कितनी देर में, कितने समय तक और किन-किन इलाकों में बारिश होने वाली है। उन्हें वैकल्पिक रास्तों की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।

उत्तर और पश्चिम भारत इन दिनों लगातार बारिश और बाढ़ से हलकान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब जैसे तमाम राज्यों में यह चौथा हफ्ता है, जब सामान्य से अधिक बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी दो दिन और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है।

आखिर इतनी अधिक बरसात क्यों हो रही है? मौसम विभाग दो बार मानसून को लेकर आकलन जारी करता है- पहली बार अप्रैल में और दूसरी बार पूर्व के आंकड़ों में सुधार करते हुए मई में। इस साल दोनों ही बार मौसम विभाग ने सामान्य से 104 से 106 प्रतिशत अधिक पानी बरसने का अनुमान लगाया था। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि भारत में मानसूनी बारिश की वजह बनने वाली दोनों प्रणालियां (एक, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र व दूसरा, प्रशांत महासागर से उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का गुजरना) सक्रिय हैं। नतीजतन, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, यहां तक कि उत्तरी पाकिस्तान तक अत्यधिक बारिश का सिलसिला जारी है।

इस साल उत्तर भारत की नदियों में स्थानीय स्तर पर हो रही बारिश का पानी तो समा ही रहा, ऊपर पश्चिमी तिब्बत के हिस्सों में भी बादल खूब बरस रहे हैं, जहां सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। इस कारण सिंधु नदी प्रणाली में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गंगा और यमुना की सहायक नदियों का भी यही हाल है। अब तो निम्न दबाव के क्षेत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने से गुजरात और राजस्थान जैसे इलाके भी मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। इतना ही नहीं, 8 और 9 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। वह भी खूब बरसेगा। इसका अर्थ है कि अगले कुछ दिन हमें राहत नहीं मिलने वाली।

दिक्कत यह है कि 'ग्लोबल वार्मिंग' का भी इसे साथ मिल रहा है। इसकी वजह से बारिश की आवृत्ति

और तीव्रता बढ़ गई है। दरअसल, वैश्विक गर्मी में यदि एक फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो वायुमंडल में नमी सोखने की दर सात फीसदी तक बढ़ जाती है। अभी ग्लोबल वार्मिंग डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी है, जिसका अर्थ है कि आबोहवा की जल थामने की क्षमता पहले से ही 10 प्रतिशत बढ़ चुकी है। इस पर मुश्किल यह कि हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में दो से तीन डिग्री तक गर्मी बढ़ चुकी है, जिसका अर्थ है, वहां हवा में नमी 15-20 प्रतिशत बढ़ चुकी है। यही नमी बेहिसाब बारिश की वजह बन रही है और कभी-कभी बादल फटने के रूप में सामने आ रही है।

पहाड़ों पर अनियोजित विकास से नुकसान कहीं अधिक बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को चोट पहुंचाने, जल-विद्युत परियोजनाओं पर जोर देने, जलग्रहण क्षेत्र बनाने, खनन, निर्माण-कार्यों में विस्फोटकों के इस्तेमाल आदि से यहां के पहाड़ लगातार कमजोर हो रहे हैं। इस कारण तेज बारिश होते ही भू-स्खलन होने लगता है। पिछले तीन-चार वर्षों से ये नुकसान बढ़े हैं, फिर भी हम जरूरी उपाय नहीं कर रहे, जिसके कारण जान-माल की हानि हर साल की कहानी बनने लगी है।

वैसे, मुश्किलें मैदानी इलाकों में भी कम नहीं हैं। गुरुग्राम में महाजाम की खबर तो दो दिन तक सुर्खियों में थी। मैदानी इलाकों में जलभराव बड़ी समस्या बनकर सामने आता है और पांच सेंटीमीटर बारिश भी सड़कों को पूरी तरह डूबो देती है। चूंकि जल-निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था बहुमंजिली इमारतों की भेंट चढ़ चुकी है, इसलिए बारिश होते ही जलभराव और सड़कों पर जाम भारतीय शहरों की नियति बन चुकी है।

कुछ लोग सवाल करते हैं कि केरल आते और जाते, दोनों मानसून से खूब भीगता है, मगर वहां से ऐसी खबरें क्यों नहीं आतीं? इसकी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है। केरल पश्चिमी घाट पर स्थित है, इसलिए वहां से पानी तुरंत निकल जाता है। हालांकि, साल 2018 में वहां भी अचानक बाढ़ आई थी, लेकिन उसका कारक जलाशयों में रोके गए पानी को अचानक छोड़ना था। उस घटना के बाद से ही इस राज्य ने फूंक-फूंककर कदम बढ़ाए हैं। अब वहां अचानक पानी नहीं छोड़ा जाता, बल्कि धीमे-धीमे ऐसा किया जाता है, ताकि पानी का दबाव शहरों पर न पड़े।

आखिर इसका समाधान है क्या? धराली के हादसे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल, एक महीने पहले उत्तराखंड के इस इलाके में बादल फटने की घटना हुई और खीर गंगा नदी में ऐसा सैलाब उठा कि सब कुछ तहस-नहस हो गया। चूंकि, इस नदी में बीते चार-पांच दशकों से पानी नहीं आया था, इसलिए इसकी पेटी में ही तमाम निर्माण-कार्य कर लिए गए थे। वहां अच्छा-खासा बाजार बसा दिया गया था। जबकि, यह 'रिस्क जोन' था। इसका नतीजा यह निकला कि जब यह नदी उफनकर बहने लगी, तो अपने साथ सबको बहा ले गई।

कहने का अर्थ है कि यदि हम निर्माण-कार्य पर बल देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वहां के खतरे का गहराई से आकलन करना चाहिए। लोगों को 'खतरे का स्तर' बताना जरूरी है, ताकि वे सजग रह सकें। 'रिस्क जोन' बताने से मुमकिन है कि वित्तीय संस्थाएं ऐसे इलाकों में कर्ज देने से परहेज बरतें, जिससे यहां पर निर्माण-कार्य खुद-ब-खुद हतोत्साहित होगा। फिर भी, यदि कुछ लोग यहां निर्माण करते हैं, तो पूर्व-चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाकर उन्हें बताना होगा कि खतरे के समय वे कैसे सुरक्षित बाहर निकलें, ताकि जान-माल की हानि न हो।

मैदानी इलाकों में इससे इतर व्यवस्था करनी होगी। वहां तकनीक का इस्तेमाल लोगों तक सही-सही सूचना पहुंचाने में करना होगा। उन्हें बताना चाहिए कि कितनी देर में, कितने समय तक और किन-किन इलाकों में बारिश होने वाली है। उन्हें वैकल्पिक रास्तों की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। भीड़ का प्रबंधन संबंधित विभागों को सिखाना होगा। झील, जल-निकासी मार्ग और अन्य सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की निगरानी और रोकथाम के उपाय भी करने होंगे। कुछ इलाकों में प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। मसलन, हैदराबाद में 'हाइड्रा एजेंसी' अतिक्रमण की स्थिति, बंद जल-निकासी की जानकारी देने के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर सुगम यातायात की सूचनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस तरह की व्यवस्था महानगरों अथवा बड़े नगरों में महाजाम की समस्या का समाधान कर सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हमारी तकनीकी महारत की मिसाल सेमीकंडक्टर

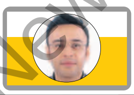

यहां स्कैन करें

प्रवीण कौशल | तकनीक और सामाजिक उद्यमी

बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 'विक्रम-32' सौंपी गई। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आकांक्षाओं का ऐतिहासिक मोड़ भी है। भारत अब डिजाइन और सॉफ्टवेयर में ही नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण की वैश्विक दौड़ में भी नेतृत्व करने को तैयार है।

भारत ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में दशकों से बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी यह भूमिका डिजाइन और सॉफ्टवेयर तैयार करने तक सीमित रही। दुनिया की हर बड़ी चिप कंपनी, इंटेल से लेकर क्वालकॉम तक के डिजाइन केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा में मौजूद हैं। आईआईटी और अन्य शीर्ष संस्थानों से निकले हजारों भारतीय इंजीनियर इनमें अगली पीढ़ी की चिप डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अब तक इनका निर्माण ताइवान, दक्षिण कोरिया या अमेरिका में होता था। विक्रम-32 के निर्माण ने इस कहानी को अब बदल दिया है। भारत अब चिप उत्पादन की पूरी शृंखला में आत्मनिर्भर बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह कामयाबी इतनी अहम क्यों है? सेमीकंडक्टर डिजिटल युग की रीढ़ हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा प्रणाली, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई सब इन्हीं चिप पर आधारित हैं। जिन देशों का चिपों पर नियंत्रण है, उनकी आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा व राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़त है। कोविड काल में चिप की कमी ने यह साफ कर दिया था कि इसके आयात पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है।

स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम-32 की सफलता ने साफ कर दिया है कि भारत अब वैश्विक प्रौद्योगिकी शृंखला का नेता बनेगा।

हमारी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर-निर्माण में आत्मनिर्भरता विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। भारत के पास तीन बड़ी ताकत हमेशा से रही है। एक, प्रतिभा। दुनिया के सबसे बड़े 'स्टेम स्नातक' भारत से निकलते हैं। आईआईटी, आईआईएससी और एनआईटी जैसे संस्थान इस क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी शक्ति है बाजार। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग लगातार बढ़ रही है। और तीसरी ताकत है नीतिगत समर्थन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत केंद्र और राज्य सरकारें चिप निर्माण, पैकेजिंग और शोध एवं विकास में हजारों करोड़ रुपये का निवेश कर रही हैं।

भारत के सामने दो चुनौती थी- बड़े पैमाने पर निर्माण अवसंरचना और उद्योग-अकादमिक सहयोग। पहली कमी गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नए फैब्स से पूरी की जा रही है, तो दूसरी कमी को आईडीएसपीएस इंडस्ट्री कंसोर्टियम जैसी पहल से दूर किया जा रहा है, जहां 50 से भी अधिक वैश्विक कंपनियां व शीर्ष शैक्षणिक संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं।

सेमीकंडक्टर उद्योग देश में रोजगार सृजन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा, क्योंकि हरेक फैब्रिकेशन प्लांट (फैब्स) हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करते हैं। पैकेजिंग और जांच कंपनियों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र और आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिलती है। फिर चिप डिजाइन स्टार्टअप नए बौद्धिक संपदा बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से भारत रणनीतिक स्वायत्तता हासिल कर सकेगा।

विक्रम-32 पहला कदम है। असली काम अभी बाकी है। इस दशक के अंत तक तीन-चार वाणिज्यिक फैब्स शुरू करने होंगे। हमें एक लाख से अधिक विशेषज्ञ तैयार करने होंगे। पैकेजिंग व सिस्टम इंटीग्रेशन पर विशेष ध्यान देना होगा, जहां भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ सकता है। स्टार्टअप को और बढ़ावा देना होगा, ताकि देशी चिप बनाई जा सके।

इस सफलता ने साफ कर दिया है कि भारत अब वैश्विक प्रौद्योगिकी शृंखला में केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा, वह निर्माता और नेता भी बनेगा। हमारे पास दृष्टि है, अपार प्रतिभाएं हैं और अब अवसर भी हैं। जरूरत है, तो केवल ठोस क्रियान्वयन की। यह तो निर्विवाद है कि भविष्य की दुनिया, यानी डिजिटल दुनिया सिलिकॉन पर खड़ी होगी और विक्रम-32 के साथ भारत ने पहली पंक्ति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अधिकार जताना प्रेम नहीं

प्रेम लक्ष्य है, पर उस तक पहुंचने का साधन भी प्रिय होना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग पर प्रसन्न रहो- साधन से प्रसन्न रहो, साधन को प्रेम करो। जहां कोई प्रयत्न नहीं होता, जब क्रियाशीलता का ज्वर नहीं, तुम प्रयासहीन होते हो, तब प्रेम सहज उमड़ता है।

प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन इसको अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया में प्रायः तुम विषय-वस्तु में उलझ जाते हो, और ऐसा तब होता है, जब तुम्हारी दृष्टि बाहर अटकी है। अपने मूल स्वरूप में वापस आने के लिए तुम्हें आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता है।

याद रखो, पीड़ा प्रथम अंतर्दृष्टि है। यह तुम्हें विषय-वस्तु से परे ले जाकर शरीर और मन की ओर मोड़ती है। ऊर्जा दूसरी अंतर्दृष्टि है। इसका तीव्र झोंका तुम्हें वापस आत्मा की ओर लाता है। दिव्य प्रेम तीसरी अंतर्दृष्टि है। दिव्य प्रेम की एक झलक संपूर्णता लाती है और यह सभी सांसारिक सुखों को तुच्छ बना देती है। समाधि चतुर्थ अंतर्दृष्टि है, यानी वह स्थिति, जिसमें चेतना के उत्थान के साथ भौतिक वास्तविकता के प्रति आंशिक सजगता भी होती है। अद्वैत के प्रति सजगता पांचवीं अंतर्दृष्टि है, अर्थात यह बोध कि सब कुछ एक से बना है।

प्रेम सबके वश की बात नहीं। केवल वही मनुष्य सच्चा प्रेम कर सकता है, जिसने त्याग किया है। जिस मात्रा में तुम त्याग करते हो, वही प्रेम करने की तुम्हारी क्षमता है। प्रायः लोग सोचते हैं कि वैरागी प्रेम नहीं कर सकते और जो प्रेम करते हैं, वे त्याग नहीं कर सकते। इसका कारण है कि तथाकथित वैरागी प्रेमी नहीं प्रतीत होते और जो प्रेमी हैं, वे बहुत अधिकार जमाते हैं और बेबस होते हैं। वास्तव में, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताता; यह स्वतंत्रता लाता है, वैराग्य भी कुछ और नहीं, स्वतंत्रता ही है। केवल स्वतंत्रता में ही प्रेम पूरी तरह खिल सकता है। प्रेम में तुम कहते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए। वैराग्य यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुक्त हूं।

प्रेम में और कोई इच्छा नहीं। वैराग्य में कोई इच्छा ही नहीं। प्रेम और वैराग्य, विपरीत प्रतीत होते हुए भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल वैराग्य ही प्रेम और खुशी को कायम रख सकता है। वैराग्य के बिना प्रेम दुख, आधिपत्य, ईर्ष्या और क्रोध में बदल जाता है। वैराग्य तृप्ति लाता है और तृप्ति प्रेम का पोषण करती है। वैराग्य के बिना व्यक्ति असंतुष्ट, हताश, दुखी, भयभीत, शक्की और विवादी हो जाता है और फिर वही पुराना नाटक शुरू हो जाता है।

केवल स्वतंत्रता में ही प्रेम पूरी तरह खिल सकता है। प्रेम में तुम कहते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए। वैराग्य यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुक्त हूं।

तथाकथित वैरागी जीवन से कुंठित और निराश होकर भागे हुए लोग हैं। वास्तविक वैराग्य तो ज्ञान और प्रज्ञा से उत्पन्न होता है- काल और स्थान के आधार पर, इस विशाल ब्रह्मांड से अनुभव में मिले जीवन के ज्ञान से।

श्री श्री रविशंकर

जे डी वेंस | उपराष्ट्रपति, अमेरिका

हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा दिल टूटा हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारी सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर रहस्यमय ढंग से काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

भविष्य में सेमीकंडक्टर हमारी ताकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'सेमीकॉन इंडिया-2025' के मंच से भारत ने तकनीक की दुनिया में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की पहली स्वदेशी 'विक्रम 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप' प्रधानमंत्री को भेंट की। इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में विकसित इस प्रोसेसर का इस्तेमाल विपरीत हालात में रॉकेट लॉन्चिंग में होगा। साफ है, भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। यह उपलब्धि केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मवशिवास और नवाचार का प्रतीक है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है, जिसने भारत को उपभोक्ता से निर्माता और अब तकनीकी नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर अग्रसर किया है।

लुम्बाराम चौधरी, टिप्पणीकार

इलेक्ट्रॉनिक चिप के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है। सेमीकॉन इंडिया में स्वदेशी सेमीकंडक्टर का प्रदर्शन इस मंजिल की महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे दुनिया का विश्वास भारत पर बढ़ेगा। मुमकिन है कि कई देश अब भारत के साथ सेमीकंडक्टर को विकसित करने के लिए आगे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेमीकॉन इंडिया' का उद्घाटन करते हुए उचित ही कहा कि भारत लगातार सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। भारत में निर्मित इस छोटे चिप में 21वीं सदी की शक्ति समाहित है। अगर हम सफल रहे, तो निस्संदेह भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। यह करना जरूरी है, जिसे सरकार भी बखूबी समझ रही है। यही कारण है कि इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधियों को भरपूर मौका दिया गया। इससे एक अनुकूल माहौल का निर्माण होगा, जिसका हमें खूब फायदा मिलेगा। सेमीकॉन इंडिया-2025 का मुख्य उद्देश्य भारत को चिप बनाने के मामले में दुनिया भर में स्थापित करना है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से नई तकनीक, पैसा लगाने के मौके, नए स्टार्टअप और सरकारी नीतियों पर चर्चा हुई। इसके नतीजे हमें आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे। भारत अब तक चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। चूंकि आने वाले दिन तकनीकी तरक्की के हैं, यानी जो देश तकनीक के मामले में जितना संपन्न होगा, उसके आगे बढ़ने की संभावना उतनी अधिक होगी, इसीलिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर बनाना जरूरी था। अच्छी बात है कि हम ऐसा करने में सफल रहे हैं। उम्मीद है, यह गति आगे भी बनी रहेगी और सेमीकंडक्टर निर्माण के मामले में कोई दूसरा देश हमारा हाथ शायद ही पकड़ सकेगा।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
स्वदेशी सेमीकंडक्टर

सही नीति और निवेश की चुनौती कायम

सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को महाशक्ति बनाने का आह्वान किया गया है। मगर क्या भारत आज निर्यात पर इतना निर्भर नहीं है कि वह अपने बूते आत्मनिर्भर नहीं बन सकता? बेशक, प्रधानमंत्री की मंशा ठीक है और हर कोई यही चाहता है कि भारत दुनिया में सिरमौर बने, लेकिन इसके लिए जरूरी नीति और निवेश की चुनौती बनी हुई है। आज भी अनुसंधान और विकास पर अपने देश में ज्यादा रकम खर्च नहीं की जाती। यह भारत के लिए ठीक नहीं, वह भी तब, जब हम दुनिया भर में अपनी सेवा देने के लिए जाने जाते हैं। अगर वाकई भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो उसे न केवल नीतिगत प्रयास करने होंगे, बल्कि अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने होंगे। विडंबना यह है कि सरकार तो सरकार, निजी संस्थाएं भी इस ओर अग्रसर नहीं दिखतीं, जिस कारण हमारी कई परियोजनाएं समय-पूर्व दम तोड़ देती हैं। यह समझना होगा कि बिना नवाचार और अनुसंधान के हम चीन की चुनौती का सामना नहीं कर सकते। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को इस दिशा में आगे बढ़ाना हमारे हित में होगा।

गुंजन कुमारी, टिप्पणीकार

भारत में स्वनिर्मित पहली सेमीकंडक्टर चिप बताते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को भेंट की। यह 'सबसे पहले' प्रचार परंपरा, जो 2014 से शुरू हुई है, उसमें एक और इवेंट है। पचास साल पहले 1976 में भारत सरकार ने 'सेमीकंडक्टर कॉम्प्लैक्स लिमिटेड' (एससीएल), मोहाली की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि भारत खुद की इंटिग्रेटेड सर्किट बनाए और इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनर्भिर हो। 1980 के दशक की शुरुआत में एससीएल ने एमओएस और सीएमओएस तकनीक पर आधारित छोटे इंटिग्रेटेड सर्किट (जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, डिफेंस, और कंप्यूटर बोर्ड्स के लिए) बनाने शुरू किए। 1989 में एससीएल के मोहाली प्लांट में भीषण आग लग गई और उत्पादन ठप हो गया। यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसी समय ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा निवेश शुरू कर दिया था। 2005 में इसका पुनर्जन्म हुआ और एससीएल को इसरो के अधीन कर दिया गया। इसका मुख्य फोकस अंतरिक्ष और सुरक्षा एप्लिकेशन के लिए चिप बनाने पर रखा गया। हालांकि, एससीएल की उत्पादन क्षमता बहुत सीमित रही। इसीलिए, सरकार को चिप उत्पादन की हायर टेक्नालॉजी पर काम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

भूपेंद्र गुप्ता अगम, राजनेता

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अतीत को कोसते रहने से भविष्य भी बिगड़ता है

आफत बनी बरसात

जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम चक्र में आई तब्दीली का परिणाम है आवश्यकता से अधिक बारिश अथवा कम समय में ज्यादा वर्षा। इसके नतीजे में देश के एक बड़े हिस्से में बाढ़ और जल भराव के चलते लोगों को गंभीर समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। चूंकि इस बार अर्से बाद इतनी लंबी अवधि तक बरसात हो रही है, इसलिए वर्षा जनित समस्याएं कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं। सबसे अधिक समस्याओं से दो-चार हैं देश के पर्वतीय राज्य। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में अधिक बारिश के कुछ ज्यादा ही दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इन राज्यों में भूस्खलन की जितनी अधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, वे गंभीर चिंता का कारण हैं, लेकिन यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि चेतने से इन्कार किया जा रहा है। इसका एक प्रमाण यह है कि उन कारणों के चलते जान-माल की अधिक क्षति हो रही है, जो ज्ञात हैं और जिनका निवारण किया जाना चाहिए था। समझना कठिन है कि पहाड़ों से अनावश्यक छेड़छाड़ और पहाड़ी नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण कार्य से क्यों नहीं बचा जा रहा है? आखिर इस तथ्य को क्यों ओझल किया जा रहा है कि यदि नदियों के स्वाभाविक मार्ग को बाधित किया जाएगा तो वे तबाही का कारण बनेंगी? पर्वतीय राज्यों को इससे भी चिंतित होना चाहिए कि आखिर अब बादल फटने की इतनी अधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस बार बारिश पर्वतीय राज्यों के साथ-साथ मैदानी राज्यों में भी कहर ढा रही है। इसका कारण केवल जरूरत से ज्यादा बारिश होना नहीं है। इसका एक कारण कमजोर आधारभूत ढांचे का निर्माण और जल निकासी के उपयुक्त उपाय न किया जाना है। यही कारण है कि नई बनी सड़कों और यहां तक कि एक्सप्रेसवे और हाईवे तक पर जाम लग रहे हैं। शहरों के अंदर की सड़कें भी जल भराव और जाम से जूझ रही हैं। स्थिति यह है कि महानगर तक की सड़कों में जल निकासी के पर्याप्त उपाय नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि कहीं पर भी ज्यादा बारिश होगी तो उससे कुछ न कुछ समस्याएं उपजेंगी ही, लेकिन इन समस्याओं पर एक बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। यह तभी संभव है, जब बुनियादी ढांचे का निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए और जल निकासी के बेहतर उपाय किए जाएं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतर उपायों की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन उनके अनुरूप कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखता। यही स्थिति जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को बढ़ाने वाले कारणों का निवारण करने के उपायों के मामले में भी है। एक बड़ी व्यथा यह है कि मानसून विदा होते ही यह भुला दिया जाएगा कि देश के लोगों को अति वर्षा, बाढ़, जल भराव आदि के कारण कैसे-कैसे संकटों से जूझना पड़ा?

उपचार में सुविधा

राज्य में सात नए मेडिकल कालेज व अस्पताल खोलने का नीतीश सरकार का निर्णय समय की मांग के साथ उचित निर्णय है। इसके कई फायदे होंगे। उन जिलों में चिकित्सा सुविधा मिलने से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के आर्थिक शोषण से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इन जिलों से पटना तक रेफर होकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी। शिवहर, किशनगंज, कटिहार, रोहतास, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में ये मेडिकल कालेज खुलेंगे। शिवहर के ही अधिकतर मरीज रेफर होकर मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज व अस्पताल पहुंचते हैं। इस कारण यहां दबाव पड़ता है। संसाधन कम पड़ जाते हैं। जिले में ही सुविधा मिलने से ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा इन मेडिकल कालेजों के खुलने से मेडिकल की सीटें भी बढ़ेंगी। इसका लाभ उन्हें मिलेगा, जो मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। हर वर्ष इनकी संख्या लाखों में होती है। कम सीट के कारण मेरिट लिस्ट काफी ऊंची रहती है। इस कारण अधिकतर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। नए मेडिकल कालेजों में उन्हें प्रवेश मिलेगा और पढ़ाई पूरी होने पर देश में डाक्टरों की कमी भी दूर होगी। लेकिन, सरकार को यह ध्यान देना होगा कि मेडिकल कालेजों के खुलने में देरी न हो। साथ ही वहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें।

> नए मेडिकल कालेज व अस्पताल खुलने से चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ देशभर में चिकित्सकों की कमी दूर होने में मदद मिलेगी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

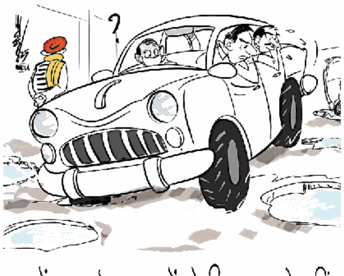

हमें सड़क के इन गड्ढों को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए! ये हमारे जल संचयन के लघु केंद्र हैं!

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एससीओ के मंच से एक नई वैश्विक व्यवस्था के संकेत मिले हैं?

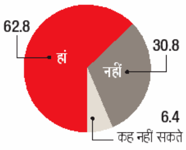

आज का सवाल

क्या राज्यपालों-राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए किसी समय सीमा में बांधा जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

राष्ट्रीय चिंता का विषय बने घुसपैठिए

अशोक कुमार

घुसपैठिए भारत की आंतरिक शांति को खतरे में डालने और विकास को बाधित करने के अलावा लोकतांत्रिक तानेबाने एवं संप्रभुता के लिए भी खतरा बन रहे

सीमा पार से घुसपैठ भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंताओं में से एक बन गई है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस खतरे को रेखांकित करते हुए कहा, 'अवैध घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियों और बहनों को निशाना बना रहे हैं और निर्दोष आदिवासियों की वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।' उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में इन जनसांख्यिकीय बदलावों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन के गठन की घोषणा भी की है। यह इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक दृढ़ प्रयास का संकेत देता है। घुसपैठ अब केवल सीमा-विशेष के स्तर पर ही समस्या नहीं रह गई है। दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे शहरी सेवाओं और व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। इसके दूरगामी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

घुसपैठ एक राष्ट्रीय चिंता बन गई है। बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों ने असम, बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदल दिया है। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ा है। इसके चलते भूमि, भाषा और पहचान को लेकर टकराव पैदा हो रहा है। स्थानीय लोगों में धारणा बढ़ रही है कि घुसपैठिए कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक तुष्टीकरण का लाभ उठा रहे हैं। इस धारणा ने जातीय राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। कट्टरपंथी समूह ऐसी भावनाओं का फायदा उठाने में तत्पर रहते हैं, जिससे सामाजिक एकता को और खतरा पैदा होता है। इस समस्या को विकराल बनाने में राजनीतिक दल भी कम दोषी नहीं। अधिकांश दलों ने वोट-बैंक के लिए जाली दस्तावेजों के जरिये घुसपैठियों को सरकारी जमीनों खासकर नदियों के निकट और वन क्षेत्रों में बसाने में मदद की है। अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दीर्घकालिक समझौता हो जाता है। इससे नागरिकों और राज्य के बीच अविश्वास गहराता है। समय रहते अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भारी अशांति का कारण बन सकता है, विशेषकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है। इसके तब और विध्वंसक परिणाम सामने आते हैं जब घुसपैठिए कृषि, निर्माण और घरेलू मजदूरी से जुड़े काम में संलग्न हो जाते हैं। इससे बाजार सस्ते मजदूरों से भर जाता है और स्थानीय श्रमिकों के हितों पर चोट पहुंचती है। सुरक्षा के जोखिम अलग बढ़ जाते हैं। कई घुसपैठिए अनौपचारिक या ग्रे इकोनमी में भी लिप्त होते हैं, जहां वे पशु तस्करी, मादक पदार्थों, जाली मुद्रा और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ये गतिविधियां न केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट को भी मजबूत बनाती हैं। इनमें से कुछ के आतंकवादियों से संबंध भी होते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर भी घुसपैठिए बोझ बढ़ा रहे हैं। इस बोझ के चलते 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना भी पटरी से उतर सकता है।

अवधेश राजपूत

शत्रु पक्ष की रणनीतियों के कारण भारत की सीमाओं पर समस्याएं बढ़ रही हैं। पंजाब में ड्रोन के जरिये ड्रग्स और हथियार से जुड़े आतंकवाद ने जोर पकड़ लिया है। भारत-म्यांमार सीमा पर दुर्गम इलाके उग्रवादियों की आवाजाही और अवैध प्रवेश को बढ़ावा देते हैं। साइबर अपराधियों और मजदूरों के वेश में छिपे गुप्त एजेंट जांच को और जटिल बना देते हैं। बीते दिनों बांग्लादेश-मेघालय सीमा पर पाकिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है, जो अब पूर्वी सीमा पर कमजोरियों का फायदा उठाने के फेर में है। सुरक्षा बलों की भरसक कोशिशों के बावजूद व्यापक भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। 2011 में मालदा जिले में पशु तस्करों ने एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार 500 मीटर क्षेत्र पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने कब्जा किया हुआ था। इससे सुरक्षा अभियान के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गईं। स्थानीय खुफिया नेटवर्क भी प्रभावित हो रहा है। ऐसी वास्तविकताएं यही संकेत करती हैं कि घुसपैठ केवल सीमा उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, यह आंतरिक समन्वय को भी कमजोर कर सकती है। संकट के समय दुश्मन देशों के साथ साठगांठ को बढ़ावा दे सकती है।

नवघोषित जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन एक आवश्यक कदम है। इसे सफल बनाने के लिए इस राह में आने वाली चुनौतियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। नकली पहचान पत्र, दस्तावेज वालों पर कानूनी शिकंजा कसना होगा। उन्नत सीमा बाड़, निगरानी तकनीकें और नागरिक सत्यापन प्रणालियां भी जरूरी होंगी। कौटिल्य ने यथार्थ ही लिखा है, 'सीमाओं पर स्थित प्रदेशों में विश्वसनीय लोगों और सैनिकों से आबाद किलेबंद नगर स्थापित करने चाहिए। विदेशियों को सीमावर्ती प्रदेशों में बसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' यह सलाह आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्र की संप्रभुता जनसांख्यिकीय अखंडता पर भी निर्भर करती है।

घुसपैठ एक क्षेत्रीय चुनौती ही नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत संकल्प और सामाजिक एकता की एक बुनियादी परीक्षा भी है। इसके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आवश्यक है, जो अल्पकालिक राजनीति से ऊपर उठे। यदि यह मुद्दा अनसुलझा रहा तो अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी। घुसपैठिए देश की आंतरिक शांति को खतरे में डालने के साथ ही विकास को बाधित कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब अनियंत्रित घुसपैठ देश के लोकतांत्रिक तानेबाने और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बन जाए। यह न भूला जाए कि जो राज्य अपनी सीमाओं की उपेक्षा करता है, वह अव्यवस्था को आमंत्रित करता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने भविष्य की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए।

(बीएसएफ में भी रह चुके लेखक उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी हैं)
response@jagran.com

रोका जाए धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग

सीबीपी श्रीवास्तव

इस पर जोर देने की आवश्यकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है

उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के अगले सत्र में पेश किए जाने वाले धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में प्रविधान है कि नौकरी, धन या अन्य उपहारों का लालच देकर किसी व्यक्ति का मतांतरण करने के प्रयास को जबरन पंथ परिवर्तन माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। अंतःकरण व्यक्ति के ज्ञान, अंतर्ज्ञान और तर्कशक्ति का मिश्रण है, जो उसे किसी मत-मजहब के सिद्धांतों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम आस्था में परिवर्तन को भी एक अधिकार मान लेते हैं। इसलिए जब भी राज्य उपासना पद्धति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा निर्धारित करने या मत परिवर्तन रोकने का प्रविधान करता है तो कुछ लोग इसे अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करार देते हैं। यह अक्सर विवाद और टकराव का रूप ले लेता है।

मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित करीब दस राज्यों में ऐसे कानून लागू हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने भी मत परिवर्तन निषेध कानून बनाए हैं। कई और राज्य भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। मतांतरण के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने भी ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इन सभी कानूनों में एक बात समान है कि विवाह के लिए मतांतरण को संज्ञेय और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध हैं। इसलिए इन अधिकारों के संवैधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है। इसलिए और भी, क्योंकि छल-छद्म से मतांतरण के मामले सामने आते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कथित छांगुर बाबा की ओर से कराए जाने वाले मतांतरण अभियान का षड्यंत्र आंखें खोलने वाला है।

संविधान में अनुच्छेद 25-28 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। एक ओर ये अधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं, वहीं दूसरी ओर इनका सार धार्मिक सहिष्णुता है।

मतांतरण के विरुद्ध प्रदर्शन करतीं महिलाएं ● फाइल

यही भारत में पंथनिरपेक्षता का आधार भी है। इसीलिए संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े जाने के बाद इसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता इसे स्पष्ट कर देती है। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 मामले में उच्चतम न्यायालय ने न केवल पंथनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया, बल्कि यह भी कहा कि भारतीय संविधान लागू होने के समय से ही पंथनिरपेक्ष था। अनुच्छेद 25-28 के तहत मिले अधिकारों में अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ-साथ अपनी उपासना पद्धति को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रचार-प्रसार करने का अधिकार भी शामिल है।

भारत में पंथनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है। इसी कारण राज्य सामान्यतः धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता, पर सांप्रदायिकता भड़कने की आशंका की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 25(2) में उल्लेख है कि राज्य पंथ से संबंधित राजनीतिक, वित्तीय या अन्य लौकिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकता है। इस आधार पर यह कहना उचित है कि भारत में पंथनिरपेक्षता संविधान में राज्य की नीति के रूप में शामिल है। यह न तो किसी मत के पक्ष में है, न उसके विरुद्ध और न ही यह किसी मत के प्रति तटस्थ है। यह मतविरोधी नहीं, बल्कि संप्रदायवाद विरोधी है। ये सभी प्रविधान दर्शाते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग और संस्थाएं इसे अधिकार की तरह इस्तेमाल करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 18 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपासना पद्धति को मानने, न मानने या उसे बदलने का अधिकार है। भारत संयुक्त राष्ट्र की नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करता है, लेकिन भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर अपनी उपासना पद्धति बदल तो सकता है, लेकिन वह इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। मत परिवर्तन के इस अधिकार को न देने के पीछे मूल विचार सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को रोकना है। अफसोस कि ये प्रवृत्तियां थम नहीं रहीं और इसीलिए राज्य सरकारें कानून बनाने के लिए विवश हैं।

यदि मत परिवर्तन के अधिकार को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में दिया जाएगा तो इसका दुरुपयोग बढ़ेगा और जबरन मतांतरण की घटनाओं में भी वृद्धि होगी। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस प्रकार दिया गया है कि भारत का पंथनिरपेक्ष चरित्र मजबूत रहे और इन अधिकारों के किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में राज्य सांप्रदायिक ताकतों को नियंत्रित कर सके। हमें यह देखना ही होगा कि मतांतरण में संलग्न ताकतें देश के पंथनिरपेक्ष चरित्र में छेड़छाड़ न करने पाएं।

(लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

विनम्रता

व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है और आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण में विनम्रता जैसे गुणों का प्रमुख योगदान होता है। विनम्रता का भाव ही व्यक्तित्व की आभा बढ़ाकर उसे लोकप्रिय बनाता है। जीवन संघर्ष में विनम्र व्यक्ति प्रत्येक झंझावात को सहजता से पार कर लेता है। वह उस हरी लकड़ी की भांति होता है जो वायु के जोर से स्वयं को बचाने में सक्षम रहती है। जबकि कड़क मिजाज वाला व्यक्ति सूखी हुई टहनी की भांति टूटकर बिखर जाता है। विनम्रता सफलता को स्थायी बनाए रखती है। सफल व्यक्ति विनम्रता के रथ पर आरूढ़ होकर लंबी दूरी कर लेता है। जबकि सफलता के बाद अभिमान के रथ पर सवार हुआ व्यक्ति कुछ दूरी तय करने के बाद ही हांफने लगता है। उसकी सफलता स्थायी नहीं रह पाती।

विनम्र व्यक्ति से सभी सहजता से सामीप्य बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करते। उनके आसपास मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है। विनम्रता का गुण व्यक्ति के कार्यों को और अधिक श्रेष्ठ बना देता है। विनम्र व्यक्ति कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित करता है तो सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अगर वह व्यक्ति इसके विपरीत स्वभाव रखता है तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसकी असफलता पर उपहास होने लगता है, जबकि विनम्र व्यक्ति को असफलता की स्थिति में भी ढांढ़स बंधाने वालों की कमी नहीं होती।

हम कालजयी महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं तो एक पहलू सबके व्यक्तित्व में एकसमान मिलता है और वह है उनका विनम्र स्वभाव। भगवान राम की विनम्रता के अनेकों प्रसंग पढ़ने को मिल जाते हैं। शबरी के जूठे बेरों को ग्रहण करना उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा ही तो है। विनम्रता का तेज व्यक्ति के ललाट को तेजस्विता प्रदान करता है। विनम्रता की पोथी पढ़कर जीवन की कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया जा सकता है।

ललित शौर्य

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

एक बड़ी उपलब्धि जनधन योजना

'गरीबों को सशक्त बनाने वाली योजना' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में रमेश कुमार दुबे ने जिस वित्तीय क्रांति का संदर्भ दिया, वह देश के लिए निःसंदेह मील का पत्थर साबित हुई है। वित्तीय क्षेत्र में जनधन योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति बैंक से जुड़ने में सक्षम हुआ। अन्यथा बैंकिंग सेवाओं तक सभी की सहज पहुंच नहीं हो पाई थी। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय क्षेत्र में क्रांति की जो उम्मीद जगी थी, वह जनधन के बाद ही पूरी तरह साकार हो सकी। जनधन योजना ने सरकारी योजनाओं से रिसाव रोककर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। लेखक ने उचित ही रेखांकित किया कि कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू तो बहुत गाजे-बाजे के साथ होती हैं, लेकिन एक समय के बाद शिथिलता की शिकार होकर अपने उद्देश्यों को पूरा नही कर पातीं। इस संदर्भ में जनधन जैसी योजना अपवाद रही। इसकी सफलता में यह पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण रहा कि सरकार ने इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए इसमें आवश्यक सुधार किए। निःसंदेह, यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

डा. मिथिलेश कुमार भागलपुर (बिहार)

आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक

भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली स्वदेशी 32-बिट सूक्ष्म प्रोसेसर चिप 'विक्रम-32' का सफल अनावरण किया है। यह उपलब्धि केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता की पहचान ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्धचालक परिदृश्य में भारत की गंभीर प्रविष्टि का भी संकेत है। सेमिकान इंडिया 2025 के मंच पर जब इसे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया, तब संदेश स्पष्ट था कि भारत अब मात्र उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार का अग्रणी स्रोत बनने की दिशा में बढ़ रहा है। यह चिप इसरो की अर्धचालक प्रयोगशाला मोहाली में 180 नैनोमीटर सीएमओएस तकनीक से निर्मित की गई है और इसे विशेष रूप से अंतरिक्ष अभियानों के लिए बनाया गया है। इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण हाल ही में पीएसएलवी-सी 60 मिशन में इसके सफल उपयोग से मिल चुका है। 'विक्रम-32' न केवल अंतरिक्ष मिशनों में विदेशी निर्भरता को समाप्त करेगा, बल्कि रक्षा, अंतरिक्ष यान और वाहन उद्योग में भी भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता देगा। वैश्विक स्तर पर अर्धचालक उद्योग महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। ऐसे में भारत की यह उपलब्धि बड़ी है। 'विक्रम-32' का विकास किसी नकल या ठेके पर आधारित नहीं, बल्कि पूर्णतः भारतीय मस्तिष्क और संसाधनों का योगदान है। वास्तव में यह चिप भारत के लिए केवल एक तकनीकी उत्पाद नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। यह संदेश पूरे विश्व को गया है कि भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। 'विक्रम-32' ने सिद्ध कर दिया है कि जब संकल्प और संसाधन एकत्रित होते हैं तो भविष्य की परिभाषा स्वयं बदल जाती है।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

संवाद के दरवाजे खुले

हर्ष वी. पंत द्वारा लिखित आलेख 'चीन को सुधारना होगा अपना रवैया' पढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनर्गल टैरिफ नीति ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग की आत्मीय मुलाकात ने अमेरिका की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भारत और रूस के बीच दशकों से गहरा संबंध रहा है, लेकिन भारत और चीन के बीच दशकों से सीमा विवाद जारी है। भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को चीन ने हमेशा संरक्षण देने का कार्य किया है। गलवान की घटना के उपरांत दोनों देशों का आपसी भरोसा कमज़ोर हुआ, परंतु इस मुलाकात ने यह संदेश दिया है कि संवाद के दरवाजे अभी भी खुले हैं। भारत की विदेश नीति ''वसुधैव कुटुंबकम'' के आदर्श पर आधारित है, लेकिन चीन की नीतियां अक्सर विस्तारवाद के आरोपों से घिरी रहती हैं। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका के तानाशाही रवैये का जवाब देने के लिए भारत और चीन का संयुक्त तालमेल अनिवार्य हैं। इस तालमेल को बनाए रखने के लिए चीन को अपने रवैये में सुधार लाना होगा और भारत विरोधी गतिविधियों से अपने आप को अलग रखना होगा।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

पोस्ट

मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई और देश अफगान लोगों के साथ इतनी तन्मयता एवं तत्परता के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है जैसे कि भारत। हर आपदा के समय भारत मदद के हाथ आगे बढ़ाने वाला पहला देश होता है। हालिया भूकंप के बाद भी ऐसा ही देखने को मिला।

मरियम@Mariamistan

इस समय जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से त्रस्त है। आपदा की इस घड़ी में हम सभी को अपनी ओर से हरसंभव सहायता करने का प्रयास करना चाहिए।

प्रीटी जिंटा@realpreityzinta

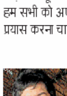

भारतवंशी रो खन्ना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में आगे आए हैं। यह देखकर अच्छा लगा कि प्रभावशाली भारतीय आखिरकार वहां अपनी आवाज उठाने लगे हैं। अमेरिका में भारतवंशियों का खासा प्रभाव है और उनकी गिनती भी सबसे समृद्ध समुदायों में होती है। भारत के खिलाफ ट्रंप के बेतुके अभियान से उन्हें भी नुकसान ही होगा।

विक्रम चंद्रा@vikramchandra

जनपथ

सैयां व्यापारी बने रहे दोस्ती खोय,
घाटे का सौदा करें चहुंदिश थू-थू होय।
चहुंदिश थू-थू होय घिर गए खुद के घर में,
अब तो ताऊ ट्रम्प जिएंगे खुद ही डर में!
डूबें मियां मुनीर पकड़ कर उनकी बहियां,
अपना बंटाधार करें मतवाले सैयां!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 144

****

कल्पमेधा

विज्ञान ज्यादातर बुरी चीजों का सामाधान निकाल चुका है या निकाल लेगा, पर अभी तक उनमें से सबसे बुरी चीज का हल नहीं खोज पाया है। वह है मानव की उदासीनता एवं अनिच्छा।

- हेलेन केलर

खतरे का संकेत

हिमनदों का तेजी से पिघलना जलवायु परिवर्तन और इसके परिणामस्वरूप आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है। इससे विनाशकारी बाढ़, जल संकट, समुद्र के स्तर में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन जैसे संकट की स्थिति और गंभीर हो सकती है। यह भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हिमनदों के पिघलने से पहाड़ों पर नई झीलें बन रही हैं और पहले से बनीं झीलों का दायरा भी बढ़ रहा है, जो कभी भी आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही मचा सकती हैं। केंद्रीय जल आयोग की हालिया रपट में कहा गया है कि भारत के हिमालयी क्षेत्र में 432 हिमनद झीलों का आकार चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। इस वर्ष जून के दौरान इन झीलों के जल क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। सवाल यह है कि ये झीलें बढ़ते पानी का दबाव आखिर कब तक झेल पाएंगी? ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में जल का यह अथाह भंडार बड़ी आपदाओं का कारण बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन हिमनद झीलों का गहन अध्ययन किया जाए और इनकी नियमित रूप से निगरानी की जाए।

केंद्रीय जल आयोग की रपट के मुताबिक, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं और वहां बनी झीलों का आकार लगातार बढ़ रहा है। भारत में हिमनद झीलों का कुल क्षेत्रफल वर्ष 2011 में 1,917 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2025 में बढ़ कर 2,508 हेक्टेयर हो गया। यानी इन झीलों के क्षेत्रफल में 30.83 फीसद की वृद्धि हुई है, जो आसपास की आबादी के लिए कभी भी प्रलयकारी साबित हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक 197 विस्तारित हिमनद झीलें हैं। इसके बाद लद्दाख में 120, जम्मू-कश्मीर में 57, सिक्किम में 47, हिमाचल प्रदेश में छह और उत्तराखंड में पांच हिमनद झीलों का क्षेत्रफल बढ़ा है। देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान और दून विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी पाया गया है कि उत्तराखंड में हिमनदों के पिघलने से बन रही झीलों में मिट्टी, मलबा और पत्थर भी जमा हो रहे हैं। प्रदेश में पिछले दस वर्षों में हिमनद झीलों की संख्या 19.2 फीसद तक बढ़ी है। इससे साफ है कि खतरा लगातार बढ़ रहा है।

वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात साफ हो चुकी है कि बढ़ता वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन हिमनदों के पिघलने का मुख्य कारण है। इसका नतीजा न केवल विनाशकारी बाढ़ के रूप में देखने को मिल सकता है, बल्कि गंभीर जलसंकट जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाकर और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर सतत विकास के माडल पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सरकार, समाज, विज्ञान और जनमानस को मिल कर इस चुनौती से निपटने के उपायों पर काम करना होगा। जिन पर्वतीय इलाकों में हिमनद झीलों का विस्तार हो रहा है, वहां निचले इलाकों में रह रहे समुदायों के लिए वास्तविक समय पर आधारित निगरानी प्रणाली और उपग्रह-आधारित सतर्कता एवं पूर्व-चेतावनी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही पहाड़ों पर ऐसी गतिविधियों को भी सीमित करने की अत्यंत जरूरत है, जिनसे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो भविष्य में किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है।

शुचिता पर सवाल

देश के नागरिक जनप्रतिनिधियों को इस उम्मीद के साथ चुनते हैं कि वे व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करेंगे, जन-समस्याओं का समाधान निकालेंगे और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े रहेंगे। मगर जनप्रतिनिधियों के व्यवहार में आ रहे बदलाव से अब लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। आपराधिक छवि के नेताओं को जिस तरह राजनीति में जगह मिली है, इसके लिए सियासी दल भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। दुखद है कि लोकतंत्र की रक्षा करने की शपथ लेने वाले नेता लोक के लिए ही खतरा बन गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी राजनीति में शुचिता लाने और विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन इन वादों की हकीकत ने लोगों को निराश ही किया है। ताजा उदाहरण राज्य में इस पार्टी के एक विधायक का है, जिन पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और पुलिस की हिरासत से फरार हो गए।

पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी को शायद ही इस बात की कोई चिंता होगी कि उसके विधायक क्या कर रहे हैं। पार्टी के कुछ विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। कई आरोपों से घिरी आम आदमी पाटी और उसकी सरकार की ओर से किए जा रहे विकास के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी तस्वीर इस बार राज्य में बने बाढ़ जैसे हालात से साफ दिख रही है। पार्टी के विधायक इस संकट में जनता के बीच जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। अगर, बाढ़ से निपटने के समय पर बंदोबस्त किए गए होते, तो आज राज्य में हालात ऐसे नहीं होते। पंजाब में करीब साढ़े आठ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में जब लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों की सबसे अधिक जरूरत है, तो एक विधायक के गोलियां चलाकर पुलिस हिरासत से फरार होने की घटना सामने आ रही है। अगर जनप्रतिनिधि ही सड़क पर हथियार लेकर चलेंगे तो वे समाज में किस तरह का आदर्श कायम करेंगे?

विकास की रफ्तार और घटता रोजगार

भारतीय व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक असमानता, घटते संसाधन और बढ़ती जनसंख्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चिंता बढ़ रही है।

अजय प्रताप तिवारी

देश के आर्थिक विकास का पैमाना कुछ इस तरह होना चाहिए, जिसमें सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समानता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, गरीबी और भुखमरी में गिरावट, सामाजिक असमानताओं में कमी, रोजगार की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खुशहाली हो। एक समृद्ध लोकतंत्र में आर्थिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जहां व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हो और समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास संभव हो। विकास का माडल ऐसा हो, जिसमें रोजगार के अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा महंगाई की दर कम रहे। भारत की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ रही है। आने वाले तीन वर्षों में देश के पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।

एशियाई विकास बैंक के मुताबिक, भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.5 फीसद और 2026 में 6.7 फीसद की दर से बढ़ने की संभावना है। ऐसे में तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। भारतीय व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक असमानता, घटते संसाधन और बढ़ती जनसंख्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वक्त बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, जो देश के संपूर्ण विकास में अवरोधक है। उसी अर्थव्यवस्था को संतुलित माना जाता है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हों। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्तूबर, 2022 से सितंबर, 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इस कारण करीब 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कार्यबल तथा जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहां युवाओं की आबादी अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है। हाल में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रपट के मुताबिक, देश में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6 फीसद, जबकि महिलाओं में 5.8 फीसद है। देश में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में इस वर्ष अप्रैल में बेरोजगारी 13.8 फीसद से बढ़कर मई में 15 फीसद हो गई। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल में 17.2 फीसद से बढ़कर मई में 17.9 फीसद हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अप्रैल के 12.3 फीसद की तुलना में मई में 13.7 फीसद थी।

मगर हमारे यहां जनसंख्या और श्रमबल क्षमता अधिक होने के बावजूद आर्थिक असमानता भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। देश में बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही आर्थिक असमानता विकास की राह बड़ी बाधक है। आक्सफैम-2024 की एक रपट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, पिछले कई वर्षों से भारत समेत विश्व में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। यह आर्थिक तंत्र के लिए बहुत निराशाजनक और चिंताजनक बात

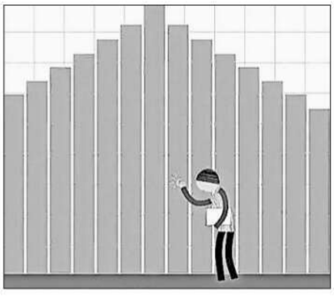

है। आर्थिक असमानता के मामले में भारत के संदर्भ में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल संपत्ति का चालीस फीसद हिस्सा देश के एक फीसद अमीर लोगों के पास है। वर्तमान में भारत के इक्कीस सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश के सत्तर करोड़ लोगों से ज्यादा

> **भारत में श्रमबल की भागीदारी लगभग 46 फीसद है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर नजर डालें तो इसके कई कारण स्पष्ट नजर आते हैं। इनमें जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण है। कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक दिक्कतें, व्यावसायिक कौशल की कमी, खराब शैक्षिक उपलब्धियां, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश और अपर्याप्त ढांचागत विकास विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को सीमित करता है। भारत में आर्थिक विकास दर बढ़ी, उद्योगों से लाभ हुआ, संवेदी सूचकांक में भी उछाल आया, पर रोजगार के अवसरों में अपेक्षाजनक बढ़ोतरी नहीं हुई।**

संपत्ति है। आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का केवल तीन फीसद है। यहां अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में वर्ष 2020 में 102 अरबपति थे, 2022 में 166 और 2023 में यह आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है। इस तरह की आर्थिक असमानता से गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ती है और देश का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। अगर भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करें तो इसे दूर करने संबंधी प्रयास निराशाजनक नजर आते हैं। बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव से देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इंडिया स्किल्स रपट-2025 के अनुसार, भारत में स्नातकों के बीच रोजगार योग्यता बढ़ कर 54.81 फीसद हो गई है।

वहीं, 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' की रपट से पता चलता है कि भारत में हर वर्ष पचास लाख युवा उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं, जिनकी उम्र करीब उन्नीस-बीस वर्ष होती है। ये युवा अपनी स्नातक की पढ़ाई लगभग 24 वर्ष की उम्र तक पूरी कर लेते हैं। जबकि भारत में पच्चीस वर्ष से कम उम्र के युवाओं में स्नातक स्तर पर बयालीस फीसद बेरोजगार हैं। परास्नातक की पढ़ाई करने के बाद या जिनकी उम्र पच्चीस से उनतीस वर्ष के बीच है, उनमें बेरोजगारी 22.8 फीसद है। इसी तरह तीस से पैंतीस वर्ष उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी 9.8 फीसद है। इससे ऊपर की उम्र के शिक्षित लोगों में बेरोजगारी दर लगभग पांच फीसद है। देश में पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014 में यह 5.44 फीसद और 2020 में आठ फीसद थी। वर्ष 2023 के अक्तूबर में बेरोजगारी दर 10.1 फीसद पर पहुंच गई थी।

भारत में श्रमबल की भागीदारी लगभग 46 फीसद है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर नजर डालें तो इसके कई कारण स्पष्ट नजर आते हैं। इनमें जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण है। कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक दिक्कतें, व्यावसायिक कौशल की कमी, खराब शैक्षिक उपलब्धियां, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश और अपर्याप्त ढांचागत विकास माध्यमिक क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को सीमित करता है। भारत में आर्थिक विकास दर बढ़ी, उद्योगों से लाभ हुआ, संवेदी सूचकांक में उछाल भी आया, पर रोजगार के अवसरों में अपेक्षाजनक बदलाव नहीं हुआ। सरकारी मुहिम 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद बेचने के उद्देश्य से यहां उद्योग लगा रही हैं, पर ये युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। भारत में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योग सृजित करते हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, देश में लघु एवं मध्यम उद्योग कुल चालीस फीसद रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इन क्षेत्रों को भी सरकारी नीतियों से अपेक्षाजनक प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा साठ फीसद श्रमशक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में है। वर्तमान समय में देश में रोजगार की दर चालीस फीसद है। यानी यहां पर सौ लोगों में से सिर्फ चालीस लोगों के लिए काम उपलब्ध है, बाकी साठ लोगों के पास कोई काम नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जब देश में आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ रहा है, तो रोजगार के स्रोत क्यों घट रहे हैं। देश में रोजगार की उपलब्धता कम होने से प्रतिभा संपन्न युवाओं का अन्य देशों में पलायन होने लगता है, जो देश के लिए कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में जरूरी है कि एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर रोजगार सृजन, आर्थिक समानता लाने और प्रतिभा संपन्न युवाओं की श्रमशक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाएं।

महत्त्वाकांक्षा की परतें

मनीष कुमार चौधरी

महत्त्वाकांक्षा के सकारात्मक पहलू भी होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक इंजन, जो व्यक्तियों को जीवित रहने के दायरे से परे सृजन, विघटन और परिवर्तन के क्षेत्र में ले जाता है। महत्त्वाकांक्षा यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार करना है और व्यक्तिगत व सामाजिक सीमाओं को बढ़ाने का आंतरिक दबाव है। यह जोखिम लेने, दृढ़ता और इस जिद्दी विश्वास के लिए उत्प्रेरक के रूप में उद्यमशीलता को रेखांकित करती है कि एक बेहतर तरीका न केवल संभव है, बल्कि आवश्यक भी है। इसके बिना नवाचार रुक जाता है। विज्ञान से लेकर कला और राजनीति तक सभी क्षेत्रों में इतिहास की सफलताएं शायद ही कभी आत्मसंतुष्टि का परिणाम हैं- वे बेचैन, महत्त्वाकांक्षी दिमागों के अवशेष हैं। महत्त्वाकांक्षी लोगों के बारे में कई बार नकारात्मक धारणाएं फैलाई जाती हैं, लेकिन दुनिया काफी हद तक महत्त्वाकांक्षी लोगों का उत्पाद है। इसे वे लोग आकार देते हैं जो शांत नहीं बैठ सकते। वे लोग भी, जो विरासत में मिली सीमाओं से संतुष्ट नहीं थे और अपने विचारों पर काम करने के लिए खुद को बाध्य महसूस करते थे, चाहे वे कितने भी कठिन या अलोकप्रिय क्यों न हों।

प्रगति कभी भी समान रूप से वितरित नहीं हुई है। यह उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा संचालित की गई है जो अपनी छाप छोड़ने की अत्यधिक इच्छा रखते हैं। महत्त्वाकांक्षा असंतोष को गति में और कल्पना को बुनियादी ढांचे में बदल देती है। यह न केवल यह बताती है कि कौन नेतृत्व या आविष्कार करने के लिए उठता है, बल्कि यह भी बताती है कि सभ्यताएं क्यों फैलती हैं, प्रौद्योगिकियां आगे बढ़ती हैं और संस्कृतियां विकसित होती हैं। एक विद्वान ने कहा है, 'महत्त्वाकांक्षा के बगैर बुद्धिमत्ता पंखों के बिना पक्षी के समान है।' यह महत्त्वाकांक्षा का एक उजला पक्ष हो सकता है, लेकिन तब तक, जब वह संयमित और नियंत्रित हो। बहुत अधिक होने पर महत्त्वाकांक्षा जुनून में बदल सकती है। विनम्रता, सहयोग और यहां तक कि नैतिक निर्णयों को भी पीछे छोड़ सकती है।

जब महत्त्वाकांक्षा असीमित हो जाती है, तो यह व्यक्ति की सेवा करना बंद कर देती है और त्याग की मांग करने लगती है- रिश्तों, मूल्यों और दीर्घकालिक कल्याण की। यह आत्म-धारणा को विकृत कर सकती है और खुद को शून्य-योग प्रतियोगिता में अकेले नायक के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनियंत्रित महत्त्वाकांक्षा अक्सर लालच में बदल जाती है। न केवल सफल होने की, बल्कि हावी होने की एक अतृप्त भूख। लालच एक उत्तेजक मंत्र तो हो सकता है, लेकिन अंधाधुंध रूप से लागू होने पर इसे एक खतरनाक दर्शन में बदलते देर नहीं लगती। लालच सामाजिक अनुबंधों को नष्ट कर देता है और शोषण को उचित ठहराता है, अनैतिक संक्षिप्त रास्तों को सहन करता है, लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में देखता है। बेलगाम महत्त्वाकांक्षा अर्श से फर्श पर ला सकती है। स्वस्थ महत्त्वाकांक्षा उद्देश्य पर आधारित होती है, आत्म-जागरूकता से संतुलित होती है और सामूहिक सफलता के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ी होती है। यह सभी को ऊपर उठाती है, न कि केवल सबसे तेज गति से ऊपर चढ़ने वाले को। जब 'आगे बढ़ने' की इच्छा 'मिलकर चलने' की प्रवृत्ति से अधिक हो जाती है, तो महत्त्वाकांक्षा सामाजिक सामंजस्य को मटियामेट कर सकती है।

जैसे-जैसे महत्त्वाकांक्षा बढ़ती है, वैसे-वैसे श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति उपेक्षा की भावना भी बढ़ती है। इसमें हेरफेर, बदमाशी, सयानेपन या आलोचना को स्वीकार करने से इनकार करने जैसे विषाक्त व्यवहार हो सकते हैं। जब महत्त्वाकांक्षा असामाजिक लक्षणों के साथ जुड़ जाती है, तो यह एक गुण नहीं रह जाती और एक दायित्व बन जाती है- व्यक्ति और उस प्रणाली दोनों के लिए, जिसका वे हिस्सा हैं। महत्त्वाकांक्षा अक्सर समझौते की मांग करती है, लेकिन जब वे समझौते बलिदान बन जाते हैं, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तीव्र व्यावसायिक लक्ष्यों से प्रेरित लोग परिवार, दोस्तों और आत्म-देखभाल की उपेक्षा कर सकते हैं, यह मानते हुए कि सफलता लागतों को उचित ठहराती है। समय के साथ उपेक्षा बढ़ती जाती है, रिश्ते खराब होते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, बड़ी उपलब्धियों के बाद भी खालीपन की भावना पैदा हो सकती है।

आमतौर पर बेलगाम महत्त्वाकांक्षाओं को सतही माना जाता है, क्योंकि यह हमेशा परिणाम की तलाश में रहती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। यह याद रखना जरूरी है कि कभी-कभी पर्याप्त लक्ष्य रखना सबसे बुद्धिमानी और सबसे टिकाऊ रणनीति होती है। हम भूल जाते हैं कि महत्त्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ नहीं होती, यह केवल पहले से मौजूद चीजों को बढ़ाती है। सही हाथों में यह नवाचार, सेवा और प्रगति को उत्प्रेरित करती है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि यह किसी व्यक्ति के भीतर की क्षमताओं में उभार लाकर उसे अपने सामान्य और यथास्थिति का शिकार हो गए जीवन में कोई नया मुकाम बनाने को प्रेरित कर सकता है, लेकिन यह तभी तक संभव है, जब तक अपनी इस आकांक्षा को मानवीय और संवेदनशीलता की कसौटी पर कसते हुए अपनी उन्नति की राह पर आगे बढ़ाया जाए। यह भले लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। मगर गलत लोगों में यह अहंकार, शोषण और आखिरकार पतन को बढ़ावा देती है। भविष्य उन लोगों का नहीं होगा जो सबसे तेज चढ़ते हैं, बल्कि उनका होगा जो उद्देश्य के साथ चढ़ते हैं और दूसरों को अपने साथ लाते हैं। हेनरी वड्र्सवर्थ के शब्दों में, 'अधिकांश लोग छोटी-छोटी चीजों में भी सफल हो जाते, अगर वे बड़ी महत्त्वाकांक्षाओं से ग्रसित न होते।'

दुनिया मेरे आगे

> **इसमें दोराय नहीं कि महत्त्वाकांक्षा व्यक्ति के भीतर की क्षमताओं में उभार लाकर उसे अपने यथास्थिति का शिकार हो गए जीवन में कोई नया मुकाम बनाने को प्रेरित कर सकती है। मगर यह तभी तक संभव है, जब तक आकांक्षा को मानवीय संवेदनशीलता की कसौटी पर कसते हुए इसे अपनी उन्नति की राह पर आगे बढ़ाया जाए।**

रणनीतिक जवाब

अमेरिका के मनमाने शुल्क के आगे भारत झुका नहीं, बल्कि उसने कूटनीतिक और रणनीतिक जवाब देना शुरू कर दिया है। इससे अमेरिका की कोशिशों को झटका लगा है। चीन के साथ संबंधों में सुधार लाना भारत की इसी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन के प्रभाव को कम करने और उस पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया था। अमेरिका को यह बात अच्छी तरह पता है कि एशिया में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा ताकतवर देश है, जो चीन से टक्कर लेने का साहस रखता है। इसलिए उसने पिछले एक दशक में भारत के साथ अपने रिश्तों को और अधिक मजबूती दी थी, लेकिन अब भारत और चीन के साझेदार देश बनने के प्रयासों के बाद एशिया महाद्वीप में अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत-रूस और चीन की दोस्ती की नई रूपरेखा अमेरिका को कड़ी चुनौती देगी। चीन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर सहमति बनी है।

- युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

बढ़ता जोखिम

देश में हवाई जहाजों में तकनीकी खराबी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में दिल्ली से इंदौर जा रही एअर इंडिया की उड़ान के दौरान इंजन में आग लगने से यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। इससे पहले 29 अगस्त को स्पाइसजेट के दिल्ली से श्रीनगर जा रहे विमान को आपातस्थिति में उतारा गया। इसी तरह सूरत से दुबई जा रहे इंडिगो के विमान को तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद भेजना पड़ा। कुछ समय पहले अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि हमारे विमानन बेड़े में बड़ी संख्या में 20-25 वर्ष पुराने जहाज शामिल हैं, जिनमें तकनीकी खराबियां आए दिन सामने आती रहती हैं। आश्चर्य की बात है कि सरकार 10-15 वर्ष पुरानी कारों को सड़क पर चलाने पर रोक लगाती है, जबकि पुराने विमानों को उड़ान भरने की अनुमति देना कहीं अधिक खतरनाक है।

- अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

मानसून की मार

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां कृषि मूलतः मानसून पर निर्भर है। हर वर्ष हम सभी बेहतर मानसून की कामना करते हैं। आज स्थिति उलट है। उत्तर भारत खास तौर से पहाड़ी राज्य अब मानसून की मार झेल रहे हैं। लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। मानव प्रबंधन क्षमता सीमित नजर आ रही है। वहीं हर घंटे कुछ न कुछ त्रासद घट रहा है। अनुसंधानकर्ता, विभिन्न संस्थान और संगठन पिछले लगभग पांच दशकों से जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के मध्य सीधा संबंध बता रहे हैं। लोगों को चेता रहे हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में सही नहीं है। मनुष्य का लालच और आय-उपभोग के खोखले पैमाने धरती-पहाड़, समुद्र और नदियों के अस्तित्व के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। जान-माल के नुकसान का आकलन करते हैं, तो समस्या मानसून की लगती है। मगर इसका मिजाज भी तो मनुष्य की गलतियों से बिगड़ा है।

- जोगिंद्र भारद्वाज, मामूरपुर, दिल्ली

भेदभाव की दीवारें

आज भारत तेजी से विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और उद्योग में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन इस प्रगति को वास्तविक और स्थायी तभी बनाया जा सकता है, जब हमारे समाज से भेदभाव की दीवारें पूरी तरह टूट जाएं। अमीर-गरीब, जाति-धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव समाज की जड़ों को खोखला करता है। यह न केवल मनुष्य की क्षमताओं को रोकता है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और विकास में भी बाधा बनता है। एक सशक्त भारत वही होगा, जहां हर नागरिक को समान अवसर, बराबर सम्मान और समान अधिकार मिले। समानता केवल संविधान में लिखे शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि यह व्यवहार और सोच का हिस्सा बने। जब हर इंसान बराबरी का दर्जा पाएगा, तभी भारत वास्तव में सशक्त कहलाएगा।

- रागिनी कुशवाहा, सिंगरौली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरूवार 4 सितम्बर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

उमर खालिद को फिर नहीं मिली जमानत

2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए उमर खालिद, शरज़ील इमाम, गुलफ़िशां फ़ातिमा, अतहर ख़ान, अब्दुल ख़ालिद सैफ़ी, मोहम्मद सलीम ख़ान, शिफ़ा-उर-रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद की जमानत याचिका 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने यह फैसला लिया है। इन सब पर आरोप है कि ये सभी दिल्ली दंगे में किसी 'बड़ी साज़िश' का हिस्सा थे। अब ये साज़िश कौन सी थी, उसका सच क्या है। क्या वाकई इन्हीं लोगों ने दंगे भड़काए, जैसा कि दिल्ली पुलिस का आरोप है या असल गुनहगार कोई और है, ये सारे खुलासे तो तभी हो पाएंगे जब मुकदमा चलना शुरु होगा। आश्चर्य है कि पिछले पांच सालों से उमर खालिद जेल में बंद हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई मुकदमा चलाया नहीं गया है, जहां सुनवाई हो तो आरोपी भी अपना पक्ष रखे, अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत करे।

पांच सालों में देश और दुनिया में कितना, कुछ बदल गया है। एआई का इस वक्त ऐसा बोलबाला हो गया है कि स्क्रीन पर दिखने वाली कोई घटना, कोई किरदार असली है या नकली इसका पता ही नहीं चलता। सच और झूठ के बीच हमेशा से एक अदृश्य महीन रेखा होती है, जिसे अनुभवी लोग परख लेते हैं। लेकिन एआई ने इन अनुभवों को भी चुनौती दी है। ऐसे में दिल्ली दंगों का सच भी क्या पूरी तरह कभी सामने आ पाएगा, इसमें संदेह है। और जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा, सच पर झूठ की परतें चढ़ाना आसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर तो यही होता कि इस मामले में मुकदमा चलना शुरु हो जाता।

दिल्ली दंगों में ही एक और आरोपी तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका भी मंगलवार को खारिज हुई है, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ कर रही थी। इस बेंच का कहना है कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में विभिन्न समय पर मुकदमे में देरी के लिए आरोपी स्वयं ज़िम्मेदार हैं, न कि दिल्ली पुलिस या निचली अदालत। गौरतलब है कि करीब छह महीने पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ ने पत्रकार बरखा दत्त को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि उमर ख़ालिद को जमानत इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके वकील बार बार समय मांगते थे। वे मुकदमा शुरु नहीं होने देते और केस स्थगन की मांग जजों से करते थे। इस साक्षात्कार में जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर एक खास नजरिया सामने लाया जाता है, जबकि जजों के पास अपने बचाव के लिए कोई मंच नहीं है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रहते हुए डी वाय चंद्रचूड़ ने ही बयान दिया था कि जमानत कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक नियम है और निचली अदालतों में इसे लागू करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई लोगों को जमानत दी और इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़मानत देने में उदारता बरती जानी चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक दिल्ली दंगों में आरोपियों के वकील ही जमानत की राह में आड़े आ रहे हैं और यही विचार अब हाईकोर्ट के माननीय जजों ने व्यक्त किए।

इस लिहाज से तो अब उमर खालिद समेत तमाम आरोपियों का पक्ष रखने वाले वकीलों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि अगली बार जमानत की अर्जी लगे तो उसे खारिज करने के नौबत न आए। बिना सुनवाई या सजा के पांच साल का लंबा वक्त जेल में गुजारना न्यायिक व्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। पिछले साल अमेरिका के अखबार न्यूयार्क टाइम्स ने उमर खालिद को जेल पर पूरे पन्ने की स्टोरी प्रकाशित की थी, जिसमें मोदी सरकार पर तो गंभीर सवाल उठे ही थे, देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के लिहाज से भारत की छवि कुछ खास अच्छी नहीं है और ऐसी घटनाएं इस दाग को और गहरा करती हैं।

जहां तक उमर खालिद की जमानत इस बार खारिज होने का सवाल है, तो उनके वकील त्रिदीप पैस ने अदालत में तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप बिना सबूत के हैं और पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों को दंगों के साथ जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि खालिद ने कोई हिंसा नहीं भड़काई और न ही वह दंगों के दौरान दिल्ली में मौजूद थे। पैस ने यह भी बताया कि खालिद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में केवल पांच संदेश भेजे थे, जिनमें से तीन गूगल मैप्स लोकेशन थे, और एक संदेश में उन्होंने पुलिस की ओर से विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की अपील की थी। वहीं दिल्ली पुलिस की दलील है कि खालिद ने 'दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप' व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साजिश रची और उनकी गतिविधियां सरकार को 'घुटनों पर लाने' की मंशा को दिखाती थीं। पुलिस ने उनके अमरावती में दिए गए भाषण में 'इंकलाबी सलाम' और 'क्रांतिकारी इस्तकबाल' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को हिंसा भड़काने के रूप में पेश किया।

यहां दिल्ली पुलिस से पूछा जा सकता है कि जब अनुराग ठाकुर भरी सभा में देश के गद्दारों को गोली मारो, जैसे नारे लगाते हैं, तब क्या हिंसा भड़काने का आह्वान नहीं होता? इंकलाबी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल ये जुमले उर्दू में हैं, क्या इस वजह से किसी को हिंसा भड़काने का आरोपी बनाया जा सकता है। देश में जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, या धर्म संसदें लगाई जाती हैं, उनमें कहीं ज्यादा हिंसक शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर पांच साल बिना सुनवाई के जेल में नहीं रखा जाता। अगर किसी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज होती भी है, तो जेल से पहले ही जमानत मिल जाती है।

कई हाईप्रोफाइल मामलों में भी पेशेवर अपराधी या तो जेल में ठाठ से रहते हैं या बाहर खुले घूमते हैं। जबकि उमर खालिद की तो कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। वे गांधी और अहिंसा की बात करते हैं, आदिवासियों के हक से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने पीएचडी की है। जेएनयू में छात्र नेता रहते हुए वंचितों के लिए आवाज उठाई और मजहब से वे मुसलमान हैं, क्या उनकी इस लंबी गिरफ्तारी के लिए ये असल कारक हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए।

वैसे याद दिला दें कि बलात्कार और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम पांच अगस्त को 40 दिन की पैरोल पर फिर बाहर आया था। इससे पहले दिल्ली चुनाव के वक्त 30 दिन और हरियाणा चुनाव के वक्त 20 दिन की पैरोल उसे दी गई थी। पैरोल का यह सिलसिला बार-बार चलता ही रहता है। कानून के रक्षक इस पर भी विचार करे।

भंडारे में गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

प्रचलित मुहावरा है भंडारे में गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। अनुभवी कह गए हैं कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलते, न ही दो नावों की सवारी एक साथ की जा सकती है। वैसे तो ये सारी बातें जैविक तरीके से इस दुनिया में जन्म लेने वाले लोगों अर्थात साधारण मनुष्यों पर लागू होती हैं, लेकिन इस वक्त अपवादस्वरूप नॉन बायलॉजिकल तरीके से धरती पर आने का दावा करने पर श्रीमान मोदी पर भी लागू हो रही हैं। बिहार चुनाव जीतने के लिए अपनी मां के नाम पर कहे अपशब्द को रोकर भुनाने की जो कोशिश 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसका तो कोई फायदा फिलहाल मिलते नहीं दिख रहा है, बल्कि लोग पुराने वीडियो निकाल कर और दिखा दे रहे हैं कि खुद श्री मोदी ने कितनी बार महिलाओं का अपमान किया, या महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ वो खड़े रहे। वहीं जापान और चीन की यात्रा से जो सुर्खियां नरेन्द्र मोदी को बटोरने का मौका मिला था, वो भी खाक हो गया। ऐसा लग रहा है कि श्री मोदी के सलाहकारों की रणनीति या तो चूक रही है, या वे अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं। चीन में वैश्विक नेताओं से नजदीकी और मोदी के जलवे का जो बुलबुला मीडिया ने तैयार किया था, उसे खुद मोदी ने अपने बयान से ध्वस्त कर दिया। 2 सितंबर से लेकर अगले दिन तक पूरा मीडिया मोदी की मां का अपमान, कांग्रेस राजद माफी मांगों जैसे नैरेटिव सेट कर माहौल बनाता रहा कि बिहार में महागठबंधन की हार इस मुद्दे पर हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि मोदी के लिए दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम वाली बात भी चरितार्थ हो रही है। चीन में शाहबाज शरीफ महफिल लूट रहे हैं और इधर भाजपा महिला सम्मान पर अपना बचाव नहीं कर पा रही है।

गौरतलब है कि विपक्ष की बिहार में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली वोटर अधिकार यात्रा की सफलता को भाजपा ने कई तरीके से खारिज करने की कोशिश की। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बल्कि ट्रंप के लगाए टैरिफ और भारत-पाक पर दिए बयान से श्री मोदी की उलझनें और बढ़ती गईं। चुनाव आयोग भी अब तक विपक्ष की तरफ से उठाए गए वोट चोरी के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। यही वजह रही कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद रहा। यात्रा की सफलता राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रही है, जिससे भाजपा का घबराना स्वाभाविक है।

इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन की यात्राओं पर गए। जापान यात्रा में तो मोदी मेरे भगवान टाइप स्वागत सत्कार और बुलेट ट्रेन की सवारी जैसी खबरें मीडिया दिखाता रहा। लेकिन असली टीआरपी कमाने का मौका चीन के दौरे पर मिला, जब सात साल बाद नरेन्द्र मोदी चीन पहुंचे, मौका था शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक का। यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से नरेन्द्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। मीडिया ने गान गाया ड्रैगन-हाथी साथ आए तो अमेरिका डर गया। फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, श्री मोदी को अपने साथ अपनी अत्याधुनिक कार में सम्मेलन स्थल तक ले गए, इसका वीडियो सामने आया। कैमरामैन ने एंगल मोदी की तरफ से रखा था, ताकि उन पर अच्छे से फोकस हो। मीडिया ने बताया कि दस मिनट के सफर में मोदी-पुतिन के बीच अच्छी बातचीत हुई। हालांकि ये कभी पता ही नहीं चलता कि असल में क्या बात हुई, क्योंकि ऐसे वीडियो बिना आवाज के भाजपा प्रसारित करती है। एक वीडियो में मोदी पुतिन और जिनपिंग के बीच हो रही चर्चा में बीच में दिख रहे हैं, पुतिन का हाथ पकड़कर

> **प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन की यात्राओं पर गए। जापान यात्रा में तो मोदी मेरे भगवान टाइप स्वागत सत्कार और बुलेट ट्रेन की सवारी जैसी खबरें मीडिया दिखाता रहा। लेकिन असली टीआरपी कमाने का मौका चीन के दौरे पर मिला, जब सात साल बाद नरेन्द्र मोदी चीन पहुंचे, मौका था शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक का। यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से नरेन्द्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई।**

जोर-जोर से हँस रहे हैं। पता नहीं मोदीजी को विदेश जाते ही क्या हो जाता है, उनके ठहाके गूंजने लगते हैं। देश में तो कभी इस तरह उन्हें किसी के साथ हँसते नहीं देखा गया। बहरहाल, इस वीडियो पर भी सवाल उठे कि जब पुतिन रूसी और जिनपिंग मंदारिन (चीन की भाषा) बोल रहे थे, तो उनके अनुवाद से पहले ही मोदी को ऐसा कौन सा चुटकुला समझ आ गया कि जोर से हँसने लगे। ऐसे ही ठहाके मोदी ने जो बाइडेन के सामने लगाए, फिर कनाडा में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के दौरान लगाए। लेकिन इस हँसी-खेल में भारत के हित कितने सुरक्षित हैं, इसका जवाब न भाजपा देती है, न नरेन्द्र मोदी। भाजपा को इसी से मतलब है कि किसी भी तरह विश्वगुरु वाली छवि बनाई जाए। इसलिए पुतिन और जिनपिंग के साथ मोदी की तस्वीरों को शक्तिशाली तिकड़ी, मोदी की ताकत की तरह मीडिया से पेश करवाया गया। मोदी तो लौट आए, लेकिन चीन के तियेनमान चौक पर चीनी सेना की परेड की जो तस्वीरें सामने आईं वो नए सवाल खड़े कर रही हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान को हराने के 80 बरस पूरे होने की इस परेड में शामिल होने उ.कोरिया से किम जोंग उन भी पहुंचे। पुतिन ने किम जोंग उन को भी अपनी कार में बिठाया। परेड स्थल पर शी जिनपिंग, व्लादीमीर पुतिन और किम जोंग उन के ठीक पीछे शाहबाज़ शरीफ थे। पुतिन-शरीफ वार्ता के वीडियो भी सामने आए हैं। पुतिन ने पाकिस्तान को अपना पुराना सहयोगी बताया है। वहीं शरीफ ने पुतिन से कहा है कि आप भारत से दोस्ती निभाइए, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हमारा भी सहयोग करिए क्योंकि क्षेत्र की स्थिरता के लिए यह जरूरी है। ट्रंप पहले ही पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाक की पूरी मदद की, रूस भी उसके साथ आ रहा है। क्या इस नए समीकरण को मोदी ठहाकों में उड़ा सकते हैं, यह देखना होगा।

मोदी के लिए इस समय भारत की कुशलता से ज्यादा जरूरी शायद बिहार चुनाव जीतना है। इसलिए चीन से लौटते ही अगले दिन बिहार की महिलाओं से वर्चुअली संवाद किया और इस मौके पर करीब एक सप्ताह पहले दरभंगा में घटी घटना पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा। जिसमें किसी ने श्री मोदी को मां का नाम लेकर अपशब्द कहे। इस घटना की निंदा कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने फौरन की, लेकिन उस वक्त मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया। इस बीच उनके बाकी कार्य-व्यापार, सैर-सपाटा सब चले। चीन में हँसी-मजाक करने में उन्हें गुरेज नहीं हुआ। लेकिन बिहार की महिलाओं से सतबहिनी और छठी मईया का नाम लेकर अपनी मां के अपमान की बात मोदी ने की और रोए, इस दौरान बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी रो पड़े। जबकि दो महीने पहले श्री जायसवाल ने कैमरे पर ही बताया था कि उनके गांव में मास्टर को मां का नाम लेकर गाली दी जाती है।

पिछले लोकसभा चुनावों के वक्त ही एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी के शब्द थे कि जब तक मां जीवित थीं, मैं मानता था कि मेरा जन्म बायलॉजिकल तरीके से हुआ है, लेकिन मां के जाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। यह भी सीधे-सीधे अपनी मां का अपमान था, जिसके 9 महीने के कष्ट को एक झटके में मोदी ने खारिज किया। नोटबंदी के वक्त अपनी मां को बैंक की लाइन में खड़ा करवाना या जब वे आईसीयू में थी, तो उन्हें देखने के लिए कैमरामैनों की टीम के साथ भीतर जाना, यह भी उन्हें कष्ट देना ही था। लेकिन इन सबमें श्री मोदी को मां का अपमान नहीं दिखा। आसाराम, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना, प्रेम शुक्ला ऐसे दसियों लोग मोदी के साथ दिखे हैं या उनके करीबी रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरह महिलाओं का अपमान किया या उनका शोषण किया।

विवाहित होने के बावजूद मोदी अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। अब तक यही बताया गया है कि श्री मोदी ने विवाह के कुछ वक्त बाद ही इस संबंध से खुद को अलग कर लिया था। मगर क्या उनकी पत्नी जसोदाबेन की मर्जी कभी पता चली है कि क्या वे भी विवाहिता होने के बाद परित्यक्ता की तरह रहना चाहती थीं या नहीं, या उनकी कुछ और इच्छा थी। अपने विवाहित होने का सच चुनाव के शपथपत्र में न बताना, यह भी तो विवाह जैसी संस्था का अपमान है। क्या यह सब नारी शक्ति का अपमान नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राबड़ी देवी, रेणुका चौधरी, बिल्किस बानो, कर्नल सोफिया कुरैशी ऐसी कितनी ही महिलाओं का अपमान मोदी या भाजपा या उनसे जुड़े लोगों ने किया है। मणिपुर तो महिला अपमान की पराकाष्ठा दिखा चुका है। इसका हिसाब करने बैठे तो भाजपा पूरी तरह कटघरे में दिखाई देगी। कांग्रेस समेत विपक्ष के बाकी दलों में कुछ लोग ऐसे होंगे, जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में पूरी तरह बेदाग हैं। मोदी कभी इस मामले में उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भी अनेक मौकों पर देखा गया है कि कैसे महिलाएं खुद बढ़कर उनसे मिलती है, हाथ मिलाती हैं, गले लगती हैं और बेझिझक अपना स्नेह और प्यार उनके लिए दिखाती हैं। इसलिए भले ही विपक्ष के मंच से श्री मोदी के लिए अपशब्द कहे गए, लेकिन उसमें राहुल गांधी या तेजस्वी यादव पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि वे वहां थे ही नहीं।

जहां तक महिलाओं के अपमान की बात है तो यह भारतीय समाज का कड़वा सच है। सारे अपशब्द महिलाओं से जुड़े होते हैं। महिलाएं कारोबार, राजनीति, फिल्म, कला, खेल किसी भी क्षेत्र में तरक्की करें, उन्हें लांछित करना शुरु हो जाता है। नरेन्द्र मोदी चाहते तो 11 बरसों में समाज की इस मानसिकता को बदलने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन जिन्हें कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय जैसे शब्दों के सहारे भाषण देना आता हो, वे अब रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते।

खामोश की जातीं पर्यावरण बचाने वालों की आवाज़ें

■ कुमार सिद्धार्थ

वैश्विक स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर मंडरा रहे भयावह संकट को उजागर करने वाली हाल की 'ग्लोबल विटनेस' रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2012 से अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष करते हुए 2,106 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इनमें से एक-तिहाई से अधिक हत्याएं लैटिन अमेरिका में हुईं। अकेले वर्ष 2023 में कम-से-कम 196 लोगों की जानें गईं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग आज भयंकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खतरों का सामना कर रहे हैं। खनन, औद्योगिक और निर्माण परियोजनाओं के खिलाफ खड़े होने के कारण ये कार्यकर्ता सत्ता और पूंजी के निशाने पर आ जाते हैं।

'ग्लोबल विटनेस,' जो बीते ढाई दशक से तेल, गैस, खनन और वन क्षेत्रों में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय शोषण की जांच करता रहा है, ने इस रिपोर्ट को 200 से अधिक देशों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 90 फीसदी से अधिक लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है और 25 फीसदी से अधिक पर हिंसक हमले हुए हैं। 70 फीसदी हत्याएं खनन, बड़े बांधों और जंगलों की कटाई के खिलाफ आंदोलन करने वालों की हुई हैं।

> **आज जब जलवायु संकट के प्रभाव दुनिया के हर कोने में महसूस किए जा रहे हैं - बाढ़, सूखा, जंगल की आग, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोत्तरी- ऐसे समय में पर्यावरण रक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट कुछ अहम सुझाव भी देती है - जैसे पर्यावरण रक्षकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाना, उनके खिलाफ दमनकारी मुकदमों को रोका जाना और जिम्मेदार कंपनियों की जवाबदेही तय करना, लेकिन यह तभी संभव है जब नागरिक समाज, मीडिया और आम जनमानस इन मुद्दों को अपने विमर्श के केंद्र में लाएं।**

रिपोर्ट बताती है कि विकास की आड़ में स्थानीय समुदाय, विशेषकर आदिवासी, किसान, महिलाएं और मछुआरे, खास निशाने पर हैं। जब ये समुदाय अपनी ज़मीन, जंगल और नदियों के संरक्षण की आवाज उठाते हैं, तो या तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाता है या फिर वे गोलियों का शिकार होते हैं। कोलंबिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, कांगो और होंडुरास जैसे देश इस हिंसा के गवाह हैं। यहां हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वे अपने जंगल, नदियों, खेतों और अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं।

कोलंबिया लगातार दूसरे साल सबसे खतरनाक देश माना गया था जहाँ 2023 में 79 पर्यावरण रक्षकों की हत्याएं हुईं। यह लगातार चौथा वर्ष है, जब कोलंबिया में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज हुई हैं। वर्ष 2012 से अब तक ऐसी 461 हत्याएं हुई हैं, जो किसी भी देश के मुकाबले अधिक हैं। इसके बाद ब्राजील में 34, मैक्सिको और होंडुरास में 18-18 और फिलीपींस में 11 पर्यावरण रक्षकों की हत्याएं हुईं। मध्य अमेरिका पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए सबसे खतरनाक क्षेत्र बन चुका है, जहां प्रति व्यक्ति हत्याओं की दर सबसे अधिक रही है।

इनमें से अधिकांश हमले वनों की रक्षा करने वालों, खनन विरोधी आंदोलनों में शामिल लोगों और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों पर हुए हैं। अक्सर ये हमले संगठित अपराधियों, सरकार समर्थित ठेकेदारों या निजी कंपनियों के इशारों पर होते हैं। इंडोनेशिया और थाईलैंड में कार्यकर्ताओं को 'रेड टैगिंग' (देशद्रोही) करार देकर मारा या गायब किया जा रहा है।

इन मामलों में भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 के बीच भारत में 71 पर्यावरण रक्षकों की हत्या दर्ज की गई। इनमें से कई पत्रकार थे, जो ज़मीन अधिग्रहण और अवैध खनन जैसे संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वर्ष 2014 के बाद मारे गए 28 पत्रकारों में से 13 पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे थे। भारत में रेत-माफिया और अवैध खनन पर लिखने वाले पत्रकारों को खासकर निशाना बनाया गया।

रिपोर्ट इंगित करती है कि भारत में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों और पत्रकारों पर बढ़ती निगरानी, गिरफ्तारी और बदनाम करने की घटनाओं में तेज़ी आई है। साथ ही, उनके खिलाफ 'गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम' (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों का दुरुपयोग कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सरकारों द्वारा कार्यकर्ताओं को वर्षों जेल में रखना, उनकी जमानत रोकना और उन्हें 'राष्ट्रविरोधी' करार देना जैसी घटनाएं कई राज्यों में सामने आई हैं।

'ग्लोबल विटनेस' के अनुसार, भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों पर मनमाने आपराधिक आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है और उनके बैंक खाते फ्रीज़ कर दिए गए हैं, जिससे नागरिक समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट इस बात पर भी ज़ोर देती है कि कई देशों में पर्यावरण कार्यकर्ताओं को ऐसे मुकदमों का सामना करना पड़ता है जिनका उद्देश्य ही जनहित में उठी आवाज़ों को रोकना है। ये मुकदमे इतने लंबे और खर्चीले होते हैं कि आम नागरिक उनमें फँसकर टूट जाते हैं या चुप हो जाते हैं।

आदिवासी समुदाय इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं - कुल हत्याओं के 34 फीसदी शिकार आदिवासी रहे हैं। उनके पास कानूनी दस्तावेज़ों का अभाव, मुख्यधारा से दूरी और राजनीतिक समर्थन की कमी उन्हें कमजोर बनाती है, जबकि यही समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सहजीवन की मिसाल पेश करते आए हैं।

'ग्लोबल विटनेस' रिपोर्ट की भूमिका में प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डॉ. वंदना शिवा लिखती हैं - 'हम केवल जलवायु आपातकाल के दौर में नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक प्रजातीय विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में ये पर्यावरण कार्यकर्ता उन चुनिंदा लोगों में हैं, जो इस लड़ाई में डटे हुए हैं। वे न केवल नैतिक दृष्टिकोण से सही हैं, बल्कि इसलिए भी सुरक्षा पाने के अधिकारी हैं क्योंकि हमारी प्रजाति और हमारे हरित ग्रह का भविष्य उन्हीं के संघर्षों पर टिका है।'

आज जब जलवायु संकट के प्रभाव दुनिया के हर कोने में महसूस किए जा रहे हैं - बाढ़, सूखा, जंगल की आग, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोत्तरी- ऐसे समय में पर्यावरण रक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट कुछ अहम सुझाव भी देती है - जैसे पर्यावरण रक्षकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाना, उनके खिलाफ दमनकारी मुकदमों को रोका जाना और जिम्मेदार कंपनियों की जवाबदेही तय करना, लेकिन यह तभी संभव है जब नागरिक समाज, मीडिया और आम जनमानस इन मुद्दों को अपने विमर्श के केंद्र में लाएं।

हाल ही में 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस' (आईसीजे) ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जलवायु संकट से निपटना सभी देशों की कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह फैसला बताता है कि अब जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून का भी गंभीर मुद्दा बन चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इससे उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं सामाजिक कार्यों से संबद्ध हैं।)

आपके पत्र

लगातार बारिश, बढ़ते खतरे और हमारी जिम्मेदारी

बरसात का मौसम प्रकृति की सबसे सुंदर देन है। यह धरती की प्यास बुझाता है, फसलों को जीवन देता है, नदियों और तालाबों को भरता है और वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन जब यह बारिश लगातार और असामान्य रूप से होती है, तो यही वरदान कभी-कभी अभिशाप का रूप भी ले लेता है। भारत जैसे देश में, जहां अब भी बुनियादी ढांचे की मजबूती पूरी तरह से नहीं हो पाई है, वहां लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि असामान्य बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

ऐसे समय में केवल सरकार या प्रशासन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह स्वयं भी सावधानी बरते और दूसरों को जागरूक करे। यह सच है कि प्राकृतिक आपदाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन सावधानी और अनुशासन से हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। बरसात के दिनों में सबसे बड़ा खतरा बिजली से होता है। जब जमीन गीली हो, सड़कें पानी से भरी हों और चारों ओर नमी फैली हो, तो करंट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बिजली विभाग ने समय रहते जनता को चेताया है कि इस मौसम में बिजली की तारों, खंभों, केबल और मीटर से दूरी बनाए रखें। ज़रा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। भारत में हर साल बारिश के मौसम में सैकड़ों लोग बिजली के करंट की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। नेशनल क्र इम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (हृष्टक्रक्च) की रिपोर्ट के अनुसार, केवल बिजली से जुड़े हादसों में हर साल करीब 10-12 हज़ार लोगों की मौत होती है, जिनमें बड़ी संख्या बारिश के महीनों में होती है। यह आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि खतरा कितना गंभीर है।

गांव और कस्बों में अब भी खुले तार, ढीले खंभे और जर्जर पोल आम दृश्य हैं। लगातार बारिश में जब ये पानी में डूब जाते हैं, तो इनमें करंट फैलने की संभावना बढ़ जाती है। यह खतरा और भी बढ़ जाता है जब लोग असावधानीवश इनसे संपर्क में आ जाते हैं। कई बार बच्चे खेल-खेल में पानी के गड्ढों में उतर जाते हैं, जबकि उन्हें यह पता नहीं होता कि उसी पानी में कोई बिजली का तार गिरा हुआ है। ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं और यह हमारे समाज की सबसे बड़ी असावधानी को दर्शाती हैं।

बरसात जैसी प्राकृतिक चुनौती का सामना केवल प्रशासनिक उपायों से नहीं किया जा सकता। समाज को भी जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मोहल्ले और गांव के लोग मिलकर नालियां साफ रखें ताकि जलभराव न हो। बिजली के खंभों और तारों की जानकारी विभाग तक पहुंचाएं। बच्चों को सिखाएं कि बारिश में खुले तार या पोल के पास न जाएं। सोशल मीडिया पर केवल सही जानकारी फैलाएं, अफवाहें नहीं। कई बार झूठी खबरें और अफवाहें स्थिति को और गंभीर बना देती हैं।

-प्रियंका सौरभ

ललित सुरजन की कलम से

चुनावों में बदजुबानी

'नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में बार-बार जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वह असंसदीय भले न हो, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि उससे अनावश्यक कटुता उत्पन्न हो रही है। आज जब भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी को भुला दिया है तब उसे यह याद दिलाना उचित होगा कि दूसरी लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्य वाजपेयीजी ने जब अपना प्रथम वक्तव्य दिया तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें स्वयं होकर बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी थीं। एक क्षण के लिए कल्पना करें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो क्या वे इसी तरह राहुल गांधी को उनके भाषण पर बधाई देने में विशाल हृदयता का परिचय दे सकेंगे? जिस तरह से श्री मोदी बार-बार राहुल गांधी और उनके परिवार पर कटाक्ष कर रहे हैं उसे देखकर ऐसी कोई उम्मीद रखना व्यर्थ है।'

(देशबन्धु में 24 अप्रैल 2014 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2014/04/blog-post_23.html

गुरवाणी विचार

धनासरी महला 5

सिमरे सिमर सिमर सुख पावो, सांस सांस समा ले
इह लोक परलोक संग साहई, जत तत मोहे रखवाले
गुरु का बचन वसै जिओ नाले।
जल नहीं डूबे तसकर नहीं लेवे, भाये न साके जालै (रहाओ)
निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बालै
सागह महि बोइथ पायो हरि,नानक करी किरपा किरपाले।

इन शब्दों द्वारा पांचवे नानक गुरु अर्जुन देव हमें समझा रहे हैं कि प्रभु परमात्मा ने हमें इस संसार में कुछ श्वांसों की पूंजी देकर भेजा है। हमारा फर्ज है कि हम इन श्वांसों की पूंजी का सदुपयोग कर के एक अच्छे व्यापारी की तरह करके लाभ कमा ले। तभी हम गुरमुख कहला सकते हैं-

गुरमुख लाहा ले गये मनमुख चले मूल गंवाये जीओ।

परमात्मा द्वारा दी गई श्वांसों की पूंजी का उपयोग उसके सिमरन भजन करने में ही लगायें क्योंकि यही हमें प्रभु के दरबार में स्थान दिलायेगा। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। प्रभु भजन में ही हम अपना लोक और परलोक संवार सकते हैं। परंतु यह तभी संभव होगा जब हम पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे-

लख खुशियां पावशाहियां पातशाहियां जे सतगुरु नदरि करे।

हम उनकी सिमरन भक्ति में इतने लीन हो जाएं कि उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बन जाएं तभी हमारा इस संसार में आना और मानवदेही पाना सफल हो सकता है। प्रभु की नजरे इनायत होने पर ही हमें किसी बात का डर नहीं सताता। जिस तरह एक निर्धन व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, एक अंधे को लाठी के सहारे की जरूरत होती है। ऐसे ही हमें भी हर वक्त प्रभु परमात्मा के मार्गदर्शन की जरूरत होती है और इसके लिए हमें हमेशा सिमरन भक्ति करते रहना चाहिए। नामधन की प्राप्ति हो जाने पर बाकी सब धन विष के समान है-

नाम धन होर सब बिख समान,
माया मोह जले अभिमान।

परंतु हम नासमझी में मूढ़ अज्ञानी बनकर कच्चे धन से नाते जोड़ते चले जाते हैं जो हमें किसी प्रकार की मदद करने वाला नहीं है।

कांचा धन संचै मूरख गंवार मनमुख भूले अंध अंधार।
बिखिया के धन सदा दुख होय न साथ जाय न परापत होय।

इसलिए हमें सांचा धन ही खरीदना है और सांचा धन हमें किसी असहाय जरूरतमंद की मदद कर, साध संगत में जाकर कथा कीर्तन श्रवण कर प्रभु सिमरन भजन बंदगी में जुड़कर प्राप्त हो सकता है और यही सांचा धन हमें प्रभु लोक प्राप्ति में सहायक हो सकता है, यमदूतों की मार से बचा सकता और प्रभु के सांचे दरबार में स्थान दिला सकता है। हमारा लोक परलोक सुहेला कर सकता है।

नामा कहे त्रिलोचना मुख ते नाम संभालि।
हाथ पांव से काम सब चित निरंजन नालि।।

-इंदरसिंह आहुजा

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

सोशल मीडिया पर लगाम कसना समय की जरूरत

दुनियाभर में सोशल मीडिया को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसमें दोराय नहीं होनी चाहिए कि अनेक मौकों पर सोशल मीडिया में समाज में एकजुटता लाने में अहम भूमिका निभाई है। नागरिक अधिकारों को लेकर अनेक देशों में छिड़े आंदोलनों में इसी मीडिया का महती योगदान रहा। ट्यूनीशिया से लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को गति देने में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका थी। दुनिया ही नहीं, भारत में भी अण्णा आंदोलन की सफलता की जड़ में सोशल मीडिया ही था। इसका इतना प्रचार हुआ कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जड़ें देश के गांव-देहात तक पहुंचने में महज कुछ ही दिन लगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के निर्भया कांड को कौन भूल सकता है। यह सोशल मीडिया पर इतना चर्चित हुआ कि सरकार को आधी आबादी की सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव करना पड़ा। देश से लेकर विदेशों तक के लोगों को एक साथ जोड़ने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह रही कि सोशल मीडिया को वैश्विक इतिहास का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कहा जाने लगा, लेकिन बीते कुछ बरसों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिससे यही सोशल मीडिया दैत्याकार और विनाशक के रूप में देखा जाने लगा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ अच्छा प्रसारित हो रहा है, लेकिन इस अच्छे की तुलना में फेक न्यूज, भ्रामक सामग्री और किसी की भी इज्जत उछालने वाला कटेंट अधिक फैलाया जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों का भ्रम बढ़ा है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की चुनौती भी बढ़ी है। फेक न्यूज को ऐसे फैलाया जाता है कि सामान्य यूजर तक उसकी सच्चाई नहीं समझ पाता। इसी संदर्भ में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने तो यहां तक कह दिया कि वे सोच रहे हैं कि एंड्रॉयड फोन की बजाय फीचर फोन ले लें, ताकि नकारात्मकता से बचे रह सकें। सोशल मीडिया समाज में नकारात्मकता का जहर घोल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में लगभग 491 मिलियन (59.1 करोड़) सोशल मीडिया उपयोगकर्ता थे, जो देश की कुल जनसंख्या का 33.7 फीसदी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हर साल इनमें में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 56.6 करोड़ से अधिक फेसबुक उपयोगकर्ता हैं। 491 मिलियन (करीब 49.1 करोड़) लोग यूट्यूब और 414 मिलियन (41.4 करोड़) इंस्टाग्राम चलाते हैं। हालांकि इनमें एक बड़ी भीड़ महज मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर है। इन्हें जो परोसा जा रहा है, उस पर भी विचार किया जाना बहुत जरूरी है। यही टिप्पणी बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल यूट्यूब पर झूठी और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इन्हें रोकने के लिए मानहानि का कानून काफी नहीं है। लोग बेझिझक किसी को भी बदनाम कर रहे हैं और उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, इस पर काबू पाने के लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। हाईकोर्ट कन्नड़ प्रभा के एडिटर-इन-चीफ रवि हेगडे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह पहला मौका नहीं है जब किसी अदालत ने ऐसी टिप्पणी की हो। सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया को लेकर एक कानून बनाए, जिसमें एक लक्ष्मण रेखा तय की जाए ताकि कोई उसे पार करने की हिम्मत न करें। आम जनमानस को भी चाहिए कि भ्रामक प्रचार करने वाले सोशल मीडिया चैनलों का बहिष्कार करें। तभी उन पर लगाम लग सकेगी। यही समय की जरूरत है।

तूल पकड़ रहा बिहार में घुसपैठिया विवाद

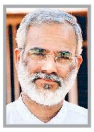

एसआईआर
शशिधर खान

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 'संदिग्ध नागरिकता' को लेकर लगभग 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और यहां तक कि अफगानिस्तान से भी आने का संदेह है। ये मतदाता पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से सटे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार में विपक्षी दलों के रवैए पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने से कई गुना ज्यादा आवेदन चुनाव आयोग को नाम काटने के लिए मिला है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया है कि असम के साथ पूरे देश को अवैध विदेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का वादा निभाएंगे। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने असम से ही यह वादा किया था, जिसे 10 साल में पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वादा निभांएगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में घोषित केन्द्र का उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिसन घुसपैठियों की पहचान दिशा में एक निर्णायक कदम है। केन्द्रीय गृह मंत्री उस समय यह बात कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का आधार और बंगला भाषा को इसका जरिया बनाने के आरोपों पर केंद्र सरकार को जवाब-तलब कर रही थी। जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस जोयमाल्या बागची की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 29 अगस्त को केंद्र सरकार से कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचना को स्पष्ट करें, जिसमें अधिकारियों को अवैध आप्रवासियों की देशव्यापी पहचान अभियान चलाने और उन्हें निकाल बाहर करने को अधिकृत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने केंद्र से इन आरोपों पर भी जवाब मांगा कि बंगला-भाषी अल्पसंख्यकों को लक्ष्य करके यह अभियान चलाया जा रहा है।

29 अगस्त को ही अमित शाह असम के मतदाताओं से अपना वादा याद दिला रहे थे। उसी दिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 'संदिग्ध नागरिकता' को लेकर लगभग 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और यहां तक कि अफगानिस्तान से भी आने का संदेह है। ये मतदाता पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से सटे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल के हैं। उनमें ज्यादातर बंगला भाषी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। किशनगंज जिले से रिपोर्ट है कि नेपाल से आयी बहुओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ रहा है। बंगला भाषी अल्पसंख्यकों को लक्ष्य करके एसओपी अभियान चलाने का केंद्र सरकार पर आरोप पश्चिम बंगाल से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सबसे ज्यादा इसको लेकर विवाद पश्चिम बंगाल में ही तूल पकड़ा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के साथ-साथ असम में भी बड़ी तादाद में बंगलाभाषी अल्पसंख्यकों के समर्थन में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने पहुंचे अटोर्नी जनरल तुषार मेहता ने पीठ के दोनों जजों को यह कहकर आश्वस्त करना चाहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) अभियान को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता संगठन के पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा समर्थन किया जाना 'दुर्भाग्यपूर्ण' है। उन्होंने शीर्ष कोर्ट पीठ को बताया कि 'भारत अवैध आप्रवासियों की विश्व राजधानी नहीं है। घुसपैठ की समस्या संसाधन चटकर जाती है,जो भारतवासी नागरिकों के लिए है।' एसओपी अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 02 मई को जब जारी की और विदेशी घुसपैठियों की पहचान निकाल-बाहर अभियान शुरू हुआ, उसी समय सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गयी। याचिका दायर करने वाले

पश्चिम बंगाल आप्रवासी कामगार कल्याण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 'बांग्लादेशी' होने के संदेह में बंगाली बोलने वाले पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को लक्ष्य करके उन्हें हिरासत में रखा जा रहा है। बंगाल आप्रवासी कामगार बोर्ड की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक गर्भवती महिला सोमाली बीबी का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया और बताया कि उसकी नागरिकता निर्धारित किए बगैर सोनाली बीबी को कथित रूप से बांग्लादेश भेज दिया गया। उन्होंने दलील दी कि इस तरह निकाल-बाहर करना अवैध है, क्योंकि इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी और इस बात के भी सबूत नहीं हैं कि ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए बांग्लादेश से कोई समझौता हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले 28 अगस्त को भारत और बांग्लादेश के बीच घुसपैठ पर रोक लगाने के संबंध में सहमति बनी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपदस्थ किए जाने के बाद 5 अगस्त को भारत आ गयीं। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हुए हैं लेकिन घुसपैठ पर अंकुश लगाने के मामले पर सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने ढाका जाकर बातचीत की। ढाका ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल पर अवैध रूप से आप्रवासियों को भेजने का आरोप लगाया। बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बल का आरोप था कि भारतीय और म्यांमार राष्ट्रीयता वालों को गैरकानूनी तरीके से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। जबकि भारतीय अधिकारियों का कहना था कि आपसी सहमति से अपनायी गयी प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने माना कि यह 'जटिल मुद्दा' है और विभिन्न देशों ने इस पर अलग-अलग नीतियां अपना रखी है। संयोग कुछ ऐसा है कि बिहार के मतदाता सूची विवाद की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट पीठ के एक जज जस्टिस सूर्यकान्त ने ही नागरिकता कानून के सेक्शन 6ए पर फैसला लिखा था, जो बांग्लादेश से आए आप्रवासियों को नागरिकता देने से जुड़ा है। अगले वर्ष असम और पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव है। इसलिए दोनों राज्यों के लिए एसओपी मायने रखता है। घुसपैठियों वाले मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में भाजपा ने अच्छी खासी विधान सभा और लोकसभा सीटें जीती हुई हैं। बिहार में इसी साल नवंबर में चुनाव है। भाजपा को यहां सरकार का नेतृत्व संभालने का अवसर नहीं मिला है। भाजपा मशहूर पलटू राम नीतीश कुमार के सहारे सत्ता में शामिल हुई है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी एसओपी अधिसूचना और उसके अनुसार चुनाव आयोग की कार्रवाई बिहार को ही लेकर विवाद में है।

संयोग कुछ ऐसा रहा कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के एसआईआर अभियान और घुसपैठ वाला विवाद एक साथ सुर्खियों में आया। इस पर संसद के मानसून सत्र में हंगामा, बिहार में मतदाता सूची विवाद और पश्चिम बंगाल में एसओपी के तहत अधिकारियों द्वारा घुसपैठियों की पहचान तथा निकाल-बाहर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगभग साथ-साथ थोड़े-थोड़े समय के अंतर से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार में विपक्षी दलों के रवैए पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने से कई गुना ज्यादा आवेदन चुनाव आयोग को नाम काटने के लिए मिला है, जबकि उन्हीं दलों ने एसआईआर पर रोक लगाने की अर्जी चुनाव आयोग पर सत्यापन के बहाने वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाकर दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि सूची से हटाए गये जिन 65 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने दावा दाखिल करने का नोटिस दिया है उनकी सहायता कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य
डॉ. नीलू तिवारी

महिलाओं में भी तेजी से घर कर रहा अवसाद

हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक दिल को छूने वाली घटना घटी, जब मानसिक अवसाद से ग्रस्त रानी देवी 17 साल बाद अपने परिवार से मिलीं। रानी देवी की यह घटना समाज के लिए एक बड़ी सीख है। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली रानी देवी वर्ष 2008 में घर से अचानक लापता हो गईं। परिवार ने हर जगह तलाश की, पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और अखबारों में गुमशुदगी का विज्ञापन छपवाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे-धीरे परिवार को यह यकीन हो गया कि वह शायद कभी लौटकर नहीं आएंगी। असल में रानी देवी गंभीर मानसिक अवसाद से जूझ रही थीं। घरेलू दबाव, आर्थिक तंगी और पारिवारिक उपेक्षा ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। इसी मानसिक स्थिति में उन्होंने घर छोड़ दिया और अजनबी शहरों में भटकती रहीं। साल 2025 में एक पुनर्वास केंद्र में समाजसेवियों की नजर उन पर पड़ी। आधार कार्ड और स्थानीय पुलिस की मदद से उनकी पहचान की गई। खबर मिलते ही परिवार को विश्वास नहीं हुआ कि 17 साल से बिछड़ी रानी देवी सचमुच मिल गई हैं। अब बात करते हैं मूल समस्या की। असल में देश में महिलाओं का मानसिक अवसाद केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी सामाजिक समस्या है। भारत जैसे देश में जहां पारंपरिक सोच और आधुनिक जीवनशैली आपस में टकराती हैं, वहां महिलाएं दोहरी चुनौतियों से गुजरती हैं। एक ओर उनसे पारंपरिक भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक प्रतिस्पर्धी समाज में बराबरी साबित करने का दबाव उन पर होता है। यह द्वंद्व की स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या एक गंभीर सामाजिक मुद्दा भी है। पारंपरिक समाज में अक्सर महिलाओं की भावनाओं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके कारण वे अवसाद, चिंता और तनाव जैसी बीमारियों का सामना करती हैं। हाल के शोध बताते हैं कि भारत में अवसाद से पीड़ित कुल मरीजों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। प्राथमिक देखभाल स्तर पर महिलाओं में अवसाद की व्यापकता औसत 41 प्रतिशत है, जो सामाजिक और आर्थिक दबाव, घरेलू हिंसा और शिक्षा की कमी जैसी वजहों से और बढ़ जाती है। वृद्ध महिलाओं में स्थिति और गंभीर होती है, 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में अवसाद की दर 21.7 प्रतिशत पाई गई, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु में यह दर 9.5 प्रतिशत थी, जो पुरुषों की तुलना में अधिक है। मानसिक स्वास्थ्य की कमी और अवसाद का परिणाम आत्महत्या की घटनाओं में भी दिखाई देता है। एनसीआरबी के अनुसार, 2021 में भारत में 164,033 आत्महत्याएं हुईं, जिनमें 48,172 महिलाएं शामिल थीं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि परिवार, समाज और स्वास्थ्य संस्थाओं की मदद के बिना महिलाएं अवसाद के प्रभाव से उबरने में सक्षम नहीं हो पातीं। 2025 के हालिया आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में अनुमानित रूप से लगभग 41.9 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में अवसाद का सामना कर रही हैं। प्रजनन आयु की महिलाओं में मानसिक संकट की दर और भी अधिक पाई गई है। प्रसवोत्तर महिलाओं में भी 19-23 प्रतिशत की दर से अवसाद की घटनाएं दर्ज की गई हैं। शहरी महिलाएं नौकरी, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में मानसिक दबाव झेलती हैं। ग्रामीण भारत में मानसिक अवसाद से ग्रस्त महिलाओं की स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि वे समय पर सही इलाज तक नहीं पहुंच पातीं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अशिक्षा, गरीबी और समाज में मानसिक रोगों को लेकर व्याप्त अंधविश्वास इसके मुख्य कारण हैं। महिलाओं में अवसाद की समस्या का समाधान केवल दवाओं या काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। योग, ध्यान, प्राणायाम और नियमित व्यायाम महिलाओं की मानसिक स्थिति को काफी हद तक संतुलित कर सकते हैं। सरकारी स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं जैसे टेली-मानस हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर विशेष योजनाएं और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। अवसाद से निपटने के लिए केवल चिकित्सकीय इलाज ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज, परिवार और सरकार को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां महिलाएं बिना डर और संकोच के अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात कर सकें। इससे वे अधिक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और स्वस्थ जीवन जी पाएंगी। हम सभी को मिलकर महिलाओं के लिए स्वस्थ माहौल का निर्माण करना होगा, तभी देश और समाज आगे बढ़ पाएंगे।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आनंद आपके भीतर है, खोजने की जरूरत नहीं

संकलित
दर्शन

कल्पना क्या है और सच्चाई क्या है! इसे समझने के लिए आपकी जड़ का मजबूत होना जरूरी है। सारी कल्पनाएं आपके अंदर हैं। यह कल्पना नहीं है, यह सच है। कल्पना में डूबना बड़ा आसान है, सच्चाई को जानना बहुत मुश्किल है। जिसको आप खोज रहे हैं, वह आपके अंदर है। उसे जानिए, पहचानिए, उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि उसमें सबकुछ है। जो आपके भीतर है, वह है शांति। किसी चीज का न होना शांति नहीं है। किसी चीज का होना शांति है। जब मनुष्य खुद को जानेगा, खुद को समझेगा, तब उसके जीवन में शांति होगी। जैसे भोजन खा लेने पर भूख खत्म होती है, उसी प्रकार खुद को जान लेने पर तृष्णा मिट जाती है। शांति मिल जाती है। सोचें कि यह शरीर आपको क्यों मिला है? जिन तत्त्वों से शरीर बना है, वे सारे तत्त्व वहीं वापस चले जाएंगे जहां से ये आये थे। जिस तरह पानी, पानी में मिल जाता है। सारी चीजें प्रकृति में घुल जाएंगी। क्या समझते हैं आप कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस धरती का वजन बढ़ता है! या जब कोई मर जाता है तो इस धरती का वजन कम होता है! वजन न तो बढ़ता है न कम होता है। क्योंकि जिन चीजों से आप बने हुए हैं वे तो अभी यही हैं। परंतु क्या आपने उस चीज को जाना, समझा जो आपके शरीर के अंदर है? इसे जान गए, पहचान गए, फिर आनंद ही आनंद है। आपका नाम आपके शरीर का नाम है। नाम कमाने से क्या होगा। नाम नहीं, ज्ञान कमाइये। आनंद कमाइए। ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं।

ह्रदय से जो जाओगे सबल समझूंगा तोहे

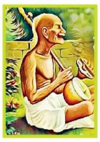

संकलित
प्रेरणा

एक बार सूरदास जी चलते-चलते मार्ग में एक गहरे गढ्ढे में गिर गए और निकलने के सारे प्रयास असफल हो गये। अपने कान्हा को ही पुकारने लगे, एक भक्त अपने जीवन में विपत्ति काल में प्रभु को ही तो पुकारता है। जैसे ही सूरदास जी ने कान्हा को याद किया, प्रभु भी उसकी पुकार सुने बिना नहीं रह पाए! सच है जब एक भक्त दिल से पुकारता है तो यह टीस प्रभु के दिल में भी उठा करती है। उसी समय एक बाल गोपाल के रूप में वहाँ प्रकट हो गए, और प्रभु के पांव की नन्ही-नन्ही सी पैजनिया की छन-छन की आवाज सुनते ही सूरदास जी को समझते देर न लगी। कान्हा उनके समीप आये और बोले अरे बाबा नीचे क्या कर रहे हो, लो मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी से ऊपर चले आओ। जैसे ही सूरदास जी ने इतनी प्यारी सी मिश्री सी घुली हुई वाणी सुनी तो जान गए की मेरा कान्हा आ गया, और बहुत प्रसन्न हो गए, और कहने लगे की अच्छा कान्हा, बाल गोपाल के रूप में आ गए, कन्हाई तुम आ ही गए न? बाल गोपाल कहने लगे अरे कौन कान्हा ? किसका नाम लेते जा रहे हो,जल्दी से हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, ज्यादा बातें न बनाओ। सूरदास जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगेः सच में कान्हा तेरी बांसुरी के भीतर भी वो मधुरता नहीं, माना कि तेरी बांसुरी सारे संसार को नचा दिया करती है लेकिन तेरे भक्तों का दुःख तुझे नचा देता है। क्यों कान्हा सच है न? तभी तो तू दौड़ा चला आया। जैसे ही उन्होंने इतना कहा सूरदास जी ने झट से कान्हा का हाथ पकड़ लिया और उस मंगलमय ब्रह्मसंस्पर्श से वे रोमांचित हो उठे।

अंतर्मन

आज की पाती

राष्ट्रभाषा का विचार अधर में लटका

दक्षिणी राज्यों में हिंदी के विरोध की खबरें प्रधानमंत्री शास्त्री के समय से आज की भाजपा सरकार के वक्त भी सुनी जा रही हैं। तीन भाषाई फार्मूला सबके ध्यान में है, मगर उसकी व्याख्या अलग-अलग ढंग से की जाती है। जिन उत्तरी राज्यों में हिंदी मातृभाषा हो, तो तीसरी भाषा तेलुगू या तमिल होना तय था। मगर ऐसा न करके संस्कृत पढ़ाई गई। दक्षिणी राज्यों में हिंदी का यूं ही सुझाव था। फार्मूला सरल रास्ते ढूंढने के चक्कर में बिखर गया। कभी हिंदोस्तानी राष्ट्रभाषा का विचार भी रहा। नेता जी सुभाषचंद्र बोस के विचार को अधर में छोड़ दिया गया। राष्ट्रभाषा का सवाल भी अधर में लटका रहा। - *ललित शुक्ला, जगदलपुर*

ट्रेंड

सुरक्षाबलों का समर्पण

जब तक सारे नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएँ या समाप्त न हो जाएँ, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस संकल्प को पूरा करने में हमारे सुरक्षाबलों के त्याग और समर्पण पर पूरे देशवासियों को गर्व है।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

राहत कार्य जारी

भारी बारिश और अधिप्रवाह से मुंगेशपुर ड्रेन में दिल्ली सीमा से लगभग 1 किलोमीटर आगे झज्जर, हरियाणा क्षेत्र से लगते किनारे के कटाव से उत्पन्न हुई आपदा पर दोनों राज्यों के अधिकारी प्रभावित इलाकों से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं और राहत कार्यों में जुटे हैं।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

शिवालय पार्क विवाद

कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क मे शिवालय पार्क बनाने का अति-विवादित प्रस्ताव रद्द करने का स्वागत है। उम्मीद है कि यूपी सरकार आगे कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने के षड्यंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती करेगी।

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

सरकार का अभियान

वर्तमान सरकार नाम बदल कर गांव चलो और शहर चलो अभियान लाना चाहती है। बेहतर होता कि हमारे समय शुरू किए गए अभियान को पहले ही नाम बदलकर जारी रख लेती और इतना विलंब न करती।

-अशोक गहलौत, पूर्व सीएम, राजस्थान

करंट अफेयर

पश्चिम एशिया की निगरानी बढ़ाने के लिए उपग्रह प्रक्षेपित

इजराइल ने एक नया जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है, जिसके बारे में रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया में उनकी निगरानी क्षमता को मजबूत करेगा।सैन्य अधिकारियों और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बुधवार को कहा कि मंगलवार देर रात प्रक्षेपित किया गया यह उपग्रह इजराइल की उस क्षमता को बढ़ाएगा, जिसके जरिए उसने इस साल की शुरुआत में हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान से जुड़ी 12,000 तस्वीरें जुटाई थीं। काट्ज ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'यह हमारे सभी दुश्मनों के लिए भी एक संदेश है, चाहे वे कहीं भी हों- हम हर समय और हर परिस्थिति में आप पर नज़र रख रहे हैं।' ईरान की निगरानी के अलावा, इजराइल ने पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता हासिल की है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे 'सात मोर्चों पर लड़े जाने वाला युद्ध' कहा है। इसी के तहत इज़राइली बलों ने 23 महीनों से जारी ग़ाज़ा युद्ध के दौरान लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में भी निशाने साधे हैं। मेजर जनरल अमीर बाराम ने कहा कि 'ओफेक-19' नामक यह उपग्रह उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद है 'पश्चिम एशिया के किसी भी बिंदु पर लगातार और एक साथ निगरानी बनाए रखना।'

ऑफ बीट

हर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ नुकसानदायक नहीं

सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ एक जैसे नहीं होते और न ही सभी हानिकारक होते हैं। यदि आप सुविधाजनक लेकिन सुरक्षित विकल्प चुनना चाहते हैं, तो खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर लेबल पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है। प्रसंस्करण की श्रेणियां क्या हैं? शोधकर्ता नोवा (एनओवीए) वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करके खाद्य पदार्थों को चार प्रसंस्करण स्तरों में बांटते हैं : समूह 1 : अप्रसंस्कृत या न्यूनतम रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्ज़ियां, दूध, अंडे, मांस, दालें, साधारण दही, अनाज आदि। इन्हें घर पर सीधे खाया या न्यूनतम पकाया जा सकता है। समूह 2 : प्रसंस्कृत पाक सामग्री जैसे तेल, चीनी, शहद, जो समूह 1 के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती हैं और स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं। समूह 3 : पारंपरिक विधियों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद फल, चीज़, टमाटर पेस्ट, अचार, साधारण ब्रेड आदि। इन्हें घर पर भी तैयार किया जा सकता है। समूह 4 : अत्यधिक प्रसंस्कृत (अल्ट्रा प्रॉसेस्ड) खाद्य पदार्थ जैसे स्नैक्स, इंस्टैंट नूडल्स, मीठे पेय, बिस्किट, जमी हुई मिठाइयां, फास्ट फूड आदि। इनमें आमतौर पर ऐसे तत्व होते हैं जो घर के रसोईघर में नहीं मिलते और इन्हें खाने की आदत जल्दी लग जाती है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 170

सरकारी मदद अहम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर उद्योग के लोगों से बातचीत में कहा कि भारत आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में 'महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी' हासिल करेगा। वह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात कर रहे थे जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में मंजूरी दी थी। अब इस मिशन के दूसरे चरण की योजना बनाई जा रही है और सरकार ने कहा है कि वह इसके लिए सहयोगी माहौल बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। सेमीकंडक्टर मिशन को सरकार से अन्य प्रकार के समर्थन की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में सब्सिडी प्राप्त हुई है। इस मिशन ने कुछ उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल की हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक परियोजना की पायलट लाइन पूरी हो चुकी है। यह परियोजना मुख्य रूप से सीजी पावर ऐंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के स्वामित्व में है, जिसमें जापान से महत्त्वपूर्ण तकनीकी सहयोग मिला है। इस परियोजना के तहत भारत में बने पहले चिप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

मिशन के दूसरे चरण में उपयुक्त माहौल बनाने पर ध्यान देना एक तरह से स्वाभाविक बदलाव है। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपये का जो आरंभिक बजटीय आवंटन किया गया उसे बार-बार दोहराना मुश्किल नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे चरण में शामिल छोटे और मझोले उपक्रमों को उनके पूंजीगत व्यय के साथ कम मदद की आवश्यकता होगी।

सरकार ने यह भी ध्यान दिया होगा कि कई निवेशकों द्वारा जगह का चयन इस बात से निर्धारित हो रहा है कि उन्हें कैसा माहौल मिल पा रहा है। उदाहरण के लिए सीजी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स (ताइवान की पावरचिप के साथ) दोनों ने गुजरात में दहेज केमिकल्स क्लस्टर के निकट बनने वाले संयंत्रों में निवेश किया है। इससे उन्हें चिप उत्पादन प्रक्रिया के लिए जरूरी करीब 250 गैसें उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसे चयन एक स्थायित्व वाली व्यवस्था की वकालत करते हैं और ऐसे में सरकार द्वारा सहायता करना सही प्रतीत होता है।

बहरहाल कई बातें ऐसी भी हैं कि जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, सहयोग की प्रकृति रणनीतिक होनी चाहिए। भारत संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण करने की नहीं सोच सकता। इस मिशन को उन विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां विदेशी निर्भरता, खासतौर पर चीन पर निर्भरता एक रणनीतिक जोखिम के रूप में देखी जा सकती है। अनुमान्य विदेशी व्यापार नीति भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। यह निवेशकों को भरोसा दिला सकती है कि आपूर्ति श्रृंखला को बाधित नहीं किया जाएगा, भले ही अन्य भू-राजनीतिक मुद्दे सामने आएं। ऐसे तय नीतियों की कोई कीमत नहीं होती और इसे सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य हिस्सा माना जाना चाहिए। सरकार को समयसीमा के मामले में अपनी महत्त्वाकांक्षा का स्तर भी बढ़ाना चाहिए। कैबिनेट द्वारा फंड को मंजूरी देने और पहली परियोजना को मंजूरी देने में 18 महीने लग गए। इसकी तुलना में, इजरायल ने 2023 में इंटेल के लिए 3.2 अरब डॉलर की मंजूरी केवल छह महीनों में दे दी, और फिर भी इसे उन्होंने बहुत लंबा समय माना।

अमेरिका के चिप्स अधिनियम के तहत पहला अनुदान अधिनियम पारित होने के कुछ माह के भीतर दे दिया गया था। जापान की रैपिडस पहल के तहत केवल छह महीनों में धन दे दिया गया। चूंकि दूसरे चरण में पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन पहले चरण में किए गए निवेश निर्णयों को सहयोग देने के लिए है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत तेज समयसीमा में पूरा किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय तुलना से यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय समर्थन की कुछ विशिष्टताएं हैं, जिनके कारण शायद घरेलू कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है।

मिशन द्वारा पूंजीगत व्यय में समानांतर समर्थन उस मॉडल से भिन्न है जो अन्य देशों में अपनाया गया है। जैसे कि अनुदान और ऋण गारंटी अक्सर प्रारंभिक और एक बार में दी जाने वाली सहायता होती है। ये मॉडल टीएसएमसी जैसे शीर्ष स्तरीय निर्माताओं को आकर्षित करने में अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि वे निवेश जोखिम को कम करते हैं और निवेशकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें दीर्घकालिक गैर-आर्थिक समर्थन भी मिलेगा, जैसे कि नियामकीय सहूलियतें। इस दृष्टिकोण के असर की समीक्षा भी दूसरे चरण में अवश्य की जानी चाहिए।

अजय मोहंती

चीन की ओर झुकाव भारत के लिए उपयोगी नहीं

चीन हमारे देश का नैसर्गिक साझेदार नहीं हो सकता। साथ ही, हमें ट्रंप को स्थायी मानकर नहीं चलना चाहिए। दीर्घकालिक नजरिये से देखें तो अमेरिका से भारत के रिश्ते सुधरेंगे। बता रहे हैं अजय शाह

कई वर्षों से भारत और चीन के बीच के रिश्तों में बर्फ जमी है और टकराव होता रहा है। डोकलाम और गलवान में सीमा पर हुई हिंसा के बाद आर्थिक संबंधों को लेकर भारत का रुख यही रहा है कि सीमा पर शांति की शर्त पर ही आर्थिक सहयोग संभव है। सितंबर 2021 में रूपा पब्लिकेशन से एक पुस्तक प्रकाशित हुई 'राइजिंग टु द चाइना चैलेंजः विनिंग थ्रू स्ट्रैटजिक पेशंस ऐंड इकनॉमिक ग्रोथ' (गौतम बंबावाले, विजय केलकर, आरए माशेलकर, गणेश नटराजन, अजित रानाडे और अजय शाह)। इस पुस्तक में कहा गयाः (अ) अल्पावधि में भारत अकेले चीन का सामना करना के लिहाज से कमजोर है, इसलिए दुनिया की प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ गठबंधन करना जरूरी है। (ब) सबसे प्रभावी विदेश नीति यही है कि भारत दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दिशा में कामयाब हो ताकि अगले 25 साल में चीन के साथ शक्ति का असंतुलन कम हो सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के रुख को देखते हुए भारत में कुछ लोग चीन के साथ रिश्तों पर नए सिरे से विचार को तैयार हैं। कुछ लोग सोवियत रूस को काबू करने के एक तरीके के रूप में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर द्वारा चीन की ओर रुख करने की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि भारत भी अमेरिका पर अंकुश के लिए इसी तरह चीन के साथ जा सकता है। इसके लिए इतिहास की गहरी समझ, अतीत पर नजर रखने की क्षमता और व्यापक रणनीतिक नजरिया के साथ आगे की सोच जरूरी है।

एक अच्छी शुरुआत यह होगी कि चीनी विजय दिवस की सैन्य परेड का विश्लेषण किया जाए। इस परेड में रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देशों के विशेष अतिथि शामिल हुए, जो चीन की रणनीतिक दिशा को दर्शाते हैं। बीजिंग में हर कोने पर दो पुलिसकर्मी तैनात थे, थ्येनआनमन चौक में सैन्य उपस्थिति थी, और स्कूलों ने रिमोट यानी ऑनलाइन तरीके से संचालन की घोषणा कर दी थी। यह सब उस स्वस्थ उदार लोकतंत्र की पहचान नहीं है, जो दिखावटी सैन्य परेड नहीं करते। भारत में हमारे दिलों में एक उदार लोकतंत्र है। भारत को चीन के साथ दिखने के लिए अपना यह रुख बदलना नहीं चाहिए। वह हमारा नैसर्गिक साझेदार नहीं है।

ट्रंप अमेरिका की ऐतिहासिक गिरावट के प्रतीक हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद का शिकार हो जाएगा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में महान संस्थान हैं लेकिन अमेरिका किसी उभरते बाजार की तरह ही है। इसके साथ ही हमें ट्रंप को स्थायी मानकर नहीं चलना चाहिए। दशकों तक अमेरिका में दोनों दलों ने भारत के उदय का समर्थन किया और ट्रंप के परे हम एक बेहतर अमेरिका की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रंप के बाद भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे।

अधिकांश चीनी कंपनियों पर वहां की सरकार का नियंत्रण है। भारत वैसा नहीं है और अमेरिका भी नहीं है। ट्रंप के शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद के सप्ताहों में ऐपल तथा किंड्रिल जैसी कंपनियों ने भारत में विस्तार की घोषणा की। अमेरिकी अदालतें जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रही हैं, चीन में तो आप ऐसा होने की सोच भी नहीं सकते। यही बात भारत-अमेरिका रिश्तों को ठहराव प्रदान करती है। वह इसे राजनीतिक जोखिम से अलग करती है। अमेरिका के साथ हमारा विवाद 50 फीसदी शुल्क को लेकर है। चीन के साथ हमारी लड़ाई इससे कहीं अधिक गंभीर है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब चीन पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दे रहा था। तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मॉरीशस में चीन के कदम भारत के हितों के विरुद्ध हैं। चीन दुनिया में बहुध्रुवीयता का उपदेश देता है लेकिन एशिया में वह अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है।

अमेरिकी बाजार सिकुड़ रहे हैं और भारत के लिए बेहतर है कि वह नए निर्यात बाजार तलाशे। ऐसा करने की नैसर्गिक जगह उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें यूरोप से लेकर कनाडा और ताइवान तक शामिल हैं। चीन का बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि चीन अनेक गैर-टैरिफ बाधाओं के साथ मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के साथ धोखाधड़ी करने का प्रमुख उदाहरण है। खुली वैश्विक व्यापार प्रणाली के धीमे पतन के लिए अगर 5 फीसदी श्रेय भारत की अनुचित नीतियों को तो 95 फीसदी श्रेय चीन को दिया जा सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए चीन को निर्यात बढ़ाने का कोई आसान रास्ता नहीं है, जब तक कि चीनी प्रणाली में गहरे बदलाव न किए जाएं, जो आर्थिक राष्ट्रवाद और कानून के शासन के अभाव जैसी बाधाओं से भरी हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था एक अनोखी समस्या से जूझ रही है जो है अति-उत्पादन। उन कई उद्योगों में जहां भारत की मौजूदगी है, चीन से आयात के लिए खुलेपन का अर्थ है, चीन द्वारा अपनी बेरोजगारी का निर्यात करना।

भारत के खिलाफ चीन का आर्थिक दबाव सक्रिय और प्रभावी है। चीन की सरकार भारत के 'चीन+1' के रूप में उभरने में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उन कुछ निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिनमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चीन पर निर्भर करती है। बंबावाले ने ज़ोर देकर कहा है, भले ही आज किसी दिखावटी समझौते के तहत ये प्रतिबंध हटाए जाएं, हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा कि ये निर्यात प्रतिबंध कल फिर से लागू हो सकते हैं। इसलिए भारतीय कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें चीन से स्वतंत्र आपूर्ति तंत्र विकसित करना ही होगा। इसलिए, इस समय कोई त्वरित समझौता वास्तव में समस्या का समाधान नहीं करता।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग मजबूत नहीं दिख रहे हैं। 72 वर्ष की उम्र में उनका प्रभाव घट रहा है। एक अधिनायकवादी व्यवस्था में शांतिपूर्ण उत्तराधिकार के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं होता। उनकी प्राथमिकता सत्ता बनाए रखना है, न कि चीनी जनता की समृद्धि के लिए रणनीतिक सोच रखना। यह भारत के साथ एक समझदारीपूर्ण शांति स्थापित करने की संभावनाओं के अनुरूप नहीं है।

अमेरिकी बाजार में गिरावट एक सीमित समस्या है, जिसे भारतीय कंपनियां हल कर सकती हैं। बशर्ते उन्हें तत्काल नीतिगत समर्थन मिले, जैसे व्यापार बाधाओं को हटाना, अप्रत्यक्ष कर सुधार और मुद्रा का अवमूल्यन। एक देश के रूप में अमेरिका ट्रंप से बेहतर स्थिति में है। आने वाले वर्षों में वहां सुधार होगा। भारत के हित उन्नत लोकतांत्रिक देशों के साथ जुड़े हैं। पश्चिमी देशों में हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, विदेशी पूंजी आती है, वह ज्ञान प्रवाह होता है जो भारत को महान बनाएगा। विदेशी तकनीक, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर यूनिक्स और एलएलएम तक की वैश्विक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, और हमारे निर्यात बाज़ार भी वहीं हैं। हमें इसी रास्ते पर बने रहना चाहिए। अमेरिका के अलावा अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, जिनका संयुक्त बाजार अमेरिका से दोगुना बड़ा है।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

प्रतिबंधों से खत्म नहीं होगी जुए की रवायत

बात 1930 के दशक की है जब मशहूर कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज खिलाड़ी और ताश बनाने वाली कंपनी के मालिक, एली कल्बर्टसन ने सोवियत संघ का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि सोवियत संघ में ताश की बिक्री में सालाना 40 फीसदी की गिरावट आई है और अधिकारियों को उम्मीद थी कि यह बिक्री हर साल कम से कम 20 फीसदी और घटेगी, जब तक कि वह शून्य न हो जाए।

जब कल्बर्टसन ने इसका कारण पूछा तब उन्हें समझाया गया कि कॉमरेड स्टालिन जुए को खत्म करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ताश के सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, बाद में पता चला कि जब स्थानीय स्तर पर ताश उपलब्ध नहीं होते थे तो रूसी लोग स्वीडन से तस्करी करके लाए गए ताश से खेलते थे। यही वजह है कि सोवियत संघ ने ताश का उत्पादन जारी रखा लेकिन साथ ही जुए के आदी लोगों को 'जागरूक' बनाने की कोशिश की जाती थी और जरूरत पड़ने पर उन्हें गुलाग (श्रम शिविर) भेजा जाता था ताकि वे इस खतरनाक आदत से छुटकारा पा सकें।

स्टालिन का निधन 1953 में हुआ था और सोवियत संघ 1991 में खत्म हो गया। लेकिन आज भी इसके बाद बने स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (सीआईएस) में कई बेहतरीन ब्रिज और पोकर खिलाड़ी हैं। इसी तरह, ईरान की इस्लामी सरकार ने भी जुए से जुड़े होने के कारण ताश पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह प्रतिबंध लागू नहीं हो पाया है। ईरानी लोग आज भी भले ही छिपकर, तस्करी करके लाए गए ताश का इस्तेमाल करके कार्ड गेम खेलते हैं।

जुए की प्रवृत्ति मानव प्रजाति के विकासवादी इतिहास में, गहराई से बसी हुई है। पुराने समय में, में तो खाने, पीने, या वंश बढ़ाने के लिए भी जोखिम उठाना पड़ता था। ऐसा भी हो सकता था कि आप खुद ही किसी का आहार बन जाते या किसी गलत संभावित साथी से बात करने पर वंश बढ़ाने के बजाय आप पर हमले का ही खतरा बढ़ जाता।

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

आज अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ता है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज्नियाक और लैरी एलिसन ने कॉलेज छोड़ दिया था, जबकि ईलॉन मस्क अपने वीजा की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से दूसरे देश में रहे थे। शेयर बाजार, बॉन्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में हर व्यापार एक तरह के जुए पर आधारित होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट इसके लिए तैयार रहते हैं कि उनके आधे से ज्यादा निवेश डूब सकते हैं और वे दिवालिया भी हो सकते हैं। जब आप जीवन बीमा का प्रीमियम भरते हैं, तब आप एक ऐसा दांव लगाते हैं जिसे आप हार जाना चाहते हैं। यहां तक कि एक अच्छा वैज्ञानिक शोध भी एक तरह का जुआ है जैसे कि क्वांटम मेकैनिक्स, नई दवाओं की खोज या पीएचडी के लिए किसी सार्थक विषय का चुनाव।

सफल लोग जोखिम लेना सीखते हैं। सफलता से मिलने वाला लाभ, असफलताओं से होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होता है। बिल गेट्स, जॉब्स और मस्क द्वारा लिए गए जोखिमों से लाखों-करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है और यह उन सभी बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों और अवैध प्रवासियों की तुलना में बहुत ज्यादा है जो सफल नहीं हो पाए।

नए ऑनलाइन गेमिंग नियम उसी जगह सफल होने की कोशिश कर रहे हैं जहां कॉमरेड स्टालिन और अयातुल्ला खुमैनी असफल रहे। ये नियम जुए के लिए सख्त दंड तय करते हैं, जो सोवियत संघ और ईरान में लगाए गए दंडों की तुलना में हास्यास्पद हैं।

इस नए नियम से तुरंत होने वाला नुकसान ऑनलाइन गेमिंग मंच के मूल्यांकन में कई अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान और भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में 20,000 से ज्यादा नौकरियों का खत्म होना है। लंबे समय में, यह कदम प्रोग्रामर और डिजिटल कलाकारों के लिए डिजिटल नवाचार के माध्यम से जीविका कमाने के कई वैध रास्ते बंद कर देगा क्योंकि यह खेलों की पूरी श्रृंखला को गैरकानूनी घोषित करता है।

ज्यादा नुकसानदेह बात यह है कि यह ऑनलाइन गेमिंग मंच के रूप में उन 'परीक्षण स्थलों' को खत्म कर देता है जहां लोग कम जोखिम के साथ दांव लगाना सीख सकते हैं और किसी कक्षा में संयोजन सूत्र, मार्कोव चेन, मांटी कार्लो सिमुलेशन और प्रायिकता सिद्धांत को सीखने की तुलना में बहुत ज्यादा आनंद ले सकते हैं।

एक प्रतिभाशाली गेमर के बारे में सोचें जो एक नए गेम की कल्पना करता है और उसे दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। सबसे पहले, उसके विचार की एक समिति द्वारा जांच की जाएगी, जो उसे 'ई-स्पोर्ट्स', 'सोशल गेमिंग', या 'मनी गेम' के रूप में वर्गीकृत करेगी। भले ही यह बाधा बिना ज्यादा समय और परेशानी के पार हो जाए, फिर भी प्रोग्रामर के पास इन नियमों के अनुसार पैसा कमाने के लिए इसे भुनाने का कोई आसान रास्ता नहीं है।

ज्यादा संभावना यह है कि ऐसा प्रोग्रामर (कई युवाओं के पास गेमिंग से जुड़े अनूठे विचार हैं) बस एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढेगा। यह आसान है और इसके लिए बस डार्क वेब पर एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत होगी जहां सभी खिलाड़ी गुमनाम हों और भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में हो।

नए नियमों के इस खतरनाक पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। यह नए नियम जुए को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा बल्कि यह इसके बजाय वैकल्पिक विदेशी मंचों और भुगतान तंत्र के इस्तेमाल को सक्रियता से बढ़ावा देगा। डिजिटल रूप से जागरुक भारतीयों की एक बड़ी तादाद पहले से ही डार्क वेब का इस्तेमाल करती है और इसका अर्थ यह है कि वे क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सभी डार्क वेब भुगतान क्रिप्टो में होते हैं। सोवियत संघ में तस्करी किए गए ताश के पत्तों के इस्तेमाल की तरह, ये नए नियम भी इस तरह के तंत्र को और तेजी से अपनाने की वजह बन सकते हैं।

आपका पक्ष

भारतीय पेशेवरों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता

अमेरिका को यह समझना चाहिए कि एच-1बी वीजा के लाभों से सिर्फ विदेशी पेशेवर ही नहीं लाभान्वित होते हैं, बल्कि नियोक्ताओं को भी इससे बहुत लाभ होता है। यह वीजा जो विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्रदान किया जाता है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को अमेरिका में प्रवेश करने और वहां की कंपनियों में काम करने का अवसर देता है। इसके अलावा कई नियोक्ता ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां कामगारों की कमी है और हो सकता है कि उनके पास ऐसे योग्य अमेरिकी कर्मचारी न हों जो उनके क्षेत्र में स्थायी रूप से बसने के इच्छुक हों। ऐसे में एच-1बी प्रक्रिया, नियोक्ताओं को परियोजनाओं को पूरा करने या विशिष्ट पदों को भरने के लिए, विदेश से अस्थायी पेशेवरों को नियुक्त करने का अवसर प्रदान करती है। भारतीय पेशेवरों का

एच-1बी वीजा विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्रदान किया जाता है

प्रभाव अमेरिकी तकनीकी उद्योग में बहुत गहरा और व्यापक है। उनके नेतृत्व, इंजीनियरिंग कौशल और प्रतिस्पर्धी मानसिकता ने उन्हें सिलिकॉन वैली और टॉप टेक कंपनियों में काफी आगे बढ़ा दिया है। लेकिन अचानक प्रतिबंध से एच-1बी कामगारों पर निर्भर उद्योगों में तत्काल श्रम की कमी पैदा हो सकती है जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास प्रभावित होंगे। वैश्विक प्रतिभा तक पहुंच में कमी के कारण नवप्रवर्तन में मंदी आ सकती है। अगर अमेरिकी कंपनियों को योग्य घरेलू कामगार खोजने में कठिनाई होती है तो उन्हें उच्च श्रम लागत का सामना करना पड़ सकता है जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें काफी बढ़ सकती हैं।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का संदेश समझें

देश में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों को खानपान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मार्च 1975 में एडीए (अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन, अब - न्यूट्रिशन और डाइट साइंस एकेडमी) ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की शुरुआत की थी। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1982 में हुई थी। बच्चों को अगर संतुलित आहार दिया जाए तो वे जिंदगी भर बहुत सी जानलेवा बीमारियों से भी बच सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2019-20 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की पांचवीं रिपोर्ट का पहला भाग जारी किया था। इसमें यह खुलासा हुआ है कि हमारे देश के बच्चों में कुपोषण और मोटापा बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में 22 राज्यों के सर्वेक्षण का जिक्र है। जिसमें कहा गया कि 20 राज्यों में 5 साल से कम बच्चों में तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। आज की भागदौड़ जीवन में लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और वे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर लोग योग अपनाएं तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। योग से लोग अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते है। देश के सभी लोगों को योग का महत्त्व समझकर इससे जुड़ना चाहिए। युवाओं को खासतौर पर योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

अफगानिस्तान में मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद तालिबानी सैनिक और स्थानीय लोग राहत एवं बचाव अभियान में लगे हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हुए। पूर्वी अफगानिस्तान में मंगलवार को आए 6.0 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,400 से अधिक हो गई और 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

04 hindi nd-06_page 02.qxd 9/3/2025 6:54 PM Page 1

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 4 सितंबर 2025

शंघाई सहयोग संगठन

अमेरिकी एकाधिकार को चुनौती

हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहाः इसने चीन के एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने की घोषणा की, एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरूआत का संकेत दिया, और भारत की इस दुविधा को रेखांकित किया कि पूर्व की ओर देखें या पश्चिम की ओर। वास्तव में, तियानजिन शिखर सम्मेलन वैश्विक भू-राजनीति में एक निर्णायक क्षण का प्रतीक है। रूस, भारत, ईरान और बेलारूस जैसे नए सदस्यों की उपस्थिति के साथ, इस सम्मेलन ने पारंपरिक पश्चिमी नेतृत्व वाले ढांचे को चुनौती देने वाले राष्ट्रों के एक वैकल्पिक गठबंधन के रूप में इस समूह के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। चीन ने अपनी ओर से इस मंच का उपयोग बहुध्रुवीयता के अग्रदूत के रूप में अपनी भूमिका को प्रस्तुत करने के लिए किया।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए, यह सम्मेलन केवल कूटनीतिक नाटक नहीं था, बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की चीन की महत्वाकांक्षा का प्रकटीकरण था, एक ऐसी व्यवस्था जहां पश्चिमी प्रभुत्व से थके हुए देशों के बीच सामूहिक सहयोग से अमेरिकी आधिपत्य को रोका जा सके। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन राजनीतिक रूप से एकजुट मास्को के साथ, बीजिंग आज की भू-राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है। व्यापार गलियारों, रेल संपर्क और सामूहिक सुरक्षा पर जोर शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का स्पष्ट विस्तार है, जिसे एक बहुपक्षीय उद्यम के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है। वाशिंगटन के लिए, यह शिखर सम्मेलन एक चिंताजनक संकेत है। एससीओ अब ईरान और बेलारूस जैसे पुराने शत्रुओं से लेकर भारत जैसे स्विंग स्टेट्स तक, सभी देशों को एक साथ लाता है, जिनकी भागीदारी चीन और रूस के विरुद्ध एकजुट गठबंधन बनाने के अमेरिकी प्रयासों को जटिल बनाती है। अमेरिकी टैरिफ, व्यापार अनिश्चितताओं और गाजा तथा यूक्रेन पर उसके रुख ने चीन के लिए खुद को एक अधिक स्थिर आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के अवसर पैदा किए हैं। हालाँकि एससीओ में अभी भी नाटो या यूरोपीय संघ जैसी संस्थागत ताकत का अभाव है, लेकिन इसका विशाल आकार–जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और विशाल प्राकृतिक संसाधनों को कवर करता है–इसे संभावित रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इसका राजनीतिक आख्यान भी उतना ही महत्वपूर्ण हैः कि अमेरिकी प्रभुत्व न तो अपरिहार्य है और न ही सार्वभौमिक रूप से वांछनीय।

भारत के लिए, एससीओ शिखर सम्मेलन अवसरों और दुविधाओं, दोनों को उजागर करता है। नई दिल्ली की भागीदारी उसे यूरेशियाई सुरक्षा और व्यापार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यह बीजिंग के प्रभुत्व वाले गुट के साथ गठबंधन करने के विरोधाभासों को भी उजागर करती है। हालाँकि एससीओ ने आतंकवाद पर भारत के रुख को स्वीकार किया है, लेकिन चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है।

तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सावधानीपूर्वक दिए गए बयान – जिसमें उन्होंने ₹पारस्परिक सम्मान₹ और ₹संवेदनशीलता₹ पर जोर दिया – इसी संतुलनकारी कार्य को दर्शाते हैं। भारत किसी भी गुट का आँख मूँदकर अनुसरण नहीं कर सकता। चीन के वैश्विक दृष्टिकोण का समर्थन करने से क्वाड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी हिंद-प्रशांत साझेदारी को कमजोर करने का जोखिम है। तियानजिन शिखर सम्मेलन ने दिखाया कि एससीओ अब एक सीमांत गुट नहीं, बल्कि एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ वैश्विक आख्यानों की लड़ाई सामने आ रही है। चीन के लिए, यह बहुध्रुवीयता की ओर एक कदम है और अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था का एक विकल्प है, जबकि भारत को खुद को स्थापित करने और बहुध्रुवीय व्यवस्था में समान भागीदार बनने के लिए और अधिक गुंजाइश की आवश्यकता है।

थाईलैंड में उपद्रव, भारत को सबक

थाईलैंड में उथल-पुथल न केवल न्यायिक हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता के चक्र को रेखांकित करती है, बल्कि भारत के लिए भी सबक लेकर आई है, क्योंकि उसे अपनी अस्थिर सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है।

अशोक के मेहता
लेखक, सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं।

मैं पिछले शुक्रवार को थाईलैंड पहुंचा, ठीक उसी समय जब बैंकॉक संवैधानिक न्यायालय द्वारा पैतोंगटार्न शिनावात्रा को बर्खास्त करने के अपेक्षित फैसले से स्तब्ध था। पैतोंगटार्न शिनावात्रा पिछले साल एक चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनी थीं, जिसमें उनकी पार्टी फ्यू थाई और मूव फॉरवर्ड पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टियों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी।

पिछले शुक्रवार को ही, उनके पिता, जो लंबे समय से सैन्य-राजतंत्र के आलोचक और पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा थे, को एक अदालत ने शाही मानहानि के आरोप से बरी कर दिया था। उनकी बेटी, बहन, बहनोई और उनसे जुड़े दो अन्य लोगों सहित, 2008 से अब तक पाँच निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायिक संवैधानिक न्यायालय का गठन 1997 में सम्राट और सेना द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किया गया था।

संवैधानिक न्यायालय का नवीनतम हस्तक्षेप कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चार दिवसीय सीमा संघर्ष (24-28 जुलाई) के बाद हुआ, जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्प ने टैरिफ के हथियार का इस्तेमाल करके युद्धविराम का श्रेय लिया था।

प्रधानमंत्री शिनावात्रा की कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन, जिन्हें वह चाचा कहती हैं, के साथ गोपनीय फोन पर बातचीत के दौरान, उन्होंने रॉयल थाई आर्मी की आलोचना करते हुए, सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बूनसिन पैडक्लांग का नाम लेते हुए, ₹सीमा की स्थिति को संभालने पर सहमति जताई। शिनावात्रा और सेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक संबंधों को देखते हुए, सेन द्वारा लीक की गई इस गोपनीय बातचीत को थाईलैंड द्वारा विश्वासघात कहा गया।

इसके अलावा, सेन ने एक सार्वजनिक भाषण में चेतावनी दीः दोस्ती के वेश में पड़ोसी का विश्वासघात₹ और शिनावात्रा पर थाई सेना और राजशाही, जो थाईलैंड में सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक है, का अनादर करने का आरोप लगाया। जुलाई के अंत में सीसी द्वारा आदेशित नैतिक जाँच का परिणाम सेन द्वारा प्रेरित था।

युद्ध का एक त्वरित अध्ययन शिक्षाप्रद है। थाईलैंड और कंबोडिया की 817 किलोमीटर लंबी सीमा है। कई सीमा पार हैं, और 2024 में सीमा व्यापार 4.4 अरब अमेरिकी डॉलर का था। थाईलैंड में हाल ही में वैध किए गए कैसीनो कंबोडियाई लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और टकराव का एक स्रोत हैं। विवाद का मुख्य बिंदु प्रीह विहियर मंदिर है जिस पर दोनों का दावा है, चार अन्य मंदिर और 12 वर्ग किलोमीटर का एमराल्ड ट्रायंगल, जो लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड के जंक्शन पर स्थित है, भी विवादित हैं। 1907 में, फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान, इस क्षेत्र का मानचित्रण किया गया था, लेकिन सीमा का उचित रूप से सीमांकन नहीं किया गया था, जिससे कई विवादित क्षेत्र बचे रहे।

सभी औपनिवेशिक शासकों ने शासन की दीघार्यु और सुविधा₹ के लिए सीमाएँ चिह्नित कीं, जो अफ्रीका के मानचित्र पर सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। थाईलैंड विशिष्ट रूप से उपनिवेशित नहीं था। सबसे हिंसक सीमा विवाद 2008 में हुआ था, जिसकी शुरूआत कंबोडिया ने प्रीह विहियर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करके की थी। 2011 में, कंबोडिया इस विवाद को फिर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया, जिसके 1962 के फैसले में प्रीह विहियर को कंबोडियाई क्षेत्र में घोषित किया गया, लेकिन अन्य विवादित क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। 24 जुलाई की नवीनतम घटना स्पष्ट रूप से सेन-शिनावात्रा कुलों के बीच के झगड़ों और प्रधानमंत्री शिनावात्रा की बर्खास्तगी से संबंध स्थापित करती है। रॉयल कंबोडियन आर्मी के डिप्टी कमांडर और थर्ड सपोर्ट डिवीजन के कमांडर जनरल स्रे डुक इस लड़ाई में मारे गए। झड़पों से पहले, डुक विवादित स्थल चोंगबुक के पास आरटीए के मेजर जनरल सोमपॉप पारंग के साथ बातचीत कर रहे थे। डुक 2011 की झड़पों के बाद से सीमा वार्ता में शामिल थे।

कथित तौर पर थाई जवाबी हमले में एक और कंबोडियाई जनरल मारा गया। डुक पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाया गया, उनकी पत्नी ने विवादित एमराल्ड ट्रायंगल में एक संगीत समारोह का आयोजन किया था। इसे तनाव बढ़ने के संकेत के रूप में देखा गया। थाईलैंड ने हाल ही में संप्रभुता की रक्षा के अधिकार के रूप में हासिल किए गए चार ग्रिपेन स्वीडिश लड़ाकू विमानों को तैनात किया। स्वीडन पर संघर्ष क्षेत्रों में घातक उपकरण बेचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक' स्तर पर ले लिया।

24 जुलाई को झड़पें तीव्र हो गईं, जब कंबोडिया ने बीएम-21 रॉकेट और तोपखाने दागे, जिससे एक थाई अस्पताल और एक 7-इलेवन स्टोर नष्ट हो गया और आठ नागरिक मारे गए। झड़पों में ग्यारह थाई सैनिक मारे गए। सीमा पर असहज शांति बनी हुई है क्योंकि युद्धविराम के बाद विवादित सीमाओं पर गश्त के दौरान थाईलैंड के सैनिकों को बारूदी सुरंगों से भारी नुकसान हुआ है। युद्धविराम के बाद से 28 जुलाई से 9 अगस्त, 12 अगस्त और 27 अगस्त (इससे पहले 16 और 23 जुलाई को दो बार) को छह बारूदी सुरंगों से होने वाली क्षति हुई है।

थाईलैंड ने कंबोडिया पर ओटावा कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जो प्लास्टिक की खदानों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। मलेशियाई प्रधान मंत्री और आसियान के अध्यक्ष अनवर इब्राहिम ने वियतनाम और सिंगापुर के साथ मिलकर युद्धविराम की मध्यस्थता की; अमेरिका ने विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, हालांकि थाईलैंड विवाद को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना चाहता था। 1 अगस्त को, थाईलैंड ने 23 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल को विवादित स्थलों पर भेजा। पर्यवेक्षकों में भारतीय नौसेना अताशे भी शामिल थे।

2 अगस्त को, थाईलैंड ने सीमा के पास लड़ाई के शहीदों को याद किया। छअउ पर भारत के चीन के साथ कई विवादित पॉकेट हैं। हाल ही में गिने गए पूर्वी लद्दाख में थे, जहां योग्य विघटन हुआ है, लेकिन डी-एस्केलेशन और डी-इंडक्शन के बहुत कम संकेत हैं।

हमारे सशस्त्र बलों के प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर के बाद नाटकीयता, भविष्य के युद्धों की प्रकृति और राजनीतिक-सैन्य निर्णय लेने के पैमाने पर सबक सीखने और मानक बनाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, यह भूलकर कि ऑपरेशन सिंदूर चार दिनों का संघर्ष था (थाईलैंड-कंबोडिया की तरह)। यह असामान्य रूप से संपर्क रहित, दृश्य सीमा से परे था, जहाँ मानवयुक्त प्रणालियाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पार नहीं कर पाईं। इसमें भारतीय वायु सेना और उसकी वायु रक्षा प्रणालियाँ तथा अन्य भूमि-आधारित रॉकेट और मिसाइलें अग्रणी भूमिका में थीं, जिससे थलसेना और नौसेना लगभग युद्ध से बाहर हो गए। किसी भी हताहत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, हालाँकि नागरिक हताहतों की संख्या सैन्य हताहतों की संख्या से अधिक थी।

127 वीरता पुरस्कारों में वीर चक्र, महावीर चक्र और सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 40 विशिष्ट सेवा पदक शामिल थे। भारतीय सैन्य अभियानों के इतिहास में पहली बार, कोई प्रशस्ति पत्र दर्ज नहीं किया गया और संपर्क रहित संघर्ष के लिए वीरता पुरस्कार दिए गए। वीरता पुरस्कार पारंपरिक रूप से दुश्मन के सामने गंभीर जोखिम के साथ दिखाए गए असाधारण साहस और बहादुरी के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। दृश्य-सीमा से परे 88 घंटे की गोलीबारी में यह पुरस्कार मामूली ही हो सकता था।

पुरस्कारों की अधिकता, प्रशस्ति-पत्रों, हताहतों और उपकरणों के नुकसान के बारे में पारदर्शिता का अभाव अभूतपूर्व है और यह एक अलग कहानी बयां कर सकता है। थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष से भारत के लिए प्रमुख राजनीतिक सबक यह है कि उसे चीन और उससे भी अधिक तत्काल पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहिए। लेकिन यह तभी हो सकता है जब दिल्ली इस्लामाबाद के साथ बातचीत के लिए सहमत हो।

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा संघर्ष के कारण एक जनरल की हत्या हुई और बैंकॉक में सत्ता परिवर्तन हुआ - एक और शिनावात्रा हताहत और निरंतर राजनीतिक अस्थिरता ने संभवतः एक और सैन्य प्रधानमंत्री के लिए रास्ता तैयार किया।

टैरिफ संकट का सुधार में रूपांतरण

सरल और स्थिर कर एवं शुल्क व्यवस्थाओं के साथ-साथ, हमें श्रम सुधारों की भी आवश्यकता है। 2020 में पारित चार श्रम संहिताएं, जो संभावित रूप से क्रांतिकारी थीं, अभी तक लागू नहीं हुई हैं।

गोविंद भट्टाचार्जी
लेखक, सीएजी कार्यालय के पूर्व डीजी हैं।

भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ निराशाजनक तो है, लेकिन इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। निर्यात हमारी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं– निर्यात-आयात का अंतर सकल घरेलू उत्पाद का एक घटक है, और यह विदेशी मुद्रा को जन्म देता है जो हमारे आयातों, खासकर तेल, के भुगतान के लिए बेहद जरूरी है, जिसका 90 प्रतिशत हम अपनी जरूरतों का आयात करते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता का आकलन अक्सर इस बात से किया जाता है कि वे कितने महीनों के आवश्यक आयातों को पूरा कर सकते हैं, और बारह महीनों को इष्टतम माना जाता है। हालांकि, विदेशी मुद्रा का संचय लागत-रहित नहीं हैः विदेशी मुद्रा को रुपये में बदलने से उत्पादन में समान वृद्धि के बिना तरलता बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।

जून 1991 में, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब डॉलर से नीचे गिर गया था, जो सिर्फ. तीन हफ़्तों के आयात के बराबर था। इसने हमें बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। तब से, हमने एक लंबा सफर तय किया है।

आज, हमारा भंडार 700 अरब डॉलर को छू रहा है, जो वस्तुओं के हमारे वार्षिक आयात बिल (वित्तीय वर्ष 2025 में 720 अरब डॉलर) के लगभग बराबर हो गया है।

जबकि हमारा व्यापार घाटा 283 अरब डॉलर था, हमारा चालू खाता घाटा, जिसमें सेवाओं का व्यापार और हस्तांतरण भुगतान भी शामिल है, केवल 94 अरब डॉलर था, और हमारा समग्र भुगतान संतुलन, जिसमें पूंजीगत लेनदेन शामिल हैं, केवल 5 अरब डॉलर का घाटा दिखा रहा था।

वास्तव में, वित्त वर्ष 2025 के दौरान शुद्ध सेवा निर्यात और प्रेषण से विदेशी मुद्रा भंडार में 22 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे कुल मिलाकर 325 अरब डॉलर की प्राप्ति हुई, जो व्यापार घाटे की भरपाई से कहीं अधिक है।

अमेरिका के साथ, हमारा व्यापार अधिशेष 41 अरब डॉलर था, जबकि अदृश्य लाभ कमोबेश संतुलित रहे। भले ही यह पूरा अधिशेष बढ़े हुए टैरिफ से खत्म हो जाए, लेकिन यह भारत की अर्थव्यवस्था या उसके बाह्य खाते के लिए विनाशकारी नहीं होगा।

हां, इससे परिधान, रत्न और झींगा जैसे महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों में कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जिसका समाधान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, एसएंडपी द्वारा भारत की रेटिंग को बीबीबी में अपग्रेड करने और जेपी मॉर्गन तथा ब्लूमबर्ग उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किए जाने के साथ, भारत के पास अब विदेशी पूंजी तक पहुंच सस्ती है, जो 1991 के बिल्कुल विपरीत है। हमारा निर्यात क्षेत्र भी अत्यधिक विविध है - यह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। व्यापार के अलावा, यह सेवाओं द्वारा भी संचालित होता है, जिसमें भारत विश्व में अग्रणी है।

हमारा विकास निर्यात आधारित नहीं है। इसका 70 प्रतिशत से अधिक घरेलू खपत से आता है। वर्तमान संकट हमें 1991 की तरह, क्रांतिकारी सुधारों को लागू करके स्वयं को सुधारने का अवसर देता है। सरकार ने जीएसटी को सुव्यवस्थित करके पहला महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा लिया है। वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में केवल 2.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, भारत के पास अपने विनिर्माण आधार को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद में अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान 17-18 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की अपार संभावना है। चीन की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत से अधिक है। इस रणनीति में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है।

आयातित पुर्जों को असेंबल करने जैसे कम मूल्य वाले कार्यों से उच्च मूल्य वाले कार्यों में बदलाव, और कपड़ा क्षेत्र जैसे उत्पादन के तरीकों को तकनीक और एआई के साथ आधुनिक बनाना। एक बार जब हमारे उत्पाद आयात पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, तो इससे कोई फर्क.नहीं पड़ता कि वे देश के अंदर बेचे जाते हैं या बाहर।

टैरिफ के इस तूफान से निपटने के लिए, हमें और ज्यादा आत्मनिर्भरता की जरूरत है, जिसका मुख्य आधार अब उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) है, जिसे 2020 में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुरू किया गया था। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर स्मार्टफोन, फार्मा उत्पादों, ऑटोमोबाइल (ईवी सहित) और नवीकरणीय ऊर्जा में सफलताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन कपड़ा, इस्पात आदि जैसे अन्य क्षेत्र बहुत पीछे रह गए हैं।

भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल अब ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन आदि सहित 27 प्रमुख क्षेत्रों में फैल गई है। इसने नीतिगत सुधारों (उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तेज मंजूरियाँ, व्यापार करने में आसानी में सुधार), बुनियादी ढांचे के विकास (औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट शहर) और कौशल विकास (कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया) को बढ़ावा दिया है जिससे भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह लगभग दोगुना होकर 81 अरब डॉलर हो गया है।

लेकिन संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रसद लागत एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जो चीन में 8-9 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 13-14 प्रतिशत अनुमानित है, और इसे बेहतर मल्टीमॉडल परिवहन, माल ढुलाई गलियारों और बढ़ी हुई बंदरगाह क्षमता के माध्यम से कम किया जाना चाहिए। उद्योगों के लिए बिजली शुल्क भी एशिया में सबसे अधिक हैं, जिससे क्रॉस-सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है।

सरल और स्थिर कर एवं शुल्क व्यवस्थाओं के साथ-साथ, हमें श्रम सुधारों की भी आवश्यकता है। 2020 में पारित चार श्रम संहिताएं, जो संभावित रूप से क्रांतिकारी थीं, अभी तक लागू नहीं हुई हैं। इस बीच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) रोजगार बाजारों को नया रूप दे रही है, लेकिन इंजीनियरिंग शिक्षा और कौशल प्रणालियाँ अभी भी बदलते परिदृश्य के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उद्योग-अकादमिक सहयोग और भी गहरा हो गया है।

आत्मनिर्भरता वैश्वीकरण से पीछे हटना नहीं है, बल्कि मजबूत स्थिति से दुनिया के साथ जुड़ने की एक रणनीति है।

आप की बात

शिक्षकों के सम्मान से मूल्यों का विकास

किसी भी देश को विकसित और मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा व्यवस्था की होती है साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुचारू सुवास्थित और मजबूत करने का दायित्व शिक्षकों का होता है जहां शिक्षकों का सम्मान अधिक होता है वहां का समाज अधिक सुदृढ़,सुसंस्कारी और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होता है।विद्यालयों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधारभूत स्तंभ माना जाता है और इस स्तंभ की संपूर्ण व्यवस्था एक शिक्षक के हाथों में होती है शिक्षक की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। शिक्षक अपने शिक्षा के जरिये व्यक्ति,समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। उनकी शिक्षा की वजह से व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार होता है और वह हर परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम हो पाता है शिक्षक एक खूबसूरत आईने की तरह है जिससे व्यक्ति अपने वजूद की पहचान कर पाता है किसी भी समाज के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षक ही समाज को सही दिशा देने की क्षमता रखता है।अपनी सृजनात्मक क्षमता के जरिए वह न सिर्फ समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, अपितु नवाचारों को स्थापित करके नए शैक्षिक वातावरण का निर्माण भी कर सकता है। शिक्षक किसी भी समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। समाज मे सबसे अहम भूमिका शिक्षा की होती है।

- **माधव पटेल**, दमोह, मप्र

तेजी से बढ़ती दिल की बीमारी

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और जहां कभी यह परेशानी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित थी वहीं अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं ऐसे समय पर सही समय पर पहचान और इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है इसी बीच डॉक्टरों ने एक नई उम्मीद जगाई है अकस्टेथोस्कोप के रूप में यह स्मार्ट डिवाइस महज पंद्रह सेकेंड में तीन जानलेवा हार्ट कंडीशन्स को पकड़ सकता है यानी मरीज को अब घंटों तक टेस्ट या महंगी जांचों का इंतजार नहीं करना होगा बल्कि तुरंत सही डायग्नोसिस मिल सकेगा और इलाज शुरू हो पाएगा यह स्टेथोस्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है जो हार्टबीट और ब्लड फ्लो की आवाजों को रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण करता है और चंद सेकेंड में बता देता है कि दिल में कोई असामान्यता है या नहीं डॉक्टरों के अनुसार यह एओर्टिक स्टेनोसिस जिसमें हार्ट वॉल्व पूरी तरह खुल नहीं पाता माइट्रल रिगर्जिटेशन जिसमें हार्ट वॉल्व ठीक से बंद नहीं होता और खून उलटी दिशा में बहता है और हार्ट फेलियर जिसमें दिल पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता जैसी गंभीर बीमारियों को पकड़ लेता है। मरीजों के लिए इसका मतलब है तेज और आसान डायग्नोसिस महंगे टेस्ट की जरूरत में कमी समय रहते सही इलाज की संभावना ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए।

- **विभुक्ति बुपक्या**, अक्षत खाचरोद, उज्जैन

संस्कृत विदेशों में पसंद

ए यूनिवर्सल सोसाइटी आफ हिंदुइजा के अध्यक्ष राजन जेड ने संस्कृत के वेदमंत्रों से मंत्रोच्चारण कर शुभारंभ कियोकई देशों में संस्कृत में हनुमान चालीसा ,आरती की चौपाइयां विदेशी लोग गाते हैकहने का मतलब ये है कि संस्कृत के प्रति उनका लगाव है। किंतु वर्तमान में ऐसा लगने लगा है की संस्कृत भाषा अपने ही देश मे पराई होकर अस्तित्व तलाश रही है। यह कटु सत्य है। एक जानकारी मुताबिक अमेरिका में ओकलाहामा प्रान्त के सीनेट सत्र की शुरआत के अवसर पर संस्कृत भाषा के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक होगा ताकि संस्कृत अपना मूल स्थान पाकर विलुप्त होने से बच सके। यह सही है कि कोई भी भाषा बोलते -लिखते समय अंग्रेजी प्रयोग का समावेश होता ही है शुद्ध भाषा का प्रतिशत इसी कारण कम होता जा रहा है ।अंग्रेजी इस समय एक वायरस के रूप मे कार्य कर रही है ,जिससे प्रभावित होकर अन्य देशों कि प्रचलित भाषाए भी अंग्रेजी से पीड़ित हो गई हैमानाकि अंग्रेजी का ज्ञान आज के इलेक्ट्रानिक युग बेहद आवश्यक है ,कितु उससे इतने भी प्रभावित न हो कि अपनी भाषा/ प्राचीन संस्कृत भाषा मे भी अंग्रेजी का प्रयोग करके उसकी गरिमा व सम्मान के हक को छिन लें`क्या हम मनीषियों कि भाषा को ऐसे ही खो जाने देंगे ? शास्त्रों ,पुराणों,ग्रंथों की मूल भाषा जिसका हम वंदन करते आये हैं।

- **संजय वर्मा**, मनावर, धार

शरणार्थियों की समस्या

भारत ने हमेशा से ही शरण देने की परंपरा निभाई है। जब-जब दुनिया के किसी कोने में धार्मिक उत्पीड़न हुआ, तब-तब भारत ने पीड़ितों के लिए अपने द्वार खोले। हाल ही में केंद्र सरकार का यह फैसला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को बिना पासपोर्ट भी भारत में रहने की अनुमति मिलेगी, वास्तव में करुणा और मानवता का उदाहरण है। यह आदेश उन लाखों लोगों के लिए जीवनदान जैसा है, जिनकी पीढ़ियां धार्मिक भेदभाव और प्रताड़ना का बोझ झेलते हुए अपनी पहचान और आस्था बचाने की जद्दोजहद कर रही थीं। मुस्लिम बहुल देशों में इन अल्पसंख्यकों की हालत किसी से छिपी नहीं है। वहाँ उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, उनकी बेटियों को जबरन उठाया जाता है, उनकी संपत्तियाँ छीनी जाती हैं और रोजमर्रा का जीवन भय और असुरक्षा में गुजरता है। जब हालात असहनीय हो जाते हैं, तब ये लोग अपनी मिट्टी, अपना घर-आँगन, अपने रिश्ते सब पीछे छोड़कर भारत की ओर देखते हैं। उनके लिए हिंदुस्तान केवल एक देश नहीं, बल्कि एकमात्र आश्रय है। यहाँ उन्हें सुरक्षा, सम्मान और जीने की आजादी मिल सकती है। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ-साथ एक और अपेक्षा भी है। जो समयसीमा 31 दिसंबर 2024 तक तय की गई है, उसे बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक कर दिया जाना चाहिए।

- **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

अतीत को कोसते रहने से भविष्य भी बिगड़ता है

आफत बनी बरसात

जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम चक्र में आई तब्दीली का परिणाम है आवश्यकता से अधिक बारिश अथवा कम समय में ज्यादा वर्षा। इसके नतीजे में देश के एक बड़े हिस्से में बाढ़ और जल भराव के चलते लोगों को गंभीर समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। चूंकि इस बार अर्से बाद इतनी लंबी अवधि तक बरसात हो रही है, इसलिए वर्षा जनित समस्याएं कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं। सबसे अधिक समस्याओं से दो-चार हैं देश के पर्वतीय राज्य। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में अधिक बारिश के कुछ ज्यादा ही दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इन राज्यों में भूस्खलन की जितनी अधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, वे गंभीर चिंता का कारण हैं, लेकिन यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि चेतने से इन्कार किया जा रहा है। इसका एक प्रमाण यह है कि उन कारणों के चलते जान-माल की अधिक क्षति हो रही है, जो ज्ञात हैं और जिनका निवारण किया जाना चाहिए था। समझना कठिन है कि पहाड़ों से अनावश्यक छेड़छाड़ और पहाड़ी नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण कार्य से क्यों नहीं बचा जा रहा है? आखिर इस तथ्य को क्यों ओझल किया जा रहा है कि यदि नदियों के स्वाभाविक मार्ग को बाधित किया जाएगा तो वे तबाही का कारण बनेंगी? पर्वतीय राज्यों को इससे भी चिंतित होना चाहिए कि आखिर अब बादल फटने की इतनी अधिक घटनाएं क्यों हो रही हैं?

इस बार बारिश पर्वतीय राज्यों के साथ-साथ मैदानी राज्यों में भी कहर ढा रही है। इसका कारण केवल जरूरत से ज्यादा बारिश होना नहीं है। इसका एक कारण कमजोर आधारभूत ढांचे का निर्माण और जल निकासी के उपयुक्त उपाय न किया जाना है। यही कारण है कि नई बनी सड़कों और यहां तक कि एक्सप्रेसवे और हाईवे तक पर जाम लग रहे हैं। शहरों के अंदर की सड़कें भी जल भराव और जाम से जूझ रही हैं। स्थिति यह है कि महानगर तक की सड़कों में जल निकासी के पर्याप्त उपाय नहीं दिख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि कहीं पर भी ज्यादा बारिश होगी तो उससे कुछ न कुछ समस्याएं उपजेंगी ही, लेकिन इन समस्याओं पर एक बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। यह तभी संभव है, जब बुनियादी ढांचे का निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए और जल निकासी के बेहतर उपाय किए जाएं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतर उपायों की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन उनके अनुरूप कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखता। यही स्थिति जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को बढ़ाने वाले कारणों का निवारण करने के उपायों के मामले में भी है। एक बड़ी व्यथा यह है कि मानसून विदा होते ही यह भुला दिया जाएगा कि देश के लोगों को अति वर्षा, बाढ़, जल भराव आदि के कारण कैसे-कैसे संकटों से जूझना पड़ा?

सपनों को उड़ान

बिहार के पूर्णिया में 15 सितंबर को एयरपोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। यह एयरपोर्ट न केवल पूर्णिया बल्कि कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के लोगों के सपनों को उड़ान दे रहा है। अभी तक यहां के लोग हवाई उड़ान के लिए पटना, बागडोगरा और दरभंगा एयरपोर्ट पर आश्रित रहते हैं। इसके लिए उन्हें सड़क मार्ग से तीन से पांच घंटे की दूरी तय करनी होती है, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट बन जाने से समय की काफी बचत होगी। मालूम हो कि इस इलाके से बड़ी संख्या में लोग नौकरी के सिलसिले में बाहर जाते हैं, जिन्हें आने-जाने में अब सुविधा होगी। यह एयरपोर्ट उद्योग जगत की राह भी आसान करेगा और उम्मीद करनी चाहिए कि इस इलाके में कल-कारखानों की संख्या बढ़ेगी। हाल ही में पटना से पूर्णिया के लिए एक्सप्रेस वे को भी मंजूरी मिली है। यानी परिवहन का हर मार्ग सुगम होने जा रहा। विकास का पहिया और तेजी से दौड़ता नजर आएगा। वैसे भी कोसी-सीमांचल और पूर्व बिहार के जिले बिहार के दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत कम विकसित हैं। बाढ़, भौगोलिक दशा के कारण आधारभूत संरचनाओं की कमी की वजह से यह इलाका पिछड़ता रहा है, लेकिन अब बेहतरी की उम्मीद की जानी चाहिए। बिहार में कुछ और एयरपोर्ट के निर्माण की राह आसान हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर भी फाइल तेजी से दौड़ रही है। अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित एयरपोर्ट से कार्गो विमानों की उड़ानों की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। ऐसा हुआ तो यहां के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मक्का, आम, केला और मखाना जैसे उत्पादों को आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकेगी।

पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ से इलाके के विकास को गति मिलेगी

राष्ट्रीय चिंता का विषय बने घुसपैठिए

अशोक कुमार

घुसपैठिए भारत की आंतरिक शांति को खतरे में डालने और विकास को बाधित करने के अलावा लोकतांत्रिक तानेबाने एवं संप्रभुता के लिए भी खतरा बन रहे

अवधेश राजपूत

सीमा पार से घुसपैठ भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंताओं में से एक बन गई है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस खतरे को रेखांकित करते हुए कहा, 'अवैध घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजी-रोटी छीन रहे हैं, हमारी बेटियों और बहनों को निशाना बना रहे हैं और निर्दोष आदिवासियों की वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।' उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में इन जनसांख्यिकीय बदलावों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन के गठन की घोषणा भी की है। यह इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक दृढ़ प्रयास का संकेत देता है। घुसपैठ अब केवल सीमा-विशेष के स्तर पर ही समस्या नहीं रह गई है। दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके दूरगामी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

घुसपैठ एक राष्ट्रीय चिंता बन गई है। बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों ने असम, बंगाल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बदल दिया है। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ा है। इसके चलते भूमि, भाषा और पहचान को लेकर टकराव पैदा हो रहा है। स्थानीय लोगों में धारणा बढ़ रही है कि घुसपैठिए कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक तुष्टीकरण का लाभ उठा रहे हैं। इस धारणा ने जातीय राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। कट्टरपंथी समूह ऐसी भावनाओं का फायदा उठाने में तत्पर रहते हैं, जिससे सामाजिक एकता को और खतरा पैदा होता है। इस समस्या को विकराल बनाने में राजनीतिक दल भी कम दोषी नहीं। अधिकांश दलों ने वोट-बैंक के लिए जाली दस्तावेजों के जरिये घुसपैठियों को सरकारी जमीनों खासकर नदियों के निकट और वन क्षेत्रों में बसाने में मदद की है। अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दीर्घकालिक समझौता हो जाता है। इससे नागरिकों और राज्य के बीच अविश्वास गहराता है। समय रहते अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भारी अशांति का कारण बन सकता है, विशेषकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां जनसांख्यिकीय दबाव बढ़ रहा है। इसके तब और विध्वंसक परिणाम सामने आते हैं जब घुसपैठिए कृषि, निर्माण और घरेलू मजदूरी से जुड़े काम में संलग्न हो जाते हैं। इससे बाजार सस्ते मजदूरों से भर जाता है और स्थानीय श्रमिकों के हितों पर चोट पहुंचती है। सुरक्षा के जोखिम अलग बढ़ जाते हैं। कई घुसपैठिए अनौपचारिक या ग्रे इकोनमी में भी लिप्त होते हैं, जहां वे पशु तस्करी, मादक पदार्थों, जाली मुद्रा और अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ये गतिविधियां न केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट को भी मजबूत बनाती हैं। इनमें से कुछ के आतंकवादियों से संबंध भी होते हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर भी घुसपैठिए बोझ बढ़ा रहे हैं। इस बोझ के चलते 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना भी पटरी से उतर सकता है।

शत्रु पक्ष की रणनीतियों के कारण भारत की सीमाओं पर समस्याएं बढ़ रही हैं। पंजाब में ड्रोन के जरिये ड्रग्स और हथियार से जुड़े आतंकवाद ने जोर पकड़ लिया है। भारत-म्यांमार सीमा पर दुर्गम इलाके उग्रवादियों की आवाजाही और अवैध प्रवेश को बढ़ावा देते हैं। साइबर अपराधियों और मजदूरों के वेश में छिपे गुप्त एजेंट जांच को और जटिल बना देते हैं। बीते दिनों बांग्लादेश-मेघालय सीमा पर पाकिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है, जो अब पूर्वी सीमा पर कमजोरियों का फायदा उठाने के फेर में है। सुरक्षा बलों की भरसक कोशिशों के बावजूद व्यापक भौगोलिक परिस्थितियां भी प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। 2011 में मालदा जिले में पशु तस्करों ने एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। एक सर्वेक्षण के अनुसार 500 मीटर क्षेत्र पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों ने कब्जा किया हुआ था। इससे सुरक्षा अभियान के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गईं। स्थानीय खुफिया नेटवर्क भी प्रभावित हो रहा है। ऐसी वास्तविकताएं यही संकेत करती हैं कि घुसपैठ केवल सीमा उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, यह आंतरिक समन्वय को भी कमजोर कर सकती है। संकट के समय दुश्मन देशों के साथ साठगांठ को बढ़ावा दे सकती है।

जनसांख्यिकीय सुरक्षा मिशन एक आवश्यक कदम है। इसे सफल बनाने के लिए राह में आने वाली चुनौतियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। नकली पहचान पत्र, दस्तावेज वालों पर कानूनी शिकंजा कसना होगा। उन्नत सीमा बाड़, निगरानी तकनीकें और नागरिक सत्यापन प्रणालियां भी जरूरी होंगी। कौटिल्य ने लिखा है, 'सीमाओं पर स्थित प्रदेशों में विश्वसनीय लोगों और सैनिकों से आबाद किलेबंद नगर स्थापित करने चाहिए। विदेशियों को सीमावर्ती प्रदेशों में बसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' यह सलाह आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्र की संप्रभुता जनसांख्यिकीय अखंडता पर भी निर्भर करती है।

घुसपैठ एक क्षेत्रीय चुनौती ही नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत संकल्प और सामाजिक एकता की एक बुनियादी परीक्षा भी है। इसके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आवश्यक है, जो अल्पकालिक राजनीति से ऊपर उठे। यदि यह मुद्दा अनसुलझा रहा तो अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी। घुसपैठिए देश की आंतरिक शांति को खतरे में डालने के साथ ही विकास को बाधित कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है जब घुसपैठ देश के लोकतांत्रिक तानेबाने और संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए। यह न भूला जाए कि जो राज्य अपनी सीमाओं की उपेक्षा करता है, वह अव्यवस्था को आमंत्रित करता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने भविष्य की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए।

(बीएसएफ में भी रह चुके लेखक उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी हैं)
response@jagran.com

रोका जाए धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग

सीवीपी श्रीवास्तव

इस पर जोर देने की आवश्यकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है

उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के अगले सत्र में पेश किए जाने वाले धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में प्रविधान है कि नौकरी, धन या अन्य उपहारों का लालच देकर किसी व्यक्ति का मतांतरण करने के प्रयास को जबरन पंथ परिवर्तन माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। अंतःकरण व्यक्ति के ज्ञान, अंतर्ज्ञान और तर्कशक्ति का मिश्रण है, जो उसे किसी मत-मजहब के सिद्धांतों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम आस्था में परिवर्तन को भी एक अधिकार मान लेते हैं। इसलिए जब भी राज्य उपासना पद्धति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा निर्धारित करने या मत परिवर्तन रोकने का प्रविधान करता है तो कुछ लोग इसे अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करार देते हैं। यह अक्सर विवाद और टकराव का रूप ले लेता है।

मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित करीब दस राज्यों में ऐसे कानून लागू हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने भी मत परिवर्तन निषेध कानून बनाए हैं। कई और राज्य भी इस दिशा में पहल कर रहे हैं। मतांतरण के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने भी ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इन सभी कानूनों में एक बात समान है कि विवाह के लिए मतांतरण को संज्ञेय और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ऐसे कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध हैं। इसलिए इन अधिकारों के संवैधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है। इसलिए और भी, क्योंकि छल-छद्म से मतांतरण के मामले सामने आते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कथित छांगुर बाबा की ओर से कराए जाने वाले मतांतरण अभियान का षड्यंत्र आंखें खोलने वाला है।

संविधान में अनुच्छेद 25-28 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। एक ओर ये अधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं, वहीं दूसरी ओर इनका सार धार्मिक सहिष्णुता है। यही भारत में पंथनिरपेक्षता का आधार भी है। इसीलिए संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े जाने के बाद इसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता इसे स्पष्ट कर देती है। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 मामले में उच्चतम न्यायालय ने न केवल पंथनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया, बल्कि यह भी कहा कि भारतीय संविधान लागू होने के समय से ही पंथनिरपेक्ष था। अनुच्छेद 25-28 के तहत मिले अधिकारों में अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ-साथ अपनी उपासना पद्धति को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और उसके प्रचार-प्रसार करने का अधिकार भी शामिल है।

मतांतरण के विरुद्ध प्रदर्शन करतीं महिलाएं। फाइल

भारत में पंथनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है। इसी कारण राज्य सामान्यतः धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता, पर सांप्रदायिकता भड़कने की आशंका की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 25(2) में उल्लेख है कि राज्य पंथ से संबंधित राजनीतिक, वित्तीय या अन्य लौकिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकता है। इस आधार पर यह कहना उचित है कि भारत में पंथनिरपेक्षता संविधान में राज्य की नीति के रूप में शामिल है। यह न तो किसी मत के पक्ष में है, न उसके विरुद्ध और न ही यह किसी मत के प्रति तटस्थ है। यह मतविरोधी नहीं, बल्कि संप्रदायवाद विरोधी है। ये सभी प्रविधान दर्शाते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग और संस्थाएं इसे अधिकार की तरह इस्तेमाल करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद 18 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपासना पद्धति को मानने, न मानने या उसे बदलने का अधिकार है। भारत संयुक्त राष्ट्र की नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करता है, लेकिन भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर अपनी उपासना पद्धति बदल तो सकता है, लेकिन वह इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। मत परिवर्तन के इस अधिकार को न देने के पीछे मूल विचार सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को रोकना है। अफसोस कि ये प्रवृत्तियां थम नहीं रहीं और इसीलिए राज्य सरकारें कानून बनाने के लिए विवश हैं।

यदि मत परिवर्तन के अधिकार को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में दिया जाएगा तो इसका दुरुपयोग बढ़ेगा और जबरन मतांतरण की घटनाओं में भी वृद्धि होगी। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस प्रकार दिया गया है कि भारत का पंथनिरपेक्ष चरित्र मजबूत रहे और इन अधिकारों के किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में राज्य सांप्रदायिक ताकतों को नियंत्रित कर सके। हमें यह देखना ही होगा कि मतांतरण में संलग्न ताकतें देश के पंथनिरपेक्ष चरित्र में छेड़छाड़ न करने पाएं।

(लेखक सेंटर फार अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

विनम्रता

व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है और आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण में विनम्रता जैसे गुणों का प्रमुख योगदान होता है। विनम्रता का भाव ही व्यक्तित्व की आभा बढ़ाकर उसे लोकप्रिय बनाता है। जीवन संघर्ष में विनम्र व्यक्ति प्रत्येक झंझावात को सहजता से पार कर लेता है। वह उस हरी लकड़ी की भांति होता है जो वायु के जोर से स्वयं को बचाने में सक्षम रहती है। जबकि कड़क मिजाज वाला व्यक्ति सूखी हुई टहनी की भांति टूटकर बिखर जाता है। विनम्रता सफलता को स्थायी बनाए रखती है। सफल व्यक्ति विनम्रता के रथ पर आरूढ़ होकर लंबी दूरी कर लेता है। जबकि सफलता के बाद अभिमान के रथ पर सवार हुआ व्यक्ति कुछ दूरी तय करने के बाद ही हांफने लगता है। उसकी सफलता स्थायी नहीं रह पाती।

विनम्र व्यक्ति से सभी सहजता से सामीप्य बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करते। उनके आसपास मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है। विनम्रता का गुण व्यक्ति के कार्यों को और अधिक श्रेष्ठ बना देता है। विनम्र व्यक्ति कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित करता है तो सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अगर वह व्यक्ति इसके विपरीत स्वभाव रखता है तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसकी असफलता पर उपहास होने लगता है, जबकि विनम्र व्यक्ति को असफलता की स्थिति में भी ढांढ़स बंधाने वालों की कमी नहीं होती।

हम कालजयी महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं तो एक पहलू सबके व्यक्तित्व में एकसमान मिलता है और वह है उनका विनम्र स्वभाव। भगवान राम की विनम्रता के अनेक प्रसंग पढ़ने को मिल जाते हैं। शबरी के जूठे बेरों को ग्रहण करना उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा ही तो है। विनम्रता का तेज व्यक्ति के ललाट को तेजस्विता प्रदान करता है। विनम्रता की पोथी पढ़कर जीवन की कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया जा सकता है।

ललित शौर्य

पोषण ट्रैकर से संभव बड़ा बदलाव

डा. मोनिका शर्मा

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह

डिजिटल टूल के रूप में पोषण ट्रैकर देश में कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

किसी भी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की नींव गुणवत्तापूर्ण पोषण पर टिकी होती है। चिंतनीय है कि भारत में कुपोषण की स्थितियों से जूझने के हालात आज भी कायम हैं। ऐसे में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के सात दिन (एक से सात सितंबर) बहुत से मोर्चों पर पोषणयुक्त खानपान को लेकर सजगता लाने से ही जुड़े हैं। दरअसल, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, सही पोषण लेने पर केंद्रित एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इस अभियान के अंतर्गत बहुत से स्थानीय और वैश्विक समुदाय विभिन्न आयोजनों और माध्यमों से उचित पोषण के महत्व को समझाते हैं। ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2025 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय भी 'बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें' है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत यह थीम स्वस्थ खान-पान की आदतों, संतुलित आहार और पोषणयुक्त भोजन को लेकर आमजन को शिक्षित-सजग करने से जुड़ी है।

पोषण ट्रैकर एप केंद्र सरकार के पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे जुटाई गई जानकारियां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुखद है कि भारत में तकनीक के माध्यम से भी कुपोषण से जूझने की राह निकाली गई। नेशनल न्यूट्रिशन वीक के स्वास्थ्य सहेजने वाले अभियान का अहम हिस्सा बना पोषण ट्रैकर ऐप महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह मोबाइल एप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण की निगरानी एवं प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सका। इस टूल ने वजन, लंबाई, टीकाकरण, भोजन आदि की जानकारी रखने और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार द्वारा एक मार्च 2021 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के माध्यम से शुरू किए गए इस एप से पोषण सेवाओं के उचित वितरण में भी रेखांकित करने योग्य बदलाव आए हैं।

वस्तुतः पोषण ट्रैकर कुपोषण और पोषण संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से ट्रैक करने में मदद करता है। डिजिटल टूल के रूप में पोषण ट्रैकर देश में कुपोषण से निपटने और सुपोषण अभियान को बल देने में अहम भूमिका निभा रहा है। पोषण ट्रैकर दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन एप है, जिसने पोषण अभियान से जुड़े अधिकारियों के लिए कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने और अधिक कुशलता से सेवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद की है। महिलाओं व बच्चों के लिए पोषणयुक्त खानपान और कुपोषण से बचाव के मोर्चे पर यह तकनीकी सहायता सजगता लाने और स्वास्थ्य सहेजने वाली है। **(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)**

एक बड़ी उपलब्धि जनधन योजना

'गरीबों को सशक्त बनाने वाली योजना' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में रमेश कुमार दुबे ने जिस वित्तीय क्रांति का संदर्भ दिया, वह देश के लिए निःसंदेह मील का पत्थर साबित हुई है। वित्तीय क्षेत्र में जनधन योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति बैंक से जुड़ने में सक्षम हुआ। अन्यथा बैंकिंग सेवाओं तक सभी की सहज पहुंच नहीं हो पाई थी। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय क्षेत्र में क्रांति की जो उम्मीद जगी थी, वह जनधन के बाद ही पूरी तरह साकार हो सकी। जनधन योजना ने सरकारी योजनाओं से रिसाव रोककर लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। लेखक ने उचित ही रेखांकित किया कि कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू तो बहुत गाजे-बाजे के साथ होती हैं, लेकिन एक समय के बाद शिथिलता की शिकार होकर अपने उद्देश्यों को पूरा नही कर पातीं। इस संदर्भ में जनधन जैसी योजना अपवाद रही। इसकी सफलता में यह पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण रहा कि सरकार ने इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए इसमें आवश्यक सुधार किए। निःसंदेह, यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

डा. मिथिलेश कुमार, भागलपुर (बिहार)

विदेशी वस्तुओं पर घटे निर्भरता

बुधवार को संपादकीय पेज पर ''डिजाइन इन इंडिया'' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख विचारणीय है। वर्षों से हम विदेश निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का नारा तो लगाते आ रहे हैं, किंतु यह प्रायः प्रतीकात्मक ही दिखाई देता है। ऐसे में

मेलबाक्स

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'सेमीकान इंडिया' कार्यक्रम में दिए गए वक्तव्य में ''डिजाइन इन इंडिया'' पर जो बल दिया गया है, वह वस्तुतः ''मेक इन इंडिया'' का ही विस्तारित रूप है। यह पहल तभी सार्थक होगी, जब इसे धरातल पर ठोस रूप से उतारा जाए। भारत के पास कच्चे माल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बौद्धिक क्षमता भी अपार है, धन और कामगारों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। आवश्यकता केवल दूरदर्शी कार्ययोजना की है, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकें और विदेशी वस्तुओं के आयात पर निर्भरता घटा सकें। इसके लिए केवल बड़े-बड़े उद्योगों पर निर्भर रहने के बजाय छोटे-छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा। जैसे एक कंप्यूटर निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए तो उसमें प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों का निर्माण अलग-अलग लघु उद्योगों में हो सकता है। इस प्रकार देशभर में फैली लघु एवं मध्यम इकाइयां रोजगार भी बढ़ाएंगी और उत्पादन क्षमता भी। हां, हमें तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और आयात की आवश्यकता रहेगी, लेकिन इसका लाभ तभी अधिक होगा, जब उसका उपयोग घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने और ''डिजाइन इन इंडिया'' को वास्तविक रूप में उतारने के लिए किया जाए।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

स्वदेशी अपनाए जाने पर हो जोर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में देश की जनता से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग किए जाने पर जोर दिया है। हालांकि ऐसा वह निरंतर कहते आ रहे हैं। फिर भी, त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से न केवल हमारे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हाल ही में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाए गए आयात शुल्क से देश से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होंगे, जिससे उद्योगों पर असर पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि सब मिलकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और 'लोकल फार वोकल' पर जोर दें। हमारे त्योहार वैसे भी संस्कृति, परंपराओं और विरासत से निहित हैं। त्योहारों को अपने मूल तरीके से मनाना ही सच्चे भारतीय होने की पहचान है। आज हमारा देश जिन प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, उसे देखते हुए हम सभी भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करके देश को आत्मनिर्भर बनाएं और पीड़ित लोगों के बुरे समय में साथ दें।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****